



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]
No 22]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 30, 1992/ज्येष्ठ 9, 1914
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 30, 1992/JYAISTHA 9, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 मई, 1992

को.आ. 1322:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1919
(1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की
सिफारिशों पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधि-
नियम की धारा 10-ख की उप धारा (1) एवं (2) के
उपबंध, सांगली बैंक लिमिटेड, सांगली पर 1 मई, 1992
से 30 जून, 1992 की दो मास की अवधि के लिए या
नए अध्यक्ष एवं कार्य-पालक अधिकारी के पदभार ग्रहण करने
तक, इनमें से जो भी पहले हो, लागू नहीं होंगे।

[सं. 15/3/91-बी.ओ. III(1)]

के.के. मंगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)

New Delhi, the 8th May, 1992

S.O. 1322.—In exercise of the powers conferred by Sec-
tion 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949),
the Central Government on the recommendations of the
Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions
of sub-sections (1) and (2) of Section 10B of the said
Act, shall not apply to the Sangli Bank Limited, Sangli for
a period of two months from 1st May, 1992 to 30th June,
1992 or till the new Chairman and Chief Executive Officer
takes charge, whichever is earlier.

[No. 15/3/91-B.O. III(i)]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 1992

का.आ. 1323:—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
(1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की

मिफारिशों पर, एतद्वारा घोषणा केस्ती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10-ख को उपधारा (9) के उपबंध सांगली बैंक लिमिटेड, सांगली पर पहली मई, 1992 से 30 जून 1992 तक अथवा बैंक के नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक बैंक को चार महीने से अधिक के वास्ते अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का काम करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति करने को छूट प्राप्त है।

[सं. 15/3/91-बी. ओ. III(12)]

के.के. मंगल, अवर सचिव

New Delhi, the 8th May, 1992

S.O. 1323.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on recommendations of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-sections (9) of Section 10B of the said Act, shall not, to the extent they preclude the bank from appointing a person to carry out the duties of a Chairman beyond a period exceeding four months, apply to the Sangli Bank Limited, Sangli from 1st May, 1992 to 30th June, 1992 or till the new Chairman and Chief Executive Officer takes charge whichever is earlier.

[No. 15/3/91-B.O. III(ii)]

K. K. MANGAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 मई, 1992

का.आ. 1324:—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, इस विभाग की दिनांक 10 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 1-4/77-आर.आई.बी.(1) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उपयुक्त अधिसूचना में “श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग और पुलवामा जिले” शब्दों के स्थान पर “श्रीनगर, बड़गांव, अनंतनाग, पुलवामा, ऊधमपुर और डोडा जिले” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. एफ 7-3-90-आर.आई.बी.]

वी. बी. माथुर, अवर सचिव

New Delhi, the 11th May, 1992

S.O. 1324.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in this Department's notification No. F. 14/77-RRB(I) dated 10th September, 1979 namely:—

In the said notification, for the words “districts of Srinagar, Badgam, Anantnag and Pulwama”, the words “districts of Srinagar, Badgam, Anantnag”, Pulwama, Udhampur and Doda” shall be substituted.

[No. F. 7—32/90-RRB]

V. B. MATHUR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.आ. 1325:—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खण्ड 5 के उप खण्ड (1) के साथ पठित खण्ड 3 के उप खण्ड (क), खण्ड 7 और खण्ड

8 के उप खण्ड (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के बाद, एतद्वारा, श्री एम. एस. चहल को 5 अप्रैल, 1992 से प्रारम्भ होकर 4 जुलाई, 1992 तक की और अवधि के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पुनः नियुक्त करती है।

[सं. एफ 9/64/91-बी.ओ. I]

के. जी. गोयल, निदेशक

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1325.—In pursuance of sub-clause (a) of clause 3 read with sub-clause (1) of clause 5, clause 7 and sub-clause (1) of clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby reappoints Shri M. S. Chahal as the Chairman and Managing Director of the Punjab and Sind Bank for a further period commencing on 5th April, 1992 and ending with 4th July, 1992.

[F. No. 9/64/91-BO.I]

K. G. GOEL, Director

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.आ. 1326:—मैसर्स एलोकॉन इंजिनियरिंग कम्पनी लि., वल्लभ विद्यानगर-388120, गुजरात को सामान्य मुद्रा क्षेत्र के अन्तर्गत डीजीटीडी द्वारा साक्ष्यांकित सूची के अनुसार मर्दों के आयात (गैर सूचीबद्ध मर्दों) के लिये रुपये 2,00,00,000/- (रुपये दो करोड़ मात्र) का एक आयात लाइसेंस सं. पी/डी 2022333 दिनांक 22/3/91 मंजूर किया गया था।

फर्म ने उपयुक्त लाइसेंस को सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति उनसे कहीं खो गई या गुम हो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति सीमा शुल्क प्राधिकारी, बम्बई के पास पंजीकृत कराई थी और इस प्रकार सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति का आंशिक तौर पर उपयोग किया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक, पेटलाद-388450 के समक्ष विधिवत रूप से शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथपत्र दाखिल किया है। मैं, तदनुसार संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं. पी/डी 2022333 दिनांक 22-3-91 की मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म से कहीं खो गई या गुम हो गई है। अतः यथा-संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 दिनांक 7-12-55 की उपधारा 9 (गग) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग

करते हुये मैसर्स एलीकॉन इंजीनियरिंग कम्पनी लि., वल्लभ विद्यानगर को जारी की गई उक्त मूल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति सं. पी/डी 2022333 दिनांक 22-3-91 एतद्वारा रद्द की जाती है।

3. उक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की अनु-लिपि पार्टी को अगल से जारी की जा रही है।

[एफ.सं.सप्ली/एनएस/1278/डीजीटीडी/एम 91/एसएलएस/90]

माया डी. केम, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1326.—M/s. Elecon Engineering Company Limited, Vallabh Vidyanagar-388120, Gujarat, were granted an import licence No. P/D/2022333 dated 22nd March, 1991 for Rs. 2,00,00,000 (Rupees Two Crores only) for import of items (unlisted items) as per list attested by DGTD under GCA.

The firm has applied for issue of Duplicate copy of Customs purposes copy of the above mentioned licence on the ground that the original Customs purposes copy of the licence has been lost or misplaced. It has further been stated that the Customs purposes copy of the licence was registered with Customs Authority, Bombay and as such the value of Customs purpose copy was utilised partially.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Petlad-388450. I am accordingly satisfied that the original Customs purposes copy of import licence No. P/D/2022333 dated 22nd March, 1991 has been lost or misplaced by the firm, in exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7th December, 1955 as amended the said original Customs purposes copy No. P/D/2022333 dated 22nd March, 1991 issued to M/s. Elecon Engineering Co. Ltd., Vallabh Vidyanagar is hereby cancelled.

3. A duplicate Customs purposes copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. Suppl/NS/1278/DGTD/AM91/SLS/90]

MAYA D. KEM, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports & Exports.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

पूर्व-अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के मामले में

और

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के मामले में

का.ग्रा. 1327.—जबकि भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. एस.ओ. 1955, दिनांक 25 जून, 1962 में प्रकाशित योजना के अनुसार लागू किये जाने के लिए भारत के पूर्व अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष से संबद्ध अनुसूची में निर्दिष्ट सम्पत्ति को सौंपने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन पत्र दिया गया है।

अतः अब पूर्व अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और पूर्वोक्त आवेदन पत्र के आधार पर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त सम्पत्ति भारत के पूर्व अक्षयनिधि के कोषाध्यक्ष के अधिकार में रहेगी और यह भी निर्देश देती है कि उक्त सम्पत्ति और उससे प्राप्त आय का पूर्वोक्त योजना में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाएगा।

अनुसूची

1,50,00,000/- रुपये (केवल एक करोड़, पचास लाख रु.) की राशि का 5 वर्षीय डाकघर सावधि जमा लेख में राष्ट्रीय कल्याण प्रतिष्ठान की ओर से निवेश किया गया। यह जमा राशि 12 नवम्बर, 1991 से प्रभावी होगी और इसका 22 सितम्बर, 1995 को 13.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित पुनर्भुगतान किया जाएगा।

[सं. एफ. 8-4/89-एन.एफ.टी.डब्ल्यू.]

नावेद मसूद, निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Education)

New Delhi, the 14th May, 1992

In the matter of Charitable Endowments Act, 1890.

AND

In the matter of the National Foundation for Teachers' Welfare.

S.O. 1327.—Whereas an application has been made to the Central Government for vesting the property specified in the schedule appended hereto in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be applied in accordance with the Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Education, number S.O. 1955, dated the 25th June, 1962;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890) and on the application as aforesaid, the Central Government hereby directs that the said property shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and also directs that the said property and the income thereof shall be applied in accordance with the terms set out in the aforesaid Scheme.

SCHEDULE

A sum of Rs. 150,00,000 (Rupees one hundred and fifty lakhs only) invested on behalf of the National Foundation for Teachers' Welfare in 5-Year Post Office Time Deposit Account, the deposit being effective from the 12th November, 1991 repayable on the 12th November, 1996 with interest at the rate of 13.5 per cent per annum.

[No. F. 8-4/89-NFTW]

NAVED MASOOD, Director

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

(पुरातत्व)

नई दिल्ली, 15 मई, 1992

का.ग्रा. 1328.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारक राष्ट्रीय महत्व का है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक तथा पुरा-तत्त्वमय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का

24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 4 मार्च, 1989 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति के विभाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अधिसूचना सं. का.आ. 410, तारीख 5 फरवरी, 1989 को अधिकक्रांत करते हुए उक्त संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की सूचना देती है।

केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त संस्मारक में हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आक्षेप पर विचार करेगी।

आक्षेप, निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जनपथ, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजे जा सकेंगे।

अनेसूची

संघ राज्य क्षेत्र	जिला	तहसील	परिक्षेत्र
1	2	3	4
दमण और दीव	दीव	दीव	दीवशहर
संस्मारक का नाम	संरक्षण के अधीन सम्मिलित किए जाने वाले राजस्व प्लॉट संख्यांक		
5	6		
भवनों सहित किला	सर्वेक्षण प्लॉट सं. 1/पी टी एस/88		
क्षेत्र	सीमाएं		
7	8		
5.673	उत्तर: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 5/पी टी एस/89 और अरब सागर		

8

पूर्व: अरब सागर

दक्षिण: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 3/पी टी एस/117 और 3 /पी टी एस/119 और अरब सागर

पश्चिम: सर्वेक्षण प्लॉट सं. 4 /पी टी एस/117 और 34/पी टी एस/90

स्वामित्व

टिप्पणियां

9

10

सरकार

शून्य

[फा.सं. 2/2/84-संस्मारक]

मुनीश चन्द्र जोशी, महानिदेशक

(Department of Culture)

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 15th May, 1992

(ARCHAEOLOGY)

S.O. 1328.—Whereas the Central Government is of the opinion that the ancient monument specified in the schedule annexed hereto is of national importance;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), and in supersession of the notification of the Government of India, Department of Culture (Archaeological Survey of India) number S.O. 410 dated the 6th February, 1989, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 4th March 1989, the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said monument to be of national importance;

Any objection which may be received from any person interested in the said monument within a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette will be considered by the Central Government.

The objection may be addressed to the Director, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011.

SCHEDULE

Union Territory	Distt.	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot numbes to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Daman & Diu	Diu	Diu	Diu Town	Fort together with the Buildings inside it	Survey No. 1/PTS/88	5.673 Hectares	North : Survey plot No. 5/PTS/89 and Arabian Sea East: Arabian sea. South : Survey Plot Nos. 3/PTS/	Government	Nil

1	2	3	4	5	6	7	8
							117 and 3/PTS/ 917 and Arabian Sea West.—Survey Plot Nos. 4/PTS/ 117 and 34/PTS/ 90

[F.No. 2/2/84-M]

M.D. JOSHI, Dir. General.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मई, 1992

का.आ.1329.—चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 7 और 8 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस मंत्रालय के दिनांक 30-9-1991 की अधिसूचना 809/5/91-एफ(सी) के अनुक्रम में, केन्द्र सरकार द्वारा श्री मेजर जनरल टी. वी. मनोहरन, के-44 अन्नानगर, मद्रास 600102 को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मद्रास सलाहकार पैनल में सदस्य नामित किया जाता है।

[फा. सं. 809/9/92-एफ(सी)]

एस. लक्ष्मीनारायन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 15th May, 1992

S.O. 1329.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952) read with rules 7 and 8 of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983 and in continuation of this Ministry's Notification No. 809/5/91-F(C) dated 30th September, 1991, the Central Government is pleased to appoint Maj. Gen. T. V. Manoharan, K-44 Anna Nagar, Madras-600102, as a member of the Madras advisory panel of the Central Board of Film Certification with immediate effect and until further orders.

[File No. 809/9/92-F(C)]

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 13 मई, 1992

का.आ.1430.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन एक्स जी से जी एन ए क्यू तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा शक्तियां का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बसते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आश्रय सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदा-9 कोम इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आश्रय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. O-12016/1/92 ओ.एन.डी.डी. IV]

एम माटिन, डैस्क अधिकारी

अनुसूची

जी एन एक्स जी से जी एन ए क्यू जी जी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य-गुजरात जिला-भरुच तालुका-बागरा

गांव	ब्लॉक नं.	है	आर	से
1	2	3	4	5
वांसेटा	199/ए बी	0	13	26
	191	0	10	53
	192	0	08	97
	190	0	09	62
	188	0	00	86
	194	0	05	14
	195	0	04	94
	196	0	03	38
	199	0	01	08
	182	0	00	94
	200	0	09	36
	201	0	04	55
	232	0	04	42
	233	0	05	20
	234	0	00	98
	230	0	00	72
	229	0	06	76

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	228	0	07	28		199	0	01	08
	227	0	04	42		182	0	00	94
	226	0	04	68		200	0	09	36
	225	0	06	24		201	0	04	55
	254	0	25	74		232	0	04	42
	219	0	00	68		233	0	05	20
	255	0	07	54		234	0	00	98
	कार्ट ट्रैक	0	01	17		230	0	00	72
	303	0	03	12		299	0	06	76
	304	0	08	97		228	0	07	28
	302	0	02	86		227	0	04	42
	309	0	12	98		226	0	04	68
	298/ए	0	00	62		225	0	06	24
	298/बी	0	08	06		254	0	25	74
	297	0	15	34		219	0	00	68
	296	0	00	42		255	0	07	54
	कार्ट ट्रैक	0	01	56		Cart track	0	01	17
						303	0	03	12
						304	0	08	97
						302	0	02	86
						309	0	12	98
						298/A	0	00	62
						298/B	0	08	06
						297	0	15	34
						296	0	00	42
						Cart track	0	01	56

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 13th May, 1992.

S.O. 1330.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from GNXG to GNAQ in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Fractitioner.

[No. O-12016/1/92-ONG.D. IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM GNXG TO CNAQ GGS

State : Gujarat—District—Bharuch, Taluka—Vagra

Village	Block no.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
VANCETA	189A/B	0	13	26
	191	0	10	53
	192	0	08	97
	190	0	09	62
	188	0	00	86
	194	0	05	14
	195	0	04	94
	196	0	03	38

नई दिल्ली, 13 मई, 1992.

का.आ. 1331:—यह : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी सी से जी जी एस-II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता कि ऐसे लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को को इस अधिसूचना की तारीख से 31 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा की क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. 12016/2/92-ओ. एन. जी. डी. 4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

जी एन जी सी से जी जी एस-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य-गुजरात जिला-भरुच तालुका-वाग्रा

पालडी				
356	0	04	16	
375	0	08	9	

1	2	3	4	5
	374	0	08	19
	289/ए/बी	0	05	07
	363/ए/बी	0	19	33
	288	0	37	40
	286	0	06	63
	277/बी	0	08	58
	276/बी	0	13	24
	267	0	16	34
	265/ए/बी	0	09	36
	268	0	03	38
	269	0	28	56
	273	0	08	64
	274	0	02	12

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1331.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from GNGC to GGS-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

[No. O-12016/2/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM GNGC TO GGS II

State : Gujarat District Bharuch Taluka VAGRA

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
PALDI	356	0	04	16
	375	0	08	93
	374	0	08	19
	289/A/B	0	05	07
	363/A/B	0	19	33
	288	0	37	40
	286	0	06	63
	277/B	0	08	58
	276/B	0	13	24
	267	0	15	54
	265/A/B	0	09	36
	268	0	03	38
	269	0	28	56
	273	0	08	64
	274	0	02	12

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.आ. 1332-यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पी डी ए आई से पादरा ई पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद् अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति; उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा की क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. 12016/3/92-ओ.एन.जी.डी. 4]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

पी डी. ए. आई. से पादरा ई. पी. एस. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।
राज्य-गुजरात जिला-बड़ोदा तालुका-वादरा

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	संटीयर
ताजपुरा	343	0	07	02
	344	0	05	16
	346	0	04	68
काटं ट्रेक	0	00	78	
	348	0	22	75
	355	0	04	50
	356	0	07	20
	367	0	12	48
काटं ट्रेक	0	00	52	
	412	0	08	06
	414	0	08	02
	411	0	00	43
	421	0	01	98
	415	0	06	47
	419	0	10	92
	420	0	01	82
काटं ट्रेक	0	00	52	
	483	0	08	06
	484	0	07	80
काटं ट्रेक	0	00	78	
	491	0	03	93
	490	0	06	37
	486	0	07	15
	487	0	10	92

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1332.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from PDAI to Padra EPS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

[No. O-12016/3/92-ONG.D.-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM PDAI TO PADRA EPS

State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra

Village	Block No.	Hect.	Are	Centiare
TAJPURA	343	0	07	02
	344	0	05	16
	346	0	04	68
	Cart track	0	00	78
	348	0	22	75
	355	0	04	50
	354	0	07	20
	367	0	12	48
	Cart track	0	00	52
	412	0	08	06
	414	0	08	02
	411	0	00	43
	421	0	01	98
	415	0	06	47
	419	0	10	92
	420	0	01	82
	Cart track	0	00	52
	483	0	08	06
	484	0	07	80
	Cart track	0	00	78
	491	0	03	90
	490	0	06	37
	486	0	07	15
	487	0	10	92

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.अ. 1333:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी जे डी डी से दहेज जी जी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1062 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी को मार्फत।

[सं. ओ-12016/4/92-ओ.एन.जी.डी. IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

डी जे डी डी से दहेज जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य-गुजरात जिला-भरुच तालुका-वागरा

गांव	ब्लॉक नं	हे.	आभार	से.
कोलीयाद	1/ए/बी/सी / पी	0	50	96
	231	0	14	43
	174	0	24	96
	180	0	05	20
	189/बी	0	06	24
	190	0	13	26
	191	0	18	46
	188/ए	0	01	04
	188/बी	0	00	52
	181/ए	0	00	28
	183/बी	0	17	68

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1333.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from DJDD to Dahej GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/4/92-ONG.D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM DJDD TO DAHJ CGS

State : Gujarat	Distt. : Bharuch	Taluka : Vagra			
Village	Block No.	Hec.	A.e.	Cent.	
1	2	3	4	5	
KOLIYAD	1/A/B/C/P	0	50	96	
	231	0	14	43	
	174	0	24	96	
	180	0	05	20	
	189/B	0	06	24	
	190	0	13	26	
	191	0	18	46	
	188/A	0	01	04	
	188/B	0	00	52	
	181/A	0	00	28	
	183/B	0	17	68	

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1334:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीजेएन से पक्वाजन जी जी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन-तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति; उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ - 12016/5/92 - ओ एन जी डी - IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

डीजेएन से पक्वाजन जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राज्य - गुजरात, जिला - भरुच तालुका - वागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी०
1	2	3	4	5
वाव	18	0	10	14
	5	0	09	75
	6	0	02	21

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1334.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from DJAN to Pakhajan GGS in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/5/92-D-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM DJAN TO PAKHAJAN GGS

STATE : Gujarat DISTT. Bharuch TALUKA Vagra

Village	Block No.	Hec.	Are	Cent.
WAV	18	0	10	14
	5	0	09	75
	6	0	02	21

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1335.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के आई ए सी से ई एल ए ए से एस डब्ल्यू एम बी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन-तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ - 12016/6/92 - ओ. एन. जी. डी - IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

के. आई. ए. सी. से ईएलएल एसेएस डब्ल्यूएम बी तक पाईप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - हंसोट

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
बालोता	1043	0	44	85
	1113	0	00	18
कार्ट ट्रैक		0	00	78
	1141	0	00	18
	1114	0	04	03
	1115	0	13	13
	1116	0	08	06
	1117	0	17	42
	1125	0	00	64
	1122	0	04	56
	1123	0	03	28
	1121	0	04	78
	1120	0	00	38
	1014	0	07	80
	849	0	09	08
	850	0	09	14
	851	0	09	10
	1007	0	00	28
कार्ट ट्रैक		0	01	76
	852	0	09	88
	853	0	05	46
	854	0	00	12
	843	0	08	00
	863	0	02	21
	866	0	10	06
	864	0	07	67
	865	0	08	58
	871	0	03	12
	873	0	00	32
	872	0	04	88
	790	0	39	78
	781	0	00	08
	788	0	02	99
	787	0	11	05
	786	0	05	85

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1335.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from KIAC to ELAA to SWMB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act,

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/6/92-ONG.D-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM KIAC TO ELLA TO SWMB
State : Gujarat District Bharuch Taluka Hansot

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
1	2	3	4	5
BALOTA	1043	0	44	85
	1113	0	00	18
	Cart track	0	00	78
	1141	0	00	18
	1114	0	04	03
	1115	0	13	13
	1116	0	08	06
	1117	0	17	42
	1125	0	00	64
	1122	0	04	56
	1123	0	03	28
	1121	0	04	78
	1120	0	00	38
	1014	0	07	80
	849	0	09	08
	850	0	09	14
	851	0	09	10
	1007	0	00	28
	Cart track	0	01	76
	852	0	09	88
	853	0	05	46
	854	0	00	12
	843	0	08	00
	863	0	02	21
	866	0	10	06
	864	0	07	67
	865	0	08	58
	871	0	03	12
	873	0	00	32
	872	0	04	88
	790	0	39	78
	781	0	00	08
	788	0	02	99
	787	0	11	05
	786	0	05	85

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1336.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के आई ए सी से ईएलए एसेएस डब्ल्यूएम बी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूचित में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ - 12016/7/92 - ओ. एन. जी. डी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

के. आई. ए. सी. से ई. एल. एस. से एस. ए. डब्ल्यू. एम. बी तक पाइप लाईन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - हासोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	अर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
ईलाव	575	0	04	16
	572	0	18	72
	569	0	28	86

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1336.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from KIAC to ELAA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/7/92-ONGD.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from KIAC to ELAA to SWMB.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
ILAO	575	0	04	16
	572	0	18	72
	569	0	28	86

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1337 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में के आई. सी. से ई. एल. एस. से एस. डब्ल्यू. एम. बी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ - 12016/8/92-ओ. एन. जी. डी. -IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

के आई. सी. से ई. एल. एस. से एस. डब्ल्यू. एम. बी तक पाइपलाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - हासोट

गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	अर.	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
अकलवा	463	0	57	88
	446	0	02	86
	447	0	24	05

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1337.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from KIAC to ELAA to SWAB in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/8/92-ONG D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from KIAC to ELAA To SWMB.

State : GUJARAT District ; BHARUCH Taluka : HANSOT

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
ANKALWA	463	0	57	85
	446	0	02	86
	447	0	24	05

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1338.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पखाजन जी जी एस से 'टी' बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ-12016/9/92 - ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

पखाजन जी.जी.एस से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - बागरा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
केशवान	951	0	26	72
	957	0	10	72
	956	0	09	88
	960	0	10	92
	961	0	18	72
	976	0	18	46
	962/ए/बी	0	25	74
	963	0	01	98
	913	0	06	86

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1338.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to 'T' Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/9/92-ONG D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from PAKHAJAN GGS to 'T' point

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
KESHWAN	951	0	26	72
	957	0	10	72
	956	0	09	88
	960	0	10	92
	961	0	18	72
	976	0	18	46
	962/A/B	0	25	74
	963	0	01	98
	913	0	06	86

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1339 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक-हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन सी ए से जी जी एस -II तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ-12016/10/92-ओ.एन.जी.डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

जी.एन.सी.ए. से जी.जी.एस-II तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे.	अर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
पालडी	83	0	05	20
	85	0	06	24
	90	0	10	90
	94	0	21	32
	97	0	02	08
	98	0	00	92
	100	0	00	28
	102	0	28	98
	103	0	13	91
	117	0	13	65
	109	0	22	36
	107	0	01	92
	108	0	18	36
	161/ए/बी	0	20	93
	318	0	18	46
	184	0	13	78
	185	0	12	74
	182	0	07	93
	181	0	05	20
	180	0	19	24
	206	0	11	05
	207	0	10	14
	208	0	11	70
	213	0	14	30
	224	0	13	04
	214	0	03	64
	221	0	05	85
	216/ए/बी	0	02	73
	220	0	01	80
	217/ए/बी	0	39	26
	255	0	07	28
	256	0	18	85
	257	0	02	01
	274	0	15	08

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1339.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from G.N.C.A. to G.G.S-II in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/10/92-ONG D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from GNCA To GGS-II

State : Gujarat District : Bharuch Taluka VAGRA

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent
1	2	3	4	5
PALDI	83	0	05	20
	85	0	06	24
	90	0	10	90
	94	0	21	32
	97	0	02	08
	98	0	00	92
	100	0	00	28
	102	0	28	98
	103	0	13	91
	117	0	13	65
	109	0	22	36
	107	0	01	92
	108	0	18	36
	161/A/B	0	20	93
	318	0	18	46
	184	0	13	78
	185	0	12	74
	182	0	07	93
	181	0	05	20
	180	0	19	24
	206	0	11	05
	207	0	10	14
	208	0	11	70
	213	0	14	30
	224	0	13	04
	214	0	03	64
	221	0	05	85
	216/A/B	0	02	73
	220	0	01	80
	217/A/B	0	39	26
	225	0	07	28
	256	0	18	85
	257	0	02	01
	274	0	15	08

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. प्रा. 1340.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी.जी.डी.डी. से वडोज जी.जी.एस. तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. O-12016/11/92-ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

डी. जे. डी. डी. से दहेज जी.जी.एस. तक पाइप बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागता

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टी
1	2	3	4	5
वंगणी	139	0	07	5

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1340.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to 'T' Point Gujarat State pipeline should be paid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any persons interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No O-12016/11/92-ONG. D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM DJDD TO DAHEJ GGS.

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Village	Bolck No.	Hct.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Vangani	139	0	07	54

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. नं. 1341-—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पश्वाजन जी.जी. एस. से 'टी' बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. O-12016/12/92-ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

परवाजन जी. जी. एस. से 'टी' बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य - गुजरात जिला - भरुच तालुका - वागता

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेन्टी.
1	2	3	4	5
गोलादरा	83	0	07	28
	86	0	00	56
	85	0	18	72
	89	0	14	95
	91	0	09	88
काटे ट्रेक	0	03	38	
411	0	09	26	
109	0	14	56	
108	0	06	50	
107	0	11	70	
118	0	12	74	
119/ए/बी	0	15	8	

1	2	3	4	5
	120	0	03	64
	123/ए	0	00	30
	122	0	05	46
	121	0	12	48
	कार्ट ट्रैक	0	02	60
	242	0	01	10
	241	0	18	85
	कार्ट ट्रैक	0	00	52
	255	0	01	04
	237	0	09	36
	कार्ट ट्रैक	0	00	78
	257/पी	0	01	56
	258	0	14	56
	259	0	21	84
	287	0	07	80
	286	0	04	94
	288	0	27	56
	281	0	08	32
	301	0	34	32
	300/पी	0	01	12
	302	0	15	34
	304	0	19	24

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1341.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to T Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/12/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

1	2	3	4	5
Goladara	83	0	07	28
	86	0	00	56
	85	0	18	72
	89	0	14	95

1	2	3	4	5
	91	0	09	88
	Cart track	0	03	38
	111	0	09	36
	109	0	14	56
	108	0	06	50
	107	0	11	70
	118	0	12	74
	119/A/B	0	15	08
	120	0	03	64
	123/A	0	00	30
	122	0	05	46
	121	0	12	48
	Cart track	0	02	60
	242	0	01	10
	241	0	18	85
	Cart track	0	00	52
	255	0	01	04
	237	0	09	36
	Cart track	0	00	78
	257/P	0	01	56
	258	0	14	56
	259	0	21	84
	287	0	07	80
	286	0	04	94
	288	0	27	56
	281	0	08	32
	301	0	34	32
	300/P	0	01	12
	302	0	15	34
	304	0	19	24

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1342.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पखाजण जी.जी.एस. से टी विन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा की क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ. 12016/13/92-ओ एन जी डी-IV]

एम० माटिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची				
परवाजन जीजी एस से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए				
राज्य—गुजरात जिला—भरुच तालुका—बागरा				
गांव	ब्लाक नं.	हे	आर	से
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अम्बेल	59	0	12	74
	57	0	13	26
	55	0	05	24
	58	0	08	45
	51	0	15	86
काई ट्रेक		0	01	56
42		9	29	64
43		0	18	33
31		0	22	88
32		0	08	84
काई ट्रेक		0	01	56
278/ए/बी		0	23	90
279		0	00	15
277		0	20	80
276		0	01	38

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1342.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to 'T' Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/13/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6
Ambhel	59	0	12	74	
	57	0	13	26	
	55	0	05	24	
	58	0	08	45	
	51	0	15	86	

1	2	3	4	5
	Cart track	0	01	56
	42	0	29	64
	43	0	18	33
	31	0	22	88
	32	0	08	84
	Cart track	0	01	56
	278/A/B	0	23	90
	279	0	00	15
	277	0	20	80
	276	0	01	38

नई दिल्ली, 13 मई 1992

का. आ.1343.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में परवाजन जी जी एस से 'टी' बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समझ प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. O-12016/14/92/ओ.एन.जी.डी.-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

परवाजन जी जी एस से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य—गुजरात जिला - भरुच तालुका—बागरा

गांव	ब्लाक नं.	हे	आर	से०
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरणावी	11	0	06	24
	12	0	14	56
	20	0	27	17
	21	0	11	44
	28	0	15	08
	27	0	27	04

1	2	3	4	5
	काई ट्रैक	0	00	65
	38	0	04	03
	36/ए	0	09	75
	36/बी	0	00	68
	35/ए/बी	0	06	24
	32	0	08	06
	33	0	06	24
	काई ट्रैक	0	00	65

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1343.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to 'T' Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/14/92-ONG.C.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from Pakhajan GGS to 'T' Point

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra

Villag	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Narnavai	11	0	06	24
	12	0	14	56
	20	0	27	17
	21	0	11	44
	28	0	15	08
	27	0	27	04
	Cart track	0	00	65
	38	0	04	03
	36/A	0	09	75
	36/B	0	00	68
	36/A/B	0	06	24
	32	0	08	06
	33	0	06	24
	Cart track	0	00	65

[नई दिल्ली, 13 मई, 1992]

का. आ. 1344.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन 1205 GI/92—3

एक्स एफ से जी एन ए क्यू तक पट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधिब्यवसायी की माफ़ेत।

[सं. ओ. 12016/15/92/ओएनजीडी IV]

एम० मार्टिन, डैस्क अधिकारी

अनुसूची

जी एन एक्स एफ से जी एन ए क्यू जी जी एस तक पाईप लाइन बिछाने के लिए

राज्य - गुजरात	जिला—भरुच	तालुका—वडुसर		
गांव	ब्लॉक नं.	ह.	आर	से.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वासेटा	29	0	20	80
	7	0	20	54
	6	0	11	44
	5	0	06	89
	3	0	11	57
	2	0	01	04
	काई ट्रैक	0	1	72

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1344.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from GNXF to GNAQ in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/15/92-ONGD-IV]
M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from GNXF to GNAQ GGS

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar

Village	Block No.	Hectare	Area Centiare		
1	2	3	4	5	
Vanceta	29	0	20	80	
	7	0	20	54	
	6	0	11	44	
	5	0	06	89	
	3	0	11	57	
	2	0	01	04	
	Cart track	0	21	72	

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का. आ. 1345.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में पक्खाजन जी जी एस से "टी" बिन्दु तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्प्राबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्थ) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उत्तम उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

इससे कि उक्त भूमि में हितवन्त कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समक्ष प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाव मकरपुरा रोड, बड़ोदा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चिततः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ-12916/16/91-खं. एन. जा. डी -IV
एम. माटिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

पक्खाजन जी. जी. एस. से टी बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : भारुच तालुका : वाग्रा

गांव	ब्लॉक नं.	हे.	आर.	से.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ट्रंकल	206	0	11	96
	207	0	13	52
	205	0	15	08

1	2	3	4	5
	204	0	08	45
	203	0	13	65
	226	0	25	74
	199	0	01	30
	200	0	08	58
	193	0	12	74
	192	0	17	55
	191	0	10	40
	162	0	45	50
	163	0	01	56
	182	0	08	84
	178	0	06	24
	179	0	09	36
	177/P	0	15	08
	वैरन भूमि	0	02	08

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1345.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from Pakhajan GGS to 'T' Point in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the Schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/16/92-ONGD-IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM PAKHAJAN GGS TO 'T' POINT

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra.

Village	Block No.	Hectare	Area Cent.		
1	2	3	4	5	
Trankal	206	0	11	96	
	207	0	13	52	
	205	0	15	08	
	204	0	08	45	
	203	0	13	65	
	226	0	25	74	
	199	0	01	30	
	200	0	08	58	
	193	0	12	74	
	192	0	17	55	
	19	0	10	40	
	162	0	45	50	

1	2	3	4	5
	163	0	01	56
	182	0	08	84
	178	0	06	24
	179	0	09	36
	177/P	0	15	08
	Barren land	0	02	08

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.आ. 1346.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ऐ.वी.जी.एल. टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन लिमिटेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बसते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की माफत।

[सं. ओ. 12016/17/92-ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

ए.वी.जी.एल.टी. पाइन्ट से गुजरात गारडीयन तक पाइप लाईन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तहसील : अंकलेश्वर

क्र.सं.	ब्लॉक नं.	हे.	अर	सेंटीयर
1	2	3	4	5
कयोद्रा	196	0	10	00
	195	0	27	50
	193	0	19	70
	199	0	06	00
	201	0	08	20
	226	0	09	80
	225	0	00	28
	224/ए/बी/सी/डी	0	20	75
	223	0	01	05
	222	0	13	35
	221	0	16	50
	258	0	02	85
	259	0	24	70
	260	0	00	84

1	2	3	4	5
	264/ए/बी	0	37	60
	काटे ट्रैक	0	01	20
	63	0	14	60
	62	0	21	50
	279	0	04	50
	60	0	30	80
	59	0	17	65
	284	0	02	15
	285	0	38	90
	287	0	34	60
	काटे ट्रैक	0	06	25
	291	0	02	70

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1346.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T Point to Gujarat Guardian Ltd. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/17/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM ABGL 'T' POINT TO GUJARAT GUARDIAN

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hect	Are	Cet.
1	2	3	4	5
Kapodra	196	0	10	00
	195	0	27	50
	193	0	19	70
	199	0	06	00
	201	0	08	20
	226	0	09	80
	225	0	00	28
	224/A/B/C/D	0	20	75
	223	0	01	05
	222	0	13	35
	221	0	16	50
	258	0	02	85
	259	0	24	70
	260	0	00	84
	264/A/B	0	37	60

1	2	3	4	5
	Cart track	0	01	20
	63	0	14	60
	62	0	21	50
	279	0	04	50
	60	0	30	80
	59	0	17	65
	284	0	02	15
	285	0	38	90
	287	0	34	60
	Cart track	0	06	25
	291	0	02	70

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.प्रा. 1347.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.बी.जी. एल. टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन लिमिटेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निष्ठतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं.ओ. -12016/18/92/ओ एन जी डी-IV]]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : ऊंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर आर सेंटीयर
1	2	3
अम्बोली	118	0 19 40
	108	0 05 65
	109	0 03 15
	110	0 12 30
	111	0 19 10
कार्टट्रैक		0 01 40
58		0 10 20
59		0 09 50
57/ए/बी		0 26 10
46		0 25 70

1	2	3	4	5
	43	0	05	65
	42	0	28	75
	40	0	02	34
	41	0	36	60
	37	0	05	40
	34	0	35	75
	33	0	15	40

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1347.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T Point to Gujarat Guardian in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the Schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/18/92-ONGD.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from ABGL 'T' Point to Gujarat Guardian
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
Amboli	118	0	19	40
	108	0	05	65
	109	0	03	15
	110	0	12	30
	111	0	19	10
Cart track		0	01	40
58		0	10	20
59		0	09	50
27/A/B		0	26	10
46		0	25	70
43		0	05	65
42		0	28	75
40		0	02	34
41		0	36	60
37		0	05	40
34		0	35	75
33		0	15	40

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.प्रा. 1348.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन लिमिटेड तक ट्रांसमिशन के

परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. O-12016/19/92/ओ एन जी डी-4]
एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

ऐ.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : अंकलेश्वर

गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टेयर	आर.	सेण्टीयर
1	2	3	4	5
कोसमडी	382	0	01	32
	381	0	12	20
	344	0	15	20
	343	0	25	60
	350	0	00	04
	342	0	17	60
	341	0	22	30
	340	0	34	60
	338	0	02	60
	353	0	22	20
	354	0	15	20
	355	0	25	00
	356	0	21	80
	357	0	18	30
	333	0	06	30
काटेंद्रक		0	02	20
	272	0	66	40
	273	0	36	20
	274/ए/बी	0	21	15
	256	0	51	70
	222	0	06	60
	223	0	24	20
	224	0	00	25
काटेंद्रक		0	01	60
	214	0	25	10

1	2	3	4
213	0	20	20
212	0	00	04
229	0	28	30
230	0	02	70
236	0	00	30
231/ए/बी	0	31	90
232	0	23	35
233	0	11	85
199	0	14	75
198	0	10	10

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1348.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T-Point to Gujarat Guardian Ltd. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/19/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM ABGL 'T' POINT TO GUJARAT GUARDIAN

State : Gujarat District-Bharuch Taluka Ankleshwar

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
1	2	3	4	5
Kosamdi	382	0	01	32
	381	0	12	20
	344	0	15	20
	343	0	25	60
	350	0	00	04
	342	0	17	60
	341	0	22	30
	340	0	34	60
	338	0	02	60
	353	0	22	20
	354	0	15	20
	355	0	25	00
	356	0	21	80
	357	0	18	30
	333	0	06	

1	2	3	4	5
	Carttrack	0	02	20
	272	0	66	40
	373	0	36	20
	274/A/B	0	21	15
	256	0	51	70
	222	0	06	60
	223	0	24	20
	224	0	00	25
	Cart track	0	01	60
	214	0	25	10
	213	0	20	20
	212	0	00	04
	229	0	28	30
	230	0	02	70
	236	0	00	30
	231/A/B	0	31	90
	232	0	23	35
	233	0	11	85
	199	0	14	75
	198	0	10	10

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

को.आ. 1349.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडियन लिमिटेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के योजना के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप समझ प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति निर्निश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत हो।

[सं. O-12016/20/92-ओ एन जी डी-IV]

एम. मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडियन तक पाइप लाइन बिछाने के लिये।

राज्य गुजरात	जिला	अरुच	तालुका	अंकलेश्वर
गांव	ब्लॉक नं.	हेक्टर	आर	सेंटियर
बाकरोल	185	0	30	10
	186	0	27	55
	179	0	17	85
	182	0	16	70

1	2	3	4	5
	181	0	18	60
	180	0	22	80
	168	0	04	20
	169	0	25	08
	170	0	05	28
	161	0	08	10
	159	0	25	30
	158	0	25	90
	157	0	04	25
	156	0	02	60
	132	0	48	30
	131	0	12	20
	130	0	12	60
	128	0	20	60
	127	0	05	80
	काट ट्रैक	0	01	40
	125	0	20	60

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1349.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T-Point to Gujarat Guardian Ltd. in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/20/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

Pipeline from ABGL 'T' Point to Gujarat Guardian
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hect.	Are	Cent.
Bakrol	185	0	30	10
	186	0	27	55
	179	0	17	85
	182	0	16	70
	181	0	18	60
	180	0	22	80
	168	0	04	20
	169	0	25	08
	170	0	05	28
	161	0	08	10

1	2	3	4	5	6
		159	0	25	30
		158	0	25	90
		157	0	04	25
		156	0	02	60
		132	0	48	30
		131	0	12	20
		130	0	12	60
		128	0	20	60
		127	0	05	80
	Cart track	0	01	40	
	125	0	20	60	

नई दिल्ली, 13 मई, 1992

का.प्रा. 1350.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जोरहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन लिमिटेड तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करवा आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए अपने समस्त प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आलेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

[सं. ओ. 120161/21/92-ओ.एन.जी.डी. 4.]

एम.मार्टिन, डेस्क अधिकारी

अनुसूची

ए.बी.जी.एल.टी. बिन्दु से गुजरात गारडीयन तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	ज़िला : धरम	तालुका : वालिया		
पॉल	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	घर	सेंटीयर
कोल्ह	1233	0	30	40
	1234	0	31	10
	1225	0	55	30
	1240	0	49	10
	1244	0	39	20
	1246	0	13	85
	1247	0	12	90

New Delhi, the 13th May, 1992

S.O. 1350.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of the petroleum from ABGL-T-Point to Guj. Guardian Ltd in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire that right of user in the land described in the schedule annexed hereto:—

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal Practitioner.

[No. O-12016/21/92-ONG.D.IV]

M. MARTIN, Desk Officer

SCHEDULE

PIPELINE FROM ABGL 'T' POINT TO GUJARAT GUARDIAN

STATE: GUJARAT DISTRICT : BHARUCH TALUKA : VALIA

Villa	BlockNo.	Hectare	Are	Centiare	
1	2	3	4	5	6
Kondh	1233	0	30	40	
	1234	0	31	10	
	1225	0	55	30	
	1240	0	49	10	
	1244	0	39	20	
	1246	0	13	85	
	1247	0	12	90	

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.प्रा. 1351 :—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिश्चित सरकारी स्थानों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा।

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थानों का प्रवर्ग
प्रधान (कार्मिक और प्रशासन), प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि. के या उसके द्वारा पट्टे पर लिए गए या उनकी ओर से लिए गए स्थान, जो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, नोएडा, गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश राज्य में) और फरीदाबाद (हरियाणा राज्य में) स्थित हैं।

[का.सं. 94/5/91-एक डी सी]

अकील अहमद, अवर सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Fertilizers)

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 135I—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971, (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer, mentioned in column 1 of the Table below, being an officer equivalent to the rank of gazetted officer of the Central Government, to be the estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act in respect of the public premises specified in column 2 of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of Public premises.
1	2
Chief (Personnel & Administration), Projects and Development India Limited.	Premises belonging to, or taken on lease by or on behalf of the Projects & Development India Ltd. located in the Union Territory of Delhi, NOIDA, Ghaziabad (in the State of Uttar Pradesh) and Faridabad (in the State of Haryana)

[F. No. 94/5/91-F.D.C]
Aqeel Ahmad, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 1992

का.आ.1352—केन्द्र सरकार का, दिल्ली मुख्य योजना/क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। यदि प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव, इस सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, "बी" ब्लॉक, विकास सदन, आई.एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है। आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना नाम और पता भी दे।

अधिसूचना:

1. "जोन जी-16 (विकासपुरी और तिलक नगर क्षेत्र) में पड़ने वाला और उत्तर में 18.28 मीटर चौड़े मार्ग तथा आवासीय क्षेत्र (बोडेल्ला समूह आवास सोसायटी फेज-1), से, दक्षिण में जिला पार्कों से, पूर्व में जिला-पार्कों और बोडेल्ला आवासीय योजना (पाकेट ए-4) से तथा पश्चिम में नांगलोई नाले से घिरे लगभग 8.1 हेक्टेयर (20 एकड़) क्षेत्र के भूमि उपयोग को "मनोरंजनात्मक उपयोग" से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (डी.ए.पी. बटालियन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव) है।"

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उप-निदेशक, मुख्य योजना अनुभाग, विकास मीनार, छठी मंजिल आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उक्त अधिसूचना के दौरान सभी कार्यदिवसों को उपलब्ध होगा।

[सं. एफ 20(8)/91 एम. पी.]

रणवीर सिंह, सचिव,

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th May, 1992

S.O. 1352.—The following modification which the Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan for Delhi is hereby published for public information. Any person having any objection/suggestion

with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, I.N.A., New Delhi within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection/suggestion should also give his name and address.

MODIFICATION :

"The land use of an area measuring, about 8.1 ha. (20 acres) falling in zone G-16 (Vikas Puri and Tilak Nagar Area), bounded by 18.28 mtr wide road and residential area (Bodella Group Housing Society phase I) in the North, district parks in the South, district parks and Bodella Residential Scheme (Pocket A-4) in the East and Nangloi drain in the West, is proposed to be changed from 'recreational use' to 'public and semi-public facilities' (D.A.P. Battalions)".

2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of Deputy Director, Master Plan Section, Vikas Minar, 6th Floor, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

[No. F. 20(8)/91-MP]

RANBIR SINGH, Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मई, 1992

का.आ.1353.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, लि., मद्रास के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-30012/14/89-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 1st May, 1992

S.O. 1353.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-5-92.

B. M. DAVID, Desk Officer

[No. L-30012/14/89-IR(Misc)]

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU
MADRAS

Wednesday, the 28th day of August, 1991

PRESENT :

Thiru M. Gooplaswamy, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal.
Industrial Dispute No. 92 of 1989

(In the matter of the dispute for adjudication u/s. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 between the workman and the Management of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Madras).

BETWEEN

Thiru R. Umapathy,
C/o Thiru N. Kuppuswamy,
29, Menali Chinniah Indali Garden 1st Lane,
Washermenpet Madras-600021.

AND

The General Manager,
Bharat Petroleum Corporation Ltd.,
P.B. No. 1277, 7, Kodambakkam High Road,
Madras-600034.

REFERENCE :

Order No. L-30012/14/SO IR(Misc.) dt. 12-9-89 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Monday, the 19th day of August, 1991 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru V. Prakash, Advocate appearing for the workman and of Thiruvalargal P. K. Kurian, M. S. Krishnan and B. Jayaraman Advocates for the Management and this dispute having stood-over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute between the workman and the Management of Bharat Petroleum Corporation Limited, Madras arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-30012/14/89-IR(Misc.), dated 12-9-1989 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

Whether the action of the management of Bharat Petroleum Corporation Ltd., Madras in dismissing the services of Shri R. Umapathy, ex-workman w.e.f. 24-11-87 is justified. If not, what relief is the workman entitled to ?

2. The allegations in the claim statement are as follows : The Petitioner-worker was confirmed in service as a general workman with effect from 16-8-1983 under the Respondent. His recruitment was made on compassionate ground arising 1205 GI/92.—4.

from the death of his father. Thiru R. Rathinam who served under the Respondent. On 23-11-1985, Petitioner was issued a charge memo alleging that he was violated leave rules by his absence from duty without prior permission or leave. After conducting a domestic enquiry, the Respondent passed an order dated 23-9-86 imposing a punishment by which Petitioner was made ineligible to get increment for three years. The Petitioner was issued with another show cause notice dated 11-2-1987 to which he gave an explanation dt. 13-2-87. Following the said explanation, the Petitioner was issued charge memo dated 23-3-1987 for the Petitioner's absence without leave on several days in 1986-87. On this charge memo a domestic enquiry was completed. The Respondent's General Manager passed an order based on the findings of the domestic enquiry officer for dismissal of the Petitioner. The order of dismissal is unsustainable. The principles of natural justice were violated in holding the enquiry. The standing orders have not been followed in imposing the punishment. The Petitioner is only the bread-winner of the family consisting of mother, one younger sister and two younger brothers. An award may be passed directing the Respondent to reinstate the Petitioner in service giving him back wages, continuity of service and all benefits.

3. The Respondent in its counter states as follows : Soon after the Petitioner was confirmed in service with effect from 16-8-1983, he made himself absent from work on several occasions without prior permission. Several verbal cautions and counsellings were given to him for his various acts of absenteeism. He was issued a charge memo dated 23-11-1985. Then a domestic enquiry was held, in which findings were recorded holding that charge was proved and then the General Manager passed an order dated 23-9-1986 effecting cut of increments for three years consecutively. Even then, the Petitioner did not improve his conduct. Again he made himself absent unauthorisedly and for such absence he was issued a charge sheet dated 23-3-1987. After holding a domestic enquiry, in which the charge were proved, an order of dismissal from service was passed on 1-12-1987. The domestic enquiry was held in accordance with the standing orders and observing principles of natural justice. The order of punishment has been passed in a legal manner. It is just punishment. The claim of the Petitioner is liable to be dismissed.

4. The points for determination arising in this dispute are as follows :

- (1) Whether the domestic enquiry has been held fairly and properly?
- (2) Whether the findings are correct and sustainable ?
- (3) Whether the punishment is adequate ?

5. No oral evidence was adduced on either side. Exs. W-1 to W-11 and M-1 to M-35 were marked by consent.

6. POINTS : Admittedly, the Petitioner who was recruited as a general workman on compassionate ground as a result of his father's death during service, the Petitioner was confirmed on the post on 16-8-1983 Ext. W-3 the charge sheet dated 23-11-1985 emanates from Petitioner's continued absence without prior leave on several days from January, 1985 to November, 1985. Following this earlier charge sheet, a domestic enquiry was held and the Petitioner was punished with increment cut for three years. The second charge sheet Ex. W-8 deals with Petitioner's absence over a period from April, 1986 to February, 1987. In every month from April, 1986 to January, 1987 the Petitioner has periodically absented himself from duty without giving an advance leave application. Ex. M-30 is the charge sheet dated 23-3-1987 detailing the periods of absence Ex. M-31 is a brief abstract of the domestic enquiry proceedings Ex. M-34 and Ex. M-35 contain detailed record of the evidence taken by the domestic enquiry officer. Management witnesses Thiruvalargal Mahadevan, Vijayaragavan and Mathews have spoken to the details of the unauthorised absence and its consequence. Even on the first day of the enquiry on 13-5-1987, the Petitioner Thiru R. Umapathy has admitted that he was guilty of making himself absent without taking prior leave. The Petitioner did not cross-examine the Management witnesses and he did not put up any defence witness. During the period in question, Petitioner was absent for 1244 days from April

1986 to February, 1987. Besides these days, he applied for leave and got it only in respect of 50½ days in April, 1986, May, 1986, June, 1986 July, 1986 and September, 1986. This evidence clearly proves that the Petitioner was guilty of absenting himself habitually. By this kind of absenteeism he has violated clause 16(1) and clause 16(2) of the Standing Orders which deal with the grant of leave and clause 29 which makes habitual absence without leave, a punishable misconduct. Both in view of the admissions made by the petitioner and the overwhelming evidence the domestic enquiry officer has correctly concluded that the charges have been proved.

7. The allegation by the Petitioner that the domestic enquiry had not been held fairly and properly is devoid of substance. A worker who is habitually absent without leave would be a very bad example for the other co-workers. Such absence would surely affect production and promote indiscipline among the workers. Hence for very long and habitual absence, the Respondent is justified in imposing the extreme punishment of dismissal. I do not find any reason to show mercy to the Petitioner who has been absent for more than 120 days in 1986-87 without any excuse and without taking prior leave inspite of a previous charge and enquiry which resulted in a minor punishment given to him in September, 1986. Even after this minor punishment, the Petitioner has continued to indulge in the misconduct of absenteeism from October, 1986 to February 1987. I therefore hold that the punishment is justified. I answered all the points against the Petitioner.

8. In the result, the claim of the Petitioner is dismissed. No costs.

Dated, this 28th day of August, 1991.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

vnp:

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None

Documents Marked

For workman:

- Ex. W-1/9-8-82—Appointment order issued to the Petitioner-workman Thiru R. Umapathy for the post of General workman in Tondiarpet Installation w.e.f. 16-8-82 (copy).
- Ex. W-2/11-8-83—Confirmation order issued to the Petr. Workman (copy)
- Ex. W-3/23-11-85—Charge sheet issued to the Petr. Workman (copy).
- Ex. W-4/23-9-86—Order of the Management imposing punishment to the Petr. Workman of increment cut (copy).
- Ex. W-5/1-10-86—Communication by the Management to the Petr. workman regarding increment cut. (copy)
- Ex. W-6/11-2-87—Show cause memo issued to the Petr. Workman (copy).
- Ex. W-7/23-2-87—Explanation by the Petr. Workman to Ex. W-6 (copy).
- Ex. W-8/23-3-87—Charge memo issued to the Petr. Workman (copy).
- Ex. W-9/24-11-87—Dismissal Order (copy).
- Ex. 10/1-12-87—Communication of the dismissal order to the Petr. Workman (copy).
- Ex. W-11/12-9-89—Order No. L-30012/14/88-IR(Misc.) Dt. 12-9-89 of the Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi. (copy).

For Management:

- Ex. M-1/21/31-7-84—Letter from Management to Petr. Workman advising him to explain his absence from duty. (xerox copy).

- Ex. M-2/2-8-84—Reply by the Petr. Workman to Ex. M-1 (xerox copy).
- Ex. M-3/21-12-84—Letter from Management to Petr. workman regarding his absence from duty. (xerox copy).
- Ex. M-4/7-1-85—Reply by the Petr. workman to the Management praying to excuse for his absence from duty. (xerox copy).
- Ex. M-5/ — — Translation of Ex. M-4 in English (xerox copy).
- Ex. M-6/10-1-85—Warning letter issued by the Management to the Petr. Workman (xerox copy).
- Ex. M-7/28-2-85 — —do—
- Ex. M-8/26-3-85—Letter from Assistant Divisional Manager to the Personnel Manager of the Management regarding unauthorised absence of the Petr. workman (xerox copy).
- Ex. M-9/6-5-85—Letter from the Management to the Petr. workman regarding his absence from duty. (xerox copy).
- Ex. M-10/24-5-85 — —do—
- Ex. M-11/30-5-85—Reply by the Petr. Workman to Ex. M-10 (xerox copy).
- Ex. M-12/5-7-85—Letter from Management to Dr. V. C. Chakrapani, Medical Officer, Tondiarpet requesting him to examine the Petr. Workman (xerox copy).
- Ex. M-13/22-7-85—Medical report. (xerox copy).
- Ex. M-14/ — —Letter from Management to the Petr. Workman framing charges for his absence from duty, dt. 23-11-85 (xerox copy)
- Ex. M-15/5-12-85—Enquiry notice issued to the Petr. Workman (xerox copy)
- Ex. M-16/5-12-85—Reply by the Petr. Workman to Ex. M-14 (xerox copy).
- Ex. M-17/25-2-86—Letter from the Management to the Petr. Workman regarding his absence from duty (xerox copy).
- Ex. M-18/10-3-86 — —do—
- Ex. M-19/23-4-86 — —do—
- Ex. M-20/23-4-86 — —do—
- Ex. M-21/8-8-86 — —do—
- Ex. M-22/18-8-86—Medical report. (xerox copy).
- Ex. M-23/1-10-86—Same as Ex. W-5 (")
- Ex. M-24/24-2-86—Report of the Enquiry Officer (xerox copy)
- Ex. M-25/23-9-86—Same as Ex. W-4 (xerox copy).
- Ex. M-26/11-2-87—Same as Ex. W-6 (")
- Ex. M-27/13-2-87—Reply by the Petr. Workman to Ex. W-26 (xerox copy).
- Ex. M-28/17-2-87—Letter from the Management to the Petr. Workman regarding his absence from duty (xerox copy)
- Ex. M-29/23-2-87—Same as Ex. W-7 (xerox copy).
- Ex. M-30/23-3-87—Same as Ex. W-8 (")
- Ex. M-31/19-5-87—Report of the Enquiry Officer (xerox copy)
- Ex. M-32/24-11-87—Same as Ex. W-9 (xerox copy)
- Ex. M-33/1-12-87—Same as Ex. W-10 (")
- Ex. M-34/15-5-87—Proceedings of the Enquiry Officer. (xerox copy)
- Ex. M-35/15-5-87 — —do—

vnp:

Sd/- illegible
INDUSTRIAL TRIBUNAL

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

Shri Palaniappan, S/o Kuppaswamy B. No. 692, Mazdoor w.e.f. 21-2-90? If not to what relief the workman is entitled?"

2. Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel.

3. After several adjournments, when the dispute was called today for filing claim statement of the Petitioner-Union, both parties filed a joint memorandum of settlement entered into under section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 praying to pass an award in terms of settlement. It is recorded.

4. In view of joint memorandum, an award is passed in terms of settlement which will form part of the award.

Dated, this 16th day of April, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

BEFORE THE HONOURABLE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
MADRAS

I. D. No. 40 of 1991

JOINT MEMORANDUM SUBMITTED

By

REPRESENTING THE MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPORATION
SALEM-636012
SHRI A. PARASURAMAN
Dy. General Manager (Works)
SHRI S. E. YADHAVAN
Personnel Manager

REPRESENTING THE WORKMEN :

SALEM DIST. MAGNESITE LABOUR UNION,
SALEM
SHRI R. SINGARAVELU
General Secretary
SHRI K. KARUNAKARAN
President

We pray to submit that an Industrial Dispute between the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-12 and Sri Palaniappan/Kuppaswamy, Mazdoor, B. No. 692 represented by Salem Dist. Magnesite Labour Union, Salem for non-employment is numbered as I. D. No. 40/91 and now pending before this Honourable Tribunal.

Whereas we have arrived at a settlement under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947. The copy of the settlement is submitted alongwith this memorandum. We pray the Honourable Industrial Tribunal may pass an Award in the lines of the settlement attached herewith.

REPRESENTING MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPORATION
SALEM-636012

Sd/-

(A. PARASURAMAN)

Sd/-

(S. E. YADHAVAN)

REPRESENTING WORKMAN :

SALEM DIST. MAGNESITE LABOUR UNION : SALEM

Sd/-

(R. SINGARAVELU)
Secretary

Sd/-

(K. KARUNAKARAN)
President

का.आ. 1354-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डालमिया मैगनेसाइट कारपोरेशन सेलम के प्रबंधन के संबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/35/91-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1992

S.O. 1354.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-5-92.

[No. L. 29012/35/91-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU,
MADRAS

Thursday, the 16th day of April, 1992

PRESENT :

Thiru M. Gopalaswamy, B. Sc., B.L., Industrial Tribunal.
INDUSTRIAL DISPUTE NO. 40 OF 1991

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012).

BETWEEN :

The Wholtime Director, Dalmia Magnesite Corpora-
Salem District Magnesite Labour Union, 237, Thara-
mangalam Road, Old Suramangalam, Salem-636005.

AND

The Wholtime Director, Dalmia Magnesite Corpora-
tion, Salem-636012.

REFERENCE :

Order No. L. 29012/35/91-IR (Misc) dated 21-6-1991 of
the Ministry of Labour, Government of India, New
Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiruvalargal R. Vaigai, S. Vaidyanathan, Advocates appearing for the workman and of Thiruvalargal K. Jayaraman and R. Balasubramanian, Advocates appearing for the management, upon perusing the reference and other connected papers on record and the parties having filed a joint memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workman and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L. 29012/35/91-IR(MISC), dated 21-6-1991 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

"Whether the management of the Dalmia Magnesite Corporation is justified in dismissing the services of

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE DISPUTE RELATING TO NON-EMPLOYMENT OF SHRI PALANIAPPAN KUPPUSAMY, MAZDOOR, B. NO. 692 BETWEEN MANAGEMENT OF DALMIA MAGNESITE CORPORATION, SALEM-636012 AND THE SALEM DIST. MAGNESITE LABOUR UNION, SALEM.

REPRESENTING THE MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPORATION
SALEM-636012

SHRI A. PARASURAMAN
Dy. General Manager (Works)

SHRI S. E. YADHAVAN
Personnel Manager

REPRESENTING THE WORKMEN :

SALEM DIST. MAGNESITE LABOUR UNION,
SALEM

SHRI R. SINGARAVELU
General Secretary

SHRI K. KARUNAKARAN
President

SHORT RECITAL OF THE CASE :

Shri Palaniappan Kuppasamy, Mazdoor, B. No. 692 was an employee in respondent company.

Whereas the above workman was dismissed by the Management with effect from 21st February, 1990 for his habitual absence without prior sanction of leave.

And whereas the workmen and the union raised an Industrial dispute I. D. No. 40/91 which is pending before the Industrial Tribunal of Tamil Nadu.

And whereas the Salem Dist. Magnesite Labour Union continued bilateral discussions with the Management for an amicable settlement.

And whereas after detailed discussions a settlement was reached under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 with the union on this day.

TERMS OF SETTLEMENT :

It is agreed that

1. The workman would be paid Gratuity calculated from the date of eligibility to till the date of dismissal from services.
2. The workman and the union shall have no other claim except as provided herein above.
3. In the light of this Memorandum of Settlement reached between the parties the Industrial Tribunal, Madras, will be requested to pass an Award in terms of the settlement.

In witness thereof, the parties have affixed their signatures in the settlement on this day 11th April, 1992 at Salem.

REPRESENTING THE MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPORATION
SALEM-636012

Sd/-

(A. PARASURAMAN)

Sd/-

(S. E. YADHAVAN)

Witnesses :

Sd/-

1. (C. S. MENON)

Sd/-

2. (M. G. REJITH KUMAR)

REPRESENTING THE WORKMAN

SALEM DIST. MAGNESITE
LABOUR UNION, SALEM

Sd/-

(R. SINGARAVELU)

Sd/-

(K. KARUNAKARAN)

Salem-636012

Date 11-4-92

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

का.आ. 1353-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डालमिया मैग्नेसाइट कारपोरेशन, सेलम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/34/91-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1992

S.O. 1355.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Madras as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-5-92.

[No L-29012/34/91-IR.(Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU
MADRAS

Thursday, the 16th day of April, 1992

PRESENT :

Thiru M. Gopalaswamy, B.Sc., B.L., Industrial Tribunal
Industrial Dispute No. 43 of 1991

[In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012.]

BETWEEN

The workman represented by The General Secretary,
Salem District Magnesite Labour Union, 237,
Tharamangalam Road, Old Suramangalam, Salem-
636005.

AND

The Wholtime Director, Dalmia Magnesite Corporation,
Salem-636012.

REFERENCE :

Order No. L-29012/34/91-IR.(Misc.) dated 26-6-1991 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiruvallargal R. Vaigai, S. Vaidyanathan, Advocates appearing for the workman and of Thiruvallargal K. Jayaraman and R. Balasubramanian, Advocates appearing for the management, upon perusing the reference and other connected papers on record and the parties having filed a joint memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal passed the following

AWARD

This dispute between the workman and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636 012 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-29012/34/91-IR.(Misc.) dated 26-6-1991 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue:

"Whether the management of Dalmia Magnesite Corporation is justified in dismissing the services of Shri Ponnusamy, S/o Arumugam, B. No. 5121/75 Mazdoor with effect from 3-2-90? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel.

3. After several adjournments, when the dispute was called today for filing claim statement of the Petitioner-Union, both parties filed a joint memorandum of settlement entered into under section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 praying to pass an award in terms of settlement. It is recorded.

4. In view of joint memorandum, an award is passed in terms of settlement which will form part of the award.

Dated, this 16th day of April, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal
BEFORE THE HONOURABLE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
MADRAS

I.D. No. 43 of 1991

JOINT MEMORANDUM SUBMITTED

BY

Representing the Management—Dalmia Magnesite Corporation Salem-636 012.

Shri A. Parasuraman, Dy. General Manager (Works).

Shri S. E. Yadhavan, Personnel Manager

Representing the Workmen—Salem Dist. Magnesite Labour Union, Salem.

Shri R. Singaravelu, General Secretary.

Shri K. Karunakaran, President.

We pray to submit that an Industrial Dispute between the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-12 and Sri Ponnusamy/Arumugam, Mazdoor, B. No. 5121 represented by Salem Dist. Magnesite Labour Union, Salem for non-employment is numbered as I.D. 43/91 and now pending before this Honourable Tribunal.

Whereas we have arrived at a settlement under section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947. The copy of the settlement is submitted alongwith the memorandum. We pray the Honourable Industrial Tribunal may pass an Award in the lines of the settlement attached herewith.

Representing Management :

Dalmia Magnesite Corporation, Salem-12

Sd/-

(A. Parasuraman)

Sd/-

(S. E. Yadhavan)

Representing Workman :
Salem Dist. Magnesite
Labour Union, Salem

Sd/-

(R. Singaravelu)

Sd/-

(K. Karunakaran)

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE DISPUTE RELATING TO NON-EMPLOYMENT OF SHRI PONNUSWAMY/ARUMUGAM, MAZDOOR, B. NO. 5121 BETWEEN MANAGEMENT OF DALMIA MAGNESITE CORPORATION, SALEM-636012 AND THE SALEM DIST. MAGNESITE LABOUR UNION, SALEM.

REPRESENTING THE MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPORATION
SALEM-636012

SHRI A. PARASURAMAN
Dy. General Manager (Works)

SHRI S. E. YADHAVAN
Personnel Manager

REPRESENTING THE WORKMAN :

SALEM DIST. MAGNESITE
LABOUR UNION, SALEM

SHRI R. SINGARAVELU
General Secretary

SHRI K. KARUNAKARAN
President

SHORT RECITAL OF THE CASE :

Shri Ponnusamy/Arumugam, Mazdoor, B. No. 5121 was an employee in respondent company.

Whereas the above workman was dismissed by the Management with effect from 31st January, 1990 for his habitual absence without prior sanction of leave.

And whereas the workman and the union raised an industrial dispute I. D. No. 43/91 which is pending before the Industrial Tribunal of Tamil Nadu.

And whereas the Salem Dist. Magnesite Labour Union continued bilateral discussions with the Management for an amicable settlement.

And whereas after detailed discussions a settlement was reached under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 with the union on this day.

TERMS OF SETTLEMENT :

It is agreed that—

1. The workman would be paid Gratuity calculated from the date of eligibility to till the date of dismissal from services.
2. The workman and the union shall have no other claim except as provided hereinabove.
3. In the light of this Memorandum of Settlement reached between the parties the Industrial Tribunal, Madras. will be requested to pass an Award in terms of the settlement.

In witness thereof, the parties have affixed their signatures in the settlement on this day 11th April, 1992 at Salem

REPRESENTING THE MANAGEMENT :

DALMIA MAGNESITE CORPN. SALEM-12

Sd/-

(A. PARASURAMAN)

Sd/-

(S. E. YADHAVAN)

Witnesses

Sd/-

1. (C. S. MENON)

Sd/-

2. (M. G. REJITH KUMAR)

REPRESENTING THE WORKMAN :

SALEM DIST. MAGNESITE
LABOUR UNION, SALEM

Sd/-

(R. SINGARAVELU)

Sd/-

(K. KARUNAKARAN)

SALEM-636012

Dated : 11-04-1992

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

का.आ. 1356.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु मिनरल्स लि., चेपोक, मद्रास, के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/3/91-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1992

S.O. 1356.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Tamilnadu Minerals Limited, Chepauk, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 5-5-92.

[No. L. 29012/3/91-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Friday, the 24th day of April, 1992

PRESENT :

THIRU M. GOPALASWAMY, B.Sc., B. L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 4 OF 1992

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Tamilnadu Minerals Limited, Madras-5)

BETWEEN :

Thiru R. Kuppuswamy, C/o CITU Office, Rajaganapathy Nagar, Mettur Dam. 1.

AND

The Managing Director, Tamilnadu Minerals Limited, TWAD House, Chepauk, Madras-600005.

REFERENCE :

Order No. L-29012/3/91 IR (Misc.), dated 21-1-92 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiruvallargal N. Jothi and M. L. Ramesh, Advocates appearing for the management, upon perusing the reference and other connected papers on record and the workman is reported as expired, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workman and the management of Tamilnadu Minerals Limited, Madras-5 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-29012/3/91-IR (Misc.), dated 21-1-1992 of the Ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

"Whether the management of Tamilnadu Minerals Limited is justified in dismissing the services of

Shri R. Kuppuswamy with effect from 11-9-1989 ?
And if not to what relief the workman is entitled ?"

2. Summons were issued to the parties. The Management was represented by counsel. Petitioner-worker was absent and no representation was made. Fresh notice was issued to the Petitioner-worker for the hearing on 24-4-1992. But the notice from the Petitioner-worker was returned with endorsement "Party expired. Hence returned to the sender."

3. Today, when the dispute was called, no representation was made on behalf of the deceased petitioner-workman. Hence Industrial Dispute is dismissed.

Dated, this 24th day of April, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

का.आ. 1357.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डालमिया मैग्नेसाइट कार्पोरेशन सेलम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-29012/36/91-आई.आर. (विविध)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1992

S.O. 1357.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem and their workmen, which was received by the Central Government on the 4-5-92.

[No. L-29012/36/91-IR (Misc.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 16th day of April, 1992

PRESENT :

THIRU M. GOPALASWAMY, B. Sc., B.L., Industrial Tribunal.

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 41 OF 1991

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012).

BETWEEN

The workman represented by

The General Secretary, Salem District Magnesite Labour Union, 237, Tharamangalam Road, Old Suramangalam, Salem-636005.

AND

The Wholtime Director, Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012.

REFERENCE :

Order No. L-29012/36/91-IR(Misc) dated 21-6-1991 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on this day for final disposal in the presence of Thiruvallargal R. Vaigai, S. Vaidyanathan, Advocates appearing for the workman and of Thiruvallargal K. Jayaraman and R. Balasubramanian, Advocates appearing for the management, upon perusing the reference and other connected papers on record and the parties having filed a joint memorandum of settlement and recording the same, this Tribunal passed the following.

AWARD

This dispute between the workman and the management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-636012 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-29012/36/91-IR(Misc.) dated 21-6-1991 of the ministry of Labour, for adjudication of the following issue :

"Whether the management of the Dalmia Magnesite Corporation is justified in dismissing the services of Shri Govindan, S/o Arumugam B. No. 5446, Mazdoor w.e.f. 5-1-90 ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Parties were served with summons. Both parties were represented by counsel.

3. After several adjournments, when the dispute was called today for filing claim statement of the Petitioner-Union, both parties filed a joint memorandum of settlement entered into under section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 praying to pass an award in terms of settlement. It is recorded.

4. In view of joint memorandum, an award is passed in terms of settlement which will form part of the award.

Dated, this 16th day of April, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal

BEFORE THE HONOURABLE INDUSTRIAL

TRIBUNAL, MADRAS

I. D. No. 41 of 1991

JOINT MEMORANDUM SUBMITTED

BY

Representing the Management.

Dalmia Magnesite Corporation Salem : 636 012.
Shri A. Parasuraman Dy. General Manager (Works).
Shri S. E. Yadhavan Personnel Manager.

Representing the Workmen.

Salem District Magnesite Labour Union : Salem.
Shri R. Singaravelu General Secretary.
Shri K. Karunakaran President.

We pray to submit that an Industrial Dispute between the Management of Dalmia Magnesite Corporation, Salem-12 and Shri Govindan/Arumugam, Mazdoor, B. No. 5446 represented by Salem District Magnesite Labour Union, Salem for non-employment is numbered as I. D. 41/91 and now pending before this Honourable Tribunal.

Whereas we have arrived at a settlement under section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947. The copy of the settlement is submitted alongwith this memorandum. We pray the Honourable Industrial Tribunal may pass an Award in the lines of the settlement attached herewith.

Representing Management

Dalmia Magnesite Corporation Salem-12.

Sd./-

Illegible

(A. PARASURAMAN),

Sd./-

Illegible

(S. E. YADHAVAN).

Representing Workmen

Salem Dist. Magnesite Labour Union : Salem

Sd./-

Illegible

(R. SINGARAVELU).

Sd./-

Illegible

(K. KARUNAKARAN).

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT UNDER SECTION 18(1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 IN THE DISPUTE RELATING TO RE-INSTATEMENT INTO SERVICE, BETWEEN MANAGEMENT OF DALMIA MAGNESITE CORPORATION : SALEM-636 012 AND THE SALEM DISTRICT MAGNESITE LABOUR UNION OVER DISMISSAL OF SHRI GOVINDAN/ARUMUGAM, MAZDOOR, B. NO. 5446.

Representing the Management

Dalmia Magnesite Corporation Salem-636 012.

Shri A. Parasuraman Deputy General Manager (Works).

Shri S. E. Yadhavan Personnel Manager.

Representing the Workman.

Salem District Magnesite Labour Union : Salem.

Shri R. Singaravelu General Secretary.

Shri K. Karunakaran President.

SHORT RECITAL OF THE CASE :

Shri Govindan/Arumugam, Mazdoor, B. No. 5446 was an employee in respondent company.

Whereas the above workman was dismissed by the Management with effect from 5th January, 1990 for his habitual absence without prior sanction of leave.

And whereas the workman and the union raised an industrial dispute I. D. No. 41/91 which is pending before the Industrial Tribunal of Tamil Nadu.

And whereas the Salem District Magnesite Labour Union continued bilateral discussions with the Management for an amicable settlement.

And whereas the Management re-examined the matter sympathetically and reached a settlement after detailed discussions under Section 18(1) of the Industrial Disputes Act, 1947 with the Union on this day.

(Sd./-) S. E. YADHAVAN.

TERMS OF SETTLEMENT :

It is agreed that :—

1. As a very special case the Management shall re-employ the said workman with effect from 2nd May, 1992 without any back wages.
2. For the purpose of reckoning the length of service of Shri Govindan/Arumugam the period from the date of dismissal till the date of re-appointment shall be counted.
3. The workman and the union shall have no other claim except as provided herein above.
4. In future no further leniency can be shown to the workman if he absents unauthorisedly.
5. In the light of this Memorandum of Settlement reached between the parties the Industrial Tribunal

Madras, will be requested to pass an Award in terms of the settlement.

In witness thereof, the parties have affixed their signatures in the settlement on this day 2nd April, 1992 at Salem.

Representing the Management

Dalmia Magnesite Corporation Salem-12.

Sd./ Illegible
(A. PARASURAMAN)
Sd./ Illegible
(S. E. YADHAVAN)
Witnesses :
Sd./ Illegible

1. (A. RAMAMOORTHY-Steno).

Sd./ Illegible

2. A. PALANISAMY T. No. 161

Salem : 636 012.

Dated : 02-04-1992.

Representing the Workman

Salem District Magnesite Labour Union : Salem . 5.

Sd./ Illegible
(R. SINGARAVELU).
Sd./ Illegible

(K. KARUNAKARAN).

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

का.आ. 1358—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेलीफोन्स आगरा, के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण कानपुर, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[एल-40011/5/89-डी. 2(बी) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1992

S.O. 1358.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Distt. Manager Telephones Agra and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-1992.

[No. L-40011/5/89-D.II (B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM- LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No.

In the matter of dispute :

BETWEEN

The Secretary,
Bhartiya Rashtriya Congress,
INTUC 2/236, Mnamnier,
Agra.

AND

The District Manager,
Telephones Agra.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-40011/5/39-D.II (B) dated 15th June, 1990, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the District Manager Telephones and Assistant Engineer Cables (Tel.) Agra were justified in not regularising Sri Chatur Singh and 15 others as per list given below and also illegal termination as Shri Laxaman Singh w.e.f. 1-11-85 ? If not, to what relief the workman concerned entitled ?

2. The industrial dispute on behalf of the 16 workmen has been raised by Bhartiya Rashtriya Congress, INTUC, Agra (hereinafter referred to as Union).

3. From the reference order it will appear that the Tribunal has to give its findings on two points. One is on the point of regularisation of 16 workmen and the second is on the point of illegal termination of Sri Laxaman Singh w.e.f. 1-11-85. In view of the facts pleaded by the management in para 3 of the written statement and the statement made by Sri K. L. Kushwaha, the authorised representative for the management on 10-4-92, which was a date fixed for hearing arguments, the only point left to be determined is the second point and not the first point. In para 3 of the written statement the management have pleaded that Sri Than Singh workman has been given permanent status w.e.f. 1-11-89. In his statement made on 10-4-92 Sri Kushwaha has submitted before the Tribunal that the services of the remaining workmen except Sri Laxaman Singh have been regularised. In other words so far as the case of workmen other than Sri Laxaman Singh have become infructuous. In view of it shall be only referring to such part of the pleadings and evidence of the parties as are relevant for the purpose of deciding the case of Sri Laxaman Singh.

4. The case of the Union in respect of Sri Laxaman Singh is that he was engaged by the management on 1-8-81 and his services were terminated illegally alongwith the remaining 16 workmen w.e.f. 1-11-85 when he alongwith other workmen raised a demand regarding regularisation of their services. These workmen therefore filed a petition before ALC (C) New Delhi before whom the management in writing give the assurance that on the basis of seniority they would be taken back in service. Except Sri Laxaman Singh workman others were taken back in service by the management. According to the Union even persons junior to him are working with the management. The Union has, therefore, prayed for his reinstatement with full back wages.

5. The management plead that a considerable portion of the work is carried out by the management on behalf of the Central Government is of temporary nature. As such after the completion of the particular project the employees employed cannot be absorbed on permanent basis. In the circumstances employees for projects are always employed on casual basis with a clear understanding that as soon as the projects are over their services would automatically stand terminated. So the question of the workman plead that he had himself voluntarily abandoned the is incorrect. As regards Sri Laxaman Singh the management plead that he had himself voluntarily abandoned the employment by remaining absent continuously for months and years together. At no stage the management ever terminated his services. According to the management before the ALC (C) no undertaking was given that the workmen would be given regular status straight away.

6. The management have also raised some legal pleas such as the telephone department is not an industry; persons covered by the reference are not workmen within the meaning of I. D. Act; the jurisdiction to determine the question involved lies with the Central Administrative Tribunal.

7. In support of their respective cases both sides have led oral as well as documentary evidence. Whereas the Union has examined Sri Laxaman Singh PW-1 and Sri Chatur Singh PW-2, the management have examined Sri Jagdish Prasad Assistant Engineer (T). The evidence of Sri Chatur Singh is not relevant for the purposes of considering the case of Sri Laxaman Singh.

8. By means of his affidavit Sri Laxaman Singh has proved annexure A and Annexure A/1 of the claim statement. Annexure A/1 is the copy of minutes of discussion dated 5-3-86 before ALC (C) New Delhi. It appears from the minutes of discussion that of the 19 workmen Sri Laxaman Singh was one of them. Workman named at Serial Nos. 2, 4, 5, 6, 9 and 11 were reported to be working with the management. As regards remaining 13 workmen the management clarified that their services had not been terminated and that they were in the surplus cell and their services would be utilised as and when there was work according to their seniority. Before the ALC (C) New Delhi, S/Sri N. C. Gupta, District Manager (T) Agra and B. K. Mittal Divisional Engineer (Phones) represented the management most of the workmen in respect of whom reference order has been made by the Ministry of Labour Central Government were before the ALC (C) New Delhi and all the 19 workmen were represented before ALC (C) New Delhi by S/Sri Mahesh Kumar and Mahendra Pal Singh.

9. From the above minutes of discussion it becomes abundantly clear that none of them including Laxaman Singh had abandoned the job. When the clarification made by the officers on behalf of the management before ALC (C) New Delhi is examined in the light of the facts stated by the management in paras 2 and 3 of the written statement it will appear that these 19 workmen including Sri Laxaman were found by the management as surplus, may be on account of completion of project and whereas six of them were taken back in service, about others the management gave undertaking that they would be taken back in service according to their seniority when the work would become available for them.

10. Extra W-3 is the copy of statement of the number of working days of Sri Laxaman Singh of the period December, 1981 to October, 1985, duly certified by Assistant Engineer (Cables) Agra. It shows that during 1982-83, (April 1982 to March 1983), Sri Laxaman Singh had worked for 350 days, during 1983-84 he had worked for 332 days, during 1984-85 he had worked for 276 days, during 1985-86 he had worked for 145 days and during the period December, 1981 to March 1982 he had worked for 118 days. On calculation it will be found that during the period of 12 months preceding the date of termination i.e. 1-11-85 he had worked for 249 days.

11. The important question which arises is why Sri Laxaman Singh was not taken back in service while others some of whom were junior to him were taken back in service by the management. Sri Laxaman Singh corroborated the facts stated by the Union in paras 1 and 2 of the claim statement on the point of initial engagement of all the 17 workmen. It will appear from the facts stated in para 1 of the claim statement that as many as about 10 workmen out of the 17 workmen covered by this reference order were engaged by the management much after his engagement. They joined the services in 1982 in different months.

12. From the minutes of discussion dated 5-3-86, before ALC (C) New Delhi copy annexure A/1 it appears that after the clarification given by the management before ALC (C) New Delhi by the parties authorised representatives that they agree to hold further mutual discussion in order to resolve the matter amicably, (The fact that merely all the workmen except Sri Laxaman Singh have been taken back in the service by the management shows that the management did honour the commitment made by the authorised representative before ALC (C) New Delhi faithfully. Even in para 5 of the claim statement it has been stated by the Union that all the workman except Sri Laxaman Singh were taken in service by the management. The question is why Laxaman Singh was left. There could be two possible reasons. One could be that the management were very much annoyed with him

and the second is that he did not turn up to join his duties within a reasonable time. In his case the second possibility seems to be there.

13. In para 3 of the claim statement it is stated by the Union that when all the workmen raised a demand of regularisation of their services, the management terminated their services w.e.f. 1-11-85. There is nothing in the pleadings to show that Sri Laxaman Singh had done any other act causing further annoyance to the management. In para 6 of his statement in cross examination he has deposed that he had demanded equal pay for equal work. This appears to be an after thought on his part. This is not even stated by him in his two representations copies Ext. W-1 and W-2 made on 23-3-88 and 1-6-88. Although the management have denied the giving of such representation, let us assume that he had made such representations. The question is why he did not come to join duty before making these representations. It could be that either he could not maintain contact with the management or his authorised representative did not inform him of the agreement reached between the management and them on 5-3-86 intime. But for that the management cannot be blamed. However one thing is clear from the statement of working days vide certificate dated 12-2-92 of Assistant Engg. (Cable) Agra, copy Ext. M-3, that had he come to know of the understanding given by the management to his authorised representatives before the ALC (C) New Delhi on 5-3-92 like other workmen he would have surely reported for duty on his turn coming. If persons junior to him could turn up for work, there is every reason that he too would have turned up on learning that his turn to report for duty had come. As seen above the understanding given by the A.Rs. for the management before the ALC (C) New Delhi, was that workmen would be taken back in service as and when there was work according to their seniority. It will be therefore, just and proper if his reinstatement is ordered without payment of back wages.

Held that this part of the reference as relates to the regularisation of the services of the workman other than Sri Laxaman Singh is concerned it has become infructuous in view of regularisation of their services. As regards Sri Laxaman Singh, it is held that he had not abandoned the services w.e.f. 1-11-85; rather along with other workmen he was declared surplus on completion of the job. However, in view of the understanding given by the management's representative before ALC (C) New Delhi, he did not come forward for the job within a reasonable time. As held by me above he is ordered to be reinstated in service but without back wages. I may make it clear that while examining the question of regularisation of his services, the past services rendered by him during December 1981 to October 1985 shall also be taken into consideration.

The reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 मई, 1992

का.ग्रा. 1359.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, साऊथ मालाबार ग्रामीण बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में श्रम न्यायालय, कोझीकोड के फंक्शंस को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/110/91-आई आर (बी-3)]

सुभाष चन्द्र शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th May, 1992

S.O. 1359.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Labour Court, Kozhikode

[No. L-12012/110/91-IR (B-III)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

Dated this the 20th day of April, 1992

Shri K. G. Gopalakrishnan, B.A., B.L., Presiding Officer.
I. D. (C) 4/91

**The Chairman,
South Malabar Gramin Bank,
Head Office, Malappuram** **Management**

Shri M. Majeed,
S/o Kunhimarackar,
Mudavangadan, Veedu, P.O. Edaribode,
Malappuram District. Worker.

Sri K. V. Sachidanandan, Advocate, Kozhikode—For
Management.

571 M. Asokan, Advocate, Kozhikode—For workman.

The dispute between the aforesaid parties in connection with the termination of service of a workman by name Sri Majeed, Temporary Messenger, Idarikode Branch of the South Malabar Gramin Bank was referred to this Court for adjudication by the Central Government under Section 10 of the Industrial Disputes Act by its order No. L-12012/110/91-IR (B-III) dated 2-8-1991.

2. After the receipt of the reference order in this Court both the management and the worker entered appearance and filed claim statements setting forth their stand in the dispute. The brief averments in the statement filed by the worker are as follows :—This worker was appointed as a Messenger in the Edarikode Branch of the management bank on 16-4-1987 for a daily wage of Rs. 21.95. While he was working thus his service was terminated with effect from 9-2-1988 by the management without assigning any reason. This termination is illegal and unjust as the workman has become a permanent employee having worked for more than 240 days. The management has no right to terminate his service. Even if the service of this workman has to be terminated it can be done only as provided in Section 25-F of the Industrial Disputes Act by paying the workman re/renchment compensation and notice pay. As this has not been done, on this ground alone the termination is illegal. Hence an award may be passed setting aside the order of termination and directing the management bank to reinstate the workman in service with back wages and continuity of service.

3. The brief averments in the statement filed by the management are as follows :--It is true that the workman is appointed as a Messenger in the Edarikode Branch with effect from 16-4-1987 on a daily wages of Rs. 21.95. It is also true that while he was working thus his service was terminated on 9-2-1988. But this termination cannot be questioned as the management has every right to terminate his service at any time since he being only an employee working on daily wages. Moreover Section 25(F) of the Industrial Disputes Act has no application in his case as he has not worked 240 days continuously. Hence an award may be passed upholding this action of the management.

(1) Whether the termination of service of the workman is legally valid ?

(3) Result ?

6. Point No. I.—It is the admitted case that the service of the workman who is appointed as a Messenger in the Edarikode Branch of the management bank on a daily wage of Rs. 21.95 from 16-4-1987 was terminated on 8-2-1988. Now it is this termination that is questioned by the workman. The attack is on the ground that as he has worked for more than 240 days he will be deemed to have one year service by virtue of Section 25(B) of the Industrial Disputes Act and as such his service can be terminated only as provided in Section 25-F of the Industrial Disputes Act by paying retrenchment compensation and notice pay, and as this has not been done it is illegal.

7. It is conceded by the management that if a workman has worked continuously for 240 days he will be deemed to have one year service by virtue of Section 25(B) of the Industrial Disputes Act and that the service of such a worker can be terminated only by paying retrenchment compensation and notice pay as provided in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. But the stand of the management is that this worker has not worked for 240 days and hence neither 25(B) nor 25-F has application in his case. This stand is taken up by the management since according to the management he has not actually worked 240 days. Or in other words according to the management, Section 25(B) will be attracted only if a workman has actually worked 240 days. But this contention of the management cannot be accepted in view of the decision of the Supreme Court reported in 1986-LIC-p 98 wherein it was held by the Supreme Court that while counting 240 days for the purpose of Section 25 (B) intervening holidays and Sundays also will have to be taken into account. Ext. M-1 which is a document produced by the management clearly reveals that if the intervening holidays and Sundays are counted this workman has worked 299 days from the date of his appointment to the date of his termination. Thus it is evident that this workman has worked for more than 240 days. So much so he will be deemed to have one year service by virtue of Section 25 (B) of the Industrial Disputes Act and hence his service can be terminated only by paying notice pay and retrenchment compensation as laid down in Section 25-F of the Industrial Disputes Act.

8. Now the legal position has been well settled that compliance of Section 25-F is mandatory, and condition precedent for retrenchment and if a workman is retrenched without satisfying these conditions it will be invalid in law. Thus as this workman has been retrenched without complying with these statutory requirements it is invalid in law. This point is thus decided in favour of the workman holding that the termination of service of the workman is invalid in law.

9. Point No. 2.—Then the question is whether the workman is entitled to any relief. The relief claimed by the workman is reinstatement with back wages and continuity of service. Now it is found in answer to Point No. 1 that the termination of service of the workman is illegal as it violates the mandatory provisions of Section 25-F. Now the legal position has been well-settled that a termination made by an employer violating the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act will be abinitio-void in law and hence in such cases the worker is entitled to reinstatement with back wages and continuity of service as if there is no termination at all. See in this connection the decisions of the Supreme Court reported in AIR 1960-S.C. 610, 1982-LIC-1680, 1982-LIC-1739. In these decisions the Supreme Court has held that compliance of Section 25-F of the Industrial Disputes Act is a condition precedent for retrenchment and hence if a retrenchment is made violating these provisions or without complying with these provisions, the termination will be illegal and in such cases the workman is entitled to reinstatement as if there is no termination at all. This is exactly the case here. As stated earlier, the workman in the instant case has been retrenched without paying him retrenchment compensation and notice pay as provided in Section 25-F of the Industrial

Disputes Act although he has worked for more than 240 days. This being the position the retrenchment is invalid in law and hence the workman is entitled to the relief of reinstatement with back wages and continuity of service as if there is no termination at all.

10. Point No. 3.—In the result an award is passed directing the management bank to reinstate the workman in service with back wages and continuity of service.

11. This award will come into force 30 days after its publication in the Official Gazette.

Dictated to the Confidential Assistant, transcribed by him; revised, corrected and passed by me on the 20th day of April, 1992.

K. G. GOPALAKRISHNAN, Presiding Officer

APPENDIX

Witnesses examined on either side :—

NIL

Documents marked on the side of the Worker :—

NIL

Documents marked on the side of the Management :—

Ext. M-1—Register of General charges subsidiary—Canara Bank, Edarikode.

Ext. M-2—Notification of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division) New Delhi dated 28-9-1988.

Ext. M-3—Letter of General Manager, 9/SMGB/1126/91-92/IR dated 16th July 1991.

नई दिल्ली, 6 मई, 1992

का.ग्रा. 1360 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुच्छेद में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/576/87-डी-2(ए)]

एस.सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1992

S.O. 1360.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-12012/576/87-DII-(A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 90 of 1988

In the matter of dispute between :

The District Secretary,
Bank of Baroda Employees' Association,
C/o Bank of Baroda Moti Bagh,
Faizabad.

AND

The Manager,
Bank of Baroda,
Faizabad.

APPEARANCES :

Sri M. K. Verma, & Sri M. F. Hussaini Personnel Officer
for the Management.

Sri M. Lal—for the Union/workman.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification no. L-12012/576/87, DII(A) dt. 15-7-88, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal --

Whether the action of the management of Bank of Baroda was justified in not granting the Head Cashier Category A allowance to Sri Suraj Prasad although he was the seniormost Accounts-cum-cash clerk? If not to what relief is the workman concerned entitled?

2. The Industrial Dispute on behalf of the workman has been raised by the Bank of Baroda Employees Association through its District Secretary, Faizabad.

3. The case of the Union is that by virtue of settlement dt. 3-10-78, as amended by settlement dt. 18-4-84, between the management of the bank of Baroda and All India Bank of Baroda Employees Federation, special allowance of Head Cashier Category 'A' is payable to an employee working in the clerical cadre for holding cash key and cash remittance. According to the Union, Faizabad Branch of the Bank deputed another clerk Sri Alok Kumar who is junior to the workman for remittance work in the Currency Chest at Bank's Khulda-bad Branch Allahabad and handed over to him cash key when the workman being the seniormost cash clerk at Faizabad Branch was entitled to be entrusted with the cash key for the job of cash remittance. On account of denial of opportunity to have the cash key, the workman is entitled to said special allowance of head cashier category A at the rate of Rs. 216 per month for the period 31-8-85 to 20-8-86. Since it was not paid to him despite his representations the matter had to be taken up with the ALC(C) Kanpur, by the Union. The Union, has therefore prayed that the management of the bank be directed to pay Head Cashier Category 'A' Allowance at the rate of Rs. 216 per month alongwith consequential benefits to the workman for the period 31-8-85 to 20-3-86.

4. In their written statement, the management have admitted the existence of the two settlements dt. 3-10-78 and 18-4-84. According to the management inward and outward remittance is a casual activity in the branches of the bank having no link or connection with the payment of special allowance of Head Cashier category 'A'. No category of such an activity has been fixed for the purpose of special allowance in the Bipartite Settlement. This activity is carried out within the purview of normal routine duties by persons handling cash and can by no means be regarded as a special or additional category A. The management admit that the service of cash remittance to Khuldabad Branch of Allahabad was taken from Sri Alok Kumar and not from the workman. So under no circumstances, the workman stands prejudiced. Since the job does not require any extra skill, the question of seniority and juniority is absolutely redundant. According to the management it was just by a sheer mistake that a decision was taken to make pro rata payment of Head Cashier Category 'A' allowance to cashier accompanying the remittance from 9-2-85 to December 1987. But this practice was abandoned on account of exception taken by the higher authorities to the decision.

5. Now a uniform practice has been adopted so as to make an equal and equitable formulation and under this practice Rs. 10 are payable only as additional conveyance charges to the cashiers accompanying the remittance. Hence the reference is misconceived and the claim put up by the Union on behalf of the workman is liable to be dismissed.

6. In support of their respective cases both sides have led oral as well as documentary evidence. Whereas the Union

has examined the workman, the management have examined M.W.1 Sri V. P. Singh the then Sr. Manager, Faizabad main branch and now General Manager, Regional Rural Bank Sultanpur, and M.W.2, Sri S. S. Rai, Lead Bank Officer.

cash remittance or of cash in Boards, shall be paid Head Cashier Category A allowance on prorata basis w.e.f. 1st March, 1985.

6. From the claim statement of the Union it is abundantly clear that the Union has simply claimed special allowance of Head Cashier Category A for the period 31-8-85 to 20-3-86 which allowance according to the Union is payable under the settlement dt. 3-10-78 as amended by the settlement dt. 18-4-84 arrived at between the management of the bank and All India Bank of Baroda Employees Federation for holding cash key and cash remittances.

Thus it becomes evident that the decision in this regard was taken during discussion between the Union representative and the management representatives on 9-2-85. In the letter it was made clear that the decision taken by the management at the meeting with the Union representatives was not in conformity with the bank's laid down norms/policies. It was not within the provisions of laid down Rules and that Zones or Regions are not competent to create any such post position attracting special allowance without the specific sanction of the Functional Head of the Personnel Division. It is violative of instructions conveyed vide circular No. CO/RM:72:64 dt. June 6, 1980. Towards the end of this letter all the Regional Managers were asked to stop releasing payments of Head Cashier Category A allowance with immediate effect to the staff holding cash keys during cash remittance or cash keys of bonds kept in currency chest. Thus it becomes evident that this allowance was created for the first time w.e.f. 1-3-85, in the meeting held on 9-2-85 between the representatives of the Union and officers representing the management and that by means of letter dt. 19-1-88, the said decision was overruled with immediate effect.

7. Existence of these two settlements, as we have seen from the written statement, is not denied by the management. According to the management there is no specific provisions in either of these two settlements attracting such an allowance. However, in para 7 of the written statement the management have come out with the case that by a sheer mistake a decision was taken to make prorata payments of Head Cashier Category A allowance to cashier accompanying the remittances from 9-2-85 to December 1987 whereafter the practice of making payment of such allowance was abandoned because of the exception taken by higher authorities to this decision.

11. It further becomes evident that the clause of the two documents referred to by the Union in the petition before ALC(C) Kanpur, are simply on the point of determination of the question of seniority and on no other point.

8. The Union has not filed the relevant extracts from these two settlements for reasons best known to it. However the management have got filed the relevant extracts of these two settlements from M.W.2 Sri S. S. Rai. These are annexures 2 and 3 to his affidavit. With the claim statement the Union has filed the copy of its petition dt. 11-9-86 before ALC(C) Kanpur. The document has not been admitted by the management. However it appears that the Union in its petition before ALC(C) Kanpur placed reliance on clause 3 of 1978 settlement as amended by clause 3(a) of 1984 settlement. It will be therefore suffice to refer to annexure (3) which is the copy of extract of 1984 settlement. Clause 3-1(a) of the settlement refers to the question of seniority, i.e. to say how it will be determined. Thus I find nothing in this settlement on the point of making payment of special allowance of Head Cashier Category A to employees carrying cash key and cash remittances.

12. The case set up by the Union with regard to the workman in the claim statement is that during the period 31-8-85 to 20-3-86 the workman was denied cash key when there had been cash remittance from the Faizabad to Currency Chest at Bank's Khulabad Branch, Allahabad. Instead cash key was made over to his junior Sri Alok Kumar. The fact that Sri Alok Kumar is junior to the workman has been admitted by M.W.1 Sri V. P. Singh, in his cross examination.

13. In order to show that there is no force in the class put up by the Union on behalf of the workman, Sh. M. K. Verma the authorised representative for the management has made a few submissions before the Tribunal.

9. On 27-9-91, the management examined M.W.1 Sri V. P. Singh. He was duly cross examined by M.M. Lal Advocate who appeared for the Union. The same day after the examination of this witness, the management sought time to examine another witness. The opportunity was given to the management for this purpose. On 30-10-91, management filed the affidavit of M.W.2 Sri S. S. Rai whereupon 27-12-91 was fixed for his examination. Since on 27-12-91, the management filed 5 documents, 7-2-91, was fixed for cross examination of second witness. Since none had appeared from the side of the Union on 30-10-91 and 27-9-91, a notice was ordered to be issued to the Union for the next date. Even on 7-2-92 despite issue of notice to the Union no one turned up on behalf of the Union. The authorised representative for the management examined M.W.2 Sri S. S. Rai and closed the management's evidence. On 7-2-92, 3-4-92 was fixed for arguments and on 3-4-92 arguments were heard and the case was reserved for giving of award.

14. Firstly he has urged that the workman was not senior most cash clerk during the period in question. In this connection he has referred to the statement of M.W.1, Sri V. P. Singh, who at the time of cross examination brought with him the muster roll of 1984, 1985 and 1986. He has deposed that in the muster roll the names are entered seniority wise. Not only in 1984, but also during the period in question the name of the workman appeared at Serial No. 5, in the Seniority/Muster roll.

15. Secondly, he has urged that the question of seniority and juniority has nothing to do with the entrustment of cash keys while making remittance of cash. In this connection Sri M. K. Verma, the authorised representative for the management has referred to para 9 of the affidavit of M.W.2 Sri S. S. Rai and Annexure IV to his affidavit. In para 9, the management witness has deposed that as per book of instructions Volume II of the Bank Cashier accompanying the remittance are required to be rotated to ensure safety and Security Measures in respect of cash remittance, whether locally or outside. He has further deposed that keeping in view the safety and security measures the cashier accompanying cash remittance is rotated only a day before in the after noon and no disclosure in this regard is made earlier. As such no particular cashier can be assigned with the duties of cash remittance of regular permanent basis. Annexure IV to his affidavit is the Zorex Copy of the said Book of Instructions. It deals with cash remittance, seniority and security measures in respect of cash remittance. At serial No. 3 under the heading General Precautions it is stated that where transportation of cash between two offices is a regular feature, care should be taken to ensure that specific pattern with regard to days, timings, routes, frequency etc., does not emerge. Wherever possible cashier accompanying the remittance should be rotated.

10. M.W.2, Sri S. S. Rai has filed with his affidavit one document which is annexure 7. It is the photostat copy of letter dt. 19-1-89, from the Deputy General Manager of the bank to all the Regional Managers. From this letter it appears that the decision to make payments of Special Allowance admissible to Head Cashier Category A to cashier holding keys of cash during cash remittance was taken on 9-2-85. In the letter the Deputy General Manager has quoted the demand made by the Union in this regard and the reply given by the management with regard to the demand raised by the Union. Management's reply quoted in the letter reads as follows :—

Management's reply :

The management informed that the staff members who are required to hold the keys of the cash during

16. Lastly, Sri M. K. Verma, the authorised representative for the management has submitted that the practice of payment of special allowances of Head Cashier Category 'A' which is the subject matter of this case was stopped vide letter dt. 19-1-88 of the Deputy General Manager addressed to all the Regional Managers as being against the instructions conveyed vide circular No. CO/RM:72/64 dt. 6-6-90. In fact without the specific sanction of the Functional Head of the Personnel Division no such allowance could have been sanctioned. It is annexure VII to the affidavit of M.W.2 Sri S. S. Rai. This has also been referred to by me above. In support of this point he has referred to annexure IX to XII filed by the bank with the list of documents on 27-12-91; and proved by M.W.2 Sri S. S. Rai.

17. Annexure IX is the copy of confidential D. O. dt. 18-7-75, from the Government of India, Ministry of Finance (Banking Division). In it attention has been drawn to the fact that during discussion a point was made that bank should not agree to new benefits or allowances to the award staff outside the existing settlement as otherwise the payments made in different banks will go out of alignment with each other. Reference was also made to the D. O. letter No. 6-1-74-Accounts dt. 24th May, 1974, of the Secretary, Department to Banking requesting All Chairman of Public Sector Banks not to bring any changes in wages and concessions payable to the employees of the bank (both Award Staff & Officers) without proper consultation in the Appropriate Committee of the Cabinet. Annexure X is the copy of Confidential D. O. Letter dt. 31-12-77, from Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) on the same point. Annexure XI and Annexure XII, are two more D. O. letters dt. 11-6-80, and July, 1981, from the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division), to the various officers of the Bank on the same point impressing upon the officers that such allowances and benefits as have been agreed upon even after the issue of instructions, the same may be frozen.

18. After hearing Sri M. K. Verma, the authorised representative for the management; and going through the documentary and oral evidence referred to by me, I find myself completely in agreement with the views expressed by Sri Verma. The workman having not been entrusted with the cash key, in view of withdrawal of the benefits by the bank he cannot be granted any relief. It is not necessary for the bank to have entrusted the cash keys to the workman during the said period. Under the Secretary measures it could have been entrusted even to juniors. It is a settled law that a Subordinate Authority cannot assume powers which are not conferred in it. Every decision taken by a subordinate authority beyond the powers conferred would be a nullity.

19. Thus the Union has no case at all for the workman. Held that the action of the management of the bank in not granting the Head Cashier Category A allowance to Sri Suraj Prasad cannot be assailed by the Union/workman. It was quite justified. Consequently, the workman is held entitled to no relief.

20. Reference is answered accordingly.

ARIAN DEV, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 6, मई-1992

का.आ.1361—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का. 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या: एस-12012/683/86-डी-2(ए)]

एस.सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1992

S.O. 1361.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central Bank of India and their workman, which was received by the Central Government on 5th May, 1992.

[No. L-12012/683/86-D.II(A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARIAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 91 of 1987

In the matter of dispute between :

Sri Surendra Prasad Sharma,
C/o Sri Ram Naresh Sharma,
Gwalior Student Saloon,
Station Road, Deoria, U.P.

AND:

The Regional Manager,
Central Bank of India,
Regional Office, Gandhi Nagar,
Golghar, Korakhpur.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/683/86-D.II(A) dated 29th July, 1987, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal:—

Whether the action of the management of Central Bank of India in relation to their Deoria Branch in terminating the services of Sri Surendra Prasad Sharma w.e.f. 4th December, 1985 & not considering him for further employment while recruiting fresh hands under section 25H of the Industrial Dispute Act, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?

2. The case of the workman is that with a view to avoid appointment of permanent hands, the management started the practice of appointing employees on temporary basis for doing the duties of regular nature so that they could not earn the benefits of modified Sastri Award, including the question of their regularisation in service. The workman further alleged that such temporary employees were retrenched and fresh hands appointed to avoid their continuation/absorption, which was an unfair labour practice. It is further alleged by the workman that he was appointed by the bank against a regular post of peon on 24th November, 1982 at bank's Deoria Branch and had worked as such in the said branch for 793 days upto 3rd December, 1985. He had worked for over 240 days in 1983-84 and 1985 excluding Sundays and Holidays as per statement annexure A to the claim statement. The workman was doing the duties of a regular/permanent nature of a peon and was not the junior most at the time of his termination. The bank thus violated the mandatory provisions of Sec. 25-F, 25-G and 25-H of the I.D. Act, read with Sec. 25-J & I.D. (Central) Rules. The workman has also alleged that the bank violated the provisions of the modified Sastri Award including paras 493, 495, 507, 516, 522 & 524 read with paras 20.7 & 20.8 of the 1st Bipartite Settlement. The workman has, therefore, prayed for his reinstatement in service with full back wages and all consequential benefits.

3. The management plead that the workman had worked at Bank's Deoria Branch from 25th November, 1982 to 3rd December, 1985 intermittently as a casual labourer on daily wages. His job mainly consisted of fetching and serving water to staff members. The number of his working days in the year 1983-84 and 1985 are shown in annexure A to the written statement. I may state here that no such statement was found.

annexed with the written statement. It was however filed by the management on 4th May, 1988. According to the said statement he had worked for 25 days in 1982, 133 days in 1983, 116 days in 1984 and 136 days in 1985 total 410 days. According to the management he was never appointed against a regular post of peon. The management deny that the bank ever adopted any unfair labour practice as alleged by the workman in the claim statement. The management also deny the violation of any provisions of I.D. Act, modified Sastry Award and Bipartite Settlement. According to the management one permanent sub-staff already employed in the bank was posted at Deoria branch on 31st March 1986 against the vacancy caused by the retrenchment of a sub-staff on 31st December, 1983. The other pleas raised by the management are that the reference is bad in law and that Sri Surendra Prasad Sharma is not a workman under Desai Award, Sastry Award and Bipartite Settlements.

4. In his rejoinder the workman has alleged that the reference made by the Ministry of Labour, Government of India, is not a valid reference.

5. In support of their respective cases both sides have led oral as well as documentary evidence and whereas the workman has examined himself, the management have examined Sri Ram Vilas Dubey, Regional Manager, Gorakhpur.

6. I may state here that the workman examined himself and closed his evidence on 27th October, 1989. After the filing of affidavit evidence by the management, 22nd February, 1990 was fixed as the date for examination of management witness. On 22nd February, 1990 the workman sought adjournment upon which the case was adjourned to 26th March, 1990. On 26th March, 1990, the workman and his authorised representative were absent. The management side was represented by Sri Rakesh Tondon, an officer of the bank. The management witness also attended the Tribunal for giving evidence. Since there was none from the side of the workman to cross examine the management witness, Sri Rakesh Tondon tendered in evidence the affidavit of the management witness and also examined him to prove some documents. Thereafter 5th April, 1990 was fixed as the date for hearing arguments. On 5th April, 1990, Sri V. N. Sekhari, A.R. withdrew his authority from the side of the workman upon which notice was ordered to be issued to the workman for 30th April, 1990. On 30th April, 1990, Sri J. C. Dhawan put in appearance on behalf of the workman as his authorised representative and moved an application for adjournment. On the application of Sri Dhawan the case was adjourned to 29th May, 1990. On 29th May, 1990 Sri M. Lal Advocate filed his authority on behalf of the workman and moved an application for setting aside order dated 26th March, 1990. On 16th August, 1990, the management filed objection against the said application and also took exception to the appearance of Sri M. Lal Advocate. On 16th August, 1990, 18th September, 1990 was fixed for disposal of the application dated 29th May, 1990 of the workman for setting aside the order dated 26th March, 1990. On 18th September, 1990 it was decided that first of all the question of competence of Sri M. Lal Advocate to appear before the court on behalf of the workman be examined and for that 6th November, 1990 was fixed. Before the question as to the competence of Sri M. Lal to appear on behalf of the workman could be decided Sri K. H. Soni filed his authority on behalf of the workman on 28th February, 1991. After various adjournments most of which was sought by the workman the case came up for hearing arguments on 30th October, 1991. On 30th October, 1991, Sri Soni applied for adjournment on account of his ill health. However, I heard the arguments of the management side and fixed 6th November, 1991 for hearing arguments of Sri Soni with the observation that if he happened to be unwell again on the next date he might file his written arguments by 6th November, 1991. On 6th November, 1991 arguments of Sri K. N. Soni were heard, and the case was reserved for giving award. Since while preparing the case for dictating award I had found that the workman's application dated 29th May, 1990 for setting aside order dated 26th March, 1990 had not been disposed of I vide my order dated 18th November, 1991 fixed 20th December, 1991 for the disposal of the said application. On 20th December, 1991 whereas Sri M. K. Gaur appeared for the management, Sri Soni sent application for adjournment. On this application the case was adjourned to 10th February, 1992. Since on 10th February 1992, the P.O. was on leave the case was adjourned to 23rd March, 1992. On 23rd March,

1992, neither the workman nor his authorised representative appeared to press the application dated 29th May, 1990. From the side of the management Sri Gaur appeared and the application was therefore dismissed and the case was reserved for giving award.

6. The workman's case is that he had worked for 793 days from 24th November, 1982 to 3rd December, 1985 as per details given in statement annexure A to the claim statement. According to this statement he had worked for 30 days in 1982, 259 days in 1983, 270 days in 1984 and 233 days in the year 1985 total number of working days coming to 792 days and not 793 days. On the other hand the case of the management is that he had only worked for 410 days from 25th November, 1982 to 3rd December, 1985 as per statement A to the written statement filed by the management on 4th May, 1988, the workmen is said to have worked for 25 days in 1982, 133 days in 1983, 116 days in 1984 and 136 days in 1985.

7. To ascertain the correct number of working days, the workman moved an application for joint inspection on 4th May, 1988. The application was allowed. However, on 5th May, 1989 the said order of joint inspection was vacated by me when it was found that the workman was insisting on inspection of some documents pertaining to other employees. On 20th December, 1988 the management had filed the affidavit of Sri Inder Sain Wadhan Regional Manager, Gorakhpur. In para (3) of which it was deposed by the R.M. that on 11th November, 1988 the date fixed for joint inspection the workman was present but he did not inspect any record and insisted for production of these vouchers also which were not in his name in order to increase his number of working days on which payments were made to others. In support of it he filed a report dated 11th November, 1988 of the Branch Manager Deoria with his affidavit, the management witness Sri Ram Vilas Dubey has also corroborated this fact by means of his affidavit. There has been no cross examination of the management witness on this point. In this connection it will be useful to refer to some of the statements made by the workman in para (3) of his statement in his cross examination. He has clearly stated that he also wanted to inspect the vouchers which were in the names of other persons. The management rightly did not allow the workman or his representative to inspect vouchers through which payments were made to other persons. I may state here that in his pleadings, no where the workman has set up the case that some hums payments of wages are used to be made to him in the name of other persons. The joint inspection of voucher was the best way to ascertain the number of working days of the workman, but this opportunity was not availed by the workman and his authorised representative. Ext. W.1 is the copy of proceedings dated 27th October, 1986 before ALC(C) Allahabad. Even before ALC(G) Allahabad the management reiterated their stand and to the number of working days of workman. I therefore find that the evidence given by the management with regard to the number of working days of the workman is far more reliable than the evidence of the workman.

8. If we take into consideration the period of 12 months preceding the date of termination of service of the workman as per statement annexure A to the written statement the workman will be found to have worked for 140 days which is far less than 240 days in a year. Hence, in his case section 25F I.D. Act is not attracted at all, as such the workman was not entitled to any notice or notice pay and retrenchment compensation.

9. The workman has alleged breach of paras 493, 516, 522 and 524 of the modified Sastry Award. They are not material so far as the facts of this case are concerned. As it has been found above that the workman had not completed 240 days in a year preceding the date of his termination the question of application of Section 25F I.D. Act does not arise in the present case. It is applicable only in respect of workmen who are covered under section 25B of the Act as a continuous workman. Since the workman has not been found to be a continuous workman, therefore, the provisions of section 25H, have no application in his case. Similar is the case with regard to the applicability of the I.D. (Central) Rules, 1955.

10. Thus from all that has been said above, I find no force in the case set up by the workman in his claim statement.

Hence, it is held that the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of the workman w.e.f. 4th December, 1985 and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under Section 25-H of the I.D. Act is justified. Consequently the workman is held entitled to no relief.

11. Reference is answered accordingly.

ARIJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1992

का.ग्रा. 1362-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक, के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-1992 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/94/90-डी-2(ए)]

एस. सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1992

S.O. 1362.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-1992.

[No. L-12012/94/90-D.II (A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARIJAN DEV, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,
DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 171 of 1990

In the matter of dispute :

BETWEEN

The Assistant General Secretary,
P.N.B. Staff Association,
Through R. K. Pandey,
67/99, Lalkuwan,
Lucknow.

AND

Regional Manager,
Punjab National Bank,
Faizabad.

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its notification No. L-12012/94/90-D.II (A) dated 3-6-90, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the management of Punjab National Bank in imposing the punishment of stoppage of one increment on Sri R. N. Tripathi, clerk-cum-cashier is justified? If not, to what relief the workman is entitled?

2. The industrial dispute on behalf of the workman has been raised by Punjab National Bank Staff Association Lucknow (hereinafter referred to as Union) through its Assistant General Secretary.

3. The admitted facts are that while the workman was posted as clerk-cum-cashier in the Balrampur Branch of the Bank he was served with chargesheet dated 13-11-87 copy Ext. W-1. The charges were—

On 30-10-87 at 10.45 a.m. when Sr. S. R. Soni Officer of this office was entering office with the help of Police alongwith other managerial staff/willing workers, Sri K. K. Shukla suddenly obstructed his way by keeping his both the hands on the channel gate of the office, when he took the entry after bending from one side.

You came to office at about 1.30 p.m. and started shouting loudly and extremely, disorderly and in riotous manner. You had also abused Sri S. R. Soni in the following language—Sale Soni Bhosari wale teri andar jane ki himmat kaise hui. Madarchod bahar nikal sale pachas jute maroonga, chehra pahchanne me nchin ayega, Kya tumne mujha T. N. Dwivedi samajh rakha hai.

The aforesaid act on your part is a gross misconduct in terms of para 19.5(c) of the Bipartite Settlement dated 19-10-66.

Further you had resorted alongwith your companions instigated staff members of this office on 30-10-87 to participate in the illegal strike.

You had indulged in acts of force and holdout threats of intimidation against non striking employees/managerial Personnel of this office on 30-10-87.

You had alongwith your companions raised filthy/indecent language while raising slogans when a demonstration was staged between 2 PM to 3 PM on 30-10-87. Some of the slogans are reproduced as under—

1. P.N.B. Management Murdabad.
2. Ghushkor Management Murdabad.
3. Bhrasht Management Murdabad.
4. PNB Management ka nom 'illegible'
5. Police bulane wale manager ka nam ko.
6. PNB Ke Sabhi adhikariyon ki ma ka bhosra.
7. Police bulane wale manager ki ma ka bhosra.
Sab karte hai yoh ghoshna Sitaram Soni ki ma ka bhosra va chut.

Due to your aforesaid conduct, the bank had not only lost its considerable business on date but our valuable customers were put to lot of inconvenience. Thus it has caused unnecessary annoyance against us, and the bank may lose their valuable clientage—Moreover the normal functioning of the office was also affected. The whole incident had tarnished the bank's image to a great extent.

You had accordingly misconducted in terms of para 19.5 (j) of the bipartite settlement dated 19-10-66, since aforesaid conduct is prejudicial to the interest of the bank.

The workman denied the charge by means of his reply dated 19-11-87 and feeling dissatisfied with the reply given by the workman, a departmental inquiry was ordered against him and Sri U. S. Awasthi was appointed Enquiry Officer. The E.O., after holding the inquiry gave his report dated nil, Ext. M-2, he held the charge relating to the abuses hurled by the workman, on Sri S. R. Soni, Assistant Manager, as proved. Ext. M-2, is the copy of inquiry report. The Regional Manager, Regional Office, Lucknow, who was the Disciplinary Authority, issued to the workman a notice to show cause why punishment of stoppage of 2 increments with cumulative effect under para 19.5(d) of the 1st Bipartite Settlement be not awarded to him. Before issuing the notice he agreed with the findings given by the E.O. After giving the workman a personal hearing the disciplinary authority vide his order dated 11-7-88, copy Ext. M-3, confirmed the show cause notice and awarded to the workman punishment of stoppage of two increments with cumulative effect. Against the said order of punishment the workman went in appeal which was heard by the Zonal Manager in his capacity as Appellate Authority. The Appellate Authority vide his order dated 13-2-88, copy

Ext. M-4 reduced punishment to stoppage of one increment with cumulative effect.

On 10-4-91, the following preliminary issue was framed in the case—

Whether the departmental inquiry was not conducted fairly and properly by the management?

On 31-10-91, it was submitted by Sri B. P. Saxena the authorised representative for the Union that on the preliminary issue he would simply show that the finding of guilt recorded by the E.O. and accepted by the Disciplinary Authority is not based on evidence recorded during inquiry. In view of it I shall be referring to the pleadings of the parties so far as they are relevant on the point pressed before me by Sri Saxena.

The only point which now remains in the claim is that the finding of guilt is not based on evidence; it is perverse. I may state here that Sri Saxena, during the course of his arguments has not pressed the pleas raised in the claim statement that the chargesheet is ambiguous and that the objection taken on behalf of the workman before the E.O. regarding the appointment of disciplinary authority was not properly decided. Even otherwise there is no force in these pleas. There is no ambiguity at all in the chargesheet.

In their written statement the management have pleaded late authority is not based on evidence, i.e. to say, is it evidence, it is not perverse. In fact on 30-10-87, there was an All India Strike by the members of All India Bank Employees Association and the workman being a member of Punjab National Bank Staff Association affiliated to All India Bank Employees Association remained on strike on 30-10-87. It has also been pleaded by the management that in case the Hon'ble Court holds that the departmental inquiry is vitiated, for any reason what so ever, in that case management be permitted to lead evidence in support of the facts/charges.

Both the sides have not led any oral evidence. They have placed reliance on documents filed by them.

Thus sole question to be determined in the case is whether the finding of guilt recorded by the E.O. and accepted by the Disciplinary Authority and confirmed by the appellate authority is not based on evidence, i.e. to say is it perverse? I may state here that during the inquiry the management examined two witnesses, namely, PW-1 Sri Jagat Singh, Manager, and PW-2 Sri S. R. Soni Assistant Manager. In defence the workmen examined two witnesses, namely, DW-1 Sri Rajender Singh and DW-2 Sri Subhash Rao. Both the DWs are the members of the Award Staff posted at P.N.B. Patampur Branch of the Bank. First of all he has argued that at the departmental inquiry no independent witness such as customers of the branch of the bank was examined by the management. In this arguments I find absolutely no force. In para 4 of the rejoinder it has been stated by the Union that on 30-10-87 there was a All India Strike. Naturally therefore, this fact must have come to the notice of the public at large, including the employees of the bank's branch. In the circumstances no customer would have come to the branch of the bank for transaction of any business.

Secondly, Sri Saxena has argued that PW-2 Sri S. R. Soni has not said anything about the part played by Sri V. K. Shukla another employee who was also chargesheeted. In this point as will evident, there is no force. The charges were being investigated against the workman and not against Sri Shukla reference in the chargesheet of the workman to the misconduct committed by Sri Shukla on that date at 10.45 a.m. appears to me to be only introductory.

Thirdly, it has been argued by Sri Saxena, that the evidence of the two defence witnesses examined at the inquiry by the workman was wrongly discarded by the E.O. Even in this point I find no force. Here I would like to refer to what has been said by the E.O. about these two witnesses in para 9 of his report. He has discussed in detail why he was not relying on the evidence of these two witnesses and I see no reason to differ with him.

DW-1, Sri Rajendra Singh is a member of Punjab National Bank Staff Union which is affiliated to NCBE. The Union to which he belong was not on strike. In his examination in chief he has said that from 1 p.m. to 2 p.m. he was present in the office and that during the said period no such incident in respect of which charge held as proved was framed against the workman had occurred. In his cross examination, when it was inquired from him as to between what hours workman was present in the premises of the bank he replied that he did not see the workman at all that day. It was again inquired from him during his cross examination whether he tried to know from any body about the whereabouts of the workman that day, his simply reply was that he did not make any such inquiry about the workman. It follows that he had not seen the workman throughout the day on 30-10-87. In his cross examination he has admitted that his duty was on Saving's bank, Long Books, and Head Office extract on that day. His evidence is therefore of no avail to the workman. Because it is in the evidence of DW-2 Sri Subhash Rao who was a member of the same Union to which the workman was the member and he had seen the workman that day in the morning till 9.30 a.m. and thereafter at 2.30 p.m. So there is no independent evidence to support his testimony. For reasons best known to the workman, the workman did not examined himself as a witness in defence.

Next it has been argued by Sri Saxena, that it does not appeal to mind that the two witnesses produced by the management would verbatim remember abuses noted in the charge held as proved.

There is nothing to be astonished as the words mentioned in the charge are not many. After all the two management witnesses are officers and not illiterate persons. It is not difficult for any literate persons to remember these words which can make a deep impact on the memory of persons hearing the same.

No other point has been pressed before me by Sri Saxena.

From the side of the management Sri Satpathi has argued that the witnesses examined at the inquiry were not enmical to the workman. So there was no reason for them to have justified at the inquiry against the workman. This fact that they were not enmical to the workman has not been disputed by Sri Saxena in reply. Secondly he has said that the workman has not dared to come in the witness box before the E.O. to deny the charge.

It is settled law that the Tribunal has to assess the findings given by the E.O. not as an appellate Court. It has simply to see whether such a view as was taken by the E.O. could be taken on the basis of evidence led at the inquiry. Further the charge in departmental proceeding has not to be proved beyond reasonable doubt as is done in the criminal case. The E.O./Dis. Auth. has simply to go by preponderance of evidence. After going through the evidence carefully I find that the finding recorded by the E.O. and accepted by the Disciplinary Authority and confirmed by the Appellate Authority is sound one. It cannot be said that it is not based on evidence.

Hence, I hold that the inquiry was conducted fairly and properly and that finding of guilt recorded is based on evidence, it is not perverse.

Therefore, it is held, that the action of the P.N.B. in imposing punishment of stoppage of one increment with cumulative effect on the workman is justified. The workman is entitled to no relief.

Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 6 मई, 1992

का.ग्रा. 1363—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय

सरकार, आन्ध्रा बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/99/89-डी-2(ए)]

एस.सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1992

S.O. 1363.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the Industrial Disputes between the employers in relation to the Mgt. of Andhra Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-12012/99/89-D.II(A)]

S.C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR-COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 199 of 1989

In the matter of dispute

BETWEEN :

Sri Rajesh Kumar
C/o Sri Shyam Lal
Agricultural Farm
Krishi Vibhag
Nawabganj, Kanpur.

AND

Chief Manager
Andhra Bank
Zonal Office Flat No. 206-209
Dusari Manjil
Rajendra Place, New Delhi

AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour vide its Notification No L-12012/99/89-D.2(A) dt. 18th August 1989 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :—

“Whether the action of the management of Andhra Bank in dismissing from service Sri Rajesh Kumar is justified? If not to what relief is the workman entitled?”

2. The admitted facts are that the workman was appointed as sub staff at Kanpur Branch of Andhra Bank on 26-7-84. On 17-10-85 he was served with a chargesheet copy annexure 2 to the claim statement of the workman. The charge sheet reads as under —

It has been brought to our notice that you managed to produce a bogus certificate,

suppressed the facts of your real qualifications and gained entry by adopting clandestine methods.

In this connection, it is alleged that you produced your school leaving certificate issued by Vishwanath Junior High School at Rawatpur in proof of your studies upto 8th class. It has come to our knowledge that there is no school with such a name existing at Rawatpur. You managed to prepare a bogus school leaving certificate and deliberately produced to the bank and gained an employment in our bank. This is a serious misconduct in terms of clause 19.5 (m) of the B. P. Settlement proper will be initiated against you without any further reference to you.

The workman denied the charges Sri S.R. Dastgir was appointed E.O. On inquiry he found the charge as proved. Accepting his findings the disciplinary authority vide his order dt. 29-12-87 awarded him the punishment of dismissal from service.

3. The workman has challenged, both the inquiry and the order of punishment on a number of grounds. Since on 6-1-92 it was submitted before the Tribunal by Sri V. Singh, the authorised representative for the workman alongwith the workman that the workman did not challenge the fairness of the inquiry and that he simply challenged the order of punishment on the ground that the finding recorded by the E.O. and accepted by the disciplinary authority and confirmed in appeal by the Appellate Authority was perverse. I need not refer to other grounds set up by the workman in the claim statement. I may state here that in their statements on 6-1-92 both the workman and his authorised representative sought indulgence of the Tribunal u/s 11-A of the I.D. Act, also. So the ground on which the order of punishment had been assailed by the workman is that the finding given by the E. O. and accepted by the Disciplinary Authority and confirmed in appeal by the Appellate Authority is perverse and not based on evidence.

4. In their written statement the management have pleaded that the finding is not perverse.

5. In this case in support of his case the workman has examined himself on 29-10-91. It was thereafter that the statement referred to above was made by the workman and his authorised representative on 6-1-92. In view of the said statement it was submitted before me by the authorised representative of the parties on 6-1-92 that there was no need for further oral evidence and that a date be fixed for arguments in the case. I may also state here that the above statement dt. 6-1-92, was given by the workman and his authorised representative in all probability on the basis of facts stated by the workman in his cross examination which show as if the inquiry was conducted by the E.O. fairly and properly in accordance with the principles of natural justice.

6. During the course of arguments, the auth. representative for the parties have simply relied upon the documents filed by the parties before the

E.O. I would like to make it clear that before me at the time of arguments it was submitted by the authorised representatives of the parties that the documents filed by the parties before E.O. should be read over and considered as if they are proved.

7. Ext. M-19, is the photostat copy of School leaving certificate dt. 31-7-80 purporting to have been issued by the Head Master of Vishwanath Junior High School Rawatpur District, Kanpur. In it the date of entry of the workman in the said educational institution has been given as 1-7-68 and the date of his leaving has been shown as 1-7-76. It further appears that at the time of leaving school he was 8th class fail. His school certificate is a matter of dispute between the parties.

8. From the side of the workman reliance has been placed on documents Ext. M-21, M-22, M-23, M-24 and M-25. These are the documents which were filed by the workman at the inquiry.

9. Ext. M-21 is the photostat copy of a certificate dt. nil issued by one Sri Ram Narain Pathak M.L.A. certifying that there was such junior high school at Rawatpur and that for some reasons the said school was closed in 1977-78. Ext. M-22 is the photostat copy of the certificate dt. 1-6-86 issued by one Sri Hori Lal, Organiser Pragati Sheel Karyakarta Mandal Kanpur City certifying that Vishwanath Junior High School existed in village Rawatpur but long back it was closed for some reasons Ext. M-24 is the photostat copy of a certificate dt. 7-10-86 given by one Sri Balram Singh of village Rawatpur certifying that Vishwanath Junior High School was running in his house in village Rawatpur and that for some reasons it was closed in 1977-78. The last certificate in this connection in this series is Ext. M-25. It is the photostat copy of certificate dated 1-6-86 issued by one Srimati Usha Singh belonging to Congress (I) Organisation. She has certified about the existence of the above school and its closure in 1977-78.

10. The above documents thus go to prove that there was such a school which for some reasons was closed in 1977-78. The last document i.e. Ext. M-23 shall be referred by me after I have dealt with the documentary evidence led by the management of the bank at the inquiry. I may make it clear that from the above documents relied upon by the authorised representative for the workman it does not stand proved that the workman had studied in Vishwanath Junior High School Village, Rawatpur and that the school leaving certificate Ext. M-19 was actually issued by the Principal of the said School. Sardar Amreek Singh the authorised representative for the management has first of all invited my attention to the endorsement dt. 18-7-85 of the Deputy Inspector of Schools, Kanpur. The endorsement is that the T.C. is fake. There is no school of the name of Vishwanath Junior High School Rawatpur, Kanpur. Ext. M-20 is the photostat copy of the letter dt. 21-8-85, from Zila Basic Shiksha Adhikari Kanpur to the Branch Manager Vikram Tower, New Delhi of the bank. In his letter he writes that on checking the HC had been found fake. From the letter it appears that it was written by Zila Basic Shiksha Adhikari Kanpur in reply to the letter of the Branch Manager dt.

14-6-85. The last document relied upon by Sardar Amreek Singh is Ext. M-18 which is the copy of letter dt. 25-4-87 from Zila Basic Shiksha Adhikari Kanpur Nagar to D.G.M. Lucknow of the Bank. This letter was written in reply to the letter dt. 25-4-87 of the Deputy General Manager, Zila Basic Shiksha Adhikari has written in it that the T.C. of the workman was fake.

11. Thus from the documents relied upon by the management prima facie it stands proved that school leaving certificate copy Ext. M-19 filed by the workman at the time of joining service was a fake one.

12. Now I come to Ext. M-23 which is the copy of letter dated 23-10-86 from Deputy Inspector of Schools Kanpur to the Branch Manager Vikram Tower New Delhi of the bank. In it he writes that he was again certifying the report already given by Sri Amba Shankar Misra Deputy Inspector of Schools. This letter was written with reference to letter dt. 14-6-85 of the branch manager which letter has also been referred by the Zila Basic Shiksha Adhikari Kanpur in his letter dt. 21-8-85 copy Ext. M-20.

13. Sri V. Singh the authorised representative for the workman has interpreted the following words in his own way :—

Sri Rajesh Kumar Dhobi ke sthanatharan pramanpatra tatkalin upvidhyalaya nirikshak Sri Amba Shanker Misra ne satyapit kiya tha. Jise punah satyapit kar aap ki sewa me avashyak karvai hetu bheja ja raha hai.

From the words underlined Sri V. Singh has tried to convince the tribunal that these words indicate that the school leaving certificate filed by the workman at the time of his appointment in the bank was the genuine one. I find myself unable to agree with it. The reference of the letter in reply to which it was sent. The name is found mentioned in the letter dt. 21-8-85 copy Ext. M-20 from the Zila Basic Shiksha Adhikari to the Branch Manager Vikram Tower New Delhi. It has been rightly argued by the authorised representative for the management that the bank's letter dt. 14-6-85 written by Zila Basic Shiksha Adhikari Kanpur was forwarded by him to the Dy. Inspector of School Kanpur. He replied the letter of the bank by means of his letter dt. 21-8-85 and subsequently the Dy. Inspector of Schools Kanpur also independently written about it to the branch manager of the bank by means of his letter dt. 23-10-86, confirming his earlier report about the school leaving certificate. Had the school leaving certificate on subsequent inquiry been found as not genuine the Dy. Inspector of Schools would have surely written that the earlier report given by his predecessor Sri Amba Shanker Misra was wrong and that on further inquiry the certificate had been found as genuine. His letter dt. 23-10-86, as said by me earlier was filed by the workman during inquiry before the E.O. There is another thing worth looking so far as this letter dt. 23-10-86 is concerned. From the note appearing at the foot of the letter it appears that alongwith it was sent the photocopy of the certification of the school leaving certificate. For reasons best known to the workman the copy of certification of the school leaving certificate was not filed at the inquiry nor it has been produced

by him before the Tribunal. If he could have got the photostat copy of letter dt. 23-10-86 from some where, he could have also obtained a photo copy of the said enclosure. The withholding of the document enclosed thus appears to be a deliberate act on the part of the workman.

13. The authorised representative for the management has also drawn my attention to the reply given by the workman during the course of inquiry to the question put to him by the management representative. The management representative had put to the workman a question that in the inquiry dt. 3-12-86, he had stated that the principal was staying near the school and that now he was saying that he had died in 1985, which one of the two statement was correct. In reply the workman stated that there were two persons of the same name but later on he came to know that as soon as school was closed he (the principal) died afterwards.

14. As we have seen above that the documentary evidence relied upon by the workman during the inquiry simply showed that the school had existed till 1977-78. If the principal had died soon after the closing of the school than how the certificate which bears the date of issue as 31-7-80 could have been issued. There is no explanation for it.

15. Thus from the above evidence I come to the conclusion that the workman has failed to prove that he had studied in Vishwanath Junior High School and that the school leaving certificate Ext. M. 19 was ever issued by the Principal/Head Master of the said school. These days it is not difficult to procure fake certificates from persons indulging in the trade of issuing fake certificates. Hence the finding of the E.O. as accepted by the Disciplinary authority and confirmed in appeal by the appellate authority cannot be assailed in the least. The charge was rightly held as proved against the workman.

16. A person who has obtained employment on production of false/fake testimonials cannot come forward and appeal to the tribunal to exercise its power under section 11-A I. D. Act to reduce the punishment. It is not possible.

17. Hence I hold that the action of the Andhra Bank in terminating Sri Rajesh Kumar from the service of the bank is justified. The workman is held entitled to no relief.

18. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

का.आ. 1364.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मे. भारत कोकिंग कोल लि. की भटडीह कोलियरी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 2) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था :

[संख्या एल-20012/202/85-डी-III(ए)]

एस.सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th May, 1992

S.O. 1364.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management Bhatdee Colliery of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. I-20012(202)/85-D.III(A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT
DHANBAD

PRESENT

Shri B. Ram, Presiding Officer

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947

Reference No. 93 of 1986

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhatdee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen.—Shri D. Mukherjee
Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy,
Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 27th April, 1992

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012(202)/85-D.III(A), dated, the February, 1986.

SCHEDULE

“Whether the demand of the workmen of Bhatdee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, that the following 29 casual workers should be regularised by the management as Wagon Loaders is justified? If so, to what relief are those workers entitled?”

1. Smt. Bedani Deshwali.
2. Smt. Kajli Modin.
3. Smt. Chhumuwa Modin.
4. Smt. Kajali Bourin.
5. Smt. Sukri Ghatwarin.
6. Smt. Manbatia Rajwarin.
7. Smt. Sukhmi Ghatwarin.
8. Smt. Tulu Ghatwarin.
9. Smt. Sari Ghatwarin.

10. Smt. Kamli Rajwarin.
11. Smt. Padina Deshwalin.
12. Smt. Inpari Deshwalin.
13. Smt. Sanmatia Bhuini.
14. Smt. Kapura Kalindi.
15. Smt. Ahilya Modin.
16. Smt. Upasi Modin.
17. Smt. Furi Bourin.
18. Smt. Sakhi Bourin.
19. Smt. Methi Bourin.
20. Smt. Jhunia Bourin.
21. Smt. Dulali Rajwarin.
22. Smt. Binodi Manjhiyan.
23. Smt. Chhota Shanti Bhuini.
24. Smt. Barni Bhuini.
25. Smt. Rohni Bhuini.
26. Smt. Amdurya Bhuini.
27. Smt. Kawiya Bhuini.
28. Smt. Baishakhi Bourin
29. Smt. Dasia Beldarin.

2. In this case both the parties appeared and filed their respective W.S. documents. Thereafter several adjournments were granted to the parties. Subsequently at the stage of oral evidence, both the parties appeared before me and filed a petition of compromise under their signature. I heard both the parties on the said petition of compromise and do find that the terms contained therein are fair, proper and beneficial to both of them. Accordingly I accept the same and pass an Award in terms thereof which forms part of the Award as Annexure.

B. RAM, Presiding Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II DHANBAD

Ref. No. 93/1986

Employers in relation to the management of
Bhatdee Colliery Mohuda Area, BCCL

AND

Their workmen

PETITION OF COMPROMISE

The Hon'ble petition on behalf of the parties to the above reference most respectfully sheweth :

1. That the above dispute has been amicably settled between the parties on the following terms :

TERMS OF SETTLEMENT

"Whether the demand of the workmen of Bhatdee Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. that the following 29 casual workers should be regularised by the management as wagon

loaders is justified ? If so, to what relief are these workers entitled ?

1. Smt. Bedani Deswalin
2. „ Kajli Modin (Expired)
3. „ Chhumuwa Modin
4. „ Kahali Bourin
5. „ Manbati Rajwarin
6. „ Banbati Rajwarla
7. „ Sushmi Ghatwarin
8. „ Tuly Ghatwarin
9. „ Saru Ghatwarin
10. „ Ch. Kamli Rajwarin
11. „ Podina Kamin
12. „ Injari Deswalin
13. „ Kapuri Kalindi
14. „ Ahilya Modin (Expired)
15. „ Sanmatia Bhuini
16. „ Upasi Modin
17. „ Furi Bourin
18. „ Sakhi Bourin
19. „ Methi Bourin
20. „ Jhunia Bourin
21. „ Dulali Rajwarin
22. „ Binoty Manjhiyan
23. „ Chhota Shanti Bhuini
24. „ Barni Bhuini
25. „ Rohni Bhuini
26. „ Amdurya Bhuini
27. „ Kalwiya Kamin
28. „ Baishakhi Bourin &
29. „ Dasia Beldarin

The matter was discussed in depth and it was seen that the concerned wagon loaders since had been working more than 5 years and have their attendance credit more than 75 days attendance in consequent calendar year during 1984 to 1990, and it is noted that Smt. Kajli Modin at sl. no. 2 has since expired and the name of Smt. Ahilya Modin at Sl. no. 15 does not find place in the list of casual wagon loaders of Bhatdee colliery.

1. In view of the aforesaid facts, it is agreed that Smt. Bedni Deswalin and 26 others whose names are mentioned herein will be regularised as Wagon Loaders, w.e.f. 1st May, 1991.

S/No.	Name	Form 'B' No.
1.	Smt. Bedni Deswalin	1810
2.	„ Chhumua Modin	1814
3.	„ Kahli Bowrin	111
4.	„ Sukri Ghatwarin	1843
5.	„ Manbati Rajwarin	10
6.	„ Susmi Ghatwarin	1830
7.	„ Tullo Ghatwarin	1828
8.	„ Saroo Ghatwarin	1829

S/No.	Name	Form 'B' No.
9.	Smt Ch. Kamli Rojwarin	104
10.	" Podina Kamin	9
11.	„ Injuri Deswalin	225
12.	„ Kapura Kalindi	235
13.	„ Upasi Modin	1784
14.	„ Furi Bowrin	1835
15.	„ Sakhi Bowrin	1781
16.	„ Methi Bolwrin	1837
17.	„ Jhunia Bowrin	1836
18.	„ Dulali Rajwarin	1777
19.	„ Binoty Manjhin	1796
20.	„ Ch. Shanti Bhuini	1803
21.	„ Beruni Bhuini	196
22.	„ Rohni Bhuini	1782
23.	„ Kabia Kamin	62
24.	„ Amrud Bhuian	270
25.	„ Baishakhi Bourin	1839
26.	„ Dasia Beldarin	1791
27.	„ Sonamatia Bhuini	204

That in view of the above settlement there is nothing to be adjudicated.

Under the fact and circumstances stated above the Hon'ble Tribunal will be graciously pleased to accept the settlement as fair and proper and be pleased to pass the Award in terms of the settlement.

For and on behalf of Union For and on behalf of Mgt.

(Sd./-) (Sd./-)
(B. Mohanthy) 1. General Manager,
Area Secretary, BCKU, Bohuda Area,
Mohuda Area. BCCL, PO :

Mohuda (Dhanbad)

Dated 5-12-1991 2. Sd/- (B. Lakra)

Dy. Personnel Manager (IR),

Mohuda Area, BCCL.

Witness :—

1. Sd./- S. R. P.A. Mohuda Area

2. Sd/- Barun Khana Camp Helper Lohapity Colliery

Sd/ Illegible

Sd/- Barun Khana,

भ्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मई, 1992

का.आ. 1365.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लि. का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. 1)

धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/36/88-डी-3(ए)]

एस.सी. शर्मा, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 7th May, 1992

S.O. 1365.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employeys in relation to the management of Civil Engg. Deptt. of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 1-5-92.

[No. L-20012/36-88-D.III(A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Referenc No. 101 of 1988

PARTIES :

Civil Engineering Department of M/s. Bharat Coking Coal Ltd

AND

Their Workmen

PRESENT :

Shri S. K. Mitra, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers : Shri D. K. Verma, Advocate.

For the Workmen : Shri R. R. Ghosh, concerned workman.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 23rd April, 1992

AWARD

By Order No. L-20012/36/88-D.3(A), dated, the 27th July, 1988, the Central Government in the Ministry of Labour, has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that Shri R. R. Ghosh be regularised as Draftsman (Civil) Civil Engineering Department of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Koyla Bhavan, Dhanbad in Technical and Supervisory Grade 'A' w.e.f. 1974 is justified ? If yes, to what relief is the workman entitled ?"

2. The case of the concerned workman, as appearing in the written statement submitted on his be-

half by the sponsoring union, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangha, details apart, is as follows :

Soon after nationalisation of the Coking Coal Mines M/s. B.C.C. Ltd. was formed and the management of M/s. B.C.C. Ltd. created Civil Engineering Department with its Headquarters as apex body for the Civil Engineering discipline. One of the major activities of the Headquarters of Civil Engineering Department is centrally controlled planning and design of all Civil Engineering Projects of M/s. B.C.C. Ltd. including Jharia Coalfield reconstruction, Central Townships, Office and industrial complexes, and independent Drawing Office came into operation under the Headquarters of Civil Engineering Department with the Chief Engineer (Civil) as the Head of Department to cope with the manifold intricate jobs. At the time of nationalisation there was not a single Draftsman (Civil) in M/s. B.C.C. Ltd. with requisite qualification and experience. Therefore, M/s. B.C.C. Ltd. recruited six qualified Draftsmen (Civil) in 1973 and placed them in Technical Grade 'B' as Draftsmen (Civil) Shri R. R. Ghosh, the concerned workman, was one of them. Out of the said six Draftsmen only two were having certificate in Draftsmanship of two years course with full marks of 580. Shri Ghosh is one of them while the rest were having a certificate of one and half year course with full marks of 150. Shri Ghosh was the recipient of merit stipend of Govt. of India amongst the six Draftsmen recruited and he passed the examination with 90 per cent marks in drawing subject and 85.2 per cent marks in aggregate. He alone completed apprenticeship course under Apprentice Act, 1961 in M/s. Hindustan Cables Ltd. He alone read up to B.Sc. Part-I Standard and obtained exemption from the studentship examination of the Institution of Engineers (I) by dint of his qualification prior to joining in M/s. B.C.C.L. on 15-6-1973. These achievements were not highlighted in the published seniority list. He having an exemplary records in Draftsmanship and wider academic background was posted in the Headquarters of Civil Engineering Department under direct control of the Head of the Department. In the absence of any staffing pattern and job specification, he was entrusted with the charge of Drawing office. Besides normal Civil Engineering drawing works, he was also responsible for leading a team of drawing office personnel for development of their skill, maintenance of records, checking detailing, architectural drawing and designing preparation and checking all types of estimates, formulation of schemes, preparation of tender documents and comparative statement, visiting and supervising sites, checking bills for payment, placing indents and procurement of stationaries, equipments, furnitures, machinaries etc. and their maintenance. In other words, he was shouldering actual responsibilities of a higher grade officer while being placed in very low grade position. An officer not less than E-5 was required to take over charge of Drawing office from him in order to release him for some other assignment on 1-12-84. This supports his claim for regularisation in E-5 grade with effect from 15-6-1986. In recognition to his exemplary performance, professional experience, achievements and contributions for the benefit of the company, he received many certificates and letter of appreciation from the high official, such as, Chief Engineer (Civil), Director, Chairman-cum-Managing Director and Secretary (Coal) to Government of India. He having ful-

filled the norms for placement in E.D.P. Grade against the notified vacancy for the post of Machine Supervisor in Technical & Supervisory Grade 'A' plus three increments on the scale, was called for appearing in a competitive test by letter dated 20-8-74. He came out successful in the test and his Controlling Officer was intimated about his selection with a request to release him to join his new assignment positively on 22-8-74 by his letter dated 21-8-74. But he was not released to join his new assignment, as his service was considered indispensable in Civil Engineering Department. Consequently he was deprived of the opportunity of being placed in Technical & Supervisory Grade 'A' plus three increments for the benefit of the company. The resultant vacancy of the Machine Supervisor was filled in on 1-1-75 and the concerned beneficiary has since been promoted to E-4 cadre in 1986. In other words, he would have reached E-4 Grade much earlier had he been regularised on 21-8-74. In 1974 the Head of the Department took up his case for upgradation and the matter was agreed to by the competent authority as revealed in his noting dated 26-9-74. Accordingly, after the delay of one year his bio-data were called for by a letter dated 30-8-75 and thereafter no action was taken. M/s. B.C.C. Ltd. for the first time published cadre scheme for non-executives in Drawing Offices by order dated 21/26-7-78 Clause 2.3.1 of this Cadre Scheme envisaged that promotion from Technical Grade 'B' to Technical & Supervisory Grade 'A' ought to be given on company basis. By an order dated 17-8-78 Shri S. Sengupta was promoted to Technical and Supervisory Grade 'A' in violation of the said clause. Further this promotion was given without holding any D.P.C. with effect from 8-11-77. Sri Sengupta superseded him as he was junior with the help of unfair managerial practice. It is alleged that the dealing officers have always made every endeavour to hide the case of Shri S. Sengupta from the Chairman-cum-Managing Director and ALC (C), Dhanbad. It is also alleged that while two more sanctioned posts were kept vacant, his case was never considered deliberately despite repeated notings of the Head of the Department dated 4-12-79, 20-3-80 and 12-6-80. The Functional Directors in their meeting held on 8-9-84 passed directive for his suitable placement and the C.M.D. also wanted the same as evidenced in his noting dated 26-3-85. The authorities of Coal India Ltd. in several letters had wondered over his long stagnation. The Ministry of Energy and the Joint Secretary, Deptt. of Coal, Govt. of India repeatedly insisted for redressal of grievance in their letters. The Director (Personnel), by his noting dated 11-4-88 passed his directive with strictures for disposing of his case positively by 18-4-88. But all these were in vain. He was compelled to continue in the same Technical Grade 'B' for long 15 years till he reached the ceiling of the scale. As per provision of common Coal Cadre, promotion from non-executive cadre to executive cadre can be effected from amongst employees who are in Tech. & Supervisory Grade 'A' only. M/s. B.C.C. Ltd. has a specific policy of regularisation in higher grades and it freely practises its policy as has been confirmed in the letter of Director (Personnel) dated 16-1-87. Even so, that has not been followed in his case. In the meantime and while in service he acquired Diploma in Architecture and AMIE Sections A & B in Civil Engineering in November 1981, December, 1981 and December, 1984 respectively. He is recipient of

the award of Gold Medal of the Institution of Engineers. He has published many articles. He represented M/s. B.C.C. Ltd. at least at four Engineering Congress. The highest official of M/s. B.C.C. Ltd. was never happy with the fashion in which his case was dealt with. After failure of conciliation proceeding, the Chairman-cum-Managing Director took up the matter in a high power meeting held on 23-8-87 in Coal India Ltd. at Calcutta and there it was held that he should be promoted to executive cadre straightway from Technical Grade 'B'. The formal order of the Coal India Ltd. dated 23-9-87 passed directive for holding only one selection test by D.P.C. in respect of his case for his promotion as an Executive in Civil Engineering cadre straight from Grade 'B'. The dealing officer whittled down the matter and he filed writ petition before Hon'ble High Court, Calcutta. While his case was under examination in the Ministry of Labour for reference for adjudication, he was given one out of turn promotion in Tech. & Supervisory Grade 'A' by order dated 26/27-5-1988. By this order the management virtually accepted the merit of his claim for regularisation in Technical and Supervisory Grade 'A' but diluted the gravity of his claim by making its effect from 1-7-85 without any monetary benefit. He was given out of turn promotion to E-2 grade in executive cadre by order dated 31-12-88. He is entitled one additional increment with effect from 25-11-81 as per rule of the company for obtaining Diploma in Architecture. The Dy. Chief Personnel Manager (NEE) accepted that there was no reason to deny his claim in his noting dated 11-9-87. He was given one more increment for his outstanding work by the Director (Personnel) on 28-2-84. But the same has not been released. He has been doing the job of higher category post as Incharge/Head/Chief of the Drawing Section with higher responsibilities. He has discharged the duties of higher nature for more than 240 days in each calendar year. The management has also admitted his merit. In the circumstance, the demand of the union that he should be placed in Technical and Supervisory Grade 'A' with effect from 15-6-74 is fully justified.

3. The case of the management of Civil Engineering Department of M/s. B.C.C. Ltd. as appearing in the written statement submitted by it, briefly stated, is as follows :

The present reference is not maintainable in law or on facts. The concerned workman has demanded his promotion through Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh. But promotion cannot be a matter of industrial dispute. The concerned workman was appointed in 1973 and he was placed as Draftsman in Technical and Supervisory Grade 'B'. As per cadre scheme of the management he was not entitled to be promoted to Technical Grade 'A' for the qualification possessed by him. However, his case was considered in D.P.C. in the year 1979, but he could not be promoted for want of vacancy as his name appeared at serial No. 6 in the seniority list. Thereafter nobody was promoted due to want of vacancies in Technical and Supervisory Grade 'A'. He was never superseded by any junior. The management of M/s. B.C.C. Ltd., referred his case to the Headquarters of Coal India Ltd. in 1985 for promotion to executive cadre in view of the qualification acquired by him, but the same was not regretted due to want of vacancies. The management

of M/s. B.C.C. Ltd. considered his case and gave him promotion in Technical and Supervisory Cadre 'A' with effect from 1-7-85 by Office Order dated 26/27-5-88 and he accepted the same. Thereafter he was promoted as Drawing Officer in Executive Grade E-2 by Office Order dated 31-12-88. As he has been working as Drawing Officer in E-2 Cadre he is no longer a workman and the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh is not justified.

4. In rejoinder to the written statement of the sponsoring union, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, the management has admitted that some Draftsmen were appointed in the year 1973, but stated that qualification of the concerned workman is within his special knowledge. His claim for promotion to higher executive cadre is hypothetical and it is not correct that somebody was promoted superseding the concerned workman and in the process the management of M/s. B.C.C. Ltd. indulged in unfair managerial practice. He was not promoted in 1979 due to want of vacancy as his name was at serial no. 6 of the seniority list. He was not given promotion to Technical & Supervisory Grade 'A' arbitrarily but according to the policy of the management. The demand of the union for placing the concerned workman in Technical & Supervisory Grade 'A' with effect from 15-6-74 is not justified.

5. In rejoinder to the written statement of the management the sponsoring union has asserted that the claim of the workman is for placing him in Technical & Supervisory Grade 'A' with effect from 15-6-74 in the present industrial dispute. He has fully satisfied the company's policy of regularisation which envisages that workman doing the job of higher grade post are entitled for placement in higher grade post by way of regularisation and this policy has been practised by the company in the cases of Prakash Bakshi, Hafiz Ansari, S. Sengupta, K.A.K. Sinha, Gurnam Singh, D.D. Mullick and others. In the instant case, in absence of any incharge in Technical & Supervisory Grade 'A' and above, the concerned workman posted in the Drawing Design Cell under Civil Engineering Department of M/s. B.C.C. Ltd. has done the jobs of higher grade posts of Technical & Supervisory Grade 'A' to E-5 as a sole-in-charge from 15-6-73 and the management has recognised this fact of his working from 15-6-73 as in-charge of the section on many occasions and so he is eligible for out of turn placement in Technical & Supervisory Grade 'A' at least with effect from 15-6-1974. The competent authorities repeatedly passed directive to consider his case for upgradation from 1974 which unfortunately could not evoke any result. The concerned workman qualified in a departmental test for the post of Machine Supervisor in E.D.P. cadre in Technical and Supervisory Grade 'A' plus three increment on 21-8-74, but he was never given the post and grade due to biased attitude of the management. In the circumstances, the union demands release of five increments to the concerned workman so long withheld with all benefits on his being regularised in Technical & Supervisory Grade 'A' with effect from 15-6-74. The union has further reiterated that the concerned workman has acquired additional qualification while he was working in Civil Engineering Department of M/s. B.C.C. Ltd. where he joined as

Senior Draftsman. The union has denied that Coal India Ltd. ever refused his claim for upgradation; on the contrary, Coal India Ltd. passed order to give him higher grade directly from Technical Grade 'B' treating him notionally in Technical & Supervisory Grade 'A' as a special case.

6. The union, in support of its demand, has examined the concerned workman, R.R. Ghosh and laid in evidence a mass of documents which have been marked Exts. W-1 to W-70.

On the other hand, the management has examined U.K. Jha as MW-1 and laid in evidence some documents which have been marked Exts. M-1 to M-2.

7. Undeniably, Coking Coal Mines in the country were nationalised with effect from 1-5-72 and with the formation of M/s. B.C.C. Ltd., a Government company in the Central Govt. Public Sector, the management of M/s. B.C.C. Ltd. created Civil Engineering Department with its Head Quarters as Apex Body for the Civil Engineering discipline. It has remained undisputed also that one of the major activities of the Head Quarters of Civil Engineering Department is centrally controlled planning and design of all Civil Engineering Projects of M/s. B.C.C. Ltd. and in order to cope with the manifold jobs, an independent Drawing Office came into being under the Head Quarters of Civil Engineering Department which was under the Direct control of the Chief Engineer (Civil) who was the Head of the Department.

8. In 1973 some qualified Draftsmen (Civil) were recruited in M/s. B.C.C. Ltd. which included the concerned workman as Draftsman (Civil) and all of them were placed in Technical Grade 'B'. Among these appointees, the concerned workman, R. R. Ghosh, read upto B.Sc. Part-I Standard and passed prescribed test in the trade of Draftsman (Civil) securing very high marks (Exts. W-24 and W-25). The testimony of the concerned workman establishes the fact that before joining M/s. B.C.C. Ltd. he worked in Hindustan Cables Ltd. for sometime as apprentice Draftsman (Civil) and that he worked for sometime as Draftsman during 1972-73 in Ratnabala Construction. His testimony further indicates that he joined M/s. B.C.C. Ltd. in 1973 and was posted to Civil Engineering Department in its Drawing Office at the Head Quarters and was placed in Technical and Supervisory Grade 'B'. This statements of facts have remained unassailed in cross-examination. Thus from the evidence on record it is concluded that the concerned workman read upto B.Sc. Part-I Standard and passed Draftsmanship (Civil) examination from a recognised Institution with excellent result and was having some experience as a Draftsman.

9. It is the firm case of the concerned workman that in the absence of any staffing pattern and job specification he was entrusted with full and absolute charge of Drawing office and that besides normal Civil Engineering Drawing works he was responsible for leading a team of Drawing office personnel for development of their skill, checking detailing, architectural drawing and designing etc. and in the process he was shouldering the responsibilities of a very high grade official while being posted at a very low grade in Technical & Supervisory Grade 'B'. In his

testimony the concerned workman, in conformity with his case as made out in his written statement, has stated that after joining M/s. B.C.C.L. in June, 1973 he was posted to the Head Quarters of Civil Engineering Department and in the absence of any staffing pattern and job description he was entrusted in-charge of Drawing office fully and absolutely. Besides, he was also entrusted with the charge of a team of Drawing officers for developing their skill, checking detailing, architectural drawing and designing, preparation and checking of all types of estimates, formulation of schemes etc. It appears that no meaningful cross-examination has been made on these statements of facts.

On the other hand, MW-1 U. K. Jha, who was posted as Personnel Officer in the Head Quarters of M/s. B.C.C. Ltd. at Koyla Bhavan from 1979 to 1988 has stated that he does not know if the concerned workman was shouldering higher responsibilities and duties in 1974 and that is why his upgradation was being considered by the higher authorities in 1974. The testimonial dated 12-2-87 (Ext. W-36) issued by T. Ghosh, who was posted as Additional Chief Engineer (Civil) in M/s. B.C.C. Ltd. on deputation, has underlined eloquently the performance of the concerned workman as a Draftsman posted to the Drawing Office under Civil Engineering Department at the Head Quarters. An excerpt of this testimony is gleaned hereinbelow :

"This is to certify that Sri R. R. Ghosh, Draftsman (Civil), had worked under my direct control from 15-6-1973 to 8-10-1978, when I was working as Additional Chief Engineer (Civil) with M/s. Bharat Coking Coal Ltd. on deputation from the Government of Bihar. His performance during the period was found to be excellent since he was shouldering the entire responsibilities of the Drawing office under the Civil Engineering Department at Head Quarters."

Another excerpt from the noting of Sri. C. Ogha, Superintending Engineer (Civil) speaks well of the concerned workman which is gleaned hereinbelow : (Ext. W-49)—

"... Particularly Sri R. R. Ghosh. has been serving the Drawing office of this Deptt. with full charge and responsibility since ab initio as if the head of the Drawing Section. If now he is compelled to work as a junior to his contemporary man, it would toll upon his morale. I strongly feel that Sri Ghosh is a most deserving incumbent in this line in the Civil Engg. Deptt. for promotion to the post of Sr. Draftsman (C) (Tech. Gr. A).

... Cases may kindly be considered in favour with effect from the very date the other three Draftsman (C) at Sl. No. 1, 3 were promoted to the post of Sr. Draftsman (C) (Tech. Gr. A)."

Another testimonial issued by D. Nath, Superintending Engineer (Tech.) underlines the fact that the concerned workman had proved his capability to control and guide a team of subordinate Drawing Office personnel with intelligence. Shri Nath has recorded

that he had shown high proficiency in Civil, Architectural and structural drawing work including checking and detailing with high accuracy (Ext. W-47).

Thus, the remarks of the superior officers of the concerned workmen establish the fact that his performance as Draftsman was excellent and that he was shouldering the entire responsibilities of the Drawing offices under Civil Engineering Department at the Head Quarters. As a Draftsman (Civil), needless to say, he was not required to shoulder the entire responsibilities of drawing office of Civil Engineering Department at Head Quarters. That being so, it is evident from evidence that he was shouldering higher responsibilities as a Draftsman (C) in Tech. & Supervisory Grade 'B'. Even so, the management did not consider his case for upgradation at that time.

Meanwhile a test was held for appointment to the post of Machine Supervisor in Technical & Supervisory Grade 'A' with three increments on Electronic Data Processing Cadre. The concerned workman appeared and was selected in the test, but he was not released as his service was considered indispensable in Civil Engineering Department. In his testimony he has stated that in 1974 he fulfilled the norms of being placed in E.D.P. Cadre (Electronic Data Processing) for posting in Technical & Supervisory Grade 'A' plus three increments, but his Department did not release him to join his new post. T. Ghosh in his testimonial (Ext. W-36) has corroborated this fact by stating that Sri Ghosh (concerned workman) had appeared in an aptitude test in August, 1974 for the post of Machine Supervisor in E.D.P. Cadre under M/s. B.C.C. Ltd. and came out successful. But he could not be released as he was at that time indispensable in the Civil Engineering Department at the Head Quarters. Thus, it is seen that the management, despite the fact that the concerned workman was discharging higher responsibilities did not upgrade him in Tech. & Supervisory Grade 'A' nor did the management released him from the post of Draftsman (Civil) for joining as Machine Supervisor on E.D.P. Cadre in Technical & Supervisory Grade 'A', with three increments.

Consequent upon the management not releasing him from the post of Draftsman (Civil) in the Civil Engineering Department, the vacancy in the post of Machine Supervisor was filled in on 1-1-1975. The concerned workman has stated in his testimony that the person who joined this post on 1-1-75 had been promoted to the post of Executive Cadre-4 in 1986.

10. The travail of the concerned workman was not over. The concerned workman has complained that S. Sengupta being junior to him was given promotion in Technical & Supervisory Grade 'A' in violation of Clause 2.3.1 of the Cadre Scheme which envisages that promotion from Grade 'B' to Technical & Supervisory Grade 'A' ought to be given on company basis. The Additional Chief Engineer while recommending the case of the concerned workman for promotion to Technical & Supervisory Grade 'A' has stated in his confidential note dated 24-3-88 that S. Sengupta who was a non-trade certificate holder, while serving in Katras Area was promoted to Grade 'A'/Chief Draftsman on 17-8-1978 with effect from 8-11-1977 super-1205 GI/92-7

seding the concerned workman (Ext. W-38). The Additional Chief Engineer has recommended that the concerned workman be promoted to Grade 'A' with effect from 8-11-77—the date when his junior Sri Sengupta was promoted. This recommendation of the Additional Chief Engineer dated 24-3-88 seems to have fallen on deaf air of the higher management.

11. It appears that sometime in 1979 D.P.C. was held for promotion from the post of Draftsman to higher post. The management has contended in its written statement that since the name of the concerned workman appeared at serial no. 6 in the seniority list, he could not be promoted nor could he claim promotion to Technical Grade 'A' for the qualification possessed by him. There is no vestige of evidence on record to indicate that seniority list prepared by the management correctly represented the qualification of the concerned workman and his other particulars. It appears that in terms of the cadre scheme framed subsequently promotion to Technical Grade 'A' is dependent upon the merit-cum-seniority. At the relevant time the concerned workman was not only having excellent certificate for Draftsmanship but also he was having some experience in other Organisation as Draftsman and excellent report about his job performance and report about shouldering higher responsibilities from his supervisors. Sri P. Banerjee, Dy. Chief Engineer, after the D.P.C. submitted a note to the higher management suggesting that in order to avoid stagnation Draftsman of higher calibre could be accommodated by creating more post in higher grade by upgrading existing post (Ext. W-39). The reaction of the higher management to this note is not known. Thus, the evidence on record reveals that the concerned workman, despite his better academic background and job performance, did not get promotion to Grade 'A' on the plea that there was no post vacant at that level. He was selected as Machine Supervisor in Technical & Supervisory Grade 'A' but was not released from his Deptt. on the ground of his indispensability. Meanwhile his junior S. Sengupta, a non-trade certificate holder, was promoted to Grade 'A'. It seems that being exasperated the concerned workman represented for his transfer to Low Temperature Carbortisation Plant at Calcutta, but the management turned down his representation by letter dated 26-8-79 on the ground that there was dearth technical personnel and it would not be possible to consider his request for transfer (Ext. W-64). Thus, it is seen that even his request for transfer was turned down.

12. I have underlined the facts as to how the management of M/s. B.C.C. Ltd. had dealt with the case of the concerned workmen with brazen indifference and apathy. I do not see any reason at all for taking such attitude as taken by the management. It must be remembered that service is not servitude or bondage. It is opt to be career oriented specially for the jobs where technical expertise is required. The concerned workman seems to be a captive of the management and the management meted out treatment to him which, in olden days, was meted out to serfs.

13. Any way, it seems that the wheel started rolling when the concerned workman submitted his representation to the Ministry of Energy sometime in 1987.

The management became wise and informed the Ministry of Energy by letter dated 13-10-87 (Ext. W-17) that the case of the concerned workman was being considered at the level of Chairman-cum-Managing Director by selection-cum-D.P.C. It may be pointed that meanwhile Shri Ghosh, the concerned workman, did not remain idle. He acquired Diploma in Architectural Drawing and Design from I.G. 8., Bombay and passed the AMIE examination of the Institution of Engineers (India) which is equivalent to a Degree in Engineering. He was awarded Gold Medal by the Institutions of Engineers (India) in 1983 for his paper captioned 'A simplified Method for optimisation of Road Transport effort in Nationalised Coal Industry' (Ext. W-36). He also got appreciation of the Secretary of the Ministry of Energy for his article (Ext. W-31). The Chairman-cum-Managing Director of M/s. BCC Ltd. was also appreciative of his performance. The relevant portion of the letter of the CMD to the concerned workman is gleaned hereinbelow (Ext. W-32) :

"I appreciate the undoubted spirit with which you have established your constructive approach and professional excellence in the diversified fields as Civil Construction Management, Architecture and Town Planning, Environmental Science, Application of Computer in Structural Engineering and Operation and Research. While I am happy to note that all of your professional activities are really dedicated to the good cause of the Company I am indeed proud to learn that you were awarded Gold Medal by the Institution of Engineers (I).

I have great hope that you will continue to maintain the high standard of your own in the field of Engineering.

I look forward to find you rightly placed and I have no doubt that your sincerity, aspirations, active habits and your dynamic approach to the problems will help you to rise soon with a glorious career.

I wish you all good fortunes."

Shri I. B. Pandey, Director (Personnel) by his note dated 11-4-88, expressed his annoyance with regard to the manner in which the case of the concerned workman for promotions to higher cadre was being dealt with. I think it apposite to glean his note hereinafter (Ext. W-44) :

"Dy. CPM (NEE) should have been the order on pre-page for promoting Shri R. R. Ghosh retrospectively in Technical Supervisory Grade-A. Instead of taking action, some other suggestions have come. This order was given in Feb. 88. I suggest that within 7 days the case of Shri Ghosh should be disposed of promoting him from Tech. Grade-B to Tech. Supervisory Grade-A notionally and report compliance."

Shri Pandey suggested promotion of the concerned workman from Technical Grade 'B' to Technical and

Supervisory Grade 'A' notionally. Thereafter B. N. Jha, Dy. Chief Personnel Manager (NEE) could not raise any further obstruction and had to pass order for promotion of the concerned workman in Technical and Supervisory Grade 'A' by Office Order dated 26/27-5-88 with effect from 1-7-85 (Ext. W-19). Then again, Shri Jha had to pass order for promotion of the concerned workman to the post of Drawing Officer in Executive Cadre in E-2 against supernumerary post by Office Order dated 31-12-88 (Ext. W-20).

Incidentally it may be mentioned that Shri Jha was very much active in informing the Ministry that AMIE Degree obtained by the concerned workman from the Institute was not recognised by the Central Government for employment (Ext. W-43). It appears that Calcutta High Court, on the application of the concerned workman, passed an interim order directing the management to hold examination for promotion to the post of Executive Cadre but one such post should be kept vacant. Presumably the concerned workman was vying for the post and in that context the Hon'ble Court passed a sumingly be innocuous order (Ext. W-45). Even then, Shri Jha had the temerity to point out that the order was erroneous and if implemented it would have a lot of repercussion on the case pending at Calcutta High Court. He suggested an appeal against the order without spelling reason of his coming to the conclusion that the order, if implemented, would cause a lot of repercussion on the case pending in the Calcutta High Court (Ext. W-45). It seems Shri Jha was disposed apathetically to the cause of the concerned workman the reason of which has remained unknown.

14. It appears that Shri I. B. Pandey, Director (Personnel) suggested promotion of the concerned workman in Technical and Supervisory Grade 'A' notionally. This the management could have done that earlier while the concerned workman was performing the job of higher responsibilities. The management could have given him promotion to Technical and Supervisory Grade 'A' when his junior Shri Sengupta was promoted to that post with effect from 8-11-77 (Ext. W-37).

The concerned workman has claimed regularisation in the post of Technical and Supervisory Grade 'A' plus three increments with effect from 1974. He has claimed this in view of his shouldering higher responsibility and of the fact that he was selected as Machine Supervisor on EDP Cadre but could not join his post as he was not released from his department and subsequently another man joined that post on 1-11-75. But it may be that he could be released from the post he held due to exigencies of circumstances. But I think that his claim for regularisation in Technical and Supervisory Grade 'A' is justified when Shri Sengupta was promoted to Tech. and Supervisory Grade 'A' with effect from 8-11-77.

15. Upon consideration of evidence on record and facts and circumstances of the case. I think that the management was not justified in holding up the case of regularisation of the concerned workman and should have regularised him in Technical and Supervisory Grade 'A' with effect from 8-11-1977.

16. Accordingly, the following award is rendered—

the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh that R. R. Ghosh be regularised as Draftsman (Civil), Civil Engineering Department of M/s. BCC Ltd., Koyla Bhavan, Dhanbad, in Technical and Supervisory Grade 'A' with effect from 8-11-1977 and not from 1974 is justified. The management is directed to regularise him in Technical and Supervisory Grade 'A' with effect from 8-11-1977.

In the circumstances of the case, I award no cost.

S. K. MITRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 मई, 1992

का.आ. 1366—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/64/84-डी-II(ए)]

सुभाष चन्द्र शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th May, 1992

S.O. 1366.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of Bikaner and Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-5-92.

[No. L-12012/64/84 D.II(A)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 76/1984

रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल. 12012/64/84 - डी. II (ए) दिनांक 19-10-84

श्री सोहन लाल मोदी द्वारा इंडियन नेशनल बैंक एम्पलाईज कांग्रेस, बीकानेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रबंधक संचालक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर सिलक मार्ग, जयपुर।

2. क्षेत्रीय प्रबंधक - 3, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, आंचलिक कार्यालय, बीकानेर।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आरएचजेएस प्रार्थी की ओर से : श्री अरविन्द सिंह
अप्रार्थी की ओर से : श्री एस. के. नेम
दिनांक अवार्ड : 24-2-1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत भेजा है :

"Whether the action of the management of Jaipur Nagpur Anchalik Gramin Bank in terminating the services of Shri Chandmal Sharma w.e.f. 10-6-1988 the provisions of Industrial Disputes Act, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. इंडियन नेशनल बैंक एम्पलाईज कांग्रेस, बीकानेर, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि बादग्रस्त श्रमिक सोहन लाल मोदी स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक आंचलिक कार्यालय बीकानेर में कलक कम टाईपिस्ट के पद पर कार्यरत हैं जो प्रार्थी यूनियन का सदस्य है। उक्त श्रमिक अक्टूबर 1964 से मई 1967 तक की अवधि में अप्राधिगण बैंक की रायसिंह नगर तथा सांगारिया शाखा में 572 दिन तक कार्यरत रहा था। श्रमिक की उपरोक्त सेवा मां क वेतन पर अस्थाई तौर पर की थी जिसके अनुसार नियामत होने पर वह श्रमिक वेतन वृद्धि पाने का अधिकारी है। प्रार्थी संघ का कथन है कि 11-12-69 को श्रमिक की नियुक्ति प्रोवेशन पर हुई थी और सामान्य पद्धति के अनुसार श्रमिक को वार्षिक वेतन वृद्धि 11-12-70 होती है परन्तु नियोजक के सरकूलर दिनांक 24-10-72 के अनुसार स्थाई नियुक्ति से पूर्व में श्रमिक ने जो अस्थाई रूप से 572 दिवस कार्य किया था उसका भी लाभ देते हुए वेतन वृद्धि देनी थी। नियोजक ने उक्त सरकूलर के अनुरूप 572 दिवस का लाभ न देते हुए केवल जनवरी 1974 से ही 196 दिवस का लाभ दिया है। संघ का कहना है कि उक्त सरकूलर के अनुसार अगर 572 दिवस का लाभ दिया गया होता तो 17-5-70 को ही श्रमिक को दूसरी वेतन वृद्धि मिल जाती और उसके पश्चात 17-5-71 को तीसरी वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती परन्तु उक्त सरकूलर के अनुसार श्रमिक को लाभ नहीं दिया गया है इसलिए प्रार्थी संघ को प्रार्थना है कि सोहन लाल मोदी को उसकी पूर्व की अस्थाई सेवाओं का पूरा लाभ देते हुए 11-12-69 को पहली तथा 17-5-70 को दूसरी वेतन वृद्धि तथा उसके आगे भी निरंतर एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेतन वृद्धि दिलाने का एवं उसका एरियर भुगतान करने के आदेश दिये जायें।

3. अप्राधिगण ने जरिये संयुक्त प्रत्युत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि प्रार्थी का स्टेट बैंक आफ क्लेम विवाद अधिनियम के आर्टिकल 136 के अन्तर्गत

काल अर्जित है, प्रार्थी संघ मान्यता प्राप्त नहीं है और श्रमिक का उक्त संघ का सदस्य होना भी विवादास्पद है। नियोजक का यह भी कहना है कि मान्यता प्राप्त यूनियन एवं मैनेजमेंट के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार बैंक से सरकूलर सं. एस/12/74 दिनांक 18-3-74 को जारी किया है जिसके अनुसार ही प्रार्थी को वेतन वृद्धियां दी गई है। इस श्रमिक ने भी उक्त सरकूलर के अनुसार ही वेतन वृद्धियां प्राप्त कर फायदा उठा लिया है इसलिए एस्टोबल के सिद्धान्त के अनुसार भी अब वह श्रमिक अन्यथा क्लेम नहीं कर सकता।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक सोहन लाल मोदी ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया है जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 फोटो प्रति पेश की गई है। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री सुब्रामनियम ने शपथ पत्र पेश किया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है। तत्पश्चात् मैने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. जहां तक एस्टोपल का प्रश्न है, नियोजक ने प्रत्युत्तर द्वारा कहा है कि सरकूलर नं. एस 12/74 दिनांक 18-3-74 के अनुसार वेतन वृद्धियां प्राप्त कर ली है इसलिए अब वह इसके विपरीत क्लेम नहीं कर सकता। उक्त तथ्यों का उल्लेख साक्षी श्री सुब्रामनियम ने भी किया है परन्तु मेरी राय में साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार एस्टोपल के प्रावधान श्रम विवादों पर लागू नहीं होते हैं या नहीं यह भी विवादास्पद है परन्तु तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि एस्टोपल के प्रावधान लागू होते हैं तो भी यह सिद्धान्त तो तथ्यों से संबंधित ही है और नियोजक ने न तो क्लेम के प्रत्युत्तर में और न ही अपनी साक्ष्य द्वारा यह प्रकट किया है कि 18-3-74 के सरकूलर के अनुसार जो वार्षिक वेतन वृद्धियां श्रमिक को दी गई हैं उसके विपरीत दिनांक 24-10-72 के सरकूलर के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि भांगने से नियोजक के प्रति किस प्रकार पक्षपात या हानि होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेंनेट कोलमैन एंड कम्पनी बनाम पी. पी. दासगुप्ता, ए. आई. आर. 1970 (एस. सी) 426 के न्याय दृष्टान्त में भी निम्न मत व्यक्त किया है :-

"It is doubtful whether technical pleas such as acquiesce, estoppel and waiver suitably apply to industrial adjudication. But assuming that the rule of estoppel as incorporated in section 115 of Evidence Act applies, even then the foundation of that rule is that, it is inequitable and unjust to a person that if another person by a representation induces him to act as he would not have otherwise acted, the person who made representation should be allowed to deny the effect of his former statement on the loss and injury of the person, who has acted on it. The rule is one of evidence only and does not create any substantive right or confer any cause of action on the other."

अतः उपरोक्त समस्त कारणों से नियोजक की यह श्रमिक आपत्ति साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है।

6. नियोजक की दूसरी आपत्ति यह थी कि प्रार्थी संघ मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए उसे विवाद खड़ा करने का अधिकार नहीं है। इस विषय में भी श्रमिक से तो प्रति परीक्षा नहीं की गई है परन्तु नियोजक साक्षी श्री सुब्रामनियम ने अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि प्रार्थी संघ अप्रार्थीगण द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ने का क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ही मैनेजमेंट आफ इंडियन एक्सप्रेस बनाम वर्कमैन, ए. आई. आर. 1970 (एस. सी) 737 तथा मैनेजमेंट आफ प्रदीप लैप वर्क्स पटना बनाम वर्कमैन, 1970। एल. एल. जे., 507 के न्याय दृष्टान्तों में मत व्यक्त किया है कि अगर कोई विवाद अन्य रजिस्टर्ड या माईनोरिटी यूनियन द्वारा भी उठाया गया हो अथवा प्रचुर श्रमिक जिसके सदस्य हों द्वारा भी उठाया गया हो तो भी उक्त विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा में ही आएगा। धर्मपाल प्रेमचंद 1975 (2) एफ. एल. आर. 53 के न्याय दृष्टान्त में तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इससे पूर्व के सभी न्याय दृष्टान्तों का विश्लेषण करते हुए हिन्दु केस में दिए गए मत पर निर्भर नहीं किया और वह प्रस्तावना को गई कि अगर कोई विवाद उस संघ द्वारा उठाया गया हो जिसका श्रमिक सदस्य हो या यूनियन की बजाय प्रचुर संख्या में श्रमिकों द्वारा उठाया गया हो तो भी औद्योगिक विवाद ही माना जाएगा। विवेचनाधीन विवाद में तो प्रार्थी संघ इंडियन नेशनल बैंक एम्पलाईज कांग्रेस है जिसमें बैंक श्रमिक ही सदस्य हैं और चाहे प्रार्थी संघ को विपक्षी ने मान्यता नहीं दी हो तो भी उसके द्वारा उठाया गया मामला औद्योगिक विवाद की परिभाषा में ही आता है। अतः यह प्रारंभिक आपत्ति भी निराधार मानते हुए खारिज की जाती है।

7. नियोजक पक्ष की तीसरी आपत्ति यह थी कि सीमा अधिनियम की आर्टिकल 136 के अनुसार मामला काल वर्जित है। यह उल्लेखनीय है कि औद्योगिक विवादों में न तो सीमा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और न ही कोई ऐसी सीमा अवधि निश्चित है जिसके अन्तर्गत ही विवाद खड़ा करना अपेक्षित हो, अतः यह आपत्ति भी निराधार मानते हुए खारिज की जाती है।

8. गुणावगुण पर श्रमिक ने क्लेम के अनुसार अपने शपथ पत्र में भी दर्ज किया है कि अक्टूबर 1964 से मई 1967 तक की अवधि में उसने रायसिंह नगर व सांगारिया शाखाओं में 572 दिवस कार्य किया था। उक्त 572 दिवस की अस्थायी सेवा में से केवल 196 दिवस का ही लाभ उसे दिया गया है। श्रमिक कहता है कि जनवरी 1974 के उपरान्त से ही उसे अस्थायी सेवा का लाभ दिया गया है उसके पूर्व की अस्थायी सेवा का लाभ नहीं दिया गया है। इस साक्षी से इस विषय में नाम मात्र की भी प्रति परीक्षा नहीं की गई है कि उसने 572 दिवस तक अस्थायी सेवा नहीं की हो। नियोजक साक्षी सुब्रामनियम ने अपने शपथ पत्र में इस विषय में कुछ भी दर्ज नहीं किया है। श्रमिक के

मौखिक कथनों की पुष्टि प्रदर्श डब्ल्यू-1 प्रलेख से भी होती है जिसके अनुसार इस श्रमिक ने 572 दिवस अस्थाई सेवा की है। अतः 572 दिवस अस्थाई सेवा करना तो अभिलेख पर साबित है, एक मात्र विवाद का विषय नियोजक द्वारा जारी किए गए सरकूलर हैं। प्रार्थी संघ के अनुसार 24-10-72 के सरकूलर में यह कोई प्रतिबंध नहीं है कि 1 जनवरी, 1974 के उपरांत की ही सेवा की गणना की जाएगी बल्कि इस सरकूलर के अनुसार तो जितने भी दिन की अस्थाई सेवा थी उस सब की गणना स्थाई होने पर श्रमिक की वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु करना अपेक्षित थी जबकि नियोजक के अनुसार 18-3-74 के सरकूलर में उक्त सीमा निर्धारित कर दी गई थी जिसके अनुसार यह श्रमिक 1 जनवरी, 1974 के उपरांत से ही सेवा के लाभ का अधिकारी था। मैंने 24-10-72 के उक्त सरकूलर का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया तो पाया कि इसमें समस्त अस्थाई सेवा को वार्षिक वेतन वृद्धि देने हेतु गणना करने का उल्लेख है जो स्थाई होने से पूर्व किसी श्रमिक ने कर ली थी। इस सरकूलर में कहीं भी ऐसी कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है कि 1-1-74 के बाद की ही अस्थाई सेवा की गणना की जाएगी। नियोजक ने 24-10-72 के उक्त सरकूलर के अधीन मीमो सं. एस. बी. बी. जे./ दिनांक 30-1-73 जारी किया कि 24-10-72 के बाद में जिस किसी ने भी अस्थाई सेवा की थी और जो तत्पश्चात् अस्थाई हो गया था तो उसे 24-10-72 के उपरांत की अस्थाई सेवा का ही लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु दिया जाएगा। परन्तु इस पर जब बैंक के श्रमिकों व संघों ने आपत्ति की तो 18-3-74 का प्रदर्श एम-1 सरकूलर जारी किया गया जिसके अनुसार 1 जनवरी, 1966 के बाद की अस्थाई किंतु बिना ब्रेक की सेवा का तो पूरा लाभ दिया गया और वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख भी उक्त लाभ के अनुसार बदल दी गई परन्तु अगर 1 जनवरी, 1966 के उपरांत किसी की अस्थाई सेवा में कोई ब्रेक था तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख नहीं बदली गई बल्कि उसे अस्थाई सेवा का लाभ तो उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु दिया गया परन्तु अस्थाई सेवा की अवधि की राशि नहीं दिलाई गई। मेरी राय में 18-3-74 के उक्त सरकूलर के अनुसार इस श्रमिक को उसकी अस्थाई सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि 18-3-74 का यह सरकूलर न तो समझौता वार्ता के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंचे अवार्ड के रूप में जारी किया गया है और न ही इससे यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संस्थान में कार्यरत किसी श्रमिक संघ के साथ बातचीत कर यह सरकूलर निकाला गया हो। इस विषय में जब नियोजक साक्षी श्री सुब्रामनियम से प्रति परीक्षा की गई तो वह कहते हैं मैं 24-10-72 के असल रिकार्ड (सरकूलर) को देखकर ही बता सकता हूं कि किस कन्टेक्सट में यह जारी किया गया, वह सरकूलर हैड आफिसर में होगा। यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय में उक्त सरकूलर की प्रति उपलब्ध थी। अगर वास्तव में यह प्रति सही नहीं थी तो नियोजक से अपेक्षा थी कि वह इस बात स्पष्ट कथन करते। तत्पश्चात् भी नियोजक साक्षी ने

न तो कोई प्रार्थना पत्र दिया और न ही कोई इस विषय की साक्ष्य पेश की कि 24-10-72 का उक्त सरकूलर सही नहीं हो। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि 18-3-74 को सरकूलर एम-1 अप्रार्थी संस्थान के मान्यता प्राप्त संघ के समझौते के उपरोक्त जारी किया गया था तो भी उसके अनुसार भी 1-1-66 से ही श्रमिक को अस्थाई सेवाओं का लाभ मिलना अपेक्षित था। जबकि नियोजक ने 1-1-74 के बाद की ही 196 दिवस की अस्थाई सेवा का लाभ इस श्रमिक को दिया है जो मेरी राय में प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर भी अनुचित है। 24-10-72 के सरकूलर के प्रभाव को 18-3-74 के सरकूलर द्वारा श्रमिकों के संघों को सुनने के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में 24-10-72 के सरकूलर के अनुसार यह श्रमिक 572 दिवस की पूरी अस्थाई सेवा का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना हेतु प्राप्त कर सकता है परन्तु इसे अस्थाई सेवा के दिनों का लाभ था ही मिलेगा अभिप्राय यह है कि श्रमिक की स्थाई नियुक्ति होने पर 572 दिवस की अस्थाई सेवा का लाभ देते हुए इसकी वार्षिक वेतन वृद्धियां उसी अनुपात में बढ़ा दी जाएंगी। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:—

“श्रमिक सोहन लाल मोदी को उसकी पिछली अस्थाई सेवाओं का लाभ नहीं देना न्यायोचित नहीं था और 572 दिवस की अस्थाई सेवा का लाभ देते हुए ही इस श्रमिक की वार्षिक वेतन वृद्धियां निश्चित एवं निर्धारित की जायें और उसके अनुरूप ही उसे राशि प्रदान की जाए।”

9. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम को धारा 17(1) के भेजा जाए।

जगतसिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 12 मई, 1992

का.आ.1367:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हाइदराबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/79/89-आई आर (बी-1)]

सुभाष चन्द शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th May, 1992

S.O. 1367.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hadoti-

kshetriya Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-5-92.

[No. L-12012/79/89-IR(B-I)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस. नं. सी.आई.टी. 16/1990

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश
क्रमांक एल-12012/79/89-आई.आर.बी. (1)
दिनांक 12-2-90

हाइड्रोक्सी ग्रामीण बैंक एम्पलाईज यूनियन, कोटा

—प्रार्थी

बनाम

हाइड्रोक्सी ग्रामीण बैंक, कोटा।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : श्री सुनील नाथ
दिनांक अर्वाद : 7 दिसम्बर, 1991

अर्वाद

प्रार्थी गैर हाजिर। यूनियन की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आया और नाही प्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य हाजिर है। विपक्षी की ओर से श्री सुनील नाथ हाजिर है। ऐसा लगता है कि यूनियन उक्त विवाद में अब पैरवी नहीं करना चाहती। ऐसी सूरत में विवाद हाजा में अदम पैरवी में अदम सबूत में नो डिस्प्यूट अर्वाद पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 12 मई, 1992

का.आ.1368 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/4/86-डी-II (ए)]

सुभाष चन्द शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th May, 1992

S.O. 1368.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur, as shown in the Annexure, in the industrial dispute

between the employers in relation to the management of Bank of Rajasthan Limited and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-5-1992.

[No. L-12012/4/86-DII(A)]
S. C. SHARMA, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 10/1987

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश
क्रमांक एल-12012/4/86-डी I (ए) दिनांक 29-12-1986

श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल, क्लर्क द्वारा राजस्थान (स्टेट) बैंक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, कोटा।

—प्रार्थी

बनाम

बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी संघ की ओर से : श्री आर.सी. जैन
अप्रार्थी की ओर से : श्री केवल राम जी
दिनांक अर्वाद : 9-12-1991

अर्वाद

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (2-ए) के तहत प्रेषित किया है :

“क्या बैंक ऑफ राजस्थान लि. जयपुर के प्रबंधतंत्र की दिनांक 19-12-84 के आदेश के तहत श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल की पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां बंद करने की कार्रवाई न्यायोचित और उचित है। यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।”

2. राजस्थान (स्टेट) बैंक वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे तत्पश्चात प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल अप्रार्थी बैंक की इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, कोटा शाखा में काउंटर क्लर्क के पद पर कार्यरत था जिसे अप्रार्थी नियोजक ने 1-6-82 को एक आरोप पत्र जारी किया कि उक्त श्रमिक 18-8-81 को बैंक की उपरोक्त शाखा में सेविंग बैंक काउंटर पर कार्यरत था। उस रोज करीब 2.00 बजे श्रमिक ने श्री पी.एल. आचार्य बैंक के अधिकारी के समक्ष 30,000 रुपये का एक विड्रावल फार्म रखते हुए प्रकट किया कि श्री हरी राम शर्मा, एस.बी. अकाउंट नं. 3120 पुराने ग्राहक हैं जिसे वह अच्छी तरह निजी तौर से जानते हैं और जो पास बुक नहीं लाये हैं और इस प्रकार आपने उपरोक्त

विद्रावल फार्म लैजर व टोकन बुक में दर्ज करने के उपरांत श्री पी.एल. आचार्य, बैंक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उनसे बिना पास बुक पेमेंट करने के आदेश करने का निवेदन किया। आपके उपरोक्त आश्वासन पर विश्वास करते हुए श्री पी.एल. आचार्य ने उक्त विद्रावल फार्म पर बिना पास बुक पेमेंट करने का आदेश दिया तत्पश्चात् खाताधारी श्री हरीराम शर्मा ने प्रकट किया कि उसने 30,000 रुपये की उपरोक्त राशि नहीं निकाली है तथा उसके खाते से 18-8-81 को 30,000 रुपये की राशि धोखा देकर निकाली गई है। श्रमिक पर आरोप यह है कि उसने सेविंग बैंक अकाउंट आपरेशनल रुस तथा सैन्ट्रल ऑफिस सरकूलर नं. 29/डीईपी/4/334/77 दिनांक 22-2-77 के विपरीत कार्यवाई की है जिसके फलस्वरूप बैंक को 30,000 रुपये की हानि हुई है तथा बैंक के साथ धोखाधड़ी हुई है और उसकी साख गिरी है। श्रमिक का उक्त कार्य द्विपक्षीय समझौते 1966 के नियम 19 (5) जे के विपरीत होने से एक दुराचरण है।

3. उपरोक्त दोनों आरोपों की बावत श्रमिक के विरुद्ध घरेलू जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा आरोप साबित पाये जाने पर श्रमिक को 19-12-84 के आदेश द्वारा 5 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकने का उपरोक्त दण्ड दिया गया था। प्रार्थी संघ का कथन यह है कि नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है क्योंकि द्विपक्षीय समझौते एवं विभिन्न अवादों के प्रावधानों के तहत श्रमिक को जवाब का अवसर दिये बिना ही विभागीय जांच प्रारंभ कर दी गई। मांगे गये दस्तावेजों की प्रतियां नहीं दी गई। अकाउंट होल्डर श्री हरीराम शर्मा का बयान नहीं कराया गया। लिखित प्रार्थना पत्र देने पर भी श्री लालचंद गुप्ता खजान्ची एवं हरी राम शर्मा शिकायकर्ता खाताधारी को बयान हेतु उपस्थित नहीं किया गया। जांच के दौरान श्रमिक ने 15-7-82 को रजिस्टर्ड पत्र सं. 5039 जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसके द्वारा वे सभी दस्तावेजात उपलब्ध कराने का निवेदन किया था जो बैंक के अधिकार में थे और न्याय हित में परमावश्यक थे। पुनः 29-7-92 को भी पत्र क्रमांक 847 द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक को भी दस्तावेजात उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था परंतु क्षेत्रीय प्रबन्धक ने 17-8-82 के पत्र डब्ल्यू. ई. एक्स-5 द्वारा सूचित किया कि दस्तावेज गोपनीय होने से नहीं दिये जा सकते। प्रार्थी संघ यह भी कहता है कि 30,000 रुपये का विद्रावल फार्म भी उपलब्ध नहीं करवाया जिससे श्रमिक के प्रति पक्षपात हुआ है और वह अपनी सुरक्षा भलीभांति नहीं कर पाया। प्रार्थी संघ कहता है कि जांच के दौरान प्रस्तुत प्रबन्धक वर्ग के गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास था जिन पर विचार किये बिना ही आरोपों को सिद्ध मान लिया गया है। बैंक के उपरोक्त परिपत्र दिनांक 22-2-77 तथा बैंक अकाउंट आपरेशन नियमों का उल्लंघन श्री पी. एल. आचार्य, बैंक अधिकारी द्वारा किया गया था क्योंकि उक्त परिपत्र के अनुसार बैंक

का प्रबन्धक या कार्यवाहक प्रबन्धक या विभाग प्रभारी ही वचत खाता में निकासी फार्म पर बिना पास बुक भुगतान करने के आदेश दे सकते थे। श्रमिक तो मात्र क्लर्क था तथा पी. एल. आचार्य ने ही उक्त परिपत्र का उल्लंघन किया है जिसे दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का ही दण्ड दिया जो भी जांच में बयान देने के उपरांत वापस ले लिया गया। प्रार्थी संघ के अनुसार इसी मामले में एक वाद सं. 83/82 जिला एवं सत्र न्यायालय, कोटा में हरीराम शर्मा द्वारा बैंक के विरुद्ध चला रहा है जिसमें बैंक ने अपना जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया है कि 30,000 रुपये का भुगतान बैंक समय में धारक हरी राम शर्मा को बैंक के नियमानुसार किया गया है और बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही नहीं हुई है। उक्त वाद में प्रबन्धक साक्षी श्री सुरेन्द्र शर्मा ने जो बयान दिया है वह जांच में दिये गये बयानों से बिल्कुल विपरीत है। इसलिए भी जांच में ली गई साक्ष्य से दुराचरण साबित नहीं है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में ही सेवा मुक्ति का दण्ड प्रस्तावित किया था जो बाद में पांच वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकने बाबत दिया गया जो भावी प्रभाव का होने से श्रमिक को लाखों रुपये का नुकसान होगा। श्रमिक द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्विचार की प्रार्थना भी नज़रअंदाज़ कर दी गई तथा दण्ड देने के उपरांत श्रमिक को पदोन्नति नहीं दी गई और उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति कर दिया गया। प्रार्थी संघ को कहना है कि 19-12-94 का दण्डादेश अपास्त किया जावे और उसके द्वारा रोकी गई वेतन वृद्धियां श्रमिक को दिलाई जायें।

4. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर क्लेम के उपरोक्त कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रारंभिक आपत्ति यह की है कि श्रमिक मनमोहन कान्त अग्रवाल ने स्वयं ही समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद खड़ा किया था इसलिए अधिनियम की धारा 2 (क) के अन्तर्गत यह विवाद औद्योगिक विवाद की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी संघ ने भी विवाद खड़ा करने बाबत किसी प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत नहीं की है और इसलिए भी धारा 2(क) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद नहीं बनता। गुणावगुण पर नियोजक का कहना है कि 1-6-82 के पत्र द्वारा श्रमिक पर आरोप अधिरोपित किया गया था और जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार दुराचरण साबित था। जांच के दौरान प्रबन्धक पक्ष ने सभी वांछित साक्ष्यों के बयान कराये थे। 18-8-81 के वाउचर का बण्डल गुम हो गया था इसलिए वादग्रस्त 30,000 रुपये का विद्रावल फार्म जांच के दौरान पेश नहीं हो सका। श्रमिक द्वारा जो प्रलेख डी. डब्ल्यू.-1 पत्र द्वारा मांगे गये थे उनकी प्रतियां दिलाई गई थीं और श्रमिक को प्रति रक्षा का पूरा अवसर दिया गया था इसलिए जांच प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप थी। जांच रिपोर्ट के उपरांत भी श्रमिक को उसकी प्रति देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई का अवसर देने के उपरांत ही पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई रूप से रोकने

का दण्ड दिया था जो भी दुराचरण को देखते हुए अनुचित एवं अत्याधिक नहीं था। 30,000 रुपये की राशि की वसूली हेतु खाताधारक श्री हरी राम शर्मा ने बैंक के विरुद्ध दावा किया था जिसका जवाब नियमानुसार दिया गया था। उस समय तक जांच पूरी नहीं हुई थी इसलिए जवाब यही दिया गया कि कार्यालय समय में खाताधारक श्री हरीराम शर्मा ने ही 30,000 रुपये का विज्ञावल फार्म दिया था जिसे नियमानुसार स्वीकार किया गया और “पे विदग्राऊट पास बुक” का आदेश दिया गया था परंतु तत्पश्चात् उक्त न्यायालय द्वारा बैंक के विरुद्ध उक्त राशि की डिम्बी दे दी गई है जिससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि 30,000 रुपये की राशि घोखाधड़ी से निकाली गई है। नोटिस के जवाब में श्रमिक श्री अग्रवाल स्वयं उपस्थित हुआ था, उसे सुनवाई का पूरा अवसर दिया था और तत्पश्चात् गुणावगुण पर उसकी अपील खारिज की थी और उसे उचित दण्ड दिया गया है। श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति बाबत इस रैफरेंस में आपत्ति नहीं की जा सकती क्योंकि उक्त विषय का विवाद रैफरेंस द्वारा पढ़ाया नहीं गया है।

5. मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पत्रकारों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत तर्क विस्तारपूर्वक सुने तथा न्याय दृष्टान्तों का भी सूक्ष्म रीति से मनन किया। जहां तक नियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति का प्रश्न है, रैफरेंस के पढ़ने से यह प्रकट होता है कि यह विवाद श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल द्वारा नहीं उठाया गया है बल्कि प्रार्थी संघ द्वारा उठाया गया है क्योंकि रैफरेंस की प्रति प्रार्थी संघ को पठाई गई है जिसका नाम क्रम सं. 3 पर दर्ज है। अगर श्रमिक द्वारा विवाद समझौता वार्ता में उठाया गया होता तो रैफरेंस की प्रति प्रार्थी संघ की बजाय श्रमिक को ही भेजी जाती। समझौता अधिकारी द्वारा 1-1-86 को विफलता रिपोर्ट भेजी गई थी उसकी प्रति से भी मामला साफ हो सकता था परंतु नियोजक की तरफ से उक्त रिपोर्ट की प्रति पेश नहीं की गई है और न ही इस न्यायालय में ऐसी कोई प्रालेखिक अथवा मौखिक साक्ष्य पेश की गई है जिससे यह प्रकट होता हो कि समझौता अधिकारी के समक्ष विवाद श्रमिक ने स्वयं न उठाया हो। यहां तक कि प्रार्थी संघ द्वारा विवाद उठाने के लिए प्रस्ताव पास करना आवश्यक है किंतु तथाकथित प्रस्ताव की प्रति न्यायालय में पेश करना आवश्यक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने (1983) 4 एस.सी.सी. 214, (1984) 4 एस.सी.सी. 392 के न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया है कि जब एक बार कोई विवाद रैफर हो जाता है तो यह उपधारित किया जायेगा कि औद्योगिक विवाद है जब तक कि इसके विपरीत साबित नहीं कर दिया जाये। नियोजक प्रतिनिधि मेरा समाधान नहीं कर पाये कि बिना प्रस्ताव पारित किए ही प्रार्थी संघ की तरफ से यह विवाद उठाया गया हो। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से प्राथमिक आपत्ति निराधार मानते हुए खारिज की जाती है।

6. जहां तक जांच के अनफेयर होने का प्रश्न है, प्रार्थी संघ का कहना है कि श्रमिक द्वारा मांगने पर भी प्रलेखों

की प्रतियां नहीं दी गईं। इस विषय में दिनांक 15-7-82 के पत्र डब्ल्यू-3 का उल्लेख किया जा सकता है जिसके द्वारा माणकचंद जी बिड़ला द्वारा की गई प्राथमिक जांच की पूर्ण रिपोर्ट की प्रति मांगी गई है तथा उन व्यक्तियों के बयानों की भी सत्य प्रति चाही है जिनके श्री बिड़ला ने बयान लिये थे विशेषकर पी.एल. आचार्य और शुभकरन शर्मा के बयानों की प्रतियां चाहीं हैं। उक्त श्री पी.एल. आचार्य एवं शुभकरन शर्मा को अगर कोई आरोप पत्र जारी किया था तो उनकी प्रतियां चाही हैं। विज्ञावल फार्म की फोटो प्रति, संबंधित टोकन बुक व कैशियर पेमेंट बुक की फोटो प्रति, खाताधारक हरी राम शर्मा के बचत खाता सं. 3120 के खाते की नकल दिनांक 1-1-81 से दिनांक 31-12-81 तक की चाही है। 1-6-81 से 30-9-91 तक के पेमेंट वाऊचर का निरीक्षण करवाने की प्रार्थना की है। 24-8-82 को श्रमिक के प्रतिनिधि श्री आर.के. कदम ने भी डब्ल्यू-4 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसके द्वारा एफ.आई.आर. की प्रति चाही गई थी। पुलिस रिपोर्ट की प्रति चाही गई थी। 22-2-77 के सरकूलर की प्रति चाही गई थी जिसके द्वारा सेविंग बैंक अकाउंट आपरेशन के नियमों का उल्लेख था। 18-8-81 के विज्ञावल फार्म 30,000 रुपये की प्रति चाही गई थी और माणकचंद बिड़ला द्वारा की गई तथाकथित प्रारंभिक जांच की फोटोप्रति चाही गई थी। दिनांक 17-8-82 को डब्ल्यू-5 द्वारा नियोजक बैंक की तरफ से श्रमिक को उक्त पत्रों का उत्तर भी आ गया था जिसके साथ 22-2-77 के परिपत्र की सत्य प्रति पठाई गई थी। 30,000 रुपये की विज्ञावल बाबत सूचित किया गया था कि वह उपलब्ध नहीं है क्योंकि 18-8-82 का पूरा बण्डल ही गायब है। बाकी प्रलेखों के लिए श्रमिक को सूचित किया गया था कि वे गुप्त प्रकृति के हैं और प्रविलेज्ड हैं। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान जो आर्डर शीट लिखी गई थी उसके निरीक्षण से प्रकट हुआ कि 28-7-82 की आदेशिका में ही श्रमिक प्रतिनिधि श्री कदम द्वारा प्रस्तुत पत्र डी.डब्ल्यू-1 का उल्लेख है और श्रमिक को जांच अधिकारी ने संलाह दी कि प्रबंधक को उक्त पत्र पेश करें जिस संलाह को श्रमिक ने स्वीकार कर लिया था। 24-8-82 की आदेशिका से प्रकट हुआ कि उस रोज़ श्री पंचार प्रबंधक प्रतिनिधि ने एम-2 लगायत एम-6 प्रलेखों की फोटो प्रतियां पेश की थी जिनकी नकलें उसी रोज़ श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल को दिलाई गई थीं तथा उक्त प्रलेखों का मूल रिकार्ड भी श्रमिक के प्रतिनिधि का दिखा दिया गया था। उक्त रोज़ की आदेशिका में यह भी दर्ज है कि श्रमिक के पत्र दिनांक 8-7-82 डब्ल्यू-1 द्वारा मांगे गये आवश्यक प्रलेखों की प्रतियां श्रमिक को दे दी गई हैं सिवाए गोपनीय प्रकृति के प्रलेखों के। तथा श्रमिक ने भी उक्त तथ्य को जांच अधिकारी के समक्ष स्वीकार किया है। उसी रोज़ प्रबंधक की साक्ष्य के लिए पत्रावली निश्चित कर दी गई। तत्पश्चात् श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि ने किसी प्रलेख की प्रति दिखाने बाबत जांच अधिकारी को न तो मौखिक रूप से निवेदन किया और न ही कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

किया। जांच के दौरान प्रबंधक के प्रतिनिधि ने जो प्रलेख प्रस्तुत किये थे उन सब की प्रतियां श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि को दिला दी गई थी और मूल प्रलेखों का भी श्रमिक प्रतिनिधि का निरीक्षण करा दिया गया था, उक्त विषय का उल्लेख जांच पत्रावली में मिलता है। अभिलेख पर नाम मात्र की भी ऐसी साक्ष्य नहीं है कि श्री माणकचंद जी बिड़ला द्वारा कोई प्राथमिक जांच की गई हो या उसके द्वारा किसी गवाह के बयान लिये गये हों। प्रबंधक प्रतिनिधि द्वारा भी उक्त श्री बिड़ला द्वारा किसी साक्षी के बयान की प्रति जांच के दौरान पेश नहीं की गई है और न ही प्रबंधक पक्ष की तरफ से जांच के दौरान प्रस्तुत साक्षियों से प्रति-परीक्षा में यह पूछा गया है कि उन्होंने श्री माणकचंद बिड़ला को भी कभी कोई बयान दिये हों। अतः श्री माणकचंद जी बिड़ला द्वारा की गई जांच की प्रति अथवा उनके द्वारा लिये गये बयानों की प्रतियां देने का प्रश्न ही नहीं था। श्री पी.एल. आचार्य को आरोप पत्र दिया गया था जिसकी प्रति श्रमिक को नहीं दिलाई गई परंतु इससे श्रमिक के प्रति पक्षपात नहीं होता क्योंकि श्री आचार्य को दिया गया आरोप पत्र भी 18-8-82 को 30,000 रुपये की विज्ञावली से ही संबंधित था जिसका श्रमिक को पूरा ज्ञान था। श्री आचार्य का परीक्षण जांच के दौरान प्रबंधक पक्ष की तरफ से हुआ है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने विस्तारपूर्वक प्रति-परीक्षा भी की है इसलिए श्री आचार्य के आरोप पत्र की प्रति इस श्रमिक को देना न तो आवश्यक था और न ही इसके अभाव में श्रमिक के प्रति कोई पक्षपात होता है। 30,000/- रुपये के विज्ञावली फार्म की प्रति जांच के दौरान भी पेश नहीं हो पाई क्योंकि 18-8-82 का पूरा बण्डल ही गायब था। हरीराम शर्मा के बचत खाता सं० 3120 की प्रति अभिलेख पर पेश की गई थी और 18-8-82 के टोकन बुक व कैशियर पेमेंट बुक की फोटो प्रति भी अभिलेख पर उपलब्ध हैं जिन पर श्रमिक के प्रतिनिधि ने विस्तारपूर्वक प्रति-परीक्षा भी की है। इसलिए जांच के दौरान श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा चाहे गये उन समस्त प्रलेखों की प्रतियां दे दी गई थीं जो प्रबंधक के अधिकार में थीं। बहस के दौरान श्री जैन, श्रमिक प्रतिनिधि का तर्क यह था कि चाहे गये प्रलेख श्रमिक को उसकी प्रति-रक्षा के लिए आवश्यक थे, परंतु न तो डब्ल्यू-3 या डब्ल्यू-4 में ऐसा उल्लेख है कि इन प्रलेखों की आवश्यकता श्रमिक की प्रति-रक्षा हेतु है और न ही बहस के दौरान श्री जैन मुझे संतुष्ट कर पाये कि इन प्रलेखों के अभाव में श्रमिक अपनी प्रति-रक्षा कैसे नहीं कर पाया था। अर्थात् श्री जैन यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि जो प्रलेख नियोजक द्वारा नहीं दिये गये हैं उनके अभाव में श्रमिक की प्रति-रक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में नियोजक द्वारा उन सभी प्रलेखों की प्रतियां श्रमिक या उसके प्रतिनिधि को दे दी गई थी जिनका प्रयोग जांच रिपोर्ट में किया गया है। माननीय श्रम न्यायालय ने चन्द्रामां तिवारी बनाम भारत सरकार 1980 (1) एल.एल.एन. 669 तथा एस.सी.एल. जे (1950-83) (वालयूम 4) 640 के न्याय दृष्टान्त में भी उपरोक्त सिद्धान्तों 1205 GI/92-8

को ही प्रतिपादित किया है कि जांच के दौरान श्रमिक को वही प्रलेख देना आवश्यक है जिनका प्रयोग जांच रिपोर्ट में श्रमिक के विरुद्ध किया गया था। तथा श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा चाहे गये उन प्रलेखों की प्रतियां भी पेश करना आवश्यक नहीं है जिनका प्रयोग जांच में नहीं किया गया था, या जो श्रमिक की सफाई के लिए आवश्यक नहीं थे। जैसा कि मैंने ऊपर प्रकट किया है श्रमिक ने अथवा उसके प्रतिनिधि ने जांच के दौरान जो प्रार्थना पत्र पेश किये हैं उनमें यह स्पष्ट अंकित नहीं किया कि वांछित प्रलेख श्रमिक की सुरक्षा के लिए आवश्यक हों। जांच अधिकारी द्वारा भी आदेश देने पर कि श्रमिक द्वारा चाहे गये प्रलेख प्रबंधक उसे दावे तथा आगामी पेशी पर कुछ प्रलेख श्रमिक को दे दिये गये थे और कुछ बाबत गोपनीय का उल्लेख किया गया था जिस बाबत श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि संतुष्ट थे क्योंकि तत्पश्चात् उन्होंने किसी भी प्रलेख की मांग जांच अधिकारी अथवा प्रबंधक पक्ष से नहीं की। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से श्री जैन की प्रथम तर्क कि जांच के दौरान उन्हें प्रलेखों की प्रतियां नहीं दी गई थीं, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. श्री जैन श्रमिक प्रतिनिधि ने हालांकि क्लेम में तो यह आपति दर्ज नहीं की है परंतु बहस के दौरान एक आपति यह भी प्रकट की कि द्विपक्षीय समझौता 19-2-66 के नियम 19.14 के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्रमिक को आरोप पत्र नहीं दिया गया। उक्त नियम के अनुसार बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अथवा प्रिंसीपल ऑफिसर ही आरोप पत्र देने के लिए अधिकृत था न कि रीजनल मैनेजर जिसने कि श्रमिक को 1-6-82 को आरोप पत्र दिया था और इसलिए अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा आरोप पत्र देने से इस पर कराई गई घरेलू जांच प्रोपर एवं फेयर नहीं हो सकती। श्री केवल राम, नियोजक प्रतिनिधि ने बैंक का सरकूलर नं. 33/पी.ई.आर./49/1060/81 दिनांक 7-12-81 की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार बैंक के चेयरमैन ने रीजनल मैनेजर को डिप्टी प्रिंसीपल ऑथॉरिटी (अनुशासनिक प्राधिकारी) घोषित किया हुआ है और तत्पश्चात् सरकूलर नं. 36/पी.ई.आर./17/1609/84 दिनांक 18-6-84 द्वारा असिस्टेंट रीजनल मैनेजर को अनुशासनिक प्राधिकारी घोषित किया गया है। उपरोक्त दोनों परिपत्रों की फोटो प्रतियां अभिलेख पर उपलब्ध हैं इसलिए श्री जैन का उपरोक्त तर्क चलने योग्य नहीं है तथा मेरी राय में भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही श्रमिक को आरोप पत्र दिया गया है।

8. श्री जैन श्रमिक प्रतिनिधि का एक तर्क यह भी था कि द्विपक्षीय समझौता 19-10-66 के नियम 19.1 के अनुसार जांच प्रारंभ करने से पूर्व श्रमिक को स्पष्टीकरण देने हेतु अवसर देना आवश्यक था जो नहीं दिया गया इसलिए भी श्रमिक के साथ पक्षपात हुआ है। अपने कथनों के समर्थन में श्री जैन ने 1974 (294-एफ.एल.आर. 305 के न्याय दृष्टान्त का उल्लेख किया है। मैंने द्विपक्षीय समझौते के

चैप्टर 19 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया तो पाया कि इससे यह निष्कर्ष यहीं निकलता कि आरोप पत्र देने के उपरांत और जांच शुरू करने से पूर्व श्रमिक को किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने का अवसर देना अपेक्षित हो। नियम 19.1 जैसी ही भाषा का प्रयोग नियम 19.12 में भी किया गया है जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोप पत्र के उपरांत श्रमिक को स्पष्टीकरण देने का तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर देना आवश्यक है। जांच पतावली के निरीक्षण से प्रकट हुआ कि 1-6-82 को जो आरोप पत्र श्रमिक को दिया गया था उन पर सर्वप्रथम 28-7-82 को जांच अधिकारी ने कार्यवाही प्रारंभ की थी और उस रोज भी श्रमिक को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया था तथा श्रमिक ने यह स्वीकार किया था कि वह आरोपों को समझ गया है। उसी रोज श्रमिक ने कुछ प्रलेख दिलवाने की अर्जी भी पेश की थी। अभिप्राय यह है कि आरोप पत्र देने के करीब 2 माह उपरांत जांच अधिकारी ने जांच प्रारंभ की थी। इस अवधि में अगर श्रमिक चाहता तो अपने स्पष्टीकरण पेश कर सकता था। नियोजक पक्ष की तरफ से प्रथम साक्षी का परीक्षण 25-11-82 को हुआ है जब तक भी श्रमिक अथवा उसके प्रतिनिधि ने आरोपों बाबत किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया था जिससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में श्रमिक को आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त समय था परंतु श्रमिक ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया था जिससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में श्रमिक को आरोपों का स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त समय था परंतु श्रमिक ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं समझा। ओ न्याय दृष्टान्त श्री जैन की तरफ से पेश हुआ है उसके तथ्य और परिस्थितियां विवेचनाधीन विवाद के तथ्यों और परिस्थितियों से भिन्न थे। उस विवाद में तो सेवा नियमों में ही ऐसे स्पष्टीकरण का अवसर देने का उल्लेख था जबकि इस द्विपक्षीय समझौते में ऐसा अवसर देने का उल्लेख नहीं है। अतः श्री जैन का यह तर्क भी निराधार मानते हुए खारिज किया जाता है।

9. श्री जैन योग्य प्रतिनिधि श्रमिक का एक तर्क यह था कि प्रबन्धक पक्ष की तरफ से श्री हरी राम शर्मा खाता-धारी तथा श्री लाल चंद गुप्ता खजांची के परीक्षण नहीं कराये गये हैं तथा वह उनकी प्रति-परीक्षा से वंचित हो गया है, इसलिए भी जांच प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हुई है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त श्री हरीराम शर्मा ने बैंक के विशद जिला न्यायालय कोटा में 30,000 रुपये की वसूली हेतु वाद प्रस्तुत कर दिया था और उक्त श्री हरीराम शर्मा ने तो अपने वाद के अनुसार यही कथन करना था कि उसने 18-8-81 को न तो विड्रावल फार्म भरकर दिया और न ही 30,000 रुपये की रशि प्राप्त की। प्रबन्धक पक्ष द्वारा उक्त श्री हरीराम शर्मा का बयान कराना आवश्यक नहीं था। अगर वास्तव में श्रमिक के लिए हरी राम शर्मा के बयान कोई महत्व रखते थे तो श्रमिक भी उसे प्रति-रक्षा में पेश कर सकता था। इसी प्रकार लाल चंद गुप्त भी 18-8-81 को कार्यवाहक विशेष सहायक के पद पर था। इसके

द्वारा 30,000 रुपये की धोखाधड़ी वाले विड्रावल फार्म बाबत कोई विशेष कथन नहीं करना था तथा प्रबन्धक पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह 18-8-81 को बैंक की शाखा में कार्यरत सभी व्यक्तियों के परीक्षण कराता। स्वयं श्रमिक ने भी प्रति-रक्षा में उक्त श्री लालचंद गुप्ता का परीक्षण नहीं कराया है। इसलिए इन दोनों साक्षियों के परीक्षण नहीं होने से श्रमिक के प्रति कोई पक्षपात नहीं होता है और न ही इस वजह से नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच में कोई त्रुटि रहती है। इसलिए यह तर्क भी अपास्त किया जाता है।

10- श्री जैन, योग्य प्रतिनिधि श्रमिक का एक तर्क यह भी था कि प्रबन्धक साक्षियों के बयानों में अन्तरविरोध था अर्थात् श्री एस. पी. शर्मा व श्री पी. एल. आचार्य के बयानों में कुछ विरोधाभास है। मैंने प्रबन्धक पक्ष के उपरोक्त दोनों साक्षियों के जांच अधिकारी द्वारा लिये गये बयानों का सूक्ष्म रीति से मनन किया तो पाया कि सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा 18-8-81 को अपना बचत खाता सं. 589 में 650/- रुपये जमा करवाने तथा 1003/ रुपये जमा करवाने करीब 12.00 बजे बैंक में आया था तथा अपनी पास बुक व विड्रावल फार्म लोन खाते में जमा कराने हेतु तथा पास बुक में प्रविष्टियां कराने हेतु मनमोहन कान्त अग्रवाल को दे गया ताकि करीब 2.00 बजे वापिस आकर ले लेगा। साक्षी ने करीब 12 बजे विड्रावल फार्म तथा अपनी पास-बुक सेविंग काउंटर पर बैठे हुए मनमोहन कान्त अग्रवाल को प्रविष्टि करने हेतु दी थी और 2.00 बजे पुनः वह अपनी पास बुक लेने आया तब उसने काउंटर पर खड़े हुए श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल व श्री पी. एल. आचार्य को आपस में बातें करते सुना था। इस साक्षी के कथनों में तथा पी. एल. आचार्य के कथनों में जो मामूली विरोधाभास बहस के दौरान श्री जैन ने इंगित किया है उनसे साक्षियों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि ऐसा मामूली विरोधाभास आना स्वाभाविक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जे डी जैन बनाम स्टेट बैंक आफ इंडिया एस. सी. एल. जे. (1950-83) (बोल्सूम 5) पेज 1 तथा बाल कृष्ण मिश्रा बनाम सी. जी. आई. टी. एस. सी. एल. जे. (1950-83) (बोल्सूम-5) 59 के न्याय दृष्टान्तों में यह प्रतिपादित किया है कि श्रम न्यायालयों में दुराचरण साबित करने के लिए साक्ष्य का जो स्तर होता है वह उतना नहीं होता जितना कि आपराधिक प्रकरणों में होना चाहिए। अर्थात् दुराचरण साबित करने के लिए प्रबन्धक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं करना होता बल्कि संभावनाओं की प्रबलता के स्तर के अनुसार ही अगर दुराचरण साबित होता है तो ही पर्याप्त है। इन परिस्थितियों में भी जैन का यह तर्क भी अपास्त किया जाता है।

11- श्री जैन का अंतिम तर्क यह था कि अपील का निर्णय करने से पूर्व श्रमिक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जिससे भी श्रमिक के साथ पक्षपात हुआ है। इस विषय में मैंने जांच पतावली का निरीक्षण किया तो पाया कि दिनांक

27-6-84 के आदेश में असिस्टेंट जनरल मैनेजर श्री एन. सी. भल्ला ने यह दर्ज दण्ड देने से पूर्व मनमोहन कान्त अग्रवाल को 7 जुलाई, 1984 को 11.00 बजे निजी सुनवाई हेतु उपस्थित होने का आदेश दिया था और तत्पश्चात श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल ने 25-7-84 को अपना लिखित स्पष्टीकरण भी दिया था और वह स्वयं भी स्थिति स्पष्ट करने हेतु उपस्थित हुआ था। तत्पश्चात 19-12-84 को श्रमिक को 5 वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया था। इसका उल्लेख 19-12-84 के आदेश में भी पाया जाता है। अतः इन परिस्थितियों में श्री जैन के इस तर्क में भी सत्यता का आभास नहीं होता अतः खारिज किया जाता है।

12- तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुरूप हुई है क्योंकि श्रमिक एवं उसके प्रतिनिधि को प्रति रक्षा एवं प्रति परीक्षा के पर्याप्त अवसर दिये गये थे तथा जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच से श्रमिक के प्रति पक्षपात नहीं होता है।

13- श्री जैन योग्य श्रमिक प्रतिनिधि को गुणावगुण पर भी मैंने विस्तारपूर्वक सुना। उनका तर्क यह था कि जांच के दौरान नियोजक द्वारा कराई गई साक्ष्य से दुराचरण साबित नहीं है। इस विषय में प्रबन्धक साक्षियों के कथनों का विश्लेषण आवश्यक है।

14- दुराचरण साबित करने के लिए प्रथम प्रमुख साक्षी श्री पी. एल. आचार्य हैं जो 18-8-81 को बैंक की इंडस्ट्रियल एस्टेट शाखा में सब मैनेजर के पद पर कार्यरत थे जिसका कहना है कि दिन के 2.00 बजे के आसपास जब वह बाथरूम से लौट रहा था तब दरवाजे के पास जहां स्पेशल असिस्टेंट की सीट है जिस पर मनमोहन कान्त अग्रवाल कार्य कर रहा था, ने 30,000/- रुपये का विड्रावल फार्म सामने रखते हुए रोका और कहा कि लाल चन्द जी नहीं है, यह हरीराम जी शर्मा का विड्रावल फार्म है जो अपने अच्छे और पुराने ग्राहक हैं तथा किसी कारणवश पास बुक नहीं लाये हैं, मैं इनको खूब अच्छी तरह जानता हूं, आप बिना पास बुक के पास करने के आदेश फरमा दें। श्री आचार्य का कहना है कि उसने, श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल का एक स्टाफ मेम्बर होने के नाते, उनकी बात पर पूरा-पूरा भरोसा करके "पे विदआउट पास बुक" लिख दिया। साक्षी कहता है उसे रामपुर कोटा शाखा से स्थानान्तरित हुए करीब साढ़े तीन माह ही हुए थे इसलिए उसने मनमोहन कान्त अग्रवाल के कहने से उन पर पूरा भरोसा करके विड्रावल फार्म नियमानुसार पास कर दिया था। श्री आचार्य का कहना है कि उसने केवल विड्रावल फार्म ही देखा जो मनमोहन कान्त जी ने बताया था। भुगतान लेने कौन आया उसे नहीं देखा। यह भी मालूम नहीं कि भुगतान कौन ले गया। श्री आचार्य से श्रमिक प्रतिनिधि ने विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की है परन्तु यह साक्षी प्रति परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है। इसने प्रति परीक्षा में पूछे गये किसी भी प्रश्न का उत्तर

दालने का प्रयास नहीं किया है तथा न ही विरोधाभासी कथन किये हैं। श्री आचार्य से सुझाव के रूप में भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गये जिससे इनका श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई हित या हेतु प्रदर्शित होता हो। इस साक्षी की श्रमिक के प्रति कोई वमनस्यता या मनमुटाव भी नहीं था इसलिए यह साक्षी निष्पक्ष/कोटि का सत्यवादी व विश्वसनीय साक्षी था। श्री पी. एल. आचार्य के कथनों की पुष्टि नियोजक साक्षी श्री एस. पी. शर्मा के कथनों से भी होती है जो 18-8-81 को बैंक की उक्त शाखा में अपने बचत खाते सं. 589 में रुपये जमा कराने के लिए 12.00 बजे दिन में आया था जिसने अपनी पास बुक एवं विड्रावल फार्म एन्ट्री करने हेतु मनमोहन कान्त अग्रवाल को दे दी थी और पुनः दिन के 2.00 बजे अपनी पास बुक लेने बैंक आया तब काउंटर पर खड़ा होकर उसने अपनी पासबुक श्री अग्रवाल से मांगी। साक्षी कहता है उस समय श्री अग्रवाल जी पीछे बैठे श्री आचार्य से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे कि आचार्य साहब हरीराम शर्मा जी अपनी बैंक के पुराने ग्राहक हैं, विदआउट पासबुक पे आर्डर कर दें, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। साक्षी कहता है मनमोहन कान्त अग्रवाल के हाथ में कोई कागज था जिसको दिखाते हुए आचार्य जी से उपरोक्त वार्ता कर रहे थे। इस साक्षी ने भी अपनी पास बुक पेश की जिसमें 18-8-81 की प्रविष्टि है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में एस. पी. शर्मा 18-8-81 को बैंक की उपरोक्त शाखा में गया था और उसने भी मनमोहन कान्त अग्रवाल द्वारा श्री आचार्य को उपरोक्त बातें कहते सुना था। इस साक्षी से भी श्रमिक प्रतिनिधि ने विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की है तथा प्रति परीक्षा में भी साक्षी के कथनों में एकरूपता एवं सामंजस्य है। श्री जैन भी साक्षी के कथनों में ऐसे कोई विरोधाभास मुझे इंगित नहीं कर पाये जिससे उसकी विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस साक्षी का भी श्रमिक के विरुद्ध मिथ्या कथन करने का कोई उचित कारण नहीं था। इसलिए यह साक्षी भी निष्पक्ष कोटि का सत्यवादी साक्षी है। यह उल्लेखनीय है कि साक्षी एस. पी. शर्मा को श्रमिक भी अपनी प्रति रक्षा में पेश करना चाहता था जिस बाबत श्रमिक प्रतिनिधि ने जांच अधिकारी को भी अर्जी दी थी और जांच अधिकारी ने उक्त साक्षी से दुबारा प्रति परीक्षा श्रमिक प्रतिनिधि को करने का अवसर दिया था। पुनः प्रति परीक्षा में साक्षी एस. पी. शर्मा कहता है उसकी मनमोहन कान्त जी से न दोस्ती है न दुश्मनी पी. एल. आचार्य से भी दोस्ती या दुश्मनी नहीं है। साक्षी कहता है उसके घर में कुछ समय पहले मनमोहन कान्त, कदम साहिब व कैलाश जी गये थे और उससे कहा था कि ऐसा कुछ करो जिससे हम बच जायें। साक्षी कहता है इससे पहले प्रताप सिंह जी. सी. आई. पुलिस को लेकर भी कैलाश जी घर पर आये थे और बताया था कि वह पंजाब नेशनल बैंक में हैं और यूनियन का आदमी है और उसका काम मदद करना है तथा पिछले बयानों के बाद ही ये लोग बार-बार सम्पर्क करते रहे थे। साक्षी कहता है कि उसे मनमोहन कान्त जी के घर ले गये थे, वहां चाय पिलाई थी। इससे

भी यही निष्कर्ष निकलता है कि श्री एस. पी. शर्मा पर श्रमिक पक्ष भी विश्वास करता है और उसके द्वारा किये गये कथनों पर निर्भर करना सुरक्षित है।

15.— दुराचरण साबित करने के लिए प्रबन्धक पक्ष की तरफ से जी. के. गुप्ता का भी परीक्षण हुआ है जो तत्कालीन समय में उक्त शाखा का मैनेजर था। जिसने भी कहा है कि 18-8-81 को मनमोहन कान्त अग्रवाल सेविंग बैंक काउंटर पर कार्य कर रहे थे। लाल चंद गुप्ता कार्यवाहक विशेष सहायक की जगह कार्य कर रहे थे। पी एल आचार्य कार्यवाहक सब मैनेजर की जगह कार्य कर रहे थे। साक्षी कहता है 9-9-81 को श्री हरी राम शर्मा मेरे पास बाबू लाल आर्य के साथ आये और कहा कि उसका 720/- रुपये का एक चेक कैसे वापस कर दिया जबकि उसके हिसाब से सेविंग खाते में काफी बैलेन्स होना चाहिए था। साक्षी कहता है उसने बी. एल. आर्य से जानकारी चाही तो उसने बताया कि 18-8-81 को 30,000/- रुपये विज्ञावल फार्म से इस खाते से निकाले गये हैं तथा 5-9-81 को 15,000/- रुपये निकाले गये हैं। उपरोक्त दो बड़ी रकम निकाले जाने के कारण बैलेन्स कम होने पर 720/- रुपये का चेक पेश नहीं किया। साक्षी कहता है कि इस पर हरी राम शर्मा ने बतलाया कि उसने 18-8-81 को 30,000/- रुपये नहीं निकाले तथा विज्ञावल फार्म दिखाने के लिए कहा। साक्षी का कहना है कि 18-8-81 के मिसलेनीयस वाउचर्स पहले ही गुम हो चुके थे अतः 30,000/- रुपये का विज्ञावल फार्म हरी राम शर्मा को नहीं बता सके लेकिन 15,000/- का चेक जो 5-9-81 को दिया था एवं अन्य विज्ञावल फार्म जिसके द्वारा हरी राम शर्मा ने अपने खाते से राशि निकलवाई थी वे सब बताये। इस पर हरी राम शर्मा ने 30,000 रुपये की एंट्री के अलावा सब को स्वीकार किया तथा 30,000 रुपये का वाउचर बताने के लिए जोर दिया। साक्षी कहता है कि मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की इस पर हरी राम शर्मा ने एक पत्र बैंक को लिखा जिसमें 30,000/- रुपये वापस उनके खाते में जमा करने की प्रार्थना की। साक्षी कहता है हरी राम शर्मा ने यह भी कहा कि 15,000/- रुपये निकाले थे जब भी 400/- रुपये क्यों कम पड़े तथा 5-9-81 को ही मनमोहन कान्त ने इसे बैलेन्स कम होने की बात क्यों नहीं बताई। साक्षी कहता है कि उसने हरीराम शर्मा को बताया कि 5-9-81 को 15,000/- रुपये का चेक आया तब भी उनके खाते में 400/- रुपये की राशि कम पड़ी थी एवं श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल ने श्री अशोक कुमार गुप्ता क्लर्क के खाते से 400/- रुपये का विज्ञावल फार्म लेकर आपके खाते में जमा कराया था क्या आपको मनमोहन कान्त अग्रवाल ने 400/- रुपये कम होने की बात नहीं बताई। इस पर हरी राम शर्मा ने कहा कि उसके पास आज के पहले कोई रुपया लेने नहीं आया और न उसे उसे इसकी सूचना दी गई। उसे तो आज ही इस बात का पता लगा था और उसने आज ही 400/- रुपये अशोक कुमार गुप्ता को दिये हैं। इस साक्षी से भी विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की गई है और प्रति परीक्षा में भी साक्षी ने मूल परीक्षण के कथनों को ही दोह-

राया है। इस साक्षी से भी सुझाव के रूप में ऐसे प्रश्न नहीं किये गये जिससे श्रमिक के विरुद्ध उसका मिथ्या कथन करने का कोई कारण हो। ऐसे भी सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये कि श्रमिक मनमोहनकान्त अग्रवाल ने 30,000/- रुपये का विज्ञावल फार्म बिना पास बुक पेमेंट करने के लिए उसने निवेदन नहीं किया हो। इसलिए यह साक्षी भी निष्पक्ष कोटि का सत्यवादी साक्षी पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि 5-9-81 को जब 15,000 रुपये का चेक हरी राम शर्मा का प्राप्त हुआ उसे भी मनमोहन कान्त ने ही खाते में पोस्टिंग किये बगैर टोकन बुक में ही इन्द्राज करके भुगतान करवा दिया था। उक्त विषय में भी श्री जी. के. गुप्ता का कहना है कि उसे बुक्स मिलाते समय बुकिंग करते वक्त कैलाश चन्द जैन स्पेशल ग्रासिसटेंट ने 15,000 रुपये का चक रैफर किया और कहा कि इसको पोस्टिंग खाते में नहीं हुई है और बैलेंस लगभग 400/- रुपये से कम है। साक्षी कहता है इस पर उसने मनमोहन कान्त से पूछा कि इसकी पोस्टिंग किये बगैर यह कैसे पास किया और जब खाते में पोस्टिंग नहीं हुई तो फोलियो नम्बर कसे डाले इस पर मनमोहनकान्त ने स्पष्टीकरण दिया कि जल्दी में हरीराम जी शर्मा 15,000 रुपये का चेक लेकर आये थे तथा उस समय काम का रश था तो बिना खाते में पोस्टिंग टोकन बुक में एंट्री कर दी। साक्षी कहता है कि उसे मनमोहनकान्त ने कहा था कि उसे लेजर फोलियो का नम्बर जुबानी याद था। 400/- रुपये पर भी 15,000/- रुपये के चेक का पेमेंट श्री मनमोहन कान्त अग्रवाल द्वारा करने पर जब इस साक्षी ने श्रमिक को कहा कि हरीराम शर्मा को बुलवा लिया जाय और 400/- रुपये का कोई चक उनसे मंगवाकर जमा खर्चा पूरा किया जाये तो मनमोहन कान्त ने साक्षी को यह बताया कि हरी राम शर्मा इस समय साईट पर गये होंगे और मिल नहीं सकेंगे तथा वह उन्हें अच्छी तरह जानता है और उनसे रुपये लाकर जमा करवा देगा अभी किसी प्रकार से चेक पास करवा दीजिये। साक्षी कहता है इस पर उसने श्रमिक को कहा कि किसी अन्य के खाते में बलेंस हो तो उससे 400/- रुपये का जमा खर्च करके 15,000/- रुपये के चेक की फिलहाल डैबिट एंट्री कर दी जाये और जिस खाते से 400/- रुपये लिये जायें उसे बाद में दे दिये जायें। तत्पश्चात् ही श्री अशोक गुप्ता ने इस श्रमिक के कहने से अपने खाते से 400/- रुपये का विज्ञावल फार्म हरीराम जी शर्मा के खाते में जमा कराने हेतु दिया। इस विषय में अशोक कुमार गुप्ता का भी प्रबन्धक पक्ष की तरफ से परीक्षण हुआ है जो तत्कालीन समय में उक्त शाखा में क्लर्क कम गोदाम कीपर थे। श्री गुप्ता का कहना है कि उसने 400/- रुपये का विज्ञावल मनमोहन कान्त के कहने से हरीराम शर्मा के लिए दिया था क्योंकि 15,000 का चेक हरीराम शर्मा का आया था और उसके खाते में 400/- रुपये कम पड़ रहे थे। साक्षी कहता है करीब डेढ़ बजे दिन वह करंट काउंटर पर खड़ा हुआ था उस समय कैलाश जी जैन के सामने मनमोहन कान्त जी ने कहा था कि 400/- रुपये कम पड़े रहे हैं जिस बाबत कैलाश जी ने लेजर देखा और मैनेजर साहय को सूचित किया

तो मैनेजर साहिब कैलाश जी को टेबिल पर आये और हरी राम जी शर्मा का खाता देखा जिसमें 400/- रुपये बलेंस कम था। साक्षी कहता है इस पर मैनेजर साहिब ने कहा कि सेविंग बैंक में ओवर ड्राफ्ट हो नहीं सकता, अगर किसी के अकाउंट में पैसा हो तो 400/- रुपये ट्रांसफर करा ले। मैनेजर साहिब ने पार्टी की बुलाने की बात भी कही थी लेकिन मनमोहन कान्त अग्रवाल ने कहा कि इस समय पार्टी को बुलाना संभव नहीं होगा, सोमवार को बुला लेंगे। साक्षी कहता है उसने मनमोहन कान्त जी से पूछा कि आपके खाते में बैलेंस नहीं हो तो मैं अपने खाते से विड्रावल दे दूँ। इस पर 400/- रुपये का विड्रावल फार्म प्रदर्श एम-8 श्री मनमोहन कान्त जी ने भरा। अशोक कुमार गुप्ता यह भी कहते हैं कि वह हरीराम शर्मा से परिचित नहीं था और उसे 14-9-81 तक 400/- रुपये वापस नहीं दिये। 14-9-81 को उसकी मुलाकात हरीराम शर्मा से बैंक में हुई थी जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गुप्ता जी आप ही हैं और 400/- रुपये आप ही ने हमारे खाते में जमा कराये थे। साक्षी कहता है कि मैंने इस पर कहा था कि 400/- रुपये का विड्रावल मनमोहन कान्त जी को दिया था जो उसने आपके खाते में जमा करावाये। साक्षी कहता है उसका मनमोहन कान्त जी से कोई झगड़ा नहीं है और वे एक दूसरे की काम में सहायता भी करते हैं। इस साक्षी से भी श्रमिक प्रतिनिधि ने विस्तारपूर्वक प्रति-परीक्षा की है। साक्षी कहता है कि उसने 400/- रुपये वापस नहीं आने पर मनमोहन कान्त जी और बाबूलाल आर्य से टेलीफोन पर बात की थी और उसे यह जवाब मिला कि हरीराम जी से सम्पर्क नहीं हो पाया है। साक्षी कहता है कि उसे 400/- रुपये मनमोहन कान्त जी के घर पर हरीराम जी ने दिये थे। इस प्रकार यह साक्षी भी निष्पक्ष कोटि का सत्यवादी साक्षी है और इसके कथनों पर भी अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

16- नियोजक पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य के विपरीत श्रमिक की तरफ से श्री बाबूलाल आर्य का बयान प्रति-परीक्षा में हुआ है जो 1981 में वादग्रस्त शाखा पर कार्यवाहक विशेष सहायक के पद पर था। साक्षी कहता है कि उसने घटना के एक माह बाद 30,000/- रुपये के फ्राड का मामला सुना था, वाऊचर गुमने की चर्चा भी हुई थी। साक्षी कहता है उसे हरीराम शर्मा ने बताया कि 720/- रुपये का चैक दिनांक 9-9-81 को बैलेंस नहीं होने से लौटाने पर हरीराम शर्मा उसके पास आया था और अपना खाता देखना चाहता था और इस साक्षी ने अपनी सीट पर खाता मंगवाकर हरीराम शर्मा को दिखाया था तथा हरीराम शर्मा के मांगने पर उसने वाऊचर मंगाकर भी दिखाये थे और 30,000/- रुपये की ऐन्ट्री के अलावा खाते की शेष ऐन्ट्रियाँ हरीराम ने स्वीकार की थी। साक्षी कहता है 30,000 रुपये का वाऊचर गुम होने के कारण वह हरीराम जी को नहीं दिखा पाया और उन्हें मैनेजर की कबिन तक ले गया और गोपाल कृष्ण जी गुप्ता मैनेजर से हरीराम शर्मा की बात करवा दी। गुप्ता जी ने भी हरीराम जी को कहा कि 18-8-81 के वाऊचर इधर उधर हो गये हैं, तलाश कर रहे हैं मिलने पर

आपको दिखा दिये जायेंगे। फिलहाल आप अपनी पास बुक ले आइये ताकि हम उसे देख लें। हरीराम शर्मा ने पासबुक लाने से इंकार कर दिया और बार बार वाऊचर दिखाने की कहने लगे। इस पर गुप्ता जी ने हरीराम जी को कहा कि हम हैड आफिस को इतला कर चुके हैं, जो जवाब आयेगा आपको बता दिया जायेगा। बाबू लाल आर्य ने यह भी कहा है कि उसे उपरोक्त शाखा के पास ही पान की दुकान पर अशोक कुमार गुप्ता और मनमोहन कान्त अग्रवाल मिल गये और बताया कि हरीराम शर्मा के खाते में पैसे कम होने की वजह से एक चैक लौट रहा था तो गोपाल कृष्ण जी के कहने से 400/- रुपये उनके खाते में जमा करवा दिये हैं। वो पार्टी कैसी है, उसने पैसे लेने हैं। साक्षी कहता है इस पर वह अशोक गुप्ता को हरीराम शर्मा के घर ले गया परन्तु वे घर नहीं मिले। श्रमिक के उक्त साक्षी ने भी प्रबन्धक पक्ष के कथन की हो पुष्टि की है और इससे श्रमिक पक्ष को बजाय प्रबन्धक पक्ष को ही लाभ होता है। इस साक्षी के सामने 30,000/- रुपये की घटना नहीं हुई थी इसलिए इस घटना बाबत इसने कोई कथन नहीं किया है। मनमोहन कान्त अग्रवाल ने भी जांच के दौरान प्रति रक्षा में कथन किया है और कहा है कि उसने हरीराम शर्मा का 30,000 रुपये का विड्रावल 18-8-81 को लेंड आवर्स में नहीं लिया था। बिना पास बुक पेमेंट करने का प्रश्न है तो उस बाबत अधिकारी से आदेश लेकर ही टोकन इश्यू किया था। प्रति परीक्षा में श्रमिक कहता है हरीराम जी कभी कभी विड्रावल फार्म के साथ पास बुक नहीं लाते थे। श्रमिक यह स्वीकार करता है कि 30,000 रुपये का विड्रावल फार्म हरीराम जी नहीं लाये थे और ही कोई सज्जन लाये थे जिसको वह नहीं जानता। तत्पश्चात यह भी कहता है कि उसने श्री आचार्य जी को यह नहीं कहा कि यह विड्रावल लेने वाले हरीराम जी नहीं हैं। साक्षी कहता है कि आचार्य जी के पूछने पर उसने कहा था कि वह हरीराम जी शर्मा को ग्राहक के रूप में जानता है तथा वे बैंक के अच्छे ग्राहक हैं। श्रमिक यह भी स्वीकार करता है कि हरीराम जी शर्मा को 15,000/- का चैक पास हुआ था, उनके खाते में 400/- रुपये का कम बलेंस था और यही 400/- रुपये अशोक गुप्ता ने विड्रावल द्वारा दिये थे। श्रमिक कहता है कि उस रोज उसके किसी खाते में 400/- रुपये से अधिक बैलेंस नहीं था। यह भी कहता है कि उसीने 400/- रुपये का ट्रांसफर वाऊचर एक्ट 589 का हरीराम शर्मा के खाते में जमा कराने का बनाया था। श्रमिक यह भी स्वीकार करता है कि जब 720/- रुपये का चैक वापस लौटा था तब हरीराम शर्मा ने उसे इस बाबत कहा था और पूछा था कि उसका चैक कैसे लौटा दिया। श्रमिक द्वारा यह कहने पर कि बैलेंस नहीं था, इसलिए लौटा दिया, हरीराम जी ने कहा कि उसके खाते में काफी बैलेंस होना चाहिए। खाता दिखाओ। श्रमिक उस समय क्लियरन्स में बैठा हुआ था इसलिए उसने हरीराम शर्मा को श्री बाबूलाल आचार्य को रैफर कर दिया। जिसने उन्हें खाता दिखाया। श्रमिक के उपरोक्त समस्त कथनों से भी प्रबन्धक पक्ष के कथनों की ही पुष्टि होती है। श्रमिक का एक मात्र कथन

यह है कि 18-8-81 को 30,000/- रुपये का विज्ञावल 2.00 बजे बाद नहीं आया बल्कि 2.00 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आया था। मेरी राय में इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि किसी भी साक्षी ने यह नहीं कहा है कि 30,000 रुपये का विज्ञावल आते ही घड़ी से समय चैक किया गया हो। निर्विवाद रूप से 30,000 रुपये का विज्ञावल फार्म 18-8-81 को 2.00 बजे के आसपास ही आया था और उसके उपरांत बैंक में कोई लेन देन नहीं हुआ इस बाबत टोकन बुक प्रदर्श एम-3 का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें 30,000 रुपये की प्रविष्टि सबसे आखिर में क्रम सं. 21 पर की हुई है। संभवतः अंत में जब उस दिवस के लेन-देन का टोटल हो रहा था तब यह 30,000 रुपये का लेन देन हुआ था इसलिए 30,000 हजार रुपये की राशि का उल्लेख उचित जगह छोड़े बिना बीच में घुसेड़कर किया गया है। अशोक कुमार गुप्ता ने जांच के दौरान अपने परीक्षण में कहा है कि टोकन बुक में इन्द्राज सं. 18 व 19 उसके द्वारा की गई है क्योंकि उस समय मनमोहनकान्त जी सीट पर नहीं थे। एम-3 टोकन बुक की शेष सभी प्रविष्टियां मनमोहनकान्त की ही करी हुई हैं। इसलिए उपरोक्त समस्त प्रोलिखिक एवं मौखिक साक्ष्य से श्रमिक पर लगाये गये दोनों आरोप झलीभांति साबित हो जाते हैं, तथा श्री जैन योग्य श्रमिक प्रतिनिधि का यह अंतिम तर्क भी अस्वीकार किया जाता है।

17. श्री जैन का एक तर्क यह था कि श्रमिक की पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकी गई हैं जबकि द्विपक्षीय समझौते 19-10-66 के नियम 19.6 (डी) के अनुसार भावी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड देने का प्रावधान नहीं है तथा एक ही इन्कीमेंट रोका जा सकता है। अपने कथन के समर्थन में श्री जैन ने 1981 (2) एस. एल. आर. 33 तथा 1983 (2) एस. एल. आर. 410 के न्याय दृष्टान्त का उल्लेख किया है। मैंने उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों का अति सूक्ष्म रीति से अध्ययन किया तो प्राया कि वे भारतीय संविधान की धारा 311 के अन्तर्गत दिये गये तथा उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों में जो सेवा नियम लागू थे उनके अनुरूप ही उक्त न्याय दृष्टान्तों में निर्णय दिये गये हैं। विवेचनाधीन विवाद में 19-10-66 का द्विपक्षीय समझौता लागू है जिसके नियम 19.16 (डी) में वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है जिसका यह मतलब नहीं निकाला जा सकता कि एक ही वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के रोकने का ही प्रावधान है क्योंकि माईनर मिसकण्डक्ट के लिए नियम 19.8 (सी) के अनुसार छः माह से अधिक अवधि के लिए वेतन वृद्धि नहीं रोकी जा सकती जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मेजर मिसकण्डक्ट के लिए तो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने को कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। जहां तक दुराचरण की प्रकृति का प्रश्न है, इस श्रमिक द्वारा नियमों का उल्लंघन करके तथा श्री आचार्य, बैंक अधिकारी को यह विश्वास दिलाकर आदेश दिया लिया गया है कि खाताधारक श्री हरीराम शर्मा को यह श्रमिक पहले से जानता है और इस प्रकार बिना पास बुक पेमेंट के आर्डर करवा लिये। जांच के

दौरान अपने बयानों में तो श्रमिक स्वीकार करता है कि 18-8-81 को 30,000 रुपये का विज्ञावल लेते समय स्वयं हरीराम शर्मा नहीं आये थे परन्तु यह तथ्य श्री पी. एल. आचार्य को श्रमिक ने नहीं बताया बल्कि श्री आचार्य को तो यही आश्वासन दिया गया कि 30,000 रुपये का विज्ञावल फार्म स्वयं श्री हरीराम शर्मा लेकर आये हैं जो किसी कारण वश पास बुक नहीं लाये हैं और पुराने अच्छे ग्राहक भी हैं जिन्हें श्रमिक अच्छी तरह से जानता है और इसी आश्वासन पर श्री आचार्य ने बिना पासबुक पेमेंट का आदेश दिया था। उक्त परिस्थिति से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस श्रमिक ने गम्भीर दुराचरण किया था और बैंक का एक कर्मचारी होने के नाते श्री पी. एल. आचार्य को विश्वास में ले लिया था तथा श्री हरीराम शर्मा स्वयं के आये बिना ही विज्ञावल फार्म पर अदायगी के आदेश करवा लिये। मेरी राय में आरोप को उपरोक्त प्रकृति के अनुसार पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकने का दण्ड अनुचित एवं अत्यधिक नहीं है क्योंकि बैंक को 30,000 रुपये की हानि हुई है और बैंक की साख गिरी है तथा बैंक नियमों का उल्लंघन हुआ है।

18. श्री जैन श्रमिक प्रतिनिधि का एक तर्क यह था कि नियमों की अवहेलना तो श्री पी. एल. आचार्य ने की थी जो ही बिना पासबुक विज्ञावल फार्म पर अदायगी का आदेश देने के लिए अधिकृत थे जिनकी दो वेतन वृद्धियां रोकी गईं जिन्हें भी तत्पश्चात वापिस ले लिया गया। नियोजक प्रतिनिधि ने दिनांक 23-8-84 के आदेश की फोटो प्रति पेश की है जिसके द्वारा भी आचार्य की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकी गई हैं। उक्त आदेश वापिस नहीं लिया गया। श्री आचार्य ने तो इस श्रमिक के आश्वासन पर भी और इस बात पर विश्वास करके ही बिना पासबुक पेमेंट का आदेश दे दिया था इसलिए श्री आचार्य द्वारा दिया गया दुराचरण उतनी गंभीर प्रकृति का नहीं है जितनी कि इस श्रमिक का था। श्री आचार्य द्वारा तो इतना ही अपेक्षित था कि वे आदेश करने से पूर्व यह निश्चित कर लेते कि खाता धारक हरीराम शर्मा स्वयं ही विज्ञावल फार्म लेकर आये थे जो श्री आचार्य ने इस श्रमिक के आश्वासन देने पर नहीं किया था। अतः इन परिस्थितियों में इस श्रमिक को दिया गया दण्ड भी मेरी राय में अत्यधिक एवं अनुचित नहीं है।

19. अन्य कोई तर्क मेरी समझ किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

20. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है :
“19-12-84 के आदेश द्वारा भी मनमोहन कान्त अग्रवाल की पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकने का दण्ड देना उचित एवं बेवध है और यह श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।”

21. उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को भेजा जाए।

जगत सिंह, पीछसीन अधिकारी

नई दिल्ली, 12 मई, 1992

का.आ. 1369 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[(संख्या एल-12011/60/89-आई आर (बी-1)]

मुभाष चन्द शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 12th May, 1992

S.O. 1369.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 12-5-92.

[No. L12011/60/89 IR(B-I)]

S. C. SHARMA, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 133/89

रैफरेंस : भारत सरकार श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12011/60/89-आई आर. (बी) दिनांक 6-12-89

श्री चांदमल शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा मारफत श्री सन्तोष भटनागर, 18 अर्जुनपुरी, इमलीवाला फाटक, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, 56 सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

-- प्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह जी, आर.एच.जे. एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री सन्तोष भटनागर

अप्रार्थी की ओर से

दिनांक अवार्ड : 20-12-91

अवार्ड

भारत सरकार ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक

विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

“Whether the action of the management of Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank in terminating the services of Shri Chandmal Sharma w.e.f. 10-6-1988 and that too without paying any compensation under the provisions of Industrial Disputes Act, is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?”

2. श्री चांदमल शर्मा, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संबोधित किया है ने जरिये कलेम प्रकट किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति 8-6-87 को दैनिक वेतन भोगी चपरासी के पद पर अप्रार्थी ने अपनी मांग शाखा में की थी और 9-6-88 को मौखिक आदेश द्वारा सेवा मुक्ति कर दिया। श्रमिक का कहना है कि उसने 10-6-89 को अप्रार्थी को एक पत्र लिखकर निवेदन किया कि वह गरीब आदमी है और उस पर पूरे परिवार का बोझ है और उसे पुनः सेवा में लिया जाए परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया, तत्पश्चात् 23-7-88 को शाखा के व्यवस्थापक श्री शर्मा ने बैंक में बुलाकर बुरी तरह डराया व धमकाया तथा कहा कि 9-6-88 को तारीख में त्याग पत्र लिख दो नहीं तो बैंक से चोरी के झूठे आरोप में बंद करवा दूंगा तथा उसे व उसके परिवार को बरबाद कर दूंगा। श्रमिक कहता इस पर उसने त्याग पत्र लिख दिया और तत्पश्चात् उसी रोज उक्त घटना का समस्त विवरण लिखते हुए पत्र अप्रार्थी बैंक को भेजा कि उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं लिखा है तथा उसकी नौकरी अन्यत्र कहीं नहीं लगी है तथा उसे पुनः सेवा में लिया जाये। 30-7-88 को भी एक स्मरण पत्र द्वारा अप्रार्थी को उक्त विषय में लिखा गया था परंतु कोई ध्यान नहीं दिया। श्रमिक कहता है 9-6-88 को समाप्त हुए एक कलेंडर वर्ष में उसने 240 दिवस से अधिक सेवा कर ली थी फिर भी उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया न ही उसे किसी दुराचरण के कारण सेवा मुक्त किया। सेवा मुक्ति के उपरांत भी अन्य व्यक्तियों को रखा गया है इसलिए धारा 25-एफ और 25-एच का उल्लंघन किया है। श्रमिक की प्रार्थना है कि सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाए और उसे सेवा मुक्ति की दिनांक से ही सवेतन नियोजन में लिया जाए क्योंकि वह सेवा मुक्ति की तारीख से ही बेरोजगार बैठा है।

3 अप्रार्थी नियोजक ने जरिये यह प्रत्युत्तर तो स्वीकार किया है कि 8-6-87 को श्रमिक को दैनिक वेतन भोगी चपरासी के पद पर रखा गया है। प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर उसे उस रोज का वेतन अदा कर दिया जाता और आगामी दिवस पर नई नौकरी दी जाती थी। नियोजक के अनुसार 8-6-88 तक श्रमिक ने बैंक में काम किया है और 9-6-88 को श्रमिक के अन्यत्र लाभकर कार्य मिलने पर बैंक का कार्य करने में असमर्थता प्रकट की और लिखकर दिया कि उसे बैंक सेवा मुक्त समझा जाए। यह भी कहा है कि 23-7-88

को श्रमिक बैंक में बुलाकर नहीं डराया धमकाया और न ही 9-6-88 की तारीख का त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया। नियोजक के अनुसार धारा 25-एफ व एच लागू नहीं होती है और श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

4 अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक चांद मल ने अपना शपथ पत्र पेश कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-4 फोटो प्रतियां पेश की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री एम. के. शर्मा, शाखा प्रबन्धक ने शपथ पत्र पेश किया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है और प्रालेखिक साक्ष्य में एम-1 तथाकथित त्याग पत्र की फोटो प्रति पेश की है। तत्पश्चात् मैने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना। निर्विवाद रूप से इस श्रमिक ने 8-6-87 से 8-6-88 तक बैंक से सेवा की थी। विवादक बिदु यह है कि क्या प्रदर्श एम-1 श्रमिक ने स्वेच्छा से दिया था अथवा शाखा प्रबन्धक ने श्रमिक को डरा-धमकाकर 23-7-88 को एम-1 त्याग पत्र लिखवाया था। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि श्रमिक चांदमल शर्मा ने क्लेम के अनुसार ही अपने शपथ पत्र में भी दर्ज किया है कि 23-7-88 को उसे शाखा प्रबन्धक श्री एम. के. शर्मा ने बैंक में बुलाया और चोरी के झूठे आरोप में बंद करवाने की धमकी देकर 9-6-88 को दिनांक में एम-1 त्याग पत्र लिखवाया गया। श्रमिक से विस्तारपूर्वक प्रति-परीक्षा यहीं की गई तथा 23-7-88 को डरा धमका कर त्याग पत्र लिखाने बाबत नाम मात्र की भी प्रति परीक्षा नहीं की है। श्रमिक यह स्वीकार करता है कि एम-1 पर उसके दस्तखत हैं और कलमी है जो उससे जबदस्ती लिखवाया था। नियोजक प्रतिनिधि का एक मात्र तर्क यह था कि श्रमिक ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की। मेरी राय में पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एम-1 त्याग पत्र डरा धमकाकर नहीं लिखाया गया हो विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि अन्यत्र नौकरी लगने बाबत न तो एम-1 में कोई उल्लेख किया गया है और न ही श्रमिक से इस विषय में कोई प्रति-परीक्षा की गई है यहां तक कि नियोजक साक्षी ने भी इस विषय में कुछ नहीं कहा। अगर वास्तव में श्रमिक की अन्यत्र कहीं नौकरी लग गई होती तो 10-6-88 को ही वह प्रदर्श डब्ल्यू-1 पत्र नियोजक को क्यों लिखता। डब्ल्यू-2 पत्र 23-7-88 को भी श्रमिक द्वारा नियोजक को लिखा गया था जिसमें उसी रोज शाखा प्रबंधक द्वारा डरा धमकाकर 9-6-88 की तारीख में त्याग पत्र लिखाने का उल्लेख है। डब्ल्यू-3 पत्र दिनांक 30-7-88 का है जिसमें भी उपरोक्त तथ्यों की ही पुनरावृत्ति है। डब्ल्यू-4 पत्र 6-8-88 का है जिसके द्वारा भी नियोजक को श्रमिक ने निवेदन किया था कि उसने स्वेच्छा से त्याग पत्र नहीं दिया है बल्कि शाखा प्रबंधक ने डरा धमकाकर 23-7-88 को त्याग पत्र 9-6-88 की तारीख में लिखवाया है। क्लेम के प्रत्युत्तर की चरण सं. 4 में नियोजक ने 30-7-88 और 6-8-88 के पत्र प्राप्त होना स्वीकार किया है परंतु फिर भी इन पत्रों के उत्तर नियोजक द्वारा नहीं दिये गये जिसे ही श्रमिक के कथनों में

सत्यता का आभास होता है। एक अन्य परिस्थिति भी श्रमिक के पक्ष में जाती है। श्री एम. के. शर्मा शाखा प्रबन्धक प्रति परीक्षा में स्वीकार करते हैं कि टूटू शाखा के चपरासी बाबू लाल ने मुख्यालय के आदेश से 8-6-88 को झांग शाखा में ज्वोइन कर लिया था। साक्षी के अनुसार झांग शाखा पर दो चपरासी नहीं रखे जा सकते थे। उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब 8-6-88 को बाबू लाल ने झांग शाखा में ज्वोइन कर लिया था तो इस श्रमिक के लिए कोई जगह खाली नहीं थी फलस्वरूप उसे 9-6-88 से काम पर नहीं लिया। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाय कि एम-1 त्याग पत्र श्रमिक ने स्वेच्छा से लिख दिया था तो भी यह अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। इस विषय में एम. के. शर्मा शाखा प्रबन्धक ने प्रति-परीक्षा में कहा है एम-1 पर त्यागपत्र नियमानुसार मंजूर करने का उल्लेख नहीं है, आदेश भी नहीं निकले। साक्षी का कहना है कि मैने तो त्याग पत्र मंजूर नहीं किया। मुख्यालय द्वारा त्याग पत्र मंजूर करने बाबत ना तो क्लेम के प्रत्युत्तर में और ना ही प्रालेखिक अथवा मौखिक साक्ष्य पेश की गई इसलिए एम-1 त्याग पत्र अभी तक मंजूर भी नहीं हुआ है। अतः प्रत्येक दृष्टिकोण से परखने पर मेरी राय में 9-6-88 से श्रमिक को काम पर नहीं लेना धारा 25-एफ की अवहेलना है क्योंकि श्रमिक की छटना किसी दुराचरण के लिए नहीं की गई थी और उसने 9-6-88 को समाप्त हुए एक कलण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी की ली थी, इसलिए वह धारा 25-एफ के लाभकारी प्रावधानों का अधिकारी भी था जिसकी पालना नहीं की गई है इसलिए यह सेवा मुक्ति स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो जाती है। परंतु मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के संदर्भ में यह श्रमिक पिछला बकाया वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है :

“श्रमिक चांद मल शर्मा को तारीख 10-6-88 से की गई सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और यह श्रमिक उक्त पद पर पुनः नियोजित घोषित किया जाता है। उसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है परंतु उसे सेवा मुक्ति की दिनांक से सेवा में लेने की तारीख तक का वेतन नहीं मिलेगा। नियोजक उसे अंदर तीन माह सेवा में ले लेंगे तथा नोशनल फिक्सेशन करते हुए नियमानुसार वेतन देंगे। 100 रुपये खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है।”

5. उक्त आशय का अवाई पारित किया जाता है जो भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 6 मई, 1992

का.आ. 1370:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार

भारतीय खाद्य निगम, मद्रास के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-5-92 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-42012 (10)/84-डी V/आई.आर. (सी-II)]

राजा लाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 6th May, 1992

S.O. 1370.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Food Corporation of India, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on the 1-5-92.

[No. L-42012(10)|84-D. V|IR(C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,
TAMIL NADU, MADRAS.

Tuesday, the 28th day of January, 1992

PRESENT :

THIRU M. GOPALASWAMY, B. Sc., B. L.,
Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 7 of 1985

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workman and the management of Food Corporation of India, Madras).

BETWEEN :

Thiru K. Kannan,
C/o. Shri K. Anandaraju,
East Street, Tiruchanpalli P.O.
Shembanarkoli (via)
Thanjavur District.

AND

The Regional Manager,
Food Corporation of India,
Regional Office,
No. 5, Greams Road, Madras-600006.

Reference : Order No. L-42012(10)|84-D. V, dated 16-1-1985 of the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Monday, 13th day of January, 1992 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru R. Arumugam for Thiru-

valargal Amar and Dolia and R. Arumugam, Advocates appearing for the workman and of Thiru V. N. Balasubramanian, Advocate for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

AWARD

This dispute between the workman and the management of Food Corporation of India, Madras-6 arises out of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in its Order No. L-42012(10)|84-D. V. dated 16-1-1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the following issue :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Regional Office, Madras in terminating the services of Shri K. Kannan, Skilled Mason Class-A vide their letter dated E/Civil/16/72, dated 10-5-74 with effect from 16-5-74 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. The petitioner Thiru K. Kannan alleges as follows : The Petitioner was employed by the Respondent as Maistry Class-I from 22-11-1972. He was transferred from one place to another now and then. He has been re-designated by an order dated 9-4-1974 as Skilled Mason and his wage increased. Though his wage was calculated on a daily rate basis, he was paid the total wages monthly once. He has worked for more than 300 days in the course of twelve months prior to 16-5-1974. He has been illegally terminated from service with effect from 16-5-1974, by order dated 10-5-1974. Provisions of the Industrial Disputes Act have not been followed in terminating his service. He has sent several letters to the Respondent requesting that he should be reinstated in service in the same way as some of his juniors who were also terminated along with the Petitioner have been reinstated in service. To one of this letters, Respondent sent a reply letter dated 16-8-1979 alleging that the actual position would be intimated to him in due course. Finally, the Petitioner approached the Labour Commissioner, Madras for conciliation. Conciliation talks failed and hence this reference. The order of termination dated 10-5-1974 is void and illegal. The Respondent did not give any notice or notice pay and compensation in accordance with the Industrial Disputes Act. The Respondent has also violated the rule 'last come first go' in effecting the retrenchment and giving re-employment. The Respondent has not honoured the seniority rule. Hence award may be passed setting aside the termination order, reinstating the Petitioner in service and give him all benefits along with continuity of service.

3. The Respondent states in its counter as follows : The Petitioner was purely a daily rated temporary employee (i.e.) N.M.R. worker. He was given employment without being sponsored by the Employment Exchange. The rules do not permit the transfer of the Petitioner from a post at one place to a post at another place and also do not provide for re-designating him as alleged. In accord-

ance with the Employment Exchange Act and also the Food Corporation of India Regulations, 1971, the Respondent cannot retain an NMR worker or temporary worker beyond 89 days. In keeping with the Regulations, the Petitioner was terminated with effect from 16-5-1974. As he was not a permanent worker and the work he did was not of a continuous nature he was terminated for valid reasons. The question of seniority cannot arise in the case of N.R.R. workers. The Petitioner should have impeached the alleged juniors who were reinstated after termination. The Petitioner has wantonly delayed commencement of conciliation proceedings and kept quiet till 1982. He is liable to prove that he sent several letters to the Respondent seeking re-employment. Some employees working in Arkonam have been retained as they were recruited through the Employment Exchange. The Industrial Disputes Act has not been violated in any manner in dealing with the Petitioner. The Petitioner is bound to prove his averments. Hence this industrial dispute is liable to be dismissed.

4. The Point for determination is :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Regional Office, Madras in terminating the service of Shri K. Kannan, Skilled Mason Class-A vide their letter dated E/Civil/16/72, dated 10-5-1974 with effect from 16-5-74 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?

5. The Petitioner-worker Thiru K. Kannan was examined as W.W.1. The Respondent Food Corporation of India did not examine any witness. Exs. W-1 to W-14 were marked.

6. The fact that the Petitioner has worked as a Maistry from 22-11-1972 and that he was redesignated as a Skilled Mason are admitted and proved. Ex. W-3 dated 9-4-1974 has enhanced the status of the Petitioner and six more Masons working in Sembankoil/Karaikal by re-designating them as Skilled Masons entitled to claim Rs. 7/- as daily wage. The Petitioner's service was terminated with effect from 16-5-1974 along with six co-workers under Ex. W-44 order dated 10-5-1974. The reason for termination which amounts to retrenchment in terms of the Industrial Disputes Act is given as "economy measure". W.W.1, the Petitioner-worker in his evidence total that he has sent to the respondent the letters whose copies are Exs. W-5, W-7 and W-8 and W-9. Letter, Ex. W-9 dt. 8-6-82 along with identical letters addressed to the different officers of the Respondent have been sent under the certificate of posting Ex. W-14. In respect of one of the letters sent by the Petitioner some time in July, 1979. The Respondent has sent Ex. W-6 reply dated 16-8-1979, wherein it was stated that the Petitioner would be intimated the position in due course of time and that he need not enter upon any further correspondence. The fact that some of the workers who are juniors to the Petitioner have been reinstated after their terminations is admitted by the Respondent in the course of cross-examination of W.W. 1.

7. When the matter was dealt with in conciliation proceedings, on the basis of the Petitioner's

letter dated 13-7-1983, the Respondent filed Ex. W-11, dated 6-9-1983 before the Commissioner of Labour. In this reply statement the Respondent has remarked that the Petitioner had worked for 307 days continuously in the preceding twelve months and that he has moved the conciliation officer after about eight years delay.

8. The Respondent has taken umbrage under the provisions of Employment Exchange Act and Staff Regulations, framed under Food Corporation of India Act. The provisions of Industrial Disputes Act have to prevail over the Employment Exchange Act and the Staff Regulations. Admittedly, the Respondent did not follow the provisions of Chapter V-B, particularly Section 25-N in terminating the Petitioner's services (i.e.) in retrenching him from service along with six others Ex. W-3 and other documents describe the job/status of the Petitioner as work-charged staff. The Respondent has not attempted at all to justify that any work or project in respect of which the Petitioner was employed has been finished and that similar work was not continuously available for retaining him for that work. The termination order termly states that in view of the economy being adopted, the workers including the Petitioner were terminating from service with effect from 16-5-1974. In a big organisation like the Respondent, there must be relevant records to show what was the economy practised and what was the scheme thereof which entailed petitioner's termination. The Industrial Disputes Act speaks termination of service in terms of a contract of employment and the stipulations therein. The Respondent has not shown any order of employment or contract of employment defining the terms and stipulations. Any provision in the Food Corporation of India Staff Regulations, 1971 cannot take away the right of the Petitioner to advance notice, notice pay and retrenchment compensation. Hence, it is very obvious that the Respondent has illegally retrenched the Petitioner from employment without giving valid reasons and by not observing the provisions of the Industrial Disputes Act. Just because the Petitioner was not sponsored by the Employment Exchange when he was employed by the Respondent, the Petitioner's case cannot suffer. The Petitioner's plea that the Respondent has retrenched some of the juniors of the Petitioner and that those juniors were again re-employed is not seriously disputed by the Respondent and it was rather admitted half-heartedly. Taking the facts and the evidence into consideration, I believe that the Petitioner has proved that he has been illegally retrenched and hence he must deemed to have been in service with effect from 16-5-1974. The very fact that the Respondent has given a reply like Ex. W-11, even though it is evasive reveals that the Respondent was aware of the real position and that it had also given re-employment to some of the retrenched workers who are juniors to the Petitioner. The claim of the Respondent that no seniority list need be maintained in the case of N.M.R. workers is not acceptable. In adhering to the Industrial Disputes Act, whatever may be the status of a worker his seniority among similarly placed workers is a matter to be recorded by the employer. Hence I accept the Petitioner's case and hold that he is entitled to the reliefs

claimed. Considering the delay in raising the dispute I am of the view that the Petitioner would have to be satisfied with half the back wages for the period upto 30-6-1983. He shall be paid wages prevailing from time to time for the job of Skilled Mason. This point is answered accordingly.

9. In the result, an award is passed directing the Respondent to reinstate the Petitioner in service giving him continuity of service with full back wages from 1-7-1983 and other attendant benefits and half the back wages from 16-5-1974 to 30-6-1983. No costs.

Dated, this 28th day of January, 1992.

THIRU M. GOPALASWAMY, Industrial Tribunal
Witnesses Examined.

For Workman: W.W.1—Thiru K. Kannan.

For Management.—None.

Documents Marked.

For Workman :

Ex. W1|30-10-73—Transfer order issued to W.W.1

Ex. W-2|5-11-73—Relieving order issued to W.W.1

Ex. W-3|9-4-74—Revision of daily wages and Redesignation order issued to W.W.1.

Ex. WW-4|10-5-74—Order of Termination.

Ex. W-5|6-7-78—Application from W.W.1 to the Management praying to consider him for appointment of Kalasi in Modern Rice Mills.

Ex. W-6|16-8-79—Reply by the Management to W.W.1

Ex. W-7|15-1-81—Letter from W.W.1 to the Management.

Ex. W-9|8-6-82 —do—

Ex. W-9|8-6-82 —do—

Ex. W-10|13-7-83—Letter from W.W.1 to the Regional Labour Commissioner, Madras.

Ex. W-11|6-9-83—Reply by the Management.

Ex. W-12|24-3-84—Conciliation Failure. Report.

Ex. W-13|7-9-77—Circular issued by the Management regarding regularisation of adhoc daily rated employees (Xerox copy)

Ex. W-14|—Acknowledgements from the Zonal Manager F.C.C., Madras-6 and 5 others.

For Management: Nil.

नई दिल्ली, 11 मई, 1992

का.आ. 1371:— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार, कानरा बैंक के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध निवोजक और उनके

कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12011/69/87-डी-2 (ए)]

वी.के. वेंगुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 11th May, 1992

S.O. 1371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Mgt. of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 8-5-1992.

[No. L-12011/69/87 DII(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, AT BOMBAY

PRESENT :

Shri P.D. APSHANKAR, Presiding Officer

REFERENCE NO. CGIT NO. 2/3 OF 1988

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of Canara
Bank

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employer : Mr. R. S. PAI, Advocate.

For the Workmen : Shri Madan Phadnis Advocate.

INDUSTRY : Banking STATE : Karnataka
Bombay dated the 23rd April, 1992

AWARD

The Central Government by their order No. L-12011/69/87-DII(A) dated 31-12-1987 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

“Whether the action of the management of Canara Bank is justified in stopping w.e.f. 1-7-1983 the special allowance paid at the rate of Rs. 96 per month to the Special Assistance posted at Delhi and Calcutta centres of the Bank? If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?”

2. The case of the Canara Bank Staff Union, which is a minority union as disclosed from statement of claim (Ex. 2) filed by its General Secretary, in short is thus:

The service conditions of the bank employees are governed by the ‘Sastri Award’, ‘Desai Award’ and the

different Bipartite Settlements. In the year 1964, the Bank Management had paid to the Special Assistants, then known as the Sub-Accountants, posted at their branches at Delhi and Calcutta an Additional Special Allowance of Rs. 25 in addition to the special allowance of Rs. 65 payable to them under the Desai Award. The payment of this additional special allowance was started by the bank of its own volition, and it was not granted as a result of any demand placed by the Union or by the workmen of the Bank. Under the first Bipartite Settlement of 1966 which modified the Desai Award, the special allowance payable to the sub-accountants was increased to Rs. 75. The bank management however continued paying the additional special allowance to the special assistants working at the Delhi and Calcutta branches in addition to the special allowance of Rs. 75. Under the second Bipartite settlement of 1970, the Special Allowance was increased to Rs. 91, and the Bank Management increased the additional Special allowances to Rs. 31, and continued paying it to the Special Assistants at Delhi and Calcutta. Under the third Bipartite Settlement of 1979, the special allowance was increased from Rs. 91 to Rs. 293. Firstly the Bank management then stopped paying the additional special allowance, to the Special Assistants. However, at the intervention of the Regional Labour Commissioner (Central), Bombay, the additional special allowance was increased by the Bank to Rs. 96, and the Bank denied paying that additional special allowance in addition to the special allowance of Rs. 293 to the Special Assistants at Delhi & Calcutta. The System of paying the additional special allowance was started by the Bank of its own will and volition, without any demand by any Union and without any Bipartite Settlement provisions. Under the fourth Bipartite settlement which was signed on 17-9-1984 the special allowance was increased from Rs. 293 to Rs. 456 to the Special Assistants. However while implementing that fourth Bipartite settlement, the bank management withdrew the payment of the additional special allowance of Rs. 96 which was being paid to the Special Assistants since 1964. Thereafter the union approached the Regional Labour Commissioner, (Central), Bombay, for the intervention in the matter. As the conciliation proceedings ended in failure, the Central Government made the Reference as above.

3. The said Staff Union further alleged thus :

The payment of the said additional special allowance was in vogue since 1964 to 1984 i.e. for 20 years. Therefore, by practice, the custom and the usage the said payment has matured in the service condition, and that service condition cannot be changed without following the due procedure as laid down under Section 9A of the Industrial Disputes Act. The bank management did not follow that procedure before withdrawing the said additional Special allowance which was being paid in addition to the special allowance to the Special Assistance of the branches at Delhi and Calcutta. The staff union therefore lastly prayed that this Tribunal should direct the Bank Management to continue paying the additional special allowance to the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta from the date it was withdrawn, and the bank's action in withdrawing that special allowance be held as unjust and illegal.

4. The Canara Bank Employees Union, which is a majority union, by their statement of claim (Ex. 3) supported the claim of the staff union.

5. The Canara Bank by their Written Statement (Ex. 4), and the further Written Statement (Ex. 5) to the statement of claim of the majority union, opposed the said claim of both the unions, and in substance contended thus :

The subject matter of the present Reference is covered by the fourth Bipartite Settlement of 1984. That settlement covers all the demands of the workmen, such as, scales of pay, dearness allowance, City compensatory allowance, special allowance payable to the workmen etc. This settlement is still in existence. Under that fourth Bipartite settlement, the special allowance payable to the Special assistants has been increased from Rs. 293/- to 456/- payable to the special assistants. Under the third Bipartite Settlement of 1979, the special allowance was of Rs. 293 and the additional special allowance was of Rs. 96 and as such the total amount was of Rs. 389. Under the fourth Bipartite Settlement, the special allowance is increased to Rs. 456. Therefore as the amount of the Special allowance is increased under the fourth Bipartite settlement it has met with the demands of the workmen and the union's demand for the continuation of the Additional Special allowance of Rs. 96 to the Special Assistants at Delhi and Calcutta is unjust, improper and illegal, as the Special Assistants are getting much more amount under the fourth Bipartite settlement as compared to the amount of the Special Allowance under the 3rd Bipartite Settlement. As such no industrial Dispute exists in the present case and the Reference is bad-in-law.

6. The Bank Management further contended thus :

In or about the year 1964, the bank had its branches mostly in the Southern parts of India. The bank desired of opening the branches in the Northern India and accordingly new branches were opened at Delhi and Calcutta. At that time it was found that the sufficient number of supervisory staff with adequate experience was not readily available locally. Under the State Award the Bank Management could not on its own accord transfer the supervisory staff, without their consent from the Southern States to Delhi and Calcutta. Therefore the Bank management introduced the payment of Additional Special allowances at the rate of Rs. 25 per month to as special assistants who were to be posted in Delhi and Calcutta on transfer, in addition to the special allowance payable for that post. Initially the Bank Management extended that incentive for the period of one year without prejudice to their right to withdraw it at the appropriate time. The Bank management

has reviewed the payment of their additional special allowance from time to time. Under the second Bipartite settlement of 1970 that additional Special allowance of Rs. 25 was increased to Rs. 31 per month, without prejudice to the Bank's right to withdraw it at the appropriate time. That additional special allowance of Rs. 31 was again increased to Rs. 96 after the execution of the third Bipartite Settlement of 1979. The said additional special allowance was granted by the Bank only as a voluntary payment by the bank and without prejudice to its right to withdraw it as and when deemed fit. After the signing of the fourth Bipartite Settlement dated 17-9-1984, the Bank Management found that there was the change in the circumstances and as such it was not necessary to continue paying the additional Special allowance, as the special allowance granted under the third Bipartite Settlement of 1978 was substantially increased to 4.56 under the fourth Bipartite Settlement of 1984. As such the Bank Management did not continue paying the additional special allowance of Rs. 96 after the signing of the fourth Bipartite settlement of 1984. That payment of additional special allowance was not a condition of service of the special assistant as alleged by the Union. There was no need to comply with the provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act for the withdrawal of the payment of the additional special allowance. The Special assistants at Delhi and Calcutta are not entitled to the additional special allowance as a matter of right or under the conditions of services applicable to them. The Bank had to maintain a parity in service conditions with regard to all its employees at other branches besides the branches at Delhi and Calcutta. Therefore the special assistants at Delhi and Calcutta were and are not entitled to claim the additional special allowance after the signing of the Fourth Bipartite settlement of 1984. The additional special allowance was being paid by the Bank of its own will not volition and not under the Desai Award of any of the Bipartite settlements. Therefore the Bank lastly contended that its action in the matter is just and proper and prayed for the rejection of the prayer of the unions.

7. The Issues framed at Ex. 6 are :

- (1) Whether the stopping of the Special allowance of Rs. 96 to the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta by the Canara Bank with effect from 1-7-1983 amounted to the violation of the provisions contained in Sec. 9A of the Industrial Disputes Act ?
- (2) Whether in view of the Fourth Bipartite settlement dated 17-9-1984, the Canara Bank is under no obligation to pay, and cannot be directed to pay the special allowance, as above claimed by the employees of the Bank?
- (3) Whether no industrial dispute concerning the

special allowance in question, exists in law between the said Bank and its employee ?

- (4) Whether the reference in question is bad in law ?
 - (5) Whether the question regarding the continuance or stoppage of the said special allowance was discussed before the said Fourth Bipartite Settlement was signed by the parties ?
 - (6) Whether the action of the management of Canara Bank is justified in stopping w.e.f. 1-7-1983 the special allowance paid at the rate of Rs. 96 per month to the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta Centres of the Bank ?
 - (7) If not, to what relief the concerned workmen are entitled ?
 - (8) What Award ?
8. My findings on the said Issues are;
- (1) Yes.
 - (2) The Bank Can be directed.
 - (3) Industrial dispute exists.
 - (4) No.
 - (5) No.
 - (6) No.
 - (7) As per Award below.
 - (8) As per below.

REASONS

ISSUE No. 1 :

9. Shri G.M.V. Nayak, the General Secretary of the Staff Union filed his affidavit (Ex. 9) in support of the case of the Union, and he was cross-examined on behalf of the Bank Management. Shri P. N. Ramesh, the law officer of the Bank, filed his affidavit (Ex. 11) in support of the case of the Bank Management, and he was cross-examined on behalf of the Union. According to the union, the stopping of the Additional Special allowance of Rs. 96 to the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta by the Bank with effect from 1-7-1983, i.e. after the signing of the Fourth Bipartite settlement, is in violation of the provisions contained in section 9A of the Industrial Disputes Act. I find that it is so. Admittedly the special allowance was being paid to the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta in 1964 and onwards in addition to the Special allowance of Rs. 65. The additional special allowance was thereafter increased to Rs. 31 in 1970, and was again increased to Rs. 96 in 1978, and it was being paid till 1984. Thus, the additional special allowance, in addition to the regular special allowance, was being paid by the Bank Management to the special assistants posted at Delhi and Calcutta for 20 years, from 1964 to 1984. This additional special allowance was being paid by the Bank management of its own will and volition, and without any demand from any of the workmen or any of the unions. Further, there was no provision under the Desai Award or under any of the four Bipartite settlements regarding the payment of that additional special allowance. As that additional special allowance was being paid voluntarily by the Bank for 20 years to the special assistants, the payment of that additional special allowance has become a service condition of the special assistants posted at Delhi and Calcutta.

10. Section 9A of the Industrial Disputes Act lays down that "No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any

workman in respect of any matter specified in the Fourth Schedule, shall effect such change, without giving to the workman likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected". Item No. 1 of the fourth Schedule is as regards the Wages including the period and the mode of payment. The item No. 3 relates to compensatory and other allowances. The item No. 8 relates to the withdrawal of any customary concession or privilege or change in usage. So the notice under Section 9A of the Industrial Disputes Act is absolutely essential in case there is a change regarding the conditions of service relating to the said three items, i.e. Item Nos. 1, 3, and 8. Admittedly, no such notice was given by the Bank management to the workmen affected by that change, i.e. to the Special Assistants at Delhi and Calcutta. Under the fourth Bipartite Settlement, the Special Assistants are to get the special allowance of Rs. 456. However the payment of the additional special allowance of Rs. 96 has been stopped by the Bank Management after the signing of that fourth Bipartite settlement of 1984. Therefore, the Special Assistants at Delhi and Calcutta, even though they would be getting much more amount as the Special allowance under the fourth Bipartite Settlement as compared to the amount under the third Bipartite Settlement still they are deprived of the additional special allowance of Rs. 96 and as such, their proposed wages are reduced. Therefore this falls under the item 1 of the fourth Schedule. The Special Assistants at Delhi and Calcutta were getting the additional special allowance which was not being paid to special Assistance at other places, and as such, the special Assistants at Delhi and Calcutta were getting that additional special allowance as the compensatory allowance, and therefore that additional special allowance falls under the item 3 of the fourth Schedule. As that additional Special allowance was being paid by the Bank management for 20 years continuously from 1964, it has turned into a customary concession, and an usage. Therefore it falls under the item 8 of the fourth Schedule. Hence, before stopping the payment of the Additional special allowance after the signing of the fourth Bipartite Settlement of 1984, notice under section 9A of the Industrial Disputes Act was absolutely essential to the Special Assistants at Delhi and Calcutta, which admittedly was not given in the present case. Therefore, that action of the bank management was not just and proper and was against the provisios of Section 9A of the Industrial Disputes Act.

11. In this connection, my attention was drawn on behalf of the applicants to the case reported in 1961-2-LLJ page 130 Dalmia Cement (Bharat) Limited. It was held in that case by the Supreme Court that :

"In view of such long and continued practice, the Tribunal was also right in holding that such encashment of privilege leave has ripened into a condition of service and when in 1957, the management refused to some of such applicants this was without lawful reasons."

In that case the practice of the encashment of the leave salary was started in 1948, and the management had tried to stop that practice in 1957, i.e. after 9 years. This period of 9 years was considered by the Supreme Court as of a Long and Continued practice. In the present case the additional special allowance

was being paid by the bank management to the Special Assistants at Delhi and Calcutta for 20 years from 1964 to 1984, and as such, it became a customary concession available to the Special Assistants at Delhi and Calcutta, and that concession cannot be withdrawn unilaterally unless the necessary notice is given to the employees concerned under Section 9A of the Industrial Disputes Act, which was admittedly not given in the present case.

Issue No. 1 is, therefore, found in the affirmative.

12. According to the bank management, in view of the fourth Bipartite settlement dated 17-9-1984, the bank was not under any obligation to pay, and cannot be directed to pay the additional Special allowance as claimed by the employees. However, this contention of the bank management is not true and correct. Admittedly the payment of that additional special allowance was not started by the bank management under any of the Awards or under any of the Bipartite settlements. Further, the payment of that additional special allowance was not stopped because of any provisions contained in the fourth Bipartite settlement of 1984. The payment of additional special allowance was started by the bank of its own volition without any demand by the workmen, and it was stopped by the bank itself without any discussion with the workmen. Therefore even after the signing of the fourth Bipartite settlement of 1984, the bank is under obligation to pay, and can be directed to pay the additional special allowance to the employees concerned.

Issue No. 2 is found accordingly.

13. Issue No. 3.—According to the bank management, no industrial dispute concerning payment of additional special allowance exists between the parties. However it is not so. Under Section 2(k) of the Industrial Disputes Act, 'industrial dispute' means any dispute or difference between the employers and the workmen which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labour of any persons. In the present case the conditions of labour of the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta implied that they were to get the additional special allowance in addition to the regular special allowance. Therefore an industrial dispute existed between the parties regarding the issue in question.

Issue No. 3 is found accordingly.

14. Issue No. 4.—According to the Bank Management, the present reference is bad-in-law. However, I find that it is not so. Under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, whenever the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may refer that dispute or any matter appearing to be connected therewith or relevant thereto to the Tribunal for adjudication. In the present case, the Central Govt. was of the opinion that an industrial dispute existed in the matter, and as such, it made the Reference as above. Therefore, the present reference is not bad-in-law.

Issue No. 4 is therefore found in the negative.

15. Issue No. 5.—Admittedly the question regarding the continuance or stoppage of the payment of that additional special allowance was not discussed with any workmen before the fourth Bipartite settlement was signed by the parties.

Issue No. 5 is therefore found in the negative.

16. Issue No. 6.—According to the Bank Manage-

ment, they had voluntarily started paying the additional special allowance to the employees posted at Delhi and Calcutta because of the then service conditions prevailing, i.e. the necessary persons for the posts of special assistants were not available for their posting at Delhi and Calcutta, and that the said circumstances have now changed, and therefore the bank management was right in stopping the payment of the additional special allowance to the Special Assistants at Delhi and Calcutta. Even then, this action is contrary to the provisions of law and is not legal and valid. Further, according to the bank management, in case the payment of the additional special allowance is to be continued only as regards the special assistants posted at Delhi and Calcutta, then that would be discriminatory, as the additional special allowance is not being paid to the special assistants at other places. This is true. Even then, the stopping of the payment of the additional special allowance is contrary to law, and hence, the bank must continue paying it till it is stopped after discussion with the workmen.

17. In the result, the action of the Bank Management in stopping the payment of the additional special allowance at the rate of Rs. 96 per month with effect from 1-7-1986 to the special assistants posted at Delhi and Calcutta is not just and proper.

Issue No. 6 is found in the negative.

18. Issue No. 7.—Therefore, the Special Assistants at Delhi and Calcutta are entitled to the arrears of the payment of the additional special allowance due from the date they were withdrawn by the bank

Issue No. 7 is found accordingly.

19. Even though the action of the Bank Management in question is not just, proper and legal, still in order that there is no discrimination regarding the payment of the special allowance to the special Assistants posted at Delhi and Calcutta and to the Special Assistants posted at other places in India, the bank management should hold discussions with the Unions in question, and the unions in question, to avoid any discrimination in the matter should respond to the request of the Bank Management in fairness, and then only the bank management should discontinue paying additional allowance to the special assistants posted at Delhi and Calcutta. These are only observations, and not directions.

20. In the result, the following Award is drawn.

AWARD

The action of the management of Canara Bank in stopping w.e.f. 1-7-1983 the special allowance paid at the rate of Rs. 96 per month to the the Special Assistants posted at Delhi and Calcutta centres of the bank is not just, legal, and proper.

The bank management is hereby directed to pay the arrears of the additional special allowance to the concerned special assistants of Delhi & Calcutta from the date they were withdrawn, within 3 months.

The parties to bear their own costs of this Reference.

P. D. APSHANKAR, Presiding Officer
नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1372:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

(संख्या 12012/127/85 डी-2(ए))

वी.के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी-5

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1372.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Mgt. of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-12012/127/85-D.II(A)]

V.K. VENUGOPOLAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई. टी. 28/86

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश

क्रमांक एल-12012/127/85-डी II (ए)

दिनांक 20-5-1986

श्री पी. आर. सरन मार्फत जनरल सैक्रेटरी, बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन राजस्थान स्टेट के/आफ बैंक आफ बड़ौदा, एम. आई. रोड, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

सहायक महाप्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, पोस्ट बैग नं. 9 डी-38/ए, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह जी, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री अशोक परिहार

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज शर्मा

दिनांक अवार्ड : 27 फरवरी, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्नविवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है:—

क्या बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर के प्रबन्धतंत्र का खजांची-एवं-लिपिक श्री पी. आर. सरन पर संचयी प्रभाव से 4 वेतन वृद्धियां रोकने का दंड लगाना न्यायोचित है? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

2. जनरल सैक्रेटरी, बैंक आफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन, राजस्थान राज्य, जयपुर, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संव संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि प्रार्थी श्री पी. आर. शरण की नियुक्ति क्लर्क-कम-कैशियर के पद पर विषक्षी बैंक द्वारा 18-12-80 को की गई थी और उसने जौहरी बाजार जयपुर की शाखा में सेवा प्रारंभ की थी। तत्पश्चात् श्रमिक का स्थानान्तरण डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा शाखा में कर दिया गया। उक्त श्रमिक ने

विपक्षी बैंक की सेवा ईमानदारी, मेहनत व लगन से की थी और उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। सन् 1982 में मिलवाड़ा शाखा में श्री आर. पी० गांधी शाखा प्रबन्धक थे जो बहुत ही विमर्शकल किस्म के थे। जिनका व्यवहार अधीनस्थ स्टाफ के साथ कभी भी अच्छा नहीं रहा। श्री गांधी अधीनस्थ स्टाफ को हैरान व परेशान करते रहते थे और दुर्भाग्यवश यह श्रमिक भी श्री गांधी के जाल में फस गया जिसने अपनी होशियारी से इस श्रमिक के विरुद्ध 18-5-82 को निराधार एवं प्रस्ता आरोप पत्र दिलावा दिया जिसका उत्तर भी श्रमिक ने देते हुए आरोपों को अस्वीकार किया और स्पष्टीकरण दिया परंतु श्री गांधी शाखा प्रबन्धक ने प्रबन्धकों तथा उच्चधिकारियों को प्रभावित करते हुए जांच अधिकारी के रूप में श्री एस. के. गांधी की नियुक्ति करवा दी जो भी श्रमिक के प्रति पूर्वाग्रह रखता था तथा शाखा प्रबन्धक श्री आर. पी. गांधी के इशारों पर ही चला रहा था। प्रार्थी संघ का कहना है कि जून 1982 में श्रमिक का "स्थानान्तरण सुजानगढ़ शाखा में कर दिया गया जबकि आरोपों की जांच मिलवाड़ा और जयपुर में ही की गई। जिससे भी श्रमिक को हैरान और परेशान होना पड़ा। हालांकि जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को अनुपालना नहीं की गई थी और 9-3-84 को जांच पूरी हो गई थी फिर भी श्रमिक को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से ही जांच रिपोर्ट 17-10-83 को दी गई जो की इसी तथ्य का द्योतक है कि जांच अधिकारी का श्रमिक के प्रति पूर्वाग्रह था। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकाला है वो भी जांच में ली गई साक्ष्य के विपरीत था और अनुचित थे। जांच अधिकारी ने श्रमिक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरक्षा साक्ष्य पर सही विचार नहीं किया। प्रबन्धक पक्ष की तरफ से एक सात साथी श्री आर. पी. गांधी शाखा प्रबन्धक का हो बयान था क्योंकि प्रबन्धक पक्ष को दूसरा साक्षी श्री पूजीलाल सिरयासिद्ध पक्षद्रोही हो गया था और अपने पूर्व में दिये हुए बयानों से मुकर गया था जो उसने शाखा प्रबन्धक के निर्देशों से दिया था। श्रमिक ने प्रतिरक्षा में जो साक्षी मेश किये थे उनसे प्रबन्धक पक्ष ने कोई जिरह नहीं की और इसलिए प्रतिरक्षा में प्रस्तुत साक्षियों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। प्रार्थी संघ यह भी कहता है कि श्रमिक को दण्डादिष्ट करने हेतु प्रबन्धक पक्ष कटिबद्ध था और उसी लिए 16-11-83 को कारण बताओं नोटिस दिया गया कि क्यों न 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोक दी जाय। हालांकि श्रमिक ने विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया था फिर भी 6-1-84 के आदेश द्वारा 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोक दी गई। उक्त आदेश के विरुद्ध श्रमिक ने अपील भी प्रस्तुत की थी जो भी बिना सुनवाई के किए निर्णित की गई और 4 की बजाय 3 वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया जिससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रबन्धक पक्ष ने श्रमिक को सबंक सिजाने का मन बना

रखा था। प्रार्थी संघ के अनुसार प्रबन्धक पक्ष द्वारा की गई पूरी कार्यवाही अवैध, अनुचित व असदभावनापूर्वक है और जो शोषण करने व श्रम विरोधी नीति की द्योतक है। इसलिए 6-1-84 एवं 17-7-84 के आदेश अमान्य किये जायें और उनके द्वारा रोक दी गई वन वृद्धियों को राशि खर्च सहित दिलाई जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने अपने क्लेम के प्रत्युत्तर द्वारा क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि प्रार्थी संघ द्वारा खड़ा किया गया विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि यह सामान्य श्रमिकों से संबंधित नहीं है तथा प्रबन्धक द्वारा स्थाई आदेशों के अनुसार की गई कार्यवाही बाबत औद्योगिक विवाद नहीं उठाया जा सकता। रैफरेंस 4 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का किया गया है जो भी श्रमिक को सुरक्षा की पूरी सुविधा देने के उपरांत जांच में ली गई साक्ष्य से दुराचरण साबित होने पर ही सेवा शर्तों के अनुसार की गई है इसलिए भी यह विवाद चलने योग्य नहीं है। गुणावगुण पर भी नियोजक कहता है श्रमिक श्री पी. आर. सारन के विरुद्ध दुराचरण की अनेकों शिकायतें थीं इसलिए उसका पूर्व का सेवा अभिलेख भी ठीक नहीं था। 11-10-83 को श्रमिक के विरुद्ध श्री हनुमानामल ने एक फौजदारी मामला भी दर्ज कराया था। नियोजक का कहना है कि तत्कालीन समय में श्री सारन लेखाधिकारी था और श्री आर. पी. गांधी शाखा प्रबन्धक थे। श्री गांधी के अधीनस्थ स्टाफ के साथ मयूर संबंध थे। वे अधीनस्थ स्टाफ को हैरान व परेशान करने के आदि नहीं थे। इस तरीके की कोई शिकायत कभी भी श्री गांधी के विरुद्ध नहीं की गई थी। श्री गांधी द्वारा मिथ्या आरोप पड़ने का क्लेम में दर्ज कथन भी गलत है और श्री गांधी द्वारा प्रबन्धक पक्ष को प्रभावित करने वाली बात भी गलत है। 18-5-82 के पत्र के आरोप गंभीर प्रकृति के थे और इसीलिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो भी शाखा प्रबन्धक से प्रभावित नहीं था। नियोजक का कहना है कि श्री एस. के. गांधी जांच अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के अनुसार जांच कार्यवाही की थी। श्रमिक श्री पी. आर. सारन का स्थानान्तरण सुजानगढ़ उसकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया था जांच भी मिलवाड़ा में इसलिए की गई क्योंकि उसी शाखा से संबंधित दुराचरण था और तीन चा तारीखों में जांच जयपुर में श्रमिक की सुविधा को देखते हुए की गई थी क्योंकि सुजानगढ़ से मिलवाड़ा की बजाय जयपुर नजदीक था और सुरक्षा में श्रमिक को श्री एम. के. दुबे के बयान कराने थे जो भी चित्तौड़गढ़ नियोजित था उक्त जगह भी मिलवाड़ा की बजाय जयपुर से नजदीक पड़ती थी। जांच के दौरान श्रमिक को अपनी सुरक्षा के लिए उचित एवं पर्याप्त अवसर दिया गया था। परंतु चूंकि जांच अधिकारी का ही स्थानान्तरण जांच के दौरान जयपुर से कोटा हो गया था इसलिए जांच रिपोर्ट देने में कुछ समय लग गया। जांच पत्रावली के निरीक्षण से ही यह स्पष्ट है कि उक्त जांच प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के

अनुरूप की गई है तथा प्रोपर एवं फेयर है। साक्ष्य विधि का यह नियम है कि अकेले साक्षी के कथनों पर निर्भर करते हुए भी आरोप साबित हो सकते हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ उक्त साक्षी के कथनों की पुष्टि करती हों। जांच रिकार्ड पर जांच रिपोर्ट से श्रमिक के विरुद्ध लगाये गये समस्त आरोप साबित हो गये थे। यह गलत है कि श्रमिक का शोषण करने के उद्देश्य से उसे दण्ड देने हेतु प्रबन्धक पक्ष का कोई पूर्वाग्रह हो बल्कि श्रमिक पर जिस गंभीर प्रकृति के आरोप सिद्ध थे उनके लिए तो सेवा मुक्ति का दण्ड देना उचित था परन्तु प्रबन्धक पक्ष ने श्रमिक के प्रति नमी का रुख अपनाते हुए उसकी 4 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ ही स्थाई प्रभाव से रोक दी और अपील अधिकारी ने भी श्रमिक के प्रति सद्भावना का रुख रखते हुए 3 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ स्थाई प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया और इसलिए प्रार्थी संघ का यह कहना गलत है कि श्रमिक का शोषण करने के लिए अनुचित श्रम नीति अपनाते हुए श्रमिक को दण्डित किया गया है। इसलिए उपरोक्त समस्त कारणों से श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

4. दिनांक 29-10-91 को प्रार्थी संघ के प्रतिनिधि श्री अशोक परिहार ने प्रकट किया कि घरेलू जांच की फेयरनेस पर उन्हें आपत्ति नहीं है तथा जांच पत्रावली के निरीक्षण करने के उपरांत भी जांच में अपनाई गई प्रक्रिया को प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुरूप पाया गया इसलिए उस रोज नियोजक द्वारा कराई गई घरेलू जांच प्रोपर एवं फेयर घोषित की गई।

5. घरेलू जांच में ली गई साक्ष्य से श्रमिक पर लगाये गये दुराचरण साबित हैं या नहीं तथा श्रमिक को दिया गया दण्ड भी दुराचरण के अनुपात में है या नहीं इसी बाबत पक्षकारों के प्रतिनिधियों की बहस सुनी और पत्रावली का निरीक्षण किया।

6. दिनांक 18-5-82 को श्रमिक पर निम्नलिखित आरोप लगाये गये थे :—

The following has been reported against you in respect of the period during which you have been working as a Head-Cashier at our Simalwara branch:

On Saturday the 6th February 1982 at about 12 noon Shri R.V. Gandhi, Manager of our Simalwara branch instructed you to release the debit vouchers after figures of cash receipts and payments for the day called out by our declared tallied with the respective scrolls maintained by him. Therefore, Mr. K.B. Patel peon of the branch was instructed by Mr. Gandhi to collect debit vouchers from you and to deliver to Mr. M.K. Dube for writing supplementary etc. You, however, refused to release the debit vouchers inspite of the repeated instructions of the branch manager.

Further on the same day at about 2.00 p.m. you locked the cash cabin with the entire cash lying inside and left the branch and the cash was not closed by you and put in the cash-safe as required under the Banks practices. Thus, you, have not acted in the interest of the bank. The cash book

could not be completed because of non-release of debit vouchers by you on 06-02-1982. Thus you have not obeyed the lawful instructions of the manager and found negligent towards the performance of your duties. On the same day i.e. 6-2-1982 at about 2.55 p.m. when you were called upon by the Manager from outside the premises of the branch through Mr. A.R. Bhoi, Peon of the branch, you refused to open the cash cabin to start the work of closing the cash but insisted upon the Manager to give you in writing for payment of overtime to complete the work. Thereafter on repeated insistence the cash was balanced at 4.55 p.m. All the start members had, therefore, to wait till 4.55 p.m. Thus, you have committed an act of insubordination and put all the Start Members to a great inconvenience.

On Monday the 8th February, 1982, at about 2.15 p.m. after close of business hours of the branch, you were asked by the Manager to release the debit vouchers when the totals of the days cash receipts and payment call out by you tallied with the totals of the respective scroll but you refused to release the vouchers stating that there was some difference, when after sometime you were again instructed to release the vouchers, you did not pay any attention on this a letter was issued to you by the Manager of the Branch. The said letter was accepted by you but you have not given any acknowledgement in token of having received the same which was requested. Mr. K.B. Patel, Peon of the branch when delivered the said letter to you and requested you to return the copy of the letter, you were excited and threw away both the copies of the letter from the cabin towards the Manager and abused the Manager in the words which follows :

(TO JO CHAHE KAR LENA BHEN CHOD)

This was done in presence in two customers. Thus you have insulted the Manager and did not maintain the discipline and decorum at the branch and as such you have not acted in the interest of the Bank. Subsequently, you did not release the debit vouchers till 5.00 p.m. when you could have done it by 2.15 p.m. on the same day, when the cash was tallied. Thus, you resorted to delay tactics and closed the cash late at 6.30 p.m. on 8-2-82 and on account of the said act the working of cash book and supplementary got delayed. Thus you deliberately slowed down your performance wilfully. Your aforesaid act's, if proved amount to gross misconduct under the provisions of Bipartite Settlement. You are, therefore, hereby charged as under :

1. You have disobeyed the lawful orders of Branch Manager wilfully and committed an act of insubordination which is a misconduct in terms of clause No. 19.5(e) of the Bipartite Settlement, 1986.

You have behaved with the Manager of the Branch in an disorderly manner which amount to misconduct as per the clause No. 19.5.0 of Bipartite Settlement of 1966.

3. You have deliberately slowed down your performance wilfully which is a misconduct in terms of clause 19.5(g) of Bipartite Settlement, 1966.

4. You have not acted in the interest of the Bank which is an act of prejudicial to the interest of the Bank and termed as misconduct in terms of clause No. 19.5(j) of Bipartite Settlement, 1966.
5. An enquiry would be conducted against you in respect of aforesaid charges by Mr. M.P. Sharma, Officer at our Regional Office, Udaipur Region, Jaipur who will advise you directly the date, time and place of enquiry.
6. You may, if you so desire, submit to the said enquiry Officer your written statement of defence at least three days before the date of enquiry.
7. You will be permitted to defend at the enquiry by representative of a recognised trade union of Bank employees of which you are a member on the date first notified by the enquiry officer for the commencement of the Enquiry. If you are not a member of any trade union of the bank employees on the said date, you will be permitted to be represented by a representative of a registered trade union of employees of the bank.
8. You will be entitled to produce relevant documentary evidence and examine relevant witnesses in support of your defence and also cross examine relevant witnesses produced by the Bank against you at the said enquiry.
9. Please note, that if you do not attend the enquiry at the date, time and place notified by the enquiry Officer and thereafter as directed by him from time to time, the enquiry may be proceeded with in your absence."

उक्त आरोपों का श्रमिक की तरफ से लिखित जवाब दिया गया था कि 6-2-82 को प्रातः 10 बजे जब वह शाखा में उपस्थित हुआ तो शाखा प्रबन्धक श्री आर. बी. गांधी ने उसे कहा कि आज मुझे आवश्यक कार्यवश (शेयर आदि खरीदने) दोपहर 2 बजे की बस से माण्डली जाकर गुजरात से मोडासा जाना है अतः कैश का काम हर हाल में 12 बजे तक पूरा कर लेना ताकि मैं 12 बजे की बस से मोडासा गुजरात जा सकूँ। आगे उन्होंने कहा कि आज श्री सी. के. शाह (आफीसर) नहीं है अगर वो होता तो 11.15 की बस से ही श्री शाह को कैश तथा ब्रांच की चाबी सौंपकर चला जाता। श्रमिक ने यह भी जवाब दिया कि उसने 6-2-82 को 12 बजे तक कैश का काम पूरा करने की पूरी कोशिश की परंतु कैश का काम पूरा नहीं हो सका और कैश का काम 12 बजे तक समाप्त नहीं होने तथा श्री गांधी के ब्रांच में रुकने के कारण वे मुझपर नाराज हो गये और लताड़ते हुए कहने लगे कि मूर्ख तेरे द्वारा 13 बजे तक कैश का काम पूरा नहीं करने के कारण आज मैं 12 बजे की बस से मोडासा नहीं जा सका अतः अब तू कैश का काम छोड़ दे और एफ. डी. के बैलेंस मिला दे, और

बंद कर दे। श्रमिक कहता है इस पर उसने आदेशानुसार कैश का काम छोड़ दिया और एफ. डी. बैलेंस मिलाने लग गया। श्रमिक कहता है उसने हमेशा की तरह 12.15 बजे डेबिट बाऊचर शाखा के खजांची को लौटाने को श्री गांधी को देने के लिए भेज दिये। लगभग 12.45 बजे शाखा के कैशियर श्री दुबे ने सप्लीमेंटरी लिस्ट दी थी तथा 1.15 बजे कैश का काम भी पूरा कर चुका था इसलिए प्रबन्धकों के आदेशों के अनुसार डेबिट बाऊचर रिलीज नहीं करने जैसा कोई कदम नहीं उठाया। श्रमिक यह भी कहता है कि 06-2-82 को प्रातः 10 बजे से 4.55 तक कैश कबिन छोड़ा ही नहीं था वह तो दोपहर 12 बजे से एफ. डी. बैलेंस मिलाने का ही कार्य कर रहा था और उक्त बैलेंस मिलाने पर शाखा प्रबन्धक के आदेशानुसार 2.55 से 4 बजे तक कैश काउंट करने का कार्य किया तथा 4 बजे से 4.55 तक श्री गांधी द्वारा कैश-री-काउंट तथा चैक करने के पश्चात् कैश जोइंट कस्टडी में अंदर रखवाया। श्रमिक कहता है वह बैंक का वफादार व हितैषी कर्मचारी है। बैंक में ओवरटाइम का प्रावधान ही नहीं है तो वह ओवरटाइम बाबत मांग कैसे कर सकता है। इस संबंध में उसके विरुद्ध बैबुनियाम व निराधार आरोप लगाये गये हैं। श्रमिक कहता है 6-2-82 को समस्त स्टाफ ने 2 बजे तक अपना अपना कार्य पूरा कर लिया था और वे सभी स्वेच्छा से हमेशा की तरह कार्यालय समय समाप्त होने के पश्चात् शाखा में कैरम खेल रहे थे। दिनांक 8-2-82 के आरोप बाबत श्रमिक ने उत्तर दिया है कि उस रोज 10 बजे सुबह शाखा में उपस्थित हुआ तो श्री गांधी ने कहा कि "सारण परसों 6-2-82 को मैं तेरे कारण ही मोडासा नहीं जा सका इसलिए अब मैं तुझे रगड़ कर रख दूंगा तथा पूरी तरह तो परेशान कर दूंगा तथा मैंने तेरी बहुत सी गलतियत क्षेत्रीय प्रबन्धक को कर दी है अतः अब तू जल्दी ही निलंबित होने वाला है। श्रमिक कहता है श्री गांधी की उपरोक्त बातों से दिनभर टेंशन बना रहा और उसे वे बातें बहुत ही बुरी लगी परंतु वह बिल्कुल ही चुप रहा और अपना काम करने लग गया। इसके पश्चात् भी श्री गांधी उसे दिन पर निलंबित करवाने की धमकी देते रहे तथा परेशान करते रहे। श्रमिक के अनुसार उक्त सभी बातें भी श्री गांधी ने स्टाफ के सामने कही थी। श्रमिक ने 8-2-82 का आरोप अस्वीकार करते हुए कहा है कि उसने हमेशा की तरह पेमेंट बाऊचर शाखा प्रबन्धक के आदेशानुसार 2.15 बजे ही श्री के. बी. पटेल को सौंप दिये थे और उस रोज सप्लीमेंटरी और कैश बुक शाम 4 बजे तक कैशियर एम. के. दुबे द्वारा पूरी लिखी जा चुकी थी इसलिए 5 बजे तक पेमेंट बाऊचर रिलीज नहीं करना, कैश में अंतर होना, पत्र की प्रतिनिधि नहीं देना, श्री पटेल पर क्रोधित होने, पत्र की दो प्रतियां फेंकने, प्रबन्धक को गाली देने, प्रबन्धक की ईसल्ट करने, अनुशासनहीनता बरतने, बैंक के हित में कार्य न करने, सप्लीमेंटरी

एवं कैश बुक के न लिये जाने व स्वेच्छा से धोमी गति से कार्य करने के संबंध में जो आरोप लगाये गये हैं वे सब श्री गांधी द्वारा मनाइत, वेबुनिगद एवं निराधार हैं। श्रमिक कहता है उसने श्री गांधी को कोई गाली नहीं दी थी, गाली तो उन्होंने मुझे ही दी थी। लंच समय में दोपहर 2.40 बजे जब उन्होंने मुझे अफारग ही एक पत्र दिया जिसमें अन्य बातों के अलावा अंबार पढ़ने का झूठा आरोप लगाया तो मैंने कहा साहब एक तो अभी लंच का समय है दूसरा आपके आदेशानुसार मैं लंच समय में भी कैश काउंट करने का ही कार्य कर रहा हूँ तो मेरे पर वह यह झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं, इस पर श्री गांधी ने सारे स्टाफ के सामने मुझे कहा कि "साले मेरे सामने बोलता है क्या, काम करता रह नहीं तो भाग चोछ को रागड़ के रख दूंगा।" इस प्रकार गाली मैंने नहीं उन्होंने ही दी थी। 8-2-82 को कैश 6.15 बजे बंद करने के संबंध में श्रमिक कहता है उस दिन से श्री गांधी द्वारा बिना कारण परेशान किये जाने से कैश काउंट करने तथा मिलाने में शाम के करीब 5.10 हो गये थे और 5.10 से 6.30 तक श्री गांधी ने रो-काउंट तथा चैक करने का कार्य किया। इसलिए कैश में देर हो गई, जो 6.30 बजे जोइंट कस्टडी में अंदर रखवाया।

7. मुझे यह देखना है कि दिनांक 18-5-92 के आरोप पत्र में जिन दुराचरणों का उल्लेख किया है, क्या वे जांच के दौरान ली गई साक्ष्य से साबित होते हैं या नहीं। प्रबन्ध पक्ष की तरफ से जांच के दौरान एम. डब्ल्यू-1 श्री पूंजीलाल सिरियासिद्धू तथा एम. डब्ल्यू.-2 श्री आर.बी. गांधी शाखा प्रबन्धक के बयान हुए हैं। जबकि इसके विपरीत श्रमिक की तरफ से भी पूंजीलाल सिरियासिद्धू का बयान भी डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में हुआ है और श्री के.एन. पटेल डी. डब्ल्यू.-3 श्री महेश कुमार दुबे डी. डब्ल्यू.-4 तथा श्री अतनाराम मोई डी. डब्ल्यू. 1 के बयान कराये गये हैं। श्रमिक ने स्वयं ने जांच के दौरान अपना बयान नहीं कराया है। घरेलू जांच में ली गई साक्ष्य का स्तर आपराधिक प्रकरणों की तरह अर्थात् युक्ति युक्त संदेह के स्तर का होना अपेक्षित नहीं है बल्कि दोषाती प्रकरणों की तरह परिस्थितियों के संभावित स्तर का ही होना अपेक्षित है। इसलिए परिस्थितियों की सम्भाव्यता स्तर की साक्ष्य की अपेक्षा रखते हुए ही पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक व प्रालेखिक साक्ष्य का विश्लेषण किया जा रहा है। साक्ष्य विधि का यह भी सर्वमान्य सिद्धान्त है कि साक्ष्य की गणना नहीं की जाती बल्कि विश्वसनीयता को ही तोला जाता है अभिप्राय यह है कि इकलौते किन्तु निष्पक्ष व सत्यवादी साक्षी के कथनों पर भी निर्भर करना सुरक्षित है चाहे उसके विपरीत अनेकों साक्षियों का परीक्षण ही क्यों न करवाया गया हो।

8. एम. डब्ल्यू-2 श्री आर.बी. गांधी दुराचरण साबित करने के लिए प्रबन्धक पक्ष के एक मात्र साथी हैं जिनसे विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा भी की गई है। श्री गांधी ने मूल परीक्षण में कहा है 6-2-82 से वह सिमलपाड़ा शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। इस रोज शनिवार था। सुबह 10 बजे कैश खोला और श्री पी. आर. सारण पीओन

द्वारा उक्त कैश अपने केबिन में ले गये और बैंक का काम शुरू हुआ। जब 12 बजे कैश रिसीट व पेमेंट बंद करवाकर एक दूसरे का कैश, रिसीट व पैमेंट टेली करना था और क्लोजिंग बैलेंस निकलना और कैश मिलाना बाकी थी, श्री पी. आर. सारण उसी वक्त कैश मिला रहे थे, करीब 12.15 बजे मैंने उनको कहा कि आपके केबिन में पेमेंट वाउचर है वे रिलीज कीजिये जिससे कैश बुक सप्लीमेंटरी लिखने का काम किया जा सके। तब उन्होंने मुझे कहा कि जब मेरा कैश आपके क्लोजिंग बैलेंस से मिल जायेगा तब मैं वाउचर रिलीज करूंगा। साक्षी कहता है तब मैंने उसको कहा कि आप कैश मिलाओ और पेमेंट वाउचर बैंक में ही रहते हैं तो आप इन्हें रिलीज कर दीजिए, श्री सारण ने फिर से वही कहा कि जब उसको कैश मिल जायेगा तब पेमेंट वाउचर रिलीज करेगा। साक्षी कहता है उसने 12.30 बजे श्री सारण को फिर कहा कि आप पेमेंट वाउचर रिलीज कीजिये जिस पर उसने जवाब दिया जब मेरा कैश मिल जायेगा तभी मैं पेमेंट वाउचर रिलीज करूंगा। साक्षी कहता है उसने 1.00 बजे करीब फिर वही कहा कि डे बुक व सप्लीमेंटरी का काम रुक रहा है आप वाउचर रिलीज कीजिये तब भी सारण ने वही जवाब दिया कि मेरा कैश मिला नहीं है और मैं वाउचर रिलीज नहीं करूंगा। साक्षी कहता है इस पर उसने श्री सारण को कहा कि आपको कितनी भूल आती है जिस पर श्रमिक ने कहा कि कैश जब मिलेगा जब आपको बता दूंगा। श्री गांधी का कहना है कि सवा बजे व डेढ़ बजे भी श्री सारण से वाउचर रिलीज करने को कहा तो भी वही जवाब मिला कि मेरा कैश मिलेगा तब मैं वाउचर रिलीज करूंगा। बाद में करीब डेढ़ व पौने दो बजे के बीच में वाउचर रिलीज करने के लिए एक लैटर श्री सारण को दिया था तब भी श्री सारण ने वाउचर रिलीज नहीं किये और 2 बजे उसने मुझे यह कहा कि मेरा कैश मिला नहीं है और मेरी ड्यूटी ओवर हो गई है इसलिए मैं जाता हूँ और दो बजे कैश केबिन का लाक लगाकर वह जा रहा था। साक्षी कहता है जब मैंने उसको रोका और कहा कि आपकी ड्यूटी है कि कैश मिलाकर व उसको कस्टडी में रखकर ही जा सकते हो। तब उन्होंने कहा कि क्या आप मुझे ओवरटाईम देंगे। साक्षी कहता है मैंने कहा कि ओवर टाईम देना बैंक की पालिसी में नहीं है इसलिए ओवर टाईम नहीं दे सकता तब श्री सारण ब्रांच छोड़कर चले गये उस समय 2 बजकर 5/10 मिनट हुए थे। साक्षी कहता है उसने उसी वक्त डूंगरपुर ब्रांच आफिस फोन करके उपरोक्त घटना बताई। उन्होंने कहा कि आप लाईटनिंग काल करके जयपुर बात करो। इस पर तुरंत ही लाईटनिंग काल बुक कर जयपुर बात की और उन्हें उपरोक्त घटना बताई तब उन्होंने पूछा कि श्री सारण कहाँ है, मैंने बताया कि वह ब्रांच में नहीं है तो उन्होंने कहा कि पीओन को भेजकर श्री सारण को बुलाओ और जो वह ओवरटाईम मांगें तो ओवरटाईम परमिट कर देना। साक्षी कहता है तब उसने आत्मा राम भोई को श्री सारण को बुलाने भेजा। श्री सारण करीब 2.55 पर ब्रांच में आये और ओवरटाईम के लिए लिखित में लैटर मांगा जो मैंने दिया। साक्षी कहता है श्री सारण ने 4.55 पर कैश मिलाकर उससे कहा कि

जब आप ओवरटाईम रजिस्टर में कन्फर्म करेंगे तब मैं कैश जोइंट कस्टडी में ले जाने दूंगा। साक्षी कहता है ओवरटाईम रजिस्टर 2 बजे से 5 बजे का टाईम श्री सारण ने मार्क किया तब मैंने कहा कि आप ब्रांच प्रेमाईसिस छोड़कर 2.05 पर कैश कैबिन को लाक करके कैश की चाबी लेकर चले गये थे और 2.55 पर आये तो आपको ओवरटाईम 2.55 से 4.55 का ही मिलेगा तब श्री सारण ने कहा कि आप जब तक 2 बजे से 5 बजे तक का मेरा ओवरटाईम कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक मैं कैश जोइंट कस्टडी में नहीं रखने दूंगा। साक्षी कहता है जबाबदार अधिकारी होने से उसे 2 बजे से 5 बजे तक ओवर टाईम कन्फर्म करना पड़ा और कैश जोइंट कस्टडी में रखवा दिया। उसके बाद श्री सारण ने पैमेंट के वाउचर रिलीज किए और सप्लोमेंटरी व डे बुक श्री दुबे ने कम्पलीट की। करीब 5.30 बजे हम ब्रांच बंद कर पाये।

9. दिनांक 8-2-82 के आरोप बाबत श्री गांधी का कहना है कि करीब सवा दो बजे पार्टी आक्स खतम होने के बाद मैंने कैश फिगर्स टेली किये और क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाशा। कैश उस समय तक टैली हुई नहीं थी इसलिये साक्षी कहता है उसने श्री सारण को पैमेंट वाउचर रिलीज करने को कहा। श्री सारण ने उस समय कैश केबिन में अखबार पढ़ते हुए कहा कि उसका कैश मिलेगा तब ही वह पैमेंट वाउचर रिलीज करेगा। साक्षी कहता है 2.30 बजे फिर उसने श्री सारण से कहा कि आपको लंच में जाना हो तो जाओ और वाउचर रिलीज कर दो। इस पर श्री सारण ने कहा कि उसे लंच में नहीं जाना है और कैश मिलेगी तभी वह वाउचर रिलीज करेगा। साक्षी कहता है तब उसने एक लैटर 2.40 पी.एम. पर श्री सारण को श्री कमल नाथ पटेल द्वारा भेजा तो श्री सारण ने लैटर की दोनों प्रतियां अपने पास रख ली। साक्षी कहता है इस पर उसने श्री सारण से कहा कि ओरिजनल लैटर आप ले लीजिये और आफिस कापी पर दस्तखत कर लौटा दीजिये इस पर सारण ने मना कर दिया। साक्षी कहता है उसने श्री पटेल को कहा कि आपको एक लैटर श्री सारण को देने को कहा था जबकि आपने दोनों दे दिये इसलिये आप एक कापी वापस ला दीजिये। तब कमल नाथ पटेल श्री सारण की केबिन के पास गये और आफिस कापी मांगी परन्तु श्री सारण ने श्री पटेल को भी आफिस कापी नहीं दी और मेरी टेबिल के सामने आफिस कापी फेंकी और मुझे गा. 1 दी। “तू चाहे वह कर देना भैनचोद।” उसी वक्त ब्रांच में श्री दुबे, श्री पटेल, श्री पूंजीलाल सिरयासिद्ध, श्री लक्ष्मण मौजूद थे। श्री नितिन शाह जो बाहर खड़ा था उसको भी मैंने अंदर बुलाकर बैठा रखा था। श्री गांधी ने कहा है कि तब उसने कागज पर लिखा कि करीब 2.50 पर जब श्री सारण ने गाली दी थी तो उसका वह साक्षी है। इसके बाद श्री नितिन शाह बाहर चले गये बाद में श्री सारण को कैश पैमेंट वाउचर रिलीज

करने के लिये 3.30 बजे कहा परन्तु उसने पैमेंट वाउचर रिलीज नहीं किये और कहा कि जब उसकी कैश मिलेगी तभी वह वाउचर रिलीज करेगा। श्री सारण ने 5 बजे तक कैश नहीं मिलाई और कहा कि उसे ओवरटाईम देना हो तभी वह कैश मिलायेगा। श्री गांधी ने कहा है कि तब उसने श्री सारण को ओवरटाईम के लिये कागज दिये और श्री सारण ने 6.30 बजे तक का ओवरटाईम मार्क करके कैश टैली करके जोइंट कस्टडी में रखा उसके बाद पैमेंट के वाउचर रिलीज किये। साक्षी कहता है तब उसने कैश बुक व सप्लीमेंटरी का काम पूरा करके करीब 7-7.15 बजे ब्रांच बंद की। श्री गांधी ने यह भी कहा है कि उसने उक्त घटना की सूचना रीजनल आफिस को डी.ओ. द्वारा दी और 8-2-82 का 5 बजे से 6.30 बजे तक का श्री सारण का ओवरटाईम रजिस्टर में उसने कहने से कन्फर्म किया क्योंकि कैश का काम पूरा नहीं हुआ था और उसे भय था कि कल 6-2-82 की तरह घटना न हो जाये।

10. श्री गांधी से विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की गई है और प्रति परीक्षा में भी श्री गांधी ने अपने कथनों की ही पुष्टि करते हुए कहा है कि 6-2-82 के पहले ब्रांच में स्टाफ से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ। 6-2-82 को भी श्री सारण ने 12.15 बजे वाउचर रिलीज नहीं किये थे। श्रमिक प्रतिनिधि के सुझावात्मक प्रश्नों पर श्री गांधी कहता है उसने 6-2-82 को 10 बजे श्री सारण को यह नहीं कहा कि आज वह मोड़ाया जायेगा और न ही उस रोज सारण को कैश के अलावा अन्य कोई कार्य करने के लिये दिया। साक्षी कहता है 6-2-82 की तारीख के एफ.डी. बैलेंस तो श्री सारण ने 10-2-82 को मिलाये थे और अपने अपने बचाव हेतु उन पर 6-2-82 की तारीख डाली थी जिस पर उसने “क्वश्चन मार्क” भी लगाया था। श्री गांधी ने यह भी कहा है कि 6-2-82 को जब श्री सारण ब्रांच छोड़कर मेरी टेबिल के पास से जाने लगे तब मैंने उन्हें रोका था। ओवरटाईम कन्फर्म नहीं करने बाबत प्रति परीक्षा में श्री गांधी ने कहा है कि दिसम्बर 1981 में रीजनल मैनेजर की डूंगरपुर में मीटिंग हुई थी तब आदेश दिया था कि ओवरटाईम बिल्कुल नहीं देना और इस संबंध में रीजनल आफिस जयपुर का एक पत्र भी ब्रांच में प्राप्त हुआ था। साक्षी कहता है जब उसने घटना की सूचना डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक को टेलीफोन पर 2 बजे दी तब सारण को भी बात कराई थी। साक्षी कहता है उसने डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक की इतना ही कहा था कि श्री सारण कैश बिना मिलाये केबिन में कैश छोड़कर जा रहे हैं। इस पर डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक ने कहा कि रीजनल मैनेजर जयपुर से बात करो। साक्षी कहता है उसी समय उसने श्री अरविंद शाह की बात कराई थी और बात कराने के बाद भी श्री सारण ब्रांच छोड़कर चले गये। श्री गांधी ने श्रमिक के

सुझावात्मक प्रश्न को गलत बताया कि श्री सारण ने टैलीफोन पर डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक को यह बताया हो कि उससे दूसरा कार्य लिया जा रहा है। श्री गांधी ने कहा है कि उसने 2.20 मिनट पर जयपुर रीजनल आफिस में भी बात की थी। उस समय स्टाफ के मैम्बर्स मौजूद थे। प्रति परीक्षा में श्री गांधी ने यह भी कहा है कि उसने 2.55 पर जो पत्र श्री सारन को दिया उसमें लिखा था कि आप कैश टैली करो, कस्टडी में रखकर जाओ और ओवरटाइम ले लो। उसके बाद भी श्री दुबे की सहायता से मैंने सप्लीमेंटरी व कैश बुक 5 बजे बाद लिखी थी। साक्षी के अनुसार श्री दुबे ने आनरेरी काम किया था अर्थात् ओवरटाइम को मांग नहीं की।

11. श्री गांधी ने प्रति परीक्षा में पूछे गये किसी भी प्रश्न के उत्तर को टालने का प्रयास नहीं किया है तथा सभी प्रश्नों के उत्तर सीधे व समाधानकारी दिये हैं और प्रति परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आरोप के प्रत्युत्तर में तो श्रमिक ने स्पष्ट दर्ज किया था कि भी गांधी दकियानुसी विचारों के थे और अपने अधीनस्थ स्टाफ से दुर्व्यवहार एवं झगड़ा करने के आदि थे और बिना बात नाराज हो जाते थे। परंतु उक्त तथ्यों बावत श्री गांधी से विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा नहीं की गई है। श्रमिक से अपेक्षा थी कि वह आरोप के प्रत्युत्तर में स्पष्ट अंकित करता कि श्री गांधी ने कब-कब और किस-किस से दुर्व्यवहार अर्थात् लड़ाई झगड़ा किया तथा श्री गांधी से तो उक्त तथ्यों पर सुझावात्मक प्रश्न करना आवश्यक था। श्रमिक ने स्वयं ने तो जांच के दौरान अपना परीक्षण नहीं कराया परंतु श्रमिक की तरफ से सर्वश्री आत्मा राम भोई पूंजीलाल सिरियासिद्धू कमलनाथ पटेल व श्री एम. के. दुबे के परीक्षण हुए थे इसमें से भी किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया कि उनसे श्री गांधी ने कभी कोई लड़ाई झगड़ा किया हो या दुर्व्यवहार किया हो इन चारों साक्षियों ने श्रमिक के उस कथन की ही पुष्टि में साक्ष्य दी है कि 6-2-82 को सुबह ही श्री गांधी ने कह दिया था कि आज उन्हें 12 बजे की बस से मोडासा जाना है और हर सूरत में 12 बजे से पहले कैश का काम पूरा हो जाना चाहिये। इन साक्षियों ने यह भी कहा है कि 12 बजे तक कैश का काम पूरा नहीं हुआ इसलिए श्री गांधी श्री सारन से नाराज हो गये और उन्हें धमकियां देने लगे। साक्षियों ने यह भी कहा है कि भी सारण बांच छोड़कर बीच में बाहर नहीं गये थे। परंतु मेरी राय में साक्षियों के उक्त कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक ने टैलीफोन पर बात करना और जयपुर रीजनल आफिस में टैलीफोन पर बात करने वाले तथ्यों की पुष्टि तो श्रमिक के उक्त साक्षियों से भी होती है। अगर वास्तव में श्री सारण ने वाउचर रिलीज कर दिये होते और कैश भी नियमानुसार जोइंट कस्टडी में जमा करा दिया होता तो डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक अथवा आर.एम. जयपुर से टैलीफोन पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सारण के कहने से

ही उक्त साक्षी उसे बचाने के उद्देश्य से कथन कर रहे हैं। श्री गांधी के मौखिक कथनों की पुष्टि ओवरटाइम रजिस्टर से तथा डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक एवं आर. एम. जापुर से टैलीफोन पर सूचित करने के तथ्यों से भी हो जाती है। श्री पूंजीलाल सिरियासिद्धू ने भी अपने बयान में कहा है कि फरवरी 1982 में वह भीवानाई मोहनराम भाई तिनतवाड़ा के यहां नौकरी करता था। 8-2-82 को वह बैंक आफ बड़ौदा की सिमलवाड़ा शाखा में ड्राफ्ट लेने गया था। पैसे जमा कराकर बैंक में चला गया। 2.30 बजे ड्राफ्ट लेने बैंक में आया तो उस समय श्री आर. बी. गांधी ने एक कागज चर्रासी द्वारा श्री सारण को दिया, श्री सारण ने वह कागज फैंक दिया और कहा "तू चाहे वह कर देना भेनचोद" साक्षी कहता है इतना उसने सुना था और उसके बाद ड्राफ्ट लेकर बैंक से चला गया। पोछे क्या हुआ उसे पता नहीं। इस साक्षी से भी विस्तारपूर्वक प्रति परीक्षा की गई है और कहा है कि वह बैंक में ड्राफ्ट ड्यूटी लेने प्रायः आया करता था। कोई दूसरा बैंक का काम नहीं करता था। करीब 11-11.30 बजे रुपये जमा कराये थे। उस रोज मैनेजर साहब ने बताया कि तुम 2.30 बजे आकर ड्राफ्ट ले जाना। साक्षी कहता है इस पर वह दुबारा 2.30 बजे बैंक में आया था उस समय ड्राफ्ट बना हुआ था परंतु उसपर दस्तखत नहीं हुए थे इसलिए मैनेजर साहब ने कहा 2-5 मिनट बैठो अभी ड्राफ्ट देना है। इस पर वह मैनेजर साहब की सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया जिन्होंने कुछ काम करके थोड़ी देर बाद हस्ताक्षर करके ड्राफ्ट दे दिया। प्रति परीक्षा में भी यह साक्षी कहता है उसने सामने मैनेजर साहब ने एक कागज चर्रासी श्री पटेल को दिया और कहा कि इसे पी० आर० सारन को दे दो। साक्षी कहता है मैनेजर साहब ने भी सारन को कहा कि कागज वापस करो इस प्रकार श्री सारण ने कागज को मैनेजर साहब को तरफ फैंक दिया और दोनों झगड़ने लगे। इस पर श्री गांधी ने पहले डूंगरपुर टैलीफोन करने लगे। साक्षी कहता है तब मैंने कहा कि मुझे मेरा ड्राफ्ट दे दो और मैं ड्राफ्ट लेकर बैंक से चला गया। हालांकि इस साक्षी ने तत्पश्चात् श्रमिक की तरफ से भी प्रति परीक्षा में बयान दिया है और कहा है कि उसने पहले वाले बयान व कागज पर हस्ताक्षर श्री गांधी के कहने से किये थे। मेरी राय में सारण के प्रभाव में आकर ही इस साक्षी ने बाद के बयानों में पूर्व के बयानों को अस्वीकार किया है। अन्यथा जब इस साक्षी से विस्तार-पूर्वक प्रति परीक्षा की गई थी तब यह अपने मूल कथनों से विचलित नहीं हुआ था और प्रति परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा था। अगर वास्तव में यह साक्षी उस रोज उपस्थित नहीं था तो उसका वहां ड्राफ्ट प्राप्त करना एवं श्री गांधी के पत्र पर हस्ताक्षर करना संभव ही नहीं था।

12. डी. डब्ल्यू -3 कमल नाथपटेल तत्काल न समय में सिमलवाड़ा शाखा में मोशन के पद पर था, ने भी यह स्वीकार किया है कि उसे 4 बजे सारण जी ने कहा कि कैश तैयार हो गया है और करीब 5 मिनट बाद ही श्री गांधी

कैश कैबिन में कैश चैक करने आये और करीब 5 बजे मेरे को कहा कि पटेल कैश अंदर रखवा दो। तब मैंने कैश अंदर रखवा दी। प्रति परीक्षा में भी कमज नाथ कहता है करीब पौने चार बजे श्री गांधी ने एक लैटर मुझे दिया था जो मैंने श्री पी. आर. सारन को दे दिया। उक्त लैटर श्री सारण ने पकड़कर श्री गांधी जी को कहा “गांधी साहब मुझे काहे को खवामबां लैटर दे रहे हो मैं काम तो कर रहा हूँ।” इस पर गांधी जी ने कहा कि “सारण तू मेरे सामने मत बोल तेरे को रगड़ दे रख दूंगा।” यह उल्लेखनीय है कि आरोप के लिखित प्रत्युत्तर में तो श्रमिक ने यह दर्ज किया है कि 8-2-82 को दोपहर 2.40 बजे श्री गांधी ने अकारण ही श्रमिक को पत्र दिया और जब श्रमिक ने कहा कि उस पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो तो स्टाफ के सामने ही श्री गांधी ने कहा कि “साले मेरे सामने बोलता है क्यों, काम करता रह नहीं तो रगड़ कर रख दूंगा।” श्रमिक के उक्त कथनों की पुष्टि उसका कोई भी साक्षी नहीं करता अगर वास्तव में 6-2-82 को मोडासा जाने से वंचित रहने के कारण ही श्री गांधी श्रमिक से नाराज हुए थे तो स्वाभाविक तौर पर 6-2-82 को ही श्री गांधी अपनी नाराजगी प्रकट करते न तो आरोप ने प्रत्युत्तर में और न ही प्रति रक्षा के किसी साक्षी ने अपने कथनों में यह कहा है कि 6-2-82 को मोडासा जाने से वंचित रहने के कारण उस रोज श्री गांधी ने इस श्रमिक के प्रतिरक्षा किसी नाराजगी का कोई प्रदर्शन किया हो। प्रति साक्षियों ने यह तो स्वीकार किया कि 6-2-82 को 5 बजे कैश अंदर रखवाया गया था परंतु इन साक्षियों का यह करना है कि जब 12 बजे मोडासा वाली बस निकल गई तो श्री गांधी ने श्रमिक को कहा कि अब आप बैलेंस निकालो और इसलिए सारण ने एफ डी बैलेंस निकाले फलस्वरूप कैश का मिलान बिलम्ब से हुआ। श्री गांधी ने श्रमिक को 6-2-82 को 12 बजे बाद एफ. डी. बैलेंस मिलाने हेतु कहा होता तो उक्त तथ्यों को इस श्रमिक ने टेलीफोन पर डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक को क्यों नहीं सूचित किया तथा उसी रोज उक्त तथ्यों को लिखित में श्री गांधी को क्यों नहीं दिया। जब 6-2-82 को ही श्री गांधी द्वारा पत्र सं. 12/83 ओवरटाईम बाबत दिया गया था तो उसके प्रत्युत्तर में भी श्रमिक लिख सकता था कि उससे कैश के अलावा एफ. डी. बैलेंस का भी काम करवाया गया है। 10-2-82 को इसी श्रमिक ने एम. ई. 4 पत्र ओवरटाईम बाबत लिखकर दिया था उसमें भी यह दर्ज नहीं है कि कैश मिलाना छोड़कर एफ. डी. के बैलेंस मिलाने का काम करवाया हो। तर्क के लिए यह मान भी लें कि 12 बजे बाद एफ. डी. बैलेंस मिलाने का काम श्रमिक से लिया गया था तो प्रदर्श एम. ई. 10 के अनुसार 6-2-82 को शाखा में कुल 16 रिसीट प्राप्त हुई थी और कुल 390 नोट प्राप्त हुए थे जिनकी गणना करने में या मिलान करने में ज्यादा समय लगने की संभावना नहीं थी।

13. 8-2-82 को जब श्री गांधी ने श्रमिक को वाउचर रिलीज करने के लिए पहले 12.15 बजे कहा, दुबारा 12.30 बजे कहा, तीसरी बार 1.00 बजे कहा फिर 1.15 बजे व 1.30 बजे भी कहा और प्रत्येक बार जब श्री सारण द्वारा यही कहा गया कि जब उसकी कैश मिलेगी तभी वह वाउचर रिलीज करेगा इस पर करीब पौने तीन बजे श्री गांधी ने श्री सारण को वाउचर रिलीज करने के लिए एक पत्र दिया। उक्त पत्र भी श्री गांधी के अनुसार श्री कमज नाथ पटेल के पास दिया गया था तो भी श्री गांधी के अनुसार श्री सारण ने अगले कैबिन में ही श्री गांधी की तरफ फेंक दिया था। श्री गांधी ने उक्त कथनों की पुष्टि श्री पटेल ने भी करते हुए कहा है कि पौने तीन बजे जो लैटर सारण जी को देने के लिए दिया था वह एक ही कागज था वह मैंने सारण जी को दिया था और गांधी जी के कहने से वापस लाया था। पटेल कहता है कि वह पत्र उसने कैबिन के पाटिये पर से उठाया था। हालांकि पटेल ने यह तो अस्वीकार किया है कि उक्त कागज श्री सारण ने फेंका हो या श्री गांधी को गांधी ही हो परंतु उक्त कागज पाटिये पर से उठाने का तथ्य ही इस निष्कर्ष का द्योतक है कि श्री सारण ने उक्त कागज फेंक दिया था।

14. प्रति रक्षा साक्षी एम० के० दुबे तत्कालीन समय में हेड केशियर भी कहता है। 8-2-82 को पौने 5 व 5 बजे श्री सारण ने श्री गांधी को कहा कि कैश मिल गई है तब श्री गांधी कैश कैबिन में चैकिंग के लिए गये और करीब 6 बजे तक कैबिन में ही कैश चैक करते रहे और करीब 6-30 बजे कैश सेफ में अंदर रखवाया। उक्त तथ्यों से यही निष्कर्ष निकला कि 8-2-82 को भी कैश 6.30 बजे बंद हुआ था। प्रति रक्षा साक्षियों का यह कथन भी कि बीच में श्री गांधी ने श्री सारण से दूसरा काम करवाया, सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम तो दूसरा काम श्री सारण से करवाया ही नहीं और तर्क के लिये यह मान भी लें कि दूसरा काम करवाया तो भी शाखा में इतना काम था ही नहीं कि इतना ज्यादा समय लगता। प्रति रक्षा के सभी साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि 6-2-82 तथा 8-2-82 को हमेशा की तरह ही सामान्य काम शाखा में था।

15. सभी प्रति रक्षा साक्षियों ने यह भी कहा है कि श्री सारण में ओवरटाईम की मांग नहीं की थी बल्कि श्री गांधी ने ही दोनों दिनों का ओवरटाईम जबर्दस्ती श्री सारण का कन्फर्म किया था। मेरी राय में उक्त कथनों में भी सत्यता का आभास नहीं होता है क्योंकि श्री गांधी का श्री सारण को जबर्दस्ती ओवरटाईम लिखने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि उससे श्री गांधी को कोई लाभ नहीं होने वाला था बल्कि जब श्री सारण ने समयावधि में कैश का काम पूरा नहीं किया और ओवरटाईम पर जोर दिया तो श्री गांधी ने डूंगरपुर शाखा प्रबन्धक से टेलीफोन द्वारा बात की और तत्पश्चात् रीजनल मैनेजर जयपुर से भी टेलीफोन

द्वारा बात करके ही श्री सारण का ओवरटाईम मंजूर किया। इस बाबत श्री गांधी ने प्रदर्श एम. ई-7 ओवरटाईम रजिस्टर में भी उक्त विषय का इनट्राज किया है तथा प्रदर्श एम. ई-1 पत्र 6-2-82 को तथा एम. ई-2 व 3 पत्र 8-2-82 को भी इस विषय में लिखे। अतएव उपरोक्त समस्त कारणों से श्रमिक पर लगाये गये सभी आरोप मौखिक व प्रालेखिक साक्ष्य से साबित हो जाते हैं।

16. श्री परिहार, संघ के प्रतिनिधि का तर्क यह था कि द्विपक्षीय समझौता 1966 के क्लॉज 19(6)(डी) के अनुसार एक ही वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का प्रावधान है जबकि श्रमिक को तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां भावी प्रभाव से रोकी गई हैं। मैंने द्विपक्षीय समझौते के संबंधित प्रावधानों का सूक्ष्म रीति से परीक्षण किया तो पाया कि धारा 19(5) में घोर ऊपचार का उल्लेख है जिसके सब-क्लॉज "ई" के अन्तर्गत किसी वारंट के वैध तथा युक्ति-संगत आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा व उल्लंघन करना तथा क्लॉज "जी" के अनुसार कार्य निष्पादन में जानबूझकर धीमी गति लाना और "जे" के अनुसार बैंक के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव करने वाला कार्य या घोर उपेक्षा करने का उल्लेख है। श्रमिक पर जो आरोप लगाये गये हैं तथा जो साक्ष्य द्वारा जांच अधिकारी ने भी साबित पाये हैं और मैंने भी प्रालेखिक व मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के अनुसार उपरोक्त सभी आरोप साबित पाये। इन आरोपों के लिए धारा 19(छ) में दण्डों का उल्लेख है और 19(छ) (डी) के अनुसार वेतन वृद्धि रोकने का भी दण्ड दर्ज है। यह सही है कि वेतन वृद्धियां रोकने का उल्लेख 19(छ)(डी) में नहीं है परन्तु श्रमिक पर 4 आरोप हैं और चारों के लिए हालांकि प्रबन्धक ने तो प्रत्येक आरोप के लिए एक-एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थाई प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया था जिसे अपील अधिकारी ने सहानुभूति-पूर्वक देखते हुए तीन वार्षिक वेतन वृद्धि भावी प्रभाव से रोकने का ही दण्ड दिया है। अतः मेरी राय में आरोपों की प्रकृति एवं परिस्थिति को देखते हुए जो दण्ड श्रमिक को दिया गया है वह अनुचित एवं अत्याधिक नहीं है और न ही द्विपक्षीय समझौते के नियम 19(छ) के विपरीत है।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि वह न्यायालय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11-ए के अन्तर्गत दण्ड के मामले में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कि सेवा मुक्ति का दण्ड दिया गया हो इससे न्यूनतम दण्ड में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस बाबत वर्कमेन आफ फायर-स्टोन एंड रबड़ कम्पनी बनाम मेनेजमेंट, 10 एस.सी. एल.जे. 159 के स्थाय दृष्टान्त का उल्लेख किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है :—

"श्री पी.आर. तारन, केशियर-कम-क्लर्क को तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां स्थाई प्रभाव से रोकने का दण्ड देना उचित एवं वैध है और वह श्रमिक किसी

अनुतोष का अधिकारी नहीं है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना बर्दाश्त करेंगे।"

18. अवार्ड की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के भेजी जाये।

जगत सिंह, पीठातीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1373—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधकता संबंधित नियोजकों और उन कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/294/84-डी-2 (ए)]

वो. के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1373.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Mgt. of Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-12012/294/84-DII(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 66/1989

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल 12012/294/84-डी-II (ए) दिनांक 27-6-89

श्री किशन लाल शर्मा मार्फत जनरल सेक्रेटरी, राजस्थान सेन्ट्रल बैंक एम्प्लॉयज यूनियन, अजमेर।

—प्रार्थी

बनाम

प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर. एच. जे. एस. प्रार्थी की ओर से श्री मानसिंह गुप्ता
अप्रार्थी की ओर से: श्री डी. एन. शर्मा
दिनांक अवार्ड: 8 जनवरी, 1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को

वास्ते अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 19(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है।

"Whether the action of the management of Central Bank of India in terminating the services of Shri Kishanlal Sharma and not considering him for further employment while recruiting fresh hands under section 25H of the Industrial Disputes Act is justified? If not to what relief is the workman entitled?"

2. राजस्थान सेन्ट्रल बैंक एम्प्लॉयज, यूनियन, अजमेर जिससे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया है कि श्रमिक किशनलाल शर्मा की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जौहरी बाजार शाखा, जयपुर में 29-10-82 को की गई थी जहां पर उसने 11-12-82 तक निरन्तर कार्य किया था, तत्पश्चात् उक्त श्रमिक की नियुक्ति उक्त शाखा में 30-8-83 को पुनः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर की गई जहां उसने 20-10-84 तक कार्य किया। प्रार्थी संघ कहता है कि 20-2-84 को मौखिक आदेशों के द्वारा उक्त शाखा प्रबन्धक ने किशनलाल की सेवाएं समाप्त कर दीं। सेवा समाप्ति के पूर्व नोटिस अथवा वेतन नहीं दिया और इस प्रकार शास्त्री अवार्ड के पैरा 522(4) की अवहेलना की जिसके अनुसार 14 दिवस का नोटिस देना आवश्यक था।

3. प्रार्थी संघ यह भी कहता है कि श्रमिक किशनलाल को स्थाई रिक्त पद पर नियमित प्रकृति का कार्य करने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगाया गया था इसलिए शास्त्री अवार्ड के पैरा 524 के अनुसार सेवा मुक्ति से पूर्व उसे एक माह का नोटिस अथवा नोटिस पे देना आवश्यक था। प्रार्थी संघ यह भी कहता है कि किशनलाल की नियुक्ति बिना किसी निश्चित अवधि के लिए की गई थी और उसने नियमित रूप से स्थाई प्रकृति के कार्य पर लगाया गया था इसलिए बार्ड-पारदाईट सूचीता 19-10-66 के पैरा 20.12 के अनुसार अन्य कर्मचारियों को लगाने से पूर्व किशनलाल को नियुक्ति के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी परंतु किशनलाल की अवैध-सेवा मुक्ति के पश्चात् अप्रार्थी ने प्रदर्श-1 में दर्ज 6 व्यक्तियों को नियुक्ति कर लिया और इस प्रकार पैरा 20.12 की अवहेलना की। प्रार्थी संघ यह भी कहता है कि श्रमिक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (बी) के अनुसार 130 दिन से अधिक बिना किसी अवरोध व हानि के कार्य किया या इसलिए यह माना जायेगा कि उसने लगातार कार्य किया है और उसी आधार पर वह सेवा में पदस्थापित होने का अधिकारी है। प्रार्थी संघ के अनुसार सेवा मुक्ति के उपरांत प्रदर्श-1 में दर्शाये गये 6 व्यक्तियों की नियुक्ति करने से पूर्व श्रमिक किशनलाल को कोई सूचना नहीं दी गई कलस्वरूप अप्रार्थी नियोजक ने धारा 25-एव की भी अवहेलना की है और प्रार्थना की है कि सेवा मुक्ति आदेश अपास्त करते हुए श्रमिक किशनलाल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर पिछले बकाया वेतन सहित पदस्थापित किया जाये।

4. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर यह तो स्वीकार किया कि इस श्रमिक को अप्रार्थी बैंक की जौहरी बाजार शाखा में प्रबन्धक ने कार्य की आवश्यकता को देखते हुए 29-10-82 से 11-12-82 तक कुल 44 दिन और तत्पश्चात् 30-8-83 से 20-2-84 तक कुल 174 दिवस के लिए रखा था परंतु नियोजक के अनुसार श्रमिकों आकस्मिक श्रमिक के बतौर रखा गया था जो कार्य की अधिकता व ब्रांव की आवश्यकता को देखते हुए शाखा प्रबन्धक द्वारा रखा गया था इसलिए श्रमिक पर शास्त्री अवार्ड लागू नहीं होता है और न ही उक्त अवार्ड का पैरा 522 (4) अथवा 524 की कोई अवहेलना होती है। श्रमिक को न तो नियुक्ति आदेश दिया गया था और ना ही सेवा मुक्ति आदेश दिया गया था इसलिए यह किसी नोटिस अथवा नोटिस वेतन का भी अधिकारी नहीं है क्योंकि किशनलाल को स्थाई प्रकृति के कार्य पर न तो लगाया गया अपितु जब जब शिपशी को काम के अनुसार आकस्मिक श्रमिक की आवश्यकता हुई उसे काम पर लगाया गया। 20-2-84 के उपरांत भी यदि श्रमिक अपने आप को काम के लिए प्रस्तुत करता तो उसे भी काम दिया जा सकता था। श्रमिक का नाम रोजगार कार्यालय से नहीं आया इसलिए 20-2-84 के उपरांत उसे नहीं रखा गया और इस प्रकार श्रमिक धारा 25-एफ के प्रावधानों के लाभ का भी अधिकारी नहीं है। नियोजक का कहना है कि श्रमिक को आकस्मिक तौर पर नौकरी देते समय ही स्पष्ट तौर पर सूचित कर दिया गया था कि उसको नियुक्ति पूर्वत आकस्मिक है और यदि बैंक में बाद में कामों निम्नितियां होती हैं तो उसे अवसर तमो दिया जा सकेगा जब उसका नाम रोजगार कार्यालय से आयेगा।

5. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक ने स्वयं का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया है जिससे नियोजक के प्रतिनिधि ने जिरह की है। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से भी श्री अग्रवाल तत्कालीन शाखा प्रबन्धक ने शपथ-पत्र भी पेश किया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है। तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. नियोजक ने ही अपने प्रत्युत्तर द्वारा वह तो स्वीकार किया है कि हम इस श्रमिक को जौहरी बाजार शाखा में 29-11-82 से 11-12-82 तक और तत्पश्चात् 30-8-83 से 20-2-84 तक लगाया गया था। प्रार्थी संघ का यह कहना है कि श्रमिक किशनलाल की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्थाई रिक्त पद पर की गई थी। उसके द्वारा किया गया कार्य नियमित रूप से स्थाई प्रकृति का था जबकि अप्रार्थी नियोजक का कथन यह है कि श्रमिक की नियुक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में की गई थी और उसने आकस्मिक श्रमिक के बतौर ही कार्य किया था उसे स्थाई प्रकृति के कार्य पर नहीं लगाया गया था। इस विषय में मैंने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विमोचन किया तो पाया कि नियोजक साक्षी श्री मोहन

लाल अग्रवाल ने ही प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि किशनलाल पानी पिनाता था, किताबें इधर उधर ले जाता था। पानी पिनाते का तथा किताबें इधर-उधर रखने का काम तो परमानेंट है। तत्पश्चात् साक्षी कहता है कि इस वाला काम पहले स्थाई कर्मचारी करता था। इसको हटाने के बाद स्थाई कर्मचारी आ गया था। उपरोक्त साक्ष्य से यही निष्कर्ष निकलता कि श्रमिक किशनलाल द्वारा किया गया कार्य तो स्थाई प्रकृति का था और उसको नियुक्त करने से पहले उक्त काम स्थाई कर्मचारी करता था तथा उसे हटाने के बाद भी स्थाई कर्मचारी आ गया था। यह उल्लेखनीय है कि न तो श्रमिक को नियुक्ति आदेश दिया गया और न ही सेवा मुक्ति आदेश। अर्थात् श्रमिक की नियुक्ति भी मौखिक आदेश द्वारा ही की गई थी और सेवा मुक्ति भी मौखिक आदेश द्वारा ही की गई है। अप्रार्थी नियोजक का प्रत्युत्तर में यह कहना है कि प्रार्थी को तौर आकस्मिक श्रमिक रखा गया था। इस विषय में प्रति परीक्षा करने पर नियोजक साक्षी मोहन लाल अग्रवाल कहता है कि श्रमिक को रैगुलर पे का डिफरेंस दिया होता उसे मालूम नहीं बैंक रिकार्ड में इसकी कैज्युअल लिखा या नहीं मालूम नहीं। उपरोक्त साक्ष्य से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि नियोजक के इन कथनों में सत्यता का आभास नहीं होता कि श्रमिक की नियुक्ति बतौर कैज्युअल लेबर की गई हो। बहस के दौरान भी नियोजक प्रतिनिधि न तो किसी द्विपक्षीय समझौते का उल्लेख कर सके और न ही नियोजक के किसी सरकूलर अथवा स्थाई आदेशों की तरफ मेरा ध्यान इंगित कर सके जिसके अनुसार शाखा प्रबंधक को आकस्मिक श्रमिक रखने को कोई अधिकार हो। स्थाई कर्मचारी रखने का अधिकार तो द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20.7 और 20.8 के अनुसार दिया गया है। इसलिए उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में श्रमिक किशनलाल शर्मा को न तो बतौर आकस्मिक श्रमिक रखा गया था और न ही इसके द्वारा किया गया कार्य ही आकस्मिक प्रकृति का था। इन परिस्थितियों में नियोजक का यह कथन अपास्त किया जाता है कि प्रार्थी को आकस्मिक कार्य के लिए बतौर आकस्मिक श्रमिक रखा गया था।

7. श्रमिक का यह कहना है कि उसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर लगाया गया था, सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि निर्विवाद रूप से न तो शाखा प्रबंधक को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार था और न ही अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कोई पद उस समय रिक्त हो। नियोजक साक्षी मोहन लाल ने अपने शपथ पत्र में की चरण सं० 5 में दर्ज किया है कि बैंक में स्थाई नियुक्तियों के लिए चयन बोर्ड द्वारा होता है और स्थाई कर्मचारियों को नियमानुसार नियुक्तियां होने पर नियुक्ति पत्र दिये जाते हैं। निर्विवाद रूप से इस श्रमिक को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और न ही इसका चयन

बोर्ड द्वारा हुआ है यहां तक कि नियोजन कार्यालय से भी इसका नाम नहीं आया। इन परिस्थितियों में यह माना जायेगा कि प्रार्थी की नियुक्ति अस्थायी कर्मचारी के रूप में की गई थी। श्रमिक ने एक कलेंडर वर्ष में 240 दिवस की सेवा पूरी नहीं की थी इसलिए वह धारा 25—एच के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी नहीं था परंतु द्विपक्षीय समझौते के पैरा 524 के अनुसार एक महीने के नोटिस अथवा उसके एवज में उक्त अवधि के वेतन का अधिकार अवश्य था।

8. श्रमिक प्रतिनिधि का यह भी कहना है कि नियोजक ने धारा 25—एच की अवहेलना की है क्योंकि सेवा मुक्ति के उपरांत प्रदर्श-1 में दर्ज व्यक्तियों को नियोजित किया गया है और इस श्रमिक की सूचना नहीं दी गई। प्रदर्श—1 के अनुसार जौहरी बाजार शाखा में एस. आर. यादव को 16-7-84 को बतौर कौश पीओन रखा गया था और जिसका नाम नियोजन कार्यालय से आया था। श्रमिक यह स्वीकार करता है कि उसका नाम नियोजन कार्यालय से नहीं आया। अभिलेख पर ऐसी नाम मात्र की भी साक्ष्य नहीं है कि उक्त एस. आर. यादव का चयन भी बोर्ड द्वारा किया गया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि एस. आर. यादव को भी अस्थायी कर्मचारी के रूप में ही नियुक्त किया गया था और इसकी नियुक्ति करने से पूर्व प्रार्थी श्रमिक को धारा 25—एच के अन्तर्गत सूचित करना आवश्यक था। मेरी राय में श्रमिक का नाम नियोजन कार्यालय से मंगवाना आवश्यक नहीं था और इसके अभाव में एस. आर. यादव को प्रार्थी श्रमिक की जगह नियोजित करना भी न्यायोचित नहीं था। इस विषय में जोगेन्द्र झा बनाम सर्विस कमीशन 1983 (3) एस. एल. आर. 4, तथा भारत सरकार बनाम हरगोपाल 1981 (1) एस. एल. आर. 5 के न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख किया जा सकता है जिनके अनुसार नियोजन कार्यालय से नाम मंगवाने पर ही नियुक्ति करना जरूरी नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से नियोजक ने धारा 25—एच की अवहेलना की है तथा एस. आर. यादव की जगह इस श्रमिक को धारा 25—एच के अनुसार सूचित करना आवश्यक था। श्रमिक प्रतिनिधि का कथन यह था कि प्रदर्श—1 के अनुसार अप्रार्थी की जौहरी बाजार के अलावा अन्य शाखाओं में भी नियुक्तियां की गई थी जिनका लाभ भी श्रमिक को मिलना अपेक्षित था परंतु मैं श्रमिक प्रतिनिधि के उक्त तर्कों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि निर्विवाद रूप से श्रमिक किशनलाल का स्थानान्तरण जौहरी बाजार शाखा से अन्य शाखाओं में नहीं हो सकता था अतः अन्य शाखाओं में नियुक्ति करने से प्रार्थी श्रमिक के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:

“श्रमिक किशनलाल शर्मा की धारा 25—एच के अनुसार नियुक्ति नहीं करना न्यायोचित नहीं था

तथा वह द्विपक्षीय समझौते के नियम 524 के अनुसार एक माह के नोटिस वेतन का अधिकारी है और 16-7-84 से जिस रोज कि श्री सीताराम यादव की नियुक्ति की गई थी उस दिनांक से जब तक सीताराम यादव नियोजित रहा तब तक की अवधि के लिए यह अधिकारी भी वेतन का अधिकारी है। 100 रुपये खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है।”

9. उक्त आशय का अर्वाइंड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17 (1) अधिनियम पठाया जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1374— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, बंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 13-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17011/9/90आई.आर. (बी-II)]

वी.के. वेनुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1374.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Bangalore as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Mgt. of LIC of India and their workmen, which was received by the Central Government on 12-5-92.

[No. L-17011/4/90-IR(B-II)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR
COURT, BANGALORE

Dated the 30th day of April, 1992

PRESENT :

Shri M. B. Vishwanath, B.Sc., B.L., Presiding
Officer.

CENTRAL REFERENCE NO. 30/90

I PARTY

Sri Chandra Naik
C/o Sri Ramakrishnappa,
Gundanna Street,
Kanakapura-562 117.

vs.

II PARTY

The Sr. Divisional
Manager,
L.I.C. of India,
Jeevan Prakash,
P.B. No. 6694,
J. C. Road,
Bangalore-560 002.

AWARD

In this reference made by the Hon'ble Central Government by order No. B.17011/9/90-IR. B.I-B.II dt. 16-5-1990 to this Tribunal U/s. 10(1)(d) of the I.D. Act 1947, the point for adjudication as per schedule is :—

“Whether the management of LIC of India is justified in terminating the services of Sri R. Chandra Naik, w.e.f. 7-3-89. If not, to what relief the workman is entitled to ?”

2. In the claim statement the I party workman has stated :—

The I party was appointed as a Probationary Development Officer by the II party in the year 1987. The I party was discharging his duties during probationary period to the satisfaction of his superiors. In spite of this, the II party has terminated the services of the I party without issuing notice or holding an enquiry. This is illegal. The I party has not committed any lack. The I party has made full efforts to reach targets fixed by the II party. The II party has taken the services of the I party for a period of about 2 years. When the I party was about to be confirmed, the II party has intentionally taken the decision to terminate the services of the I party. Assuming for a moment that the services of the I party workman were not satisfactory, the II party could have extended the probationary period of the I party. The II party has straight away terminated the services of the I party. This has resulted in grave injustice to the I party. The order of the II party terminating the services of the I party w.e.f. 7-3-89 is illegal. The I party has to be reinstated with full back wages.

3. In the counter statement, the II party has contended :—

It is true that the I party was appointed as Probationary Development Officer w.e.f. 1-10-87 after he completed the training period. He was posted to Magadi Taluk coming under Chennapatna branch of Bangalore division. But it is not true that the I party worked to the satisfaction of his superiors. During the probationary period, as per the norms, the I party had to secure through the agents under his organisation a minimum completed life insurance business of Rs. 41 lakhs with a first year scheduled premium income of not less than Rs. 1,17,000. Further, the minimum business production should cover not less than 300 lives and at least 30 of the agents appointed under the I party's organisation during the period should have become active and at least 20 agents should individually have put in during that period the minimum business required by them in an agency year according to Regulation 9 of LIC of India (Agents) Rule 1972.

4. The performance of the I party did not come upto the above standard. The I party had appointed 31 agents out of whom 10 have qualified on the minimum business basis and he had introduced 283 lives with a first year premium income of Rs. 88,341.46. The attention of the I party was drawn to the inadequacies in his performance. But the I party failed to achieve the targets, inspite of motivation by the Superior officers. Under these circumstances, the services of the I party were liable to be terminated and in fact they were terminated by the Corporation's letter dt. 1-3-89. The action taken by the II party as per letter Dt. 1-3-89 is proper and legal.

5. The I party did not fulfil the obligations cast on him. There was no need for the II party to hold an enquiry against the I party. There were many complaints against the I party. The I party was given more than adequate opportunity to correct himself. He was even advised, but all was of no avail. The termination of the services of the I party was in terms of the letter of appointment. The I party is not entitled to reinstatement or any relief.

6. On 3-9-90 I have stated in the order sheet that separate issues need not be framed, because the point in dispute is covered by the schedule in the reference made. I have stated this in regard to the issue in view of the Law laid down by the Supreme Court in 1983(2) L.L.J. 426 (D.P. Maheshwari v/s. Delhi Administration) that the Tribunal should decide all issues in dispute at the same time and because it has been laid down by our Hon'ble High Court in Writ Appeal No. 130/1976, D.D.14/9/79 (The Management of Sushendra Cafe v/s. Murugesh and others) in para 10 that the reference itself an issue. Anyway, I must hasten to add that I have been considering all the collateral issues, including point of jurisdiction and validity of reference. For these reasons I have not framed formal issues. I consider all the points urged.

7. On behalf of the I party, M.Ws.1 and 2 have been examined. M.W.1 is A. Gopalan, Branch Manager of II party Corporation of Chennapatna. M.W.2 is T. Vittal Rao, Asstt. Administrative Officer of II party at Chennapatna.

8. On behalf of the I party he has got himself examined and closed his case.

9. It is on record that the I party workman was appointed under the reservation category of S.C. and S.T. Ex. M.1 is the appointment order dt. 26-11-87. The I Party was to undergo training for a period of about 3 months. After completion of this period the I party had to undergo apprenticeship. The I party workman underwent the apprenticeship work. The I party was taken on duty for post of Probationary Development Officer w.e.f. 1-10-87. The probation period of the I party was to be for one year (12 months). This is clear from the letter of appointment Ex.M1 Ex.M.1 shows that the II party has discretion to extend the probation period of the I party.

10. Ex.M.4 Branch Manager Gopalan has stated, is a letter from Marketing Manager on behalf of the Senior Divisional Manager to the I party. From Ex. M.4 also it is clear that the I party was on probation for a period of one year from 1-10-87 to 30-9-88. So the one year probation period of I party was over on

30-9-88. In Ex.M.4 it is further stated that until the I party receives the final decision in the matter of probation, I party would be considered as being on probation.

11. It is extremely important to bear in mind that Ex.M.4 says that one year probation period of I party workman was over on 30-9-88 and that until the I party workman received final decision in the matter, he would be considered as being on probation.

12. Ex.P.27 is the order passed by the II party terminating the services of the I party workman w.e.f. 1-3-89. The one year probation period prescribed as per Ex.M.1 was over on 30-9-88. The services of the I party was terminated on 1-3-89. Read against the background of Ex.M.4, in Law it must be deemed, the probation period of the I party was extended upto 1-3-89. MW-2 Vittal Rao, Asst. Administrative Officer of II party has stated in his evidence that the proposals completed by the I party after 30-9-88 have not been considered to assess the performance of I party during the probation period. By probation period he obviously means, one year from 1-10-87 upto 30-9-88. In other words, it is abundantly clear, the performance of the I party workman from 1-10-88 to 1-3-89 has not been considered before issuing termination order Ex. M. 27. I have already stated that it must be deemed that the probation period of the I party was extended from 1-10-88 to 1-3-89. The termination order Ex. M. 27, under the circumstances, in the Law, amounts to a combined order of extending the period of probation and terminating the services. Admittedly the performance of the I party has not been considered from 1-10-88 to 1-3-89 (28-2-89). It has been laid down by the Supreme Court in JT 1987 (4) S.C. 311 (H.B. Chhatthar v/s. State of Gujarat) that a combined order extending the period of probation and terminating his services is illegal because the workman was not given an opportunity to improve himself. There is nothing on record to show that the I party workman had not improved himself during the extended period of probation from 1-10-88 to 1-3-89. To repeat, M.W. 2 has stated that they have not considered the performance of the I party during the period from 1-10-88 to 1-3-89, before issuing the termination order as per Ex. M. 27.

13. In view of Ex. M. 4 wherein it is stated by the II party that until a final decision, the I party would be considered as being on probation, it must be held that the probation period of I party was extended upto the date of Ex. M. 27 viz., 1-3-1989, for a period of 5 months.

14. It has been laid down by our Hon'ble High Court in W.P. 614/1984 D.D. 2-1-1991 (Krishnamurthy v/s. The National Institute of Mental Health and Neuro Sciences and another) at para 5 that extending the period of probation incorrectly subsequent to the period mentioned in the appointment order shall be construed that services of the employee are going to be regularised. His Lordship The Hon'ble Mr. Justice N. Y. Hanumanthappa has been pleased to lay down that there cannot be any extension of probation period with retrospective effect. On the facts and in the circumstances of the case, the termination order Ex. M. 27 means that the probation period of the I party workman was extended with retrospective

effect and his services were terminated. In view of the Law laid down by our Hon'ble High Court, the action of the II party as per Ex. M. 27 cannot be upheld. The order of termination has to be set aside. In view of the Law laid down by our Hon'ble High Court and Supreme Court, the provisions of Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations 1960 of II party cannot be pressed into service.

15. Now I will discuss another aspect of the matter.

16. Ex. M. 7 dt. 30-11-88 is a representation by one N. Mari to the Branch Manager of the II party branch at Chennai, making allegations against the I party workman. Ex. M. 9 dt. 28-12-88 shows that N. Mari has withdrawn the allegations made against the I party as per Ex. M. 7. Ex. M. 10 is another representation dt. 3-2-88 by one K. Venimadhava to the Branch Manager, LIC, Chennai, making allegations against I party workman that the I party workman had forged the proposal. Ex. M. 11 shows that this K. Venimadhava has unconditionally withdrawn the allegations made against the I party. Ex. M. 14 dt. 3-1-89 representation is given to the Branch Manager, by one Krishnamurthy denying that he had taken the policy through the I party. In Ex. M. 14 the said Krishnamurthy has stated that he does not know who the I party workman is and that he has not seen him. Ex. M. 16 is the letter dt. 10-1-89 by this Krishnamurthy withdrawing the allegations against the I party workman.

17. From what is mentioned above, it is clear that some public made allegations against the I party and they have unconditionally withdrawn their complaints. Ex. M. 25 is a confidential letter (report) addressed by M. W. 1 Gopalan, Branch Manager to the Senior Divisional Manager of the II party. Ex. M. 25 dt. 31-1-89, among other things, mentions the complaints made by the public against the I party. The termination letter Ex. P. 27 is dt. 1-3-89. This order is passed by Senior Divisional Manager to whom M. W. 1 addressed confidential letter as per Ex. M. 25 dt. 31-1-89. It is obvious from the facts of this case that the Sr. Divisional Manager who passed the termination order has taken into consideration the report of M. W. 1 as per Ex. M. 25. Ex. M. 25 mentions the complaints against the I party by the public, even when those complaints had been unconditionally withdrawn. Under these circumstances it should be held that order as per Ex. M. 27 has been passed by way of punishment.

18. Let me repeat. From the facts of this case there is no blinking the fact that the Senior Divisional Manager who passed the termination order as per Ex. M. 27 has been influenced by the confidential report Ex. M. 25, and Ex. M. 25 had taken into consideration the complaints against the I party, though those complaints had been withdrawn. It has been laid down by the Supreme Court in AIR 1984 S.C. 636 (Anoop Jaiswal v/s. Governor of India) that :

"If the Court holds that the order though in the form is merely a determination of employment is in reality a cloak for an order of punishment, the Court would not be debarred, merely because of the form of the order, in giving effect to the rights conferred by law upon the employee."

It has been further laid down by the Supreme Court that :

"the cause for the order cannot be ignored. The recommendation which is the basis or foundation for the order should be read along-with the order for the purpose of determining the character."

19. Ex. M. 27 and Ex. M. 25 read conjointly, against the background of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, I repeat, leads me to the conclusion that the termination order M. 27 has been passed by way of punishment on the basis of Ex. M. 25. Ex. M. 25 should not have been acted upon by Senior Divisional Manager since M. W. 1 had taken into consideration and Ex. M. W. 25 complaints which had been **withdrawn**.

20. The probation period of the I party started w.e.f. 1-10-87. Ex. M. 3 dt. 18-8-88 is the letter addressed by the Sales Manager to the I party. In Ex. M. 3 the Sales Manager has referred to the appointment of 20 agents by the I party, of whom 5 were qualified. Ex. M. 3 further refers to the introduction of 150 lives covering Rs. 25,89,500/- with 1 year premium income of Rs. 36,660.40. The Sales Manager has stated that the performance of the I party was fairly good and he has advised the I party to accelerate his activities. Ten months after the period of probation commenced, it is obvious from Ex. M. 3, performance of the I party was fairly good. But the order of termination as per Ex. M. 27 has been passed five months after tributes were paid to I party as per Ex. M. 3. This conduct of the II party reinforces my conclusion that Ex. M. 27 is motivated and is passed by way of punishment taking into consideration complaints which had been withdrawn.

21. It is argued on behalf of the II party that the order passed as per Ex. M. 27 does not refer to any misconduct on the part of the I party, but to the non-fulfilment of the target by the I party. This argument does not hold water since Ex. M. 25 has influenced the mind of the Senior Divisional Manager who passed the termination order Ex. M. 27. The Learned counsel for the II party argued that the order as per Ex. M. 27 was a discharge letter. It is significant to note that the word "discharge" has not been mentioned in Ex. M. 27.

22. Ex. M. 29 dt. 25-11-88 is the appraisal of the work of I party during the probation period from 1-10-87 to 30-9-88. M. W. 1 has stated that as per Ex. M. 29, as on 30-9-88, about 100 policies of the I party workman were still under scrutiny. It is argued by the learned counsel for the II party that the business introduced by the I party which got completed only after the probation period could not have been taken into account for the purposes of his appraisal. M. W. 2 Vittalrao has stated that the proposals completed after 30-9-88 have not been considered to assess the performance of the I party during probation period. M. W. 1 Gopalan also has stated that Ex. M. 29 includes only one year of premium of the policies given by the I party. The II party was bound to consider whether the I party had completed proposals as on 1-3-89, since the I party was allowed to work upto that period after one year of probation period. When the probation period of the I party, by legal implication was extended, the II party was bound to consider whether the performance of the I party was

satisfactory during the extended period of probation from 1-10-88 to 28-2-89, before passing the termination order dt. 1-3-89 as per Ex. M. 27.

23. The Learned Counsel for the II party relied on the decision of the Supreme Court reported in 1988(II) LLJ 97 (State of Gujarat vs. Sharadchandra Manohar Neve). In this case the Supreme Court has been pleased to hold that :

“the Termination of probation during or at the end of probationary period is valid and there is no necessity to institute proceedings to terminate the services of a probationer.”

I have carefully and respectfully read this decision of the Supreme Court. It is clear from the facts of this authority that the Supreme Court has been pleased to lay down about the termination of probation during or at the end of the probationary period. In the instant case, the impugned order as per Ex. M. 27, has not been passed during the probationary period or immediately after the probationary period of 12 months was over. But the II party has allowed the I party probationer to work for 5 months after the probationary period was over. So this authority is not applicable.

24. The Learned Counsel has relied on 1991 (II) LLJ 608 (Andhra Bank, Hyderabad v/s. Central Industrial Tribunal, Hyderabad). This authority relates to the reversion to the original post when the promotees work was not satisfactory in the post for which he was promoted. This authority also has no application.

25. For the aforesaid reasons, in any view of the Law, the termination order as per Ex. M. 27 has to be set aside and it is accordingly set aside.

26. All other documents and evidence not referred to by me are not relevant. In any case they do not alter the conclusions reached by me above.

AWARD

The order of termination as per Ex. M. 27 is hereby set aside.

The II party is directed to reinstate the I party workman forthwith. There shall be continuity of service. The I party workman from the day he is reinstated shall be on probation for a period of 12 months during which period the II party is entitled to ascertain the suitability of the I party.

The I party workman is entitled 50 per cent of back wages from 1-3-89 till he is reinstated as per this order. Award passed as stated herein, accepting the reference.

Advocates fee fixed at Rs. 500/-.

(Dictated to Stenographer, taken down by him, got typed, corrected and signed by me).

M. B. VISHWANATH, Presiding Officer

का.आ. 1375 :- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/280/86-डी -2 (ए)]

बी.के. वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1375.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bank of Baroda and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-12012/280/86-D.II(A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

केस नं. सी.आई.टी. 15/1987

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-12012/280/86/डी 2 (ए) दिनांक 14-4-87

श्री गजेन्द्र कुमार सैन पुत्र श्री गोपाल लाल, चौबे मोहल्ला महुआ जिला सबाईमाधोपुर।

—प्रार्थी

बनाम

क्षेत्रीय प्रबन्धक, बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री बी.एम. बागड़ा

अप्रार्थी की ओर से :

दिनांक अर्बाई : 20-2-1992

अर्बाई

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 (1) (ब) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

“बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर के प्रबन्धतंत्र की श्री गजेन्द्र कुमार सैन की 3-10-84 से सेवाएं समाप्त करने को और नई शर्तों के समय पुनः रोजगार के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-ज के अन्तर्गत उस पर विचार न करने की कार्यवाही न्यायोचित है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का अधिकारी है।”

2. प्रार्थी गजेन्द्र कुमार सैन जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी श्रमिक

संबोधित किया है ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति 4-7-84 को अप्रार्थी को बैंक में महुआ शाखा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में की गई थी। 4-7-84 से उसने कार्य प्रारंभ कर दिया था और उसका काम संतोषप्रद था। उसकी नियुक्ति भी स्याई पद पर की गई थी परंतु फिर भी 4-10-83 से मौखिक आदेश द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। श्रमिक कहता है अप्रार्थी बैंक में यह प्रथा है कि किसी भी श्रमिक से अधिकतम 90 दिवस ही कार्य लिया जाता है और तत्पश्चात् नया व्यक्ति नियुक्त कर लिया जाता है और पूर्व नियोजित व्यक्ति की सेवा समाप्त करते हुए नया व्यक्ति नियोजित कर लिया जाता है जो श्रम विरोधी नीति है। श्रमिक कहता है हालांकि बैंक के पास काम था फिर भी 4-10-84 को उसकी सेवा इसलिए समाप्त कर दी गई कि 90 दिवस से अधिक नियोजन में नहीं रखना था। सेवा मुक्ति के उपरान्त भी प्रार्थी की जगह सर्वश्री देवकी नन्दन, कैलाश व महेश बगैरह को भी आगे पीछे नियुक्ति दी है और श्रमिक को सूचित नहीं किया इसलिए धारा 25-एच की अवहेलना की गई है और इस प्रकार काम होते हुए भी 4-10-84 को सेवा मुक्ति करने से श्रमिक को सेवा में बने रहने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14, 16 व 26 का उल्लंघन किया है। श्रमिक की प्रार्थना है कि सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाये और उसे सेवा में मानते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि श्रमिक की नियुक्ति 7-7-84 को दैनिक वेतन पर लीव रिजर्व के अन्तर्गत सब-स्टाफ सर्वेंट के रूप में की गई थी। उसकी सेवाएं आकस्मिक प्रकृति की थी। 7-7-84 से 3-10-84 तक श्रमिक ने कुल 76 दिवस ही कार्य किया है इसलिए वह किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं है। नियोजक के अनुसार जब कभी किसी व्यक्ति का स्थानान्तरण हो जाता है या कोई व्यक्ति अवकाश पर चला जाता है या कार्य की अधिकता हो जाती है तो 19-10-66 के द्विपक्षीय समझौते की धारा 20.7 के अन्तर्गत अस्थायी नियुक्ति की जाती है और उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत ही इस कार्मिक की भी नियुक्ति की गई थी। तत्पश्चात् सर्वश्री देवकी नन्दन, कैलाश व महेश ने भी कुछ दिवस तक लीव बेकेन्सी के अन्तर्गत सेवा अवश्य की है। नियोजक के अनुसार 240 दिवस सेवा नहीं करने के कारण धारा 25-एच के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और न ही संविधान के अनुच्छेद 14, 16 या 19 का उल्लंघन किया है। स्याई नियुक्ति तो नियोजन कार्यालय के मार्फत ही बैंक के निर्देशानुसार की जाती है जो प्रक्रिया इस श्रमिक की नियुक्ति के समय नहीं अपनाई गई थी इसलिए कोई अनुतोष नहीं दिलाया जाये।

4. क्लेम में श्रमिक ने यह कहा है कि उसकी नियुक्ति स्याई पद पर की गई थी जिस तथ्य को नियोजक ने अस्वीकार

किया है। यह उल्लेखनीय है कि कोई नियुक्ति आदेश या सेवा मुक्ति आदेश तो नियोजक द्वारा जारी नहीं किया गया था परंतु श्रमिक की तरफ से नियोजक को प्रदर्श एम. 1 व एम. 2 प्रार्थना पत्र पेश किये गये थे उनकी फोटो प्रतियां नियोजक की तरफ से पेश हुईं ये जिनमें श्रमिक ने यह दर्ज किया है कि उसने दैनिक वेतन भोगी पीओन का काम किया है। श्रमिक स्वयं भी प्रति परीक्षा में स्वीकार करता है कि उसने बैंक में नौकरी के लिए कोई दरखारत नहीं दी थी और न ही उसका कोई इन्टरव्यू हुआ था। श्रमिक कहता है उसे पता नहीं कि बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति कौन करता है। श्रमिक ने एम-1 व एम-2 पर ए टू बी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित है कि श्रमिक की नियुक्ति दैनिक वेतन भोगी पीओन के पद पर ही की गई थी।

5. क्लेम के प्रत्युत्तर में तो नियोजक ने यह प्रकट नहीं किया कि बैंक का कौन स्याई कर्मचारी अवकाश पर अथवा स्थानान्तरण पर चला गया था जिसकी जगह इस श्रमिक से काम कराया गया परंतु नियोजक साथी श्री तारा बाबू सौगानी के अपने शपथ पत्र की चरण सं. 1 में दर्ज किया है कि नारायण लाल ने स्थानान्तरित होने के कारण और उसकी जगह अन्य कर्मचारी का पद स्थापन नहीं होने के कारण एक अवीनस्थ कर्मचारी की बैंक में आवश्यकता थी तथा कार्य की अस्थायी आवश्यकता को देखते हुए श्री गजेन्द्र कुमार सैन को 7 जुलाई को रखा था। प्रति परीक्षा में भी साक्षी कहता है कि 4-7-84 से 3-10-84 की अवधि में गजेन्द्र कुमार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कार्य जहर किया है, जितने दिन उसने कार्य किया उतने दिनों का उल्लेख एम-3 पुस्तिका में दर्ज किया था तत्पश्चात् श्री सौगानी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार करते हैं कि गजेन्द्र कुमार सैन को 154.90 पैसे का भुगतान रैगुलर पे के हिसाब से किया गया था। साक्षी कहता है उसे यह पता नहीं कि शाखा के हाजिरी रजिस्टर में गजेन्द्र कुमार का नाम दर्ज है या नहीं। नियोजक के दूसरे साक्षी श्री ओम प्रकाश तिवारी भी महुआ शाखा में कार्यवाहक शाखा प्रबन्धक थे जिन्होंने भी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि गजेन्द्र कुमार को रैगुलर पे स्कैल के मुताबिक वेतन दिया था। गजेन्द्र से वही काम लेते थे जो रैगुलर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करता है। इस प्रकार नियोजक के उपरोक्त साक्षियों से भी श्रमिक के कथनों की ही पुष्टि होती है कि उसे वेतन भी रैगुलर पे के हिसाब से दिया था और उससे काम भी रैगुलर पे स्कैल वाले श्रमिक का ही लिया गया है।

6. निर्विवाद रूप से इस श्रमिक की नियुक्ति नियोजन कार्यालय के मार्फत नहीं हुई और न ही नियोजक के स्याई श्रमिकों को नियुक्ति हेतु जो प्रावधान हैं उनकी पालना करके हुई है परंतु इस श्रमिक की 7-7-84 से 3-10-84 की नियुक्ति उपरान्त भी बैंक में वही कार्य उपलब्ध था जो यह श्रमिक करता था परंतु उसे इसलिए सेवामुक्त कर दिया गया क्योंकि बैंक की परिपाटी के अनुसार 90 दिवस या उससे अधिक

नियोजन में नहीं रखना था तथा तत्पश्चात् श्रमिक अगर सेवा-रत रहता तो उसे सेवा में बने रहने के अधिकार प्राप्त हो जाते। हालांकि उक्त तथ्यों को नियोजक ने प्रत्युत्तर द्वारा अस्वीकार किया है परंतु श्रमिक का कहना है कि उसी की जगह ही सर्वश्री देवकीनन्दन, कैलाश व महेश को भी तत्पश्चात् बके बादीगरे नियोजित किया गया है। क्लेम के प्रत्युत्तर की चरण सं. 4 में नियोजक ने भी यह स्वीकार किया है कि इन दोनों व्यक्तियों को भी कुछ दिवस के लिए लीव बेकेंसी में रखा गया है। श्रमिक गजेन्द्र कुमार ने भी अपने शपथ पत्र द्वारा कहा है कि उसे काम से अलग करके देवकीनन्दन, कैलाश, महेश आदि को नियोजित किया था जिससे वह साबित है कि बैंक में काम की कमी नहीं थी। उक्त तथ्यों बाबत श्रमिक से प्रति परीक्षा नहीं की गई है और नियोजक के किसी भी साक्षी ने अपने शपथ पत्र में यह दर्ज नहीं किया कि गजेन्द्र कुमार की सेवा मुक्ति के उपरांत उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को कितनी अवधि के लिए रखा गया था परंतु इस विषय में प्रति परीक्षा करने पर नियोजक साक्षी श्री सौगानी कहते हैं कैलाश नारायण को 13-12-84 से 17-12-84 तक उसके बाद 22-12-84 को तथा 26 लगावत 29-12-84 तक रखा था। फिर उसे 14-1-85 को रखा था। बनवारी के लिए भी नियोजक साक्षी कहता है उसे भी आवश्यकतानुसार कैज्यूअल के रूप में 14-6-84 से 19-6-84 तथा 25-6-84 से 30-6-84 तक, 1-7-84 से 25-7-84 तक, 26-7-84 से 31-7-84 तक रखा था। इसी प्रकार नियोजक साक्षी श्री प्रकाश तिवारी से जब इस विषय में प्रति परीक्षा की गई तो वह कहता है उसे ध्यान नहीं कि 3-10-84 के पश्चात् दिसम्बर अंत तक अन्य किसी व्यक्ति को रखा या नहीं। अतः नियोजक के उपरोक्त साक्षियों से ही श्रमिक के कथनों की पुष्टि होती है कि 3-10-84 के उपरांत श्रमिक वाला काम समाप्त नहीं हुआ था बल्कि श्रमिक से उक्त काम इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि 90 दिवस या उससे अधिक कार्य लेने की बैंक की परिपाटी नहीं थी और आगे काम लेने से श्रमिक को स्याई होने की संभावना थी और इस प्रकार श्रमिक की सेवा मुक्ति करते हुए कैलाश नारायण देवकी नन्दन व महेश बगैरह को नियोजित कर श्रमिक वाला कार्य करवाया गया। यह उल्लेखनीय है कि क्लेम के प्रत्युत्तर में तो नियोजक ने यह नहीं बताया कि कौन अवकाश पर गया था जिसकी एवज में श्रमिक को लगाया गया परंतु श्री सौगानी ने शपथ पत्र में श्री नारायण लाल के स्थानान्तरण होने के कारण इस श्रमिक को नियुक्त करने का उल्लेख किया है परंतु यह साक्षी भी यह यहीं बता पाया कि उक्त श्री नारायण लाल का स्थानान्तरण पर कब गया था। उक्त श्री नारायण लाल का स्थानान्तरण तो 30-3-94 को हुआ था जिसकी फोटो प्रति अभिलेख पर पेश की गई है। नियोजक ने व तो अपने प्रत्युत्तर में न ही उसके किसी साक्षी ने अपने शपथ पत्र में कहा कि उक्त श्री नारायण लाल को जुलाई 1984 में रिलीज किया गया हो। क्लेम के प्रत्युत्तर में तो यह दर्ज नहीं किया कि 4-10-84 को नारायण लाल की जगह अन्य

किसी व्यक्ति ने जोड़न कर लिया हो और न ही श्रमिक से उक्त विषय में कोई प्रतिरक्षा की गई है। परंतु नियोजक साक्षी श्री सौगानी ने अपने शपथ पत्र में दर्ज किया है 18-9-84 को फूलचंद मीणा को नारायण लाल के स्थान पर नियमित रूप से पदस्थापित किया गया था इसलिए गजेन्द्र कुमार की सेवाओं की आवश्यकता नहीं रही। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि नारायण लाल के स्थानान्तरण पर जाने पर ही उसी जगह इस श्रमिक से काम लिया गया था तो भी 18-9-84 को फूलचंद मीणा का पदस्थापन नारायण लाल के स्थान पर हो गया था तो तत्पश्चात् 3-10-84 तक गजेन्द्र कुमार को क्यों नियोजित रखा गया। नियोजक पक्ष यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि कैलाश नारायण को 13-12-84 से 17-12-84 तक फिर 22-12-84 को और उसके बाद 26 दिसम्बर से 29-12-84 तक, फिर 14-1-85 को किसी व्यक्ति की जगह दैनिक वेतन पर नियोजित किया गया। इस श्रमिक को नियुक्ति से पहले बनवारीलाल को भी 14-6-84 से 19-6-84, 25-6-84 से 30-6-84, 1-7-84 से 25-7-84 को भी किस व्यक्ति के एवज में रखा गया था। स्वीकृत रूप में जब 7-7-94 को इस श्रमिक को नारायण लाल की एवज में रखना बताया गया है तो 1-7-84 से 25-7-84 तक बनवारी लाल को दैनिक वेतन पर ही आकस्मिक श्रमिक के रूप में किसके एवज में रखा गया यह स्पष्ट नहीं है। श्रमिक यह है कि नियोजक के इस कथन में सत्यता का आभास नहीं होता कि किसी का स्थानान्तरण हो जाता है या कोई अवकाश पर चला जाता है तभी दैनिक वेतन पर लीव रिजर्व में द्वितीय समझौते की धारा 20.7 के अन्तर्गत रखा जाता हो परंतु चाहे कोई व्यक्ति अवकाश पर नहीं जाता हो फिर भी कार्य की अधिकता के कारण दैनिक वेतन पर द्वितीय समझौते की धारा 20.7 के अन्तर्गत नियोजित करते हैं। मेरे समक्ष विवाद का विषय यह है कि 3-10-84 के उपरांत भी जब नियोजक के पास काम बचा तो इस श्रमिक को धारा 25-एच के अनुसार सूचना न देकर अन्य व्यक्ति सर्वश्री देवकी नन्दन, कैलाश व महेश को नियोजित करने से धारा 25-एच के प्रावधानों की अवहेलना हुई है। नियोजित प्रतिनिधि का तर्क यह था कि जब श्रमिक ने एक वर्ष में 240 दिवस को सेवा पूरी नहीं की थी तो धारा 25-जी व एच के प्रावधान लागू ही नहीं होते। परंतु मैं नियोजक प्रतिनिधि के उक्त तर्क से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरी राय में 25-जी अथवा 25-एच को लागू करने के लिए 240 दिवस को सेवा पूरी करना आवश्यक नहीं है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने धर्मपाल/सिंह बनाम राजस्थान राज्य एस बी सो. रिट सं. 3585/89 निर्णय दिनांक 13-11-90 द्वारा निम्न मत व्यक्त किया है :

"Whether a person has completed services of statutory period or not, he is entitled for the benefits mentioned in section 25-G and 25-H of the Act and as such if the retrenchment is to be made even of a person who

has worked for less than the statutory period it has to be on the basis of 'First come Last go'."

इसी प्रकार जनरल मैनेजर, उत्तरी रेलवे डी. बी. सिविल रिट पीठिशन नं. 218/90 दिनांक 23-4-91 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालय के तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विश्लेषण के उपरान्त राजस्थान औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 को मैनडेटरी प्रकृति का होना घोषित किया था और 25-जी की पालना किये बिना श्रमिक की सेवामुक्ति को अनुचित बताया। नोरदर्न रेलवे बनाम सी.आई.टी. जयपुर 1990 (1) आर.एल.डब्ल्यू 136 तथा राम चन्द्र यादव बनाम राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन आर.एल.आर. 1989 (1) 636 के न्याय दृष्टान्तों में धारा 25-जी तथा नियम 77 को मैनडेटरी प्रकृति का बताते हुए इनकी अनुपालना किये बिना सेवा मुक्ति करना अनुचित माना है। उपरोक्त सभी दृष्टान्तों में किसी भी श्रमिक ने 240 दिवस तक कार्य नहीं किया था लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय ने धारा 25-एच और जी को लागू किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य 1984 लैब आई. सी. 1794 में बहुमत से निर्णय दिया है कि धारा 25-जी, 25-एच व 25-एन ही लागू है। कमलेश सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी 1987 (एस.सी.) (एल. एंड एस) 75 के न्याय दृष्टान्त में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-एन-6-पी से स्वतंत्र है यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6-पी धारा 25-एफ के समान है जबकि धारा 6-एन धारा 25-एच के समान है। अतः उपरोक्त संमस्त कारणों से मेरी राय में भी धारा 25-जी तथा धारा 25-एच धारा 25-एफ पर निर्भर नहीं हैं और चाहे किसी श्रमिक ने 240 दिवस कार्य नहीं किया हो, उसकी सेवा मुक्ति से पूर्व 25-जी और नियम 77 की पालना करना अपेक्षित है और उसकी सेवा मुक्ति के उपरान्त अगर वही कार्य नियोजक के पास होता है तो पहले सेवा मुक्त श्रमिक को ही अवसर दिया जायगा और तत्पश्चात ही अन्य व्यक्ति को नियोजित किया जायगा। विवेचनाधीन विवाद में दिनांक 4-10-84 को सेवा मुक्त से पूर्व दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई और न ही तत्पश्चात सर्वश्री देवकी नंदन, कैलाश व महेश को नियोजित करने से पूर्व इस श्रमिक को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा सूचना दी गई, इसलिए धारा 25-जी व 25-एच की अवहेलना हुई है।

7. इस न्यायालय के आदेशनुसार नियोजक ने बैंक की अन्य शाखाओं में दैनिक वेतन पर नियोजित व्यक्तियों की भी सूची पेश की है जिससे भी यह प्रकट होता है कि अक्तूबर 1984 से दिसम्बर 1988 तक अनेकों व्यक्तियों को बैंक की अनेकों शाखाओं में दैनिक वेतन पर नियोजित किया गया है परन्तु इस श्रमिक को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा 25-एच के अन्तर्गत सूचना नहीं दी गई। इसलिए यह श्रमिक 4-10-84

से 31-12-88 तक की अवधि का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी क्योंकि तत्पश्चात बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दैनिक वेतन पर नियोजित नहीं किया गया है। अतः इस निदेश का अधिनियम विम्न प्रकार से किया जाता है:

"श्रमिक श्री गजेन्द्र कुमार जैन की दिनांक 3-10-84 से की गई सेवा मुक्त उचित नहीं थी और तत्पश्चात सर्वश्री देवकीनंदन, कैलाश व महेश बैगरा नियोजन से पूर्ण इस श्रमिक को भी धारा 25-एच के अन्तर्गत सूचना न देने के कारण उक्त प्रावधान की अवहेलना हुई है और उतने समय अर्थात् 4-10-84 से 31-12-88 तक यह श्रमिक वेतन पाने का अधिकारी है। 100/- रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

8. आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजी जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1376:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वैस्टर्न रेलवे जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[एल-41011/37/91-आई.आर.(डीयू) (पार्टे)]

के. वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

S.O. 1376.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Western Rly., Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-41011/37/91-IR(DU) (Pt.)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 63/1991

रैफरेंस:— भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41011/37/91-आई.आर.डी. यू. दिनांक 5-12-91

अध्यक्ष, पश्चिम रेलवे कर्मचारी परिषद, अजमेर
—प्रार्थी

बनाम

सांख्यिकी एवं विश्लेषण अधिकारी संकलन कार्यालय, जी.एल.ओ. पश्चिम रेलवे, अजमेर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर.एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं
 अप्रार्थी की ओर से: कोई हाजिर नहीं
 दिनांक अर्वाड : 17 जनवरी, 1992
 अर्वाड

फरीकेन हाजिर नहीं। आज यूनियन की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश करने हेतु यह केस तय्यत था किंतु न तो कोई हाजिर आया और न ही कोई स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश हुआ। ऐसा लगता है कि यूनियन अब इस मामले में रुचि नहीं ले रही है अतः मामले में अदम पैरवी में नो डिस्प्यूट अर्वाड पारित किया जाता है जो राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी
 नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1377:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के प्रबन्धतंत्र के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध, में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल-42012/149/89-आई.आर. (डी.यू.) पाठे]]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1377.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Central School Sangathan, New Delhi and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-42012/149/89-IR(DU) (Pt.)]
 B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 68/90

रैफरेंस:— भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-42012/149/89-आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 24-9-90

श्री एस. सक्सेना मार्फत केन्द्रीय विद्यालय अध्यापकेतर संघ जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह जी आर.एच. जे. एस.
 प्रार्थी की ओर से: कोई हाजिर नहीं
 अप्रार्थी की ओर से: श्री एन. के. आहुजा
 दिनांक अर्वाड : 12-2-1992

अर्वाड

श्रमिक व उसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। नियोजक की ओर से श्री एन. के. आहुजा उपस्थित हैं।

2. श्री आहुजा ने श्री सक्सेना द्वारा नियोजक को लिखे गये पत्र की प्रति पेश की है जिसके अनुसार क्लेम विवाद करने का उल्लेख है। श्री सक्सेना गत पेशी पर भी अनुपस्थित थे और आज भी नहीं आये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच समझौता हो गया है। अतः इस विवाद में नो डिस्प्यूट अर्वाड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1378:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आल इण्डिया रेडियो, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के संबंधित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[एल-42012/33/85-डी-2(बी) (पाठे)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1378.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of All India Radio, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-42012/33/85-D.II(B) (Pt.)]

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

क्रम नं. सं. सी आई टी 6/86.

भारत सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एल. 42012/33/85, डी-2 (बी) दिनांक 14-2-86 पृथ्वी सिंह, सिधियों की गली, सूरसागर, डाकघर

के सामने जोधपुर, राज्य

बनाम

स्टेशन निदेशक, आल इंडिया रेडियो, जोधपुर,

राज्य

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर. एच. जे. एस.

श्रमिक पक्ष की ओर से अशोक परिहार
नियोजक पक्ष की ओर से श्री सम्पत राम
माथुर एवं शंकर लाल

दिनांक अर्वाइड : 7-2-92

अर्वाइड

केन्द्र सरकार ने निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनियम हेतु अपनी अधिसूचना संख्या एल 42012/33/85—डी-2 (बी) दिनांक 14-2-86 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) (घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है—

“क्या आल इंडिया रेडियो के प्रबंध तन्त्र की श्री पृथ्वी सिंह नैमित्तिक श्रमिक की सेवाओं को समाप्त करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है? यदि हां तो छटनी किया गया कर्मकार किस अनु तोष का हकदार है?”

2. प्रार्थी पृथ्वी सिंह, जिसे तत्पश्चात् श्रमिक सम्बोधित किया है, ने जरिए किलेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति जनवरी 1978 में नैमित्तिक श्रमिक के रूप में की गई थी, और उसने जनवरी 78 से जून, 83 तक लगातार सेवा की है। उससे उक्त अवधि में बागवानी के अलावा ट्रांसमीटर एवं अन्य मशीनों की रोजाना सफाई का काम भी लिया गया परन्तु वर्ष 1981 व 1982 में उसकी उपस्थिति इस उद्देश्य से कम लगाई गई है कि उसकी सेवाएँ रिकार्ड के अनुसार एक वर्ष में 240 दिवस पूरी नहीं हो सकी उक्त सारी कार्यवाही श्रम शोषण नीति के आधार पर की गई है परन्तु उसे वेतन हर माह पूरा दिया गया है। श्रमिक कहता है कि उसका कार्य संतोषजनक रहा है जिस बाबत 1-3-83 को सहायक केन्द्र निदेशक जोधपुर ने उसे एक प्रमाण पत्र दिया है जिसकी फोटो प्रतिलिपि प्रवर्ग डब्ल्यू 1 है। श्रमिक कहता है कि अप्रार्थी ने नियोजन कार्यालय जोधपुर के मार्फत माली के पद पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को बुलाया था और उक्त सूची में भी प्रार्थी का नाम था परन्तु अप्रार्थी ने श्रम शोषण नीति के उद्देश्य से श्रमिक का चयन नहीं किया श्रमिक यह भी कहता है कि समझौता वार्ता के दौरान समझौता अधिकारी श्री जी. के चौहान के समक्ष भी दिनांक 26-3-84 को अप्रार्थी ने यह मन्जूर किया था कि जब भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद रिक्त होगा तब ही श्रमिक को नियुक्ति दी जायेगी। श्रमिक के अनुसार 26 जून, 84 के पश्चात् भी अप्रार्थी के पास दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रिक्त थे क्योंकि

उन पदों पर कार्य करने वाले सर्वश्री जयप्रकाश व राजू की पदोन्नति लिपिक के पद पर कर दी गई थी और उनके द्वारा रिक्त किये गये पदों को भरने हेतु प्रार्थी ने भी सहायक केन्द्र निदेशक से भी निवेदन किया था परन्तु प्रार्थी को सेवा में लेने से इन्कार कर दिया जो भी श्रम शोषण नीति के सिद्धान्तों के आधार पर किया गया है। श्रमिक कहता है कि हालांकि उसने 240 दिन से ज्यादा दिन कार्य किया है फिर भी उसे सेवा मुक्ति के समय न तो नोटिस दिया न नोटिस की एवज में एक माह का वेतन दिया गया, यहां तक कि छटनी भत्ता भी नहीं दिया गया इसलिए धारा 25 एफ का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है और धारा 25 जी एवं एच का भी उल्लंघन किया गया है। श्रमिक की प्रार्थना है कि उसे संवेतन नियोजित घोषित किया जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिए प्रतिउत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा कि अप्रार्थी संस्थान आल इण्डिया रेडियो “उद्योग” नहीं है। बल्कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसकी सोवरन पावर (प्रभुत्व सम्पन्न शक्ति) है और इसलिए “उद्योग” की परिभाषा में नहीं आता है और इसलिए रैफरेंस अवैध है। प्रार्थी पृथ्वी सिंह ने आकस्मिक दैनिक वेतन भोगी अस्थायी कर्मचारी था जो सभी काम पर आता था। सन 1981 में उससे एक दिन भी कार्य नहीं किया और किसी भी हाल में भी 240 दिवस काम नहीं किया इसलिए भी धारा 25 एफ लागू नहीं होता है माली के पद पर नई नियुक्ति प्रत्याशी गुणा व गुण व योग्यता के आधार पर सक्षम कमेटी द्वारा की जाती है और उक्त कमेटी ने अपने विवेक से माली के पद पर प्रार्थी पृथ्वी सिंह का चयन नहीं किया इसलिए श्रम शोषण नीति का आरोप निराधार है सर्वश्री जयप्रकाश व राजेश कुमार की पदोन्नति भी तदर्थ रू. में विधिक है पद पर गई थी उन द्वारा खाली किये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद इसलिए नहीं भरे यद्ये क्योंकि उनको ही वापिस रिबर्ट होने की सम्भावना थी। जिनको अब रिबर्ट कर दिया गया है। अप्रार्थी के अनुसार 1978 से 1983 के मध्य जब कभी कोई छुटपुट काम विभाग में आवश्यक कराना होता था तब ही मस्ट्रोल पर आकस्मिक अस्थायी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में प्रार्थी को रख लिया गया था जिसने किसी भी वर्ष में पक्ष में 240 दिवस सेवा नहीं की है। इसलिए धारा 25 एफ 25 जी व 25 एच लागू नहीं होती।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक पृथ्वी सिंह ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया है

जिसने नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रलेखिक साक्ष्य में प्रार्थी ने डब्ल्यू-1 प्रमाण पत्र पेश किया है इसके विपरीत नियोजक की तरफ से सर्वश्री ए० के० गुप्ता वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक एस० एस० एल० गुप्ता सहायक केन्द्र अभियन्ता और के० एल० जलानी लेखापाल तथा शंकरलाल आचार्य प्रशासनिक अधिकारी को पेश किया है जिनसे श्रमिक के प्रतिनिधि ने जिरह की है। प्रलेखिक साक्ष्य में एन. एम० 1 लगायात एम-19 मस्ट्रोल की फोटो प्रति भी पेश की गई है तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. अप्राथी नियोजक की प्रथम आपत्ति यह है कि आल इंडिया रेडियो भारत सरकार का एक उपक्रम होने के नाते उसे सोवरन व रीगल पावर होने से उक्त विभाग "उद्योग" की परिभाषा में नहीं आता है। उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए नियोजक साक्षी श्री शंकर लाल प्रशासनिक अधिकारी ने अपने शपथ पत्र को चरण सं० 2 में इतना ही दर्ज किया है कि समाज के सुचारु रूप से संचालन करना सरकार का प्रथम एवं मुख्य कर्तव्य है इसीलिए सरकार के कार्यक्रम की व उसके सम्पादन की और उसके कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले तत्वों की जानकारी जनता को देने के उद्देश्य से ही और जनहित में स्वस्थ मनोरंजन करने के उद्देश्य से रेडियो व आकाशवाणी का अलग विभाग स्थापित किया गया है। इसके स्याई व अस्याई कर्मचारी संविधान की धारा 309 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत बताये गये नियमों से बंधित हैं। इसका उद्देश्य व्यापारिक फायदा उठाना नहीं है। नियोजक के उक्त साक्षी ने अपने शपथ पत्र में यह नहीं कहा कि आल इंडिया रेडियो को कोई सोवरन अथवा रीगल पावरें दिये गये हैं। भारत सरकार का उपक्रम होने के नाते ही यह नहीं कहा जा सकता कि अप्राथी संस्थान "उद्योग" की परिभाषा में नहीं आता है। निर्विवाद रूप से अप्राथी संस्थान में भी बंगलौर वाटर सप्लाई सीवरेज बनाम ए० राजप्पा, ए०आई०आर० 1976 (एससी) पेज 548 के न्याय दृष्टान्त के अनुसार "उद्योग" के लिए तीनों आवश्यकतायें विद्यमान हैं अर्थात् अप्राथी संस्थान में सिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती हो, नियोजक व नियोजितों के सहयोग से ही बड़ा कार्य होता हो तथा जनता व समाज की सेवा के लिए ही अप्राथी संस्थान कार्य करता है। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग आदि को तो 1987 लेब०आई०सी० पेज-89, 1985 लेब०आई०सी० 1770 आदि के न्याय दृष्टान्तों में सोवरन व रीगल फंक्शन नहीं माना गया है और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू किये गये हैं। केन्द्रीय सरकार के विभागों को भी उक्त न्याय दृष्टान्तों के अनुसार सोवरन व रीगल फंक्शन वाला नहीं माना जा सकता और उन्हें भी धारा 2(जे) के अन्तर्गत "उद्योग" ही माना जायेगा। ए०आई०आर० 1975 (एससी) 2032, ए०आई०आर० 1978 (एससी) पेज 548 के न्याय दृष्टान्तों का इस विषय में उल्लेख किया जा सकता है। केन्द्रीय सचिवालय के स्टैनोप्राफर को भी 1988 (2) एल०एल०आर०-19 के न्याय दृष्टान्त में कर्मकार मानते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया गया था। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से अप्राथी संस्थान भी धारा-2(जे) के अन्तर्गत "उद्योग" की परिभाषा में आता है और उस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और नियोजक प्रतिनिधि का प्रथम तर्क आधारहीन होने से अपास्त किया जाता है।

6. श्रमिक का यह कहना है कि उसने 1978 से 1983 तक लगातार सेवा की है और प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक नियोजित रहा है, उक्त तथ्यों को अप्राथी ने जरिये प्रतिउत्तर अस्वीकार किया है। श्रमिक पृथ्वी सिंह ने अपने क्लेम की चरण सं० 2 में भी यह

दर्ज किया है कि वर्ष 78 से जून 83 तक उसकी सेवायें लगातार रहीं हैं परन्तु प्रतिपरीक्षा में श्रमिक स्वीकार करता है कि 1981 में उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। सन 1982 में उसे पुनः नियुक्ति दी थी जिससे भी यह निष्कर्ष निकला कि श्रमिक ने सन 78 से 83 तक लगातार सेवा नहीं की है।

7. श्रमिक का यह कहना है कि उसने सेवा समाप्ति से पूर्व प्रत्येक 12 माह में 240 दिवस सेवा पूरी कर ली थी, जिस तथ्य को भी अप्राथी ने अस्वीकार किया है। हालांकि अपने शपथ पत्र में तो पृथ्वी सिंह यह कहता है कि उससे वर्ष 81, 82 में पूरे वर्ष काम लिया गया है और उसकी उपस्थिति कम लगाई है। श्रमिक स्वीकार करता है कि उसे वेतन पूरा मिल गया था और प्रतिपरीक्षा में भी कहता है कि 1979 में उसने जितने दिन काम किया उतने दिन का वेतन मिल गया। जितने समय के काम का वेतन देते थे उतने पर मस्ट्रोल पर दस्तखत कराकर वेतन देते थे। नियोजक प्रतिनिधि के सुझावत्मक प्रश्न पर साक्षी कहता है कि यह गलत है कि उसने वर्ष 79 में केवल 102 दिन ही काम किया हो। 1982 के लिए भी नियोजक प्रतिनिधि के सुझावत्मक प्रश्न पर श्रमिक कहता है कि उसे 1982 के सितम्बर माह में नहीं लगाया बल्कि मार्च या अप्रैल में लगाया है और तभी से उसे वेतन भी मिल गया है। साक्षी कहता है कि 78 से 80 तक हाई पावर ट्रांसमीटर पर वह काम करता था जो सुरसागर की तरफ है, दो वर्ष उसने लाल मंडान आकाशवाणी पर काम किया है। साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसने कभी भी हाजरियों वादात कहीं कोई इन्द्राज नहीं किया न डायरी रखी। एविज एम-1 से एम-21 तक टिकटों पर "ए" से बी) दस्तखत श्रमिक ने स्वीकार किये हैं। श्रमिक के मौखिक कथनों पर निर्भर नहीं किया जा सकता कि उसने प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस सेवा पूरी की हो जब श्रमिक यह स्वीकार करता है कि जितने दिवस उसने कार्य किया उतने दिवस का वेतन मिल गया है तथा मस्ट्रोल की फोटो प्रति प्रदर्श एम-1 लगायात एम-21 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तो इससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त मस्ट्रोल से ही सत्यता प्रदर्शित होगी। नियोजक के साक्षी ने भी यह कहा है कि श्रमिक ने किसी भी वर्ष में 240 दिवस की सेवा अवधि पूरी नहीं की है। नियोजक साक्षी के एल० जलानी लेखापाल ने अपने शपथ पत्र में ही मस्ट्रोल की प्रति एम-1 लगायात एम-20 को साबित किया है और कहा है कि सन 1983 में श्रमिक ने कुल 106 दिवस काम किया है सन 1982 में 85 दिवस काम किया है, 1981 में बिल्कुल भी काम नहीं किया, 1980 में 175 दिवस, 1979 में 102 दिवस तथा 1978 में 217 दिवस काम किया है। क्लेम की चरण सं० 3 में ही श्रमिक दर्ज करता है कि जून 83 तक ही उसने सेवा की है इसलिए जून 83 को समाप्त हुए 12 माह में उसने 240 दिवस सेवा कर ली है तो वह धारा 25(एफ) के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी है। एक्जि० एम-3 मस्ट्रोल 30-5-83 से 7-6-83 तक का है जिसके अनुसार श्रमिक ने 7 दिन का वेतन 63 रु० लिया है और एक दिन उसे रेस्ट का मिला है। उसके पश्चात एम० 9 द्वारा भी श्रमिक ने कुल 8 दिवस सेवा की है, एम-18 के द्वारा 11 दिवस, एम-17 द्वारा 10 दिवस, एम-16 द्वारा 1 दिन, एम-15 द्वारा 11 दिन, एम-14 द्वारा 10 दिन, एम-13 द्वारा 11 दिन, एम-12 द्वारा 12 दिन, एम-11 द्वारा 12 दिन, एम-10 द्वारा 11 दिन, एम-9 द्वारा 12 दिन, एम-8, 7, 6 द्वारा भी 12 दिन-12 दिन ही कार्य किया है। एम-5 द्वारा 8 दिन, एम-4 द्वारा 12 दिन एम 4(ए) द्वारा 11 दिन, एम-3 द्वारा 12 दिन, एम-2 द्वारा 3 दिन और एम-1 द्वारा 12 दिवस काम किया है जो 6-9-82 से प्रारम्भ हुआ है और 7-6-83 को समाप्त हुआ है। उक्त सभी दिवस जोड़ने पर 211 दिवस ही बनते हैं जिनमें श्रमिक को दिया गया रेस्ट भी शामिल किया गया है, यह सही है कि श्रमिक को एक मस्ट्रोल में एक दिवस ही रेस्ट दिया गया है और मस्ट्रोल प्रायः 10-11 दिन की है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये तो भी 6-9-82 से 7-6-83 तक की अवधि में पड़ने वाले पूरे रेस्ट दे दिये जायें तो भी यह श्रमिक 240 दिवस की सेवा अवधि पूरी नहीं करता है और मेरी राय में धारा 25(एफ) के लाभ का अधिकार नहीं रहता है।

8. श्रमिक ने अपने क्लेम में यह दर्ज नहीं किया कि सेवा मुक्ति के समय उससे कोई वरिष्ठ व्यक्ति कार्यरत रहा है। यदि सेवा मुक्ति के उपरान्त अन्य किसी व्यक्ति को उस ही पद पर नियुक्त किया गया हो, इसलिए धारा 25(जी) एवं 25(एस) की अवहेलना नहीं है।

9. मेरी राय में यह श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 5-3-86 से इस श्रमिक को सहायक अभियन्ता बालेश्वर, जोधपुर में नियोजित कर दिया गया है और सम्भवतः इसीलिए श्रमिक ने अब्बा उसके प्रतिनिधि ने इस न्यायालय में विशेष रूप से केस को पैरवा भी नहीं की। वास्तविकता जो भी हो अप्राप्ति संस्थान द्वारा न तो धारा 25एफ की अवहेलना की गई है और न ही धारा 25(जी) व एच की, इसलिए श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी नहीं रहता है और इस रफरेंस का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है :—

श्रमिक पृथ्वी सिंह आकस्मिक मजदूर की सेवा मुक्ति उचित एवं वैध है और यह श्रमिक किसी सहायता का अधिकारी नहीं है। उक्त आग्रह का अर्वाइड पारित किया जाता है जिसे वास्ते प्रकाशित राज्य सरकार को अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

कां० 1379. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार असिस्टेंट इंजीनियर (फोन्स) बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजक और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल-40012/23/87-डी 2(बी)(पाटें)]

बी० एम० डेविड, डस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1379.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Asstt. Eng. (Phones), Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/23/87-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

सी०आई०टी० 51/88

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/23/87-डी-II (बी) दिनांक 28-7-1988 श्री किशनलाल गहलोत द्वारा बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन काउन्सिल, मुख्यालय 1, खजान्ची बिल्डिंग, बीकानेर।

अर्थात्

बनाम

सहायक अभियन्ता (फोन्स) भारतीय डाक/तार विभाग, न्यू कम्प्यूटीकरण बिल्डिंग, बीकानेर।

अर्थात्

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जयतसिंहजी, आर०एच०जे०एस०

अर्थात् की ओर से :

श्री भारत भूषण शर्मा

अर्थात् की ओर से :

श्री प्रवीण बलदवा

दिनांक अर्वाइड :

8 जनवरी, 1992

अर्वाइड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण की वास्ते अधिनियम अन्तर्गत धारा 10(1)(ब) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रकाशित किया है :

“क्या सहायक अभियन्ता, डाक और तार विभाग, बीकानेर की श्री कृष्ण लाल गहलोत (कर्मकार) की 16-5-85 से सेवा समाप्त करने की कार्यवाही न्यायाचित है। यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है और किस तारीख से।”

बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन काउन्सिल, जिसे तत्पश्चात् प्राप्ति संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उनका संघ रजिस्टर्ड है तथा प्राप्ति किशनलाल गहलोत उनके संघ का सदस्य है। उक्त किशनलाल की नियुक्ति 8-8-83 को वायरमन के पद पर अप्राप्ति सहायक अभियन्ता के अन्तर्गत हुई थी। जहां पर उसने 16-5-85 तक निरंतर सेवा की है। 12-3-85 को अप्राप्ति ने श्रमिक को नोटिस दिया जिसके अनुसार 17-5-85 से उसकी सेवा समाप्त कर दी। प्राप्ति संघ का क्लेम है कि हालांकि 16-5-85 को समाप्त हुए कलेंडर वर्ष में श्रमिक ने 240 दिवस की सेवा प्रत्येक वर्ष में कर ली थी फिर भी उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया अर्थात् छंटनी बत्ता नहीं दिया गया। प्राप्ति संघ यह भी कहना है कि सेवा मुक्ति के समय श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति भी कार्यरत थे और सेवा मुक्ति के उपरान्त अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया है तथा वरिष्ठता सूची नहीं बनाई इसलिए धारा 25-ए का भी उल्लंघन किया है। संघ की शिकायत है कि सेवा मुक्ति अविश्व अवास्त किया जावे और 17-5-85 से श्रमिक को वॉरमेंट के पद पर मानते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाए जावें।

3. अप्राप्ति नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर प्रकट किया कि कृष्ण लाल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में मस्टररोल पर रखा गया था। उसने 16-5-85 तक नहीं बल्कि 16-4-85 तक ही कार्य किया है। वह कभी भी स्थाई कर्मचारी नहीं हुआ, हमेशा दैनिक वेतन भोगी के रूप में ही मस्टररोल पर रहा है इसलिए औद्योगिक कर्मचारी नहीं था और न ही धारा 25-एफ के लाभ का अधिकारी है। नियोजक के अनुसार पूर्व में सिर्फ ए.सी. प्लांट ही अप्राप्ति के था, बाद में पावर सप्लायेशन भी अप्राप्ति के अधीन हो गया और उसके कर्मचारी भी अप्राप्ति के पास स्थानांतरित होकर आ गये इस पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या आवश्यक मंजूर पदों से ज्यादा हो गई। स्थानांतरण होकर प्राप्ति दैनिक वेतन भोगी प्राप्ति से सीनियर थे इसलिए कनिष्ठता होने के होते एक माह का अग्रिम नोटिस देकर उसकी सेवाएं समाप्त की गई है। विभागीय नियमों के अनुसार श्रमिक मुआवजा पाने का अधिकारी नहीं था। न तो सेवा मुक्ति के समय इससे कनिष्ठ कोई व्यक्ति कार्यरत था और न ही तत्पश्चात् किसी व्यक्ति को नियोजित किया गया। 5-3-86 को भी श्रमिक को कार्यालय से पत्र जारी हुआ था पर वह कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए नियोजक ने धारा 25-जी अथवा 25-एच की अवहेलना नहीं की है। नियोजक के अनुसार उनका विभाग कानूनन औद्योगिक संस्थान की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए श्रमिक किसी लाभ का अधिकारी नहीं है।

4. अपने कथनों के समर्थन में किशन लाल श्रमिक ने स्वयं का समय-पत्र प्रस्तुत कर संस्थापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रतिलिखित साक्ष्य में डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-5 तक फोटो प्रतियां पेश की गईं। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से सर्वश्री जे.एन. विजय लंघा सागर सिंह के शपथपत्र पेश हुए हैं। पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने लिखित बहस भी पेश की है। तत्पश्चात् में वे पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के योग्य प्रतिनिधियों को ध्यानपूर्वक सुना।

5. क्लेम के प्रत्युत्तर में तो नियोजक कहते हैं कि उनका विभाग औद्योगिक संस्थान नहीं है परन्तु न तो क्लेम के प्रत्युत्तर में इसका कारण बताया है और न ही किसी नियोजक साक्षी ने उक्त विषय में कोई

शपथ पत्र दिया यहाँ तक कि श्रमिक से भी प्रति परीक्षा में उक्त विषय के सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये गये। निर्विवाद रूप से अप्राप्ती संस्थान में सिस्टमेटिक एक्टीविटी होता है, नियोजक तथा नियोजित के सहयोग से कार्य होता है तथा समाज के सदस्यों की सेवा की जाती है। इसलिए 1978 (2) एस०सी०सी० 213 राजप्पा बनाम बेंगलूर वाटर एंड सीवरेंज सप्लाई के न्याय दृष्टान्त के अनुसार अप्राप्ती संस्थान उद्योग की परिभाषा में आता है।

6. क्लेम में यह दर्ज है कि श्रमिक ने 8-8-83 से 16-5-85 तक सेवा की थी परन्तु नियोजक अपने प्रत्युत्तर द्वारा 8-8-83 से 16-4-85 तक ही श्रमिक द्वारा सेवा करना स्वीकार करता है। इन परिस्थितियों में अगस्त 16-4-85 तक ही सेवा करना मान लिया जाय तो भी 16-4-85 को समाप्त हुए एक कलण्डर वर्ष में इस श्रमिक ने निर्विवाद रूप से 240 दिवस की सेवा पूरी कर ली थी और धारा 25-एफ के अनुसार छंटनी से पूर्व यह छंटनी भत्ते का भी अधिकारी था। एक माह का नोटिस प्राप्त करना क्लेम में भी दर्ज है और किशनलाल श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में भी इसे स्वीकार किया है इसलिए धारा 25-एफ की नियोजक द्वारा श्रमिक की छंटनी के समय पालना नहीं की गई जिससे यह सेवा मुक्ति स्वतः ही अवैध एवं अनुचित हो जाती है।

7. हालांकि क्लेम में तो यह दर्ज किया गया है कि सेवा मुक्ति के समय श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति कायरत था परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति का नाम क्लेम में दर्ज नहीं किया गया जो सेवा मुक्ति के समय श्रमिक से कनिष्ठ था और सेवा में था। अपने शपथ पत्र में भी श्रमिक ने ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया और न ही प्रति परीक्षा में ऐसा कुछ कहा। इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि छंटनी के समय श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति कायरत हो।

8. क्लेम में यह भी दर्ज है कि सेवा मुक्ति के उपरांत अन्य व्यक्तियों को रखा गया और इस श्रमिक को सूचित नहीं किया गया। हालांकि क्लेम में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है जिसे सेवा मुक्ति के बाद रखा गया हो और न ही श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में ऐसे किसी व्यक्ति का नाम बताया है। नियोजक ने क्लेम के प्रत्युत्तर में कहा है कि श्रमिक को 5-3-86 को कार्य पर बुलाने के लिए पत्र जारी किया गया था परन्तु श्रमिक कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ। उक्त तथ्यों को साबित करने के लिए नियोजक साक्षी सर्वेम्बी जे०एन० विजय एवं सागर सिंह ने भी शपथ पत्र दिये हैं और प्रदर्श एम-1 तथाकथित पत्र की फोटो प्रति पेश की है। श्रमिक स्वयं भी प्रति परीक्षा में स्वीकार करता है कि उसे हटाने के बाद किसी को रखा हो तो सालूम नहीं। यह भी कहता है कि उसे दुबारा बुलाया गया था और जे०ई०एन० साहब ने कहा था कि पिछला सेवा काल खत्म करो तो नया काम देंगे। मेरी राय में श्रमिक के कथनों में सत्यता का आभास नहीं होता क्योंकि क्लेम में उक्त कथनों का उल्लेख नहीं है बल्कि इसके विपरीत कथन किया गया है और निष्कर्ष के किसी भी साक्षी से ऐसे सुझावात्मक प्रश्न नहीं किये गये कि श्रमिक को पिछला सेवा काल खत्म करने हेतु कहा गया हो इन परिस्थितियों में धारा 25-एफ और 25-जी की अवहेलना साबित नहीं है।

9. बहुस के दौरान नियोजक प्रतिनिधि का कथन यह था कि बकाया वेतन न दिलाया जाये। अपने कथनों के समर्थन में ए०आई०आर० 1983 (एस०सी०) 422 तथा 1991 लैब०आई०सी० 814 न्याय दृष्टान्तों का उल्लेख किया है। मैंने उक्त न्याय दृष्टान्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा। मेरी राय में उक्त न्याय दृष्टान्तों में दी गई व्यवस्था उन न्याय दृष्टान्तों के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में दी गई हैं तथा उनसे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि किसी भी सेवा मुक्त श्रमिक को बकाया वेतन नहीं दिलाया जा सकता हो। बल्कि इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय ने ही 1987 लैब०आई०सी० 1391 में यह व्यवस्था दी है कि जहाँ पर किसी श्रमिक की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध पाई जाती है तो सामान्यतः उसे सवेतन सेवा में लेने का आदेश देना होता है और

उच्चतम न्यायालय ने ही मोहनलाल बनाम भारत इलक्ट्रॉनिक्स लि० 1981 11(1) एल०एल०एन० 23 के न्याय दृष्टान्त में यह स्पष्ट किया है कि अगर सेवा मुक्ति "एबडनीशिगो बोर्ड" है तो न्यायालय को सिर्फ आदेश देना होता है कि श्रमिक की सेवाएं पूर्ण लाभ सहित लगातार मानी जायेंगी। 1981 (1) एल०एल०जे० 386 के अन्य न्याय दृष्टान्त के अनुसार सेवा मुक्ति अवधि का वेतन तभी और विशेष परिस्थितियों में ही अस्वीकार किया जा सकता है जैसे कि नियोजक संस्थान बंद हो चुका हो अथवा उसकी आर्थिक स्थिति बकाया वेतन सहन करने के लिए सक्षम नहीं है या सेवा मुक्ति अवधि में श्रमिक अन्य लाभदायक नियुक्ति में रहा हो। विवेचनाधीन विवाद में उक्त परिस्थितियां नियोजक द्वारा साबित नहीं की गई हैं।

10. अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है:—

"श्रमिक किशन लाल गहलोत को 16-5-85 से सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित नहीं है और इसे उसके पद पर नियोजित मानते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। 100% रुपया खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक अदर तीन माह उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज भी देना पड़ेगा।"

11. अवाई की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अतःगंत धारा 17(1) अधिनियम पठाई जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का०आ० 1380 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे जोधपुर के प्रबंधन के संबंध निोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-41012/28/89-डी० 2(बी) (पीटी)]

बी०एम० डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1380.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-41012/28/89-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं० सी०आई०टी० 126/89

रेफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41012/28/89-डी-2(बी) दिनांक 2-11-1989

श्री रतनकुमार, अखिल भारतीय रेल सफाई कर्मचारी संघ शाखा जोधपुर।

—प्राप्ति

बनाम

1. मण्डल रेल प्रबन्धक, उत्तर रेलवे मण्डल कार्यालय जोधपुर ।
2. महाप्रबन्धक, उत्तर रेलवे, बड़ोदा हाऊस, नई दिल्ली ।

--अप्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी आर०एच०जे०एस०
 प्रार्थी की ओर से : श्री एम०एफ० बेग
 अप्रार्थी की ओर से : श्री जे०पी०एस० जैन
 दिनांक अर्वाह : 7 जनवरी, 1992

अर्वाह

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधि सूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the management of Northern Railway Jodhpur Division in terminating the services of Shri Ratan Kumar, Part-time Sweeper in cash office, Jodhpur with effect from 1988 is just and legal? If not, to what relief is the worker concerned entitled?"

2. सचिव, अखिल भारतीय रेल सफाई कर्मचारी संघ, जोधपुर, जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि रतन कुमार कर्मचारी सफाई वाला रोकड़ कार्यालय उत्तर रेलवे मण्डल जोधपुर में दिनांक 6-3-82 से लगातार कार्यरत था । उसे 24-3-88 को बिना पूर्व सूचना द्वारा ही हटा दिया । प्रार्थी संघ ने कई बार उसे वापिस नौकरी में लेने की मौखिक निवेदन किया और 0-11-88 को लिखित पत्र द्वारा भी निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी नियोजक ने उसे नौकरी पर नहीं लिया फलस्वरूप 31-10-88 को प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष छत्तित कार्यवाई करने हेतु निवेदन किया गया जहां पर भी अप्रार्थी नियोजक की तरफ से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हुआ फलस्वरूप असफल वार्ता प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को पठाया गया जहां से यह औद्योगिक विवाद न्याय निर्णय हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है । प्रार्थी संघ कहता है श्रमिक रतन कुमार ने दिनांक 6-3-82 से 23-3-88 तक लगातार अप्रार्थी के कार्यालय में सेवा की है फिर भी उसे न तो किसी दुराचरण के कारण हटाया गया है और ना ही हटाने समय धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ दिया गया है इसलिए श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा में आती है जो अप्राप्त की जावे और उसे सवेतन पुनः सेवा में लेने के आदेश दिये जायें ।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर प्रकट किया है कि 4-3-82 से रतन कुमार को अंशकालीन (पार्ट टाइम) सफाई वाला केवल एक घंटे प्रतिदिन के लिए रखा गया था तथा उसे 6-3-82 से 30-11-84 तक 35 रुपये प्रति माह की दर से पारिश्रमिक भुगतान किया गया था तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पारिश्रमिक की दर 60 रुपये प्रति माह 1-12-84 को की गई । नियोजक के अनुसार श्रमिक ने 21-1-88 तक कार्य किया था और 22-1-86 से लगातार कार्य स्थल से बिना कारण बताये अनुपस्थित है । नियोजक वह भी कहते हैं कि वह श्रमिक रेल विभाग का नियमित कर्मचारी कभी नहीं था और न आज है इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और न ही श्रमिक किसी अनुतोष का अधिकारी है । 22-1-88 से सफाई कार्य वरिष्ठ स्वास्थ्य विरीक्षक जोधपुर के कर्मचारियों से करवाया जा रहा है । श्रमिक ने झूठी पर लेने हेतु कभी भी मौखिक या लिखित आवेदन नहीं किया और न ही यह पूर्व निर्धारित शर्तों पर झूठी पर आना चाहता है । नियोजक उसे अंशकालीन सफाई वाला के नाम पर लेने को तैयार है परन्तु अनुपस्थित अवधि का वेतन देना नहीं चाहता ।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक ने स्वयं के अलावा ताराचन्द व बाबूलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे निमोजक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया । इसके विपरीत नियोजक की तरफ से भी देव कृष्ण सुहार, मण्डल कोषाध्यक्ष तथा श्री पुखराज ठड्डा मण्डल कोषाध्यक्ष ने शपथ पत्र पेश हुए हैं जिनसे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की । तत्पश्चात् मैने पत्रवर्ती का निरीक्षण किया और पत्रकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना ।

5. श्रमिक का कहना है कि वह आठ घंटे काम करने वाला एक नियमित कर्मचारी था जबकि नियोजक का कहना है कि वह अंशकालीन (पार्ट टाइम) सफाई वाला था और उससे केवल एक घंटा ही प्रतिदिन कार्य लिया जाता था जिस बावत उसे 30-11-84 तक 65 रुपये प्रति माह और तत्पश्चात् 60 रुपये प्रति माह से भुगतान किया है । हालांकि श्रमिक के साक्षी सर्वश्री ताराचंद व बाबूलाल ने अपने शपथ पत्रों में दर्ज किया है कि रतन कुमार श्रमिक से प्रतिदिन 8 घंटे कार्य लिया जाता था इसमें से साक्षी ताराचंद तो इस श्रमिक के पिता हैं जबकि साक्षी बाबूलाल नियोजक के यहां जमादार के पद पर कार्यरत है । इन दोनों श्रमिक साक्षियों के उक्त कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि श्रमिक रतन कुमार ने अपने शपथ पत्र में यह दर्ज नहीं किया है कि वह रोजाना आठ घंटे काम करता हो बल्कि इसके विपरीत शपथ-पत्र की चरण सं० 4 में डब्ल्यू-1 प्रमाण पत्र का उल्लेख है जो 5-11-88 को जारी किया गया था और जिसमें 6-3-82 से 23-3-88 तक पार्ट टाइम सफाई वाला के पद का कार्य करने का उल्लेख है । वहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजक के कथनानुसार श्रमिक की प्रति परीक्षा में स्वीकार करता है कि उसे प्रति माह 60 रुपये ही मिलता था जिससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रति दिन आठ घंटे काम करने वाला व्यक्ति 60 रुपये प्रति माह को दर से काम नहीं करेगा बल्कि या तो नियमित दैनिक वेतन प्राप्त करेगा अथवा किसी वेतनमान में राशि प्राप्त करेगा । अतः उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ कि श्रमिक रतन कुमार अंशकालीन (पार्ट टाइम) सफाई वाला ही था ।

6. नियोजक ने ही अपने प्रत्युत्तर द्वारा यह स्वीकार किया है कि इस श्रमिक ने उनके यहां 6-3-82 से 21-1-88 तक कार्य किया है हालांकि श्रमिक का कहना है कि उससे 23-3-88 तक कार्य किया था और 24-3-88 से उसे सेवा में नहीं लिया गया । इन परिस्थितियों में यदि नियोजक का कथन हो मान लिया जाय तो भी 6-3-82 से 22-3-88 तक इस श्रमिक द्वारा लगातार कार्य करने से यह धारा 25-एफ के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी हो जाता है ।

7. नियोजक प्रतिनिधि का तर्क यह था कि अंशकालीन सफाई कर्मचारी नियमित कर्मचारी नहीं होता है इसलिये वह औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है जबकि इसके विपरीत श्रमिक प्रतिनिधि का तर्क यह था कि अंशकालीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार हो जाता है । श्रमिक प्रतिनिधि ने अपने कथनों के समर्थन में गोविंद भाई बनाम एन० के० देसाई 1988 जैव० आई० सी० 505 पर उपलब्ध गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्याय दृष्टान्त का उल्लेख किया है जिसके तथ्य भी विवेचनाधीन विवाद के तथ्यों से मिलते जुलते थे । वहां पर भी सफाई करने वाला अंशकालीन कर्मचारी ही नियोजित था और इस न्याय दृष्टान्त में भी नियोजक ने यही आपत्ति की थी कि अंश कालीन व्यक्ति धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में नहीं आता है और उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता । माननीय न्यायाधिरूप ने नियोजक पक्ष के उक्त कथनों को अस्वीकार करते हुए अंशकालीन श्रमिक को धारा 2(एस) के अंतर्गत कर्मकार मानते हुए उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ दिया था । राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ ने भी वाई० एस० यादव बनाम राजस्थान राज्य 1989(2) एल. एच० एन० 1011 के न्याय दृष्टान्त में दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन व्यक्ति को भी धारा 2(एस)

के अन्तर्गत कर्मकार मानते हुए धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ दिलाया था उक्त न्याय दृष्टान्तों के विपरीत नियोजक पक्ष की तरफ से किसी न्याय दृष्टान्त का उल्लेख नहीं किया गया है इसलिए उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में अंशकालीन सफाई वाला व्यक्ति भी धारा 2(एस) के अन्तर्गत कर्मकार की परिभाषा में आता है और अगर उसने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस की सेवा पूरी कर ली है तो वह धारा 28(एफ) के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी है। निविवाद रूप से श्रमिक रतन कुमार ने दिनांक 21-1-88 को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी और उसे 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया इसलिये तथाकथित सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा में मानते हुए धारा 25-एफ के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो जाती है।

8. नियोजक पक्ष के इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ कि श्रमिक स्वयं ही 22-1-88 से बिना कारण बताये अनुपस्थित हो गया क्योंकि जब इस श्रमिक ने 6-3-82 से 21-3-88 तक लगातार सेवा की थी तो उसके अनुपस्थित रहने पर नियोजक का यह दायित्व था कि श्रमिक को कारण बताओं नोटिस देता और उसके विरुद्ध धरलू जांच करता क्योंकि श्रमिक कि तथाकथित अनुपस्थित दुराचरण की परिभाषा में आती थी। निविवाद रूप से नियोजक पक्ष ने श्रमिक को अनुपस्थिति बाबत न तो कारण बताओ नोटिस दिया और न ही किसी प्रकार की जांच की। इसलिये उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :

“श्रमिक रतन कुमार पाट्टे टाईम सफाई वाला की सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है और उसे सेवा मुक्ति की दिनांक से पुनः सेवा में नियोजित मानते हुए उसके पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिखाये जाते हैं। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक अन्दर तीन माह उच्च राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।”

9. अर्वाइ की प्रति (1) धारा 17(1) अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रकाशनाय पठाई जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1881-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रेलवे मेल सर्विस अजमेर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40012/26/90-आई आर (डी यू) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1381.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Railway Mail Service, Ajmer and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/26/90-IR(DU) (Pt.)]
B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 77/90

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या :

एल 40012/26/90-आई आर (डी.यू.) दिनांक 22-30-11-90।

श्री खीम सिंह सुपुत श्री जुझर सिंह गांव पोस्ट किशनपुरा बाया काबरा जिला अजमेर।

बनाम

सुपरन्टिडेंट, रेलवे मेल सर्विस, जे डिवीजन, अजमेर।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर.एच.जे.एस.

श्रमिक पक्ष की ओर से : श्री सुरेश कश्यप

नियोजक पक्ष की ओर से : श्री प्रवीण बलबदा

दिनांक अर्वाइ : 31-10-91

अर्वाइ

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय हेतु अपनी अधिसूचना सं. एल. 40012/26/90-आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 22/30-11-90 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है—

“Whether the action of the mgt. of Supdt. R.M.S. 'J' Division, Ajmer in terminating the services of Shri Kheem Singh S/o Jujhar Singh Rest House Attendant at Abu Road is just and legal? If not to what relief the concerned workman is entitled to?”

2. प्रार्थी खीम सिंह, जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया है कि उसकी नियुक्ति अप्रार्थी द्वारा आर.एम.एस. रेस्ट हाऊस, आबूरोड में ग्रेटिण्डेंट के पद पर 6-5-88 को की गई थी उसका कार्य संतोषजनक था फिर भी उसे 14-4-89 को गैर कानूनी रूप से सेवा मुक्त कर दिया। श्रमिक कहता है कि उसे सेवा से हटाने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया न ही नोटिस की एवज में एक माह का वेतन दिया गया यहां तक की छंटनी भत्ता भी नहीं दिया गया इसलिए उक्त सेवा मुक्ति या छंटनी धारा 25(एफ) के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो गई है। श्रमिक की प्रार्थना है कि उसे ग्रेटिण्डेंट के पद पर नियोजित घोषित करते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रति उत्तर यह तो स्वीकार किया कि श्रमिक की नियुक्ति 6-5-88 को आबू रोड रेस्ट हाऊस में ग्रेटिण्डेंट के पद पर की गई थी परन्तु उक्त नियुक्ति एवजी के रूप में की गई थी। किसी प्रकार के स्थाई अथवा अस्थायी आदेश नहीं दिये गये थे बल्कि दैनिक वेतनभोगी के पद पर आवश्यकता होने पर मौखिक रूप से की गई थी। नियोजक का कहना है कि वर्ष 89 में विभागीय

नियमों के अनुसार ई.डी. कर्मचारियों की परीक्षा लेकर उक्त पद पर नियमित नियुक्ति कर दी गई इसलिए श्रमिक की सेवा मुक्ति स्वतः ही हो गई। नियोजक के अनुसार उक्त सेवा मुक्ति छंटनी की परिभाषा में नहीं आती।

4 अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक खीम सिंह ने स्वयं का शपथपत्र पेश किया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से सर्व श्री आर. एल. वर्मा तथा आर.जे. राम ने शपथपत्र पेश किये जिनसे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक सुना।

5. श्रमिक ने अपने क्लेम के अनुसार ही शपथ पत्र में भी दर्ज किया है कि उसने 6-5-88 से 14-4-89 तक लगातार सेवा की है और 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी। नियोजक ने क्लेम के प्रति उत्तर में भी यह स्वीकार किया है कि मई 88 से मई 89 तक श्रमिक ने 338 दिवस कार्य किया है तथा नियोजक साक्षी श्री आर.एल. वर्मा ने भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि मई 88 से मई 89 तक इसने 330 दिन काम किया था अतः इन परिस्थितियों में यह साबित है कि सेवा मुक्ति के समाप्त हुए एक कलेण्डर वर्ष में इस श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी। निर्विवाद रूप से नियोजक ने धारा 25एफ के प्रावधानों की पालना नहीं की न तो श्रमिक को सेवा मुक्ति से पूर्व एक माह का नोटिस दिया गया अथवा नोटिस की एवज में एक माह का वेतन भी नहीं दिया गया यहां तक कि छंटनी भत्ता भी नहीं दिया, इसलिए चाहे श्रमिक की नियुक्ति किसी भी एवजी में की गई हो इसकी छंटनी धारा 25एफ के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो जाती है, अतः सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाता है और इस निर्देश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है कि—

श्रमिक खीम सिंह रेस्ट हाउस अटैण्डेंट की छंटनी/सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है और उसे रेस्ट हाउस अटैण्डेंट के पद पर नियोजित घोषित किया जाता है, इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है। इसे 14-5-89 से उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। अगर नियोजक अन्दर तीन माह उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उक्त राशि पर ब्याज भी अदा करेगा। 100 रु. खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है। उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है, जिसे वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजा जावे।

जगत सिंह, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1382.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय

सरकार पोस्ट मास्टर जनरल, जयपुर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-91 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40012/146/89-डी-2 (बी) (पीटी)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1382.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Post Master General, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/146/89-D.II(B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.डी.टी. 42/1990

रैफरेन्स : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/146/89-डी-2 (बी) दिनांक 11-7-90।

श्री मंगतराम वर्मा पुत्र श्री मूलचन्द बसाई, ग्राम जगतपुरा, तहसील सांगानेर द्वारा श्री घनश्याम दास गुप्ता, श्रम सलाहकार, बी-223, जनता कालोनी, जयपुर।

—प्रार्थी

बनाम

पोस्ट मास्टर जनरल, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री जी. डी. गुप्ता

अप्रार्थी की ओर से : श्री कमल नैन

दिनांक अवार्ड : 9 दिसम्बर, 1991

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय अन्तर्गत धारा 10(1)(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रेषित किया है :—

"Whether the action of the management of Postmaster General, Jaipur is justified in terminating the services of Shri Mangal Ram Verma w.e.f. 11-6-89? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. प्रार्थी मंगलराम वर्मा, जिसे तत्पश्चात श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिए क्लेम प्रकट किया कि इसकी

नियुक्ति जुलाई, 1986 से दैनिक वेतन भोगी मजदूर बागवान के पद पर की गई थी। उसने अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी व कड़ी मेहनत से लगातार किया था। 10-6-89 को भी वह हमेशा की तरह अपने कार्य पर उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी ने कार्य पर लेने से मना कर दिया। बारम्बार निवेदन करने पर भी लिखित आदेश नहीं दिये और ना ही सेवा मुक्ति का कोई कारण बताया। श्रमिक का कहना है कि अप्रार्थी का कार्य लगातार चलने वाली प्रकृति का था और उसे हटाने समय उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी कार्य कर रहे थे तथा हटाने के बाद भी नये श्रमिकों को नियुक्ति की गई थी। प्रार्थी कहता है कि हालांकि उसने 10-6-89 को समाप्त हुए एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा कर ली थी फिर भी उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया। ना तो छटनी का भत्ता दिया, ना एक माह का नोटिस, न नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया गया। वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई। इसलिए नियोजक ने धारा 25-एफ, 25-जी, व 25-एल की अवहेलना की है। श्रमिक की प्रार्थना है कि 10-6-89 का मौखिक आदेश अनुचित एवं अवैध घोषित किया जावे और उसे उक्त पद पर पुनः नियोजित मानते हुए पिछला समस्त बकाया वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार किया है और कहा है कि पोस्ट मास्टर जनरल का दफ्तर उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि उसका कार्य केवल प्रशासनिक है। यह किसी प्रकार का उत्पादन, वितरण या सेवा की आपूर्ति नहीं करता है तथा सोवरन व रीगल फंक्शन्स डिस्चार्ज करता है जो देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। यह भी कहा है कि भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए रेफरेन्स चलने योग्य नहीं है। गुणावगुण पर नियोजक का कहना है कि दफ्तर में बागवान को कोई स्थाई काम नहीं था सिर्फ मौसम के कारण अल्प काल के लिए प्रार्थी को काम पर लगा लिया गया था, उसका कार्य पौधों को पानी पिलाना था जो 2-3 घंटे से अधिक का नहीं था। बागवान का कोई स्वीकृत पद भी नहीं था। उसका कार्य अनियमित था जिस बाबत उसे कह दिया गया था कि उसे कभी भी काम पर नहीं लिया जा सकता। नियोजक के अनुसार श्रमिक का काम संतोषजनक नहीं था। वह समय पर पानी नहीं देता था और पौधे सूख जाते थे जिस बाबत उसे कई बार मौखिक चेतावनी दी गई थी। नियोजक के अनुसार श्रमिक से कनिष्ठ कोई बागवान नहीं था और न किसी को बागवान के पद पर नई नियुक्ति दी गई है। अतः क्लेम खारिज किया जावे।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक मंगलराम वर्मा ने अपना स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री सी.एल. पुरी, आफिस सुपरिटेण्डेंट ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह 1205 GI/92-13

की। प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 फोटो प्रति पेश की गई है। तत्पश्चात् मैने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. नियोजक प्रतिनिधि की प्रारंभिक आपत्ति यह है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता, वितरण नहीं होता और न किसी सेवा की आपूर्ति होती है। यह विभाग देश की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है तथा उसके कार्य सोवरन व रीगल फंक्शन्स होते हैं। इस लिए यह विभाग धारा 2 (जे) के अन्तर्गत "इन्डस्ट्री" की परिभाषा में नहीं आता है। अपने कथनों के समर्थन में भारत सरकार बनाम पंजाब व हरियाणा राज्य 1984 (11) एल.एल.एन. 577 का न्याय दृष्टांत पेश किया है। मैने नियोजक प्रतिनिधि श्री कमलनैन श्री श्रीमाल के उपरोक्त तर्कों ध्यानपूर्वक सुने एवं उपरोक्त न्याय दृष्टांतों का भी अति-सूक्ष्मरीति से अध्ययन किया। नियोजक साथी श्री सी.एल. पुरी ने अपने शपथ पत्र में यह नहीं कहा कि पोस्ट मास्टर जनरल, राजस्थान सर्किल का कार्यालय कितने प्रकार के सोवरन या रीगल फंक्शन करता हो। निर्विवाद रूप से अप्रार्थी के कार्यालय में किसी सामान का उत्पादन नहीं होता है परंतु सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है और नियोजक तथा नियोजित के संबंध भी थे तथा यह विभाग भारतीय नागरिकों व समाज की सेवा करता है। डाक आदि की व्यवस्था करता है। बंगलौर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड बनाम राजपूरा 1978 (1) एल.एल.एन. 376 के न्याय दृष्टान्त के अनुसार यह विभाग भी उद्योग की परिभाषा में आता है। नियोजक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टांत सन् 1983 का है तथा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पंजाब सरकार बनाम कुलदीप सिंह 1983 (1) एल.एल.एन. 576 पर आधारित है। पंजाब उच्च न्यायालय के उपरोक्त पूर्ण पीठ के निर्णय के तत्पश्चात् अनेक उच्च न्यायालयों ने तथा उच्चतम न्यायालय ने भी नहीं स्वीकारा है। इस विषय में गुजरात उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त 1987 लैब आई.सी. 89 तथा उड़ीसा उच्च न्यायालय 1985 लैब. आई.सी. 1720 का भी उल्लेख किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी देसराज बनाम पंजाब राज्य 1988 (11) एल.एल.जे. 149 के न्याय दृष्टान्त द्वारा बंगलौर वाटर सप्लाई सीवेज बोर्ड वाले उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के अनुसार राज्य के सिचाई विभाग को धारा 2 (जे) के अन्तर्गत उद्योग घोषित किया है तथा पंजाब उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि केरला उच्च न्यायालय ने भी भास्कर बनाम एस.डी.ओ. (सब डिवीजन ऑफिसर) 1982 (11) एल.एल.जे. 248 के न्याय दृष्टान्त में पी.एन.टी. डिपार्टमेंट की धारा 2 (जे) के अन्तर्गत उद्योग घोषित किया था इसी प्रकार तत्पश्चात् भी केरला उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज बनाम के.आर.बी. कार्डवाल 1984 (1) एल.एल.एन. 743 के न्याय दृष्टान्त में पी.एन.टी. विभाग

की धारा 2 (जे) के अन्तर्गत उद्योग स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से मेरी राय में भी अप्रार्थी नियोजक का विभाग धारा 2 (जे) के अन्तर्गत उद्योग की परिभाषा में आता है क्योंकि यह विभाग भी बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड के न्याय दृष्टान्त में निर्धारित तीनों आवश्यक बिंदुओं की पूर्ति करता है और यह प्रथम खारिज की जाती है।

6. श्री श्रीमाल नियोजक प्रतिनिधि की दूसरी आपत्ति यह थी कि भारत सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा ही यह निदेश पठाया गया है और पोस्ट मास्टर जनरल राजस्थान सर्किल को विपक्षी बनाया गया है जिसके अधीन ही यह श्रमिक कार्यरत रहा था और सेवा की थी इसीलिए मेरी राय में भारत सरकार आवश्यक पक्षकार नहीं थी और इसके अभाव में भी अप्रार्थी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता है। अतः यह प्रारंभिक आपत्ति भी खारिज की जाती है।

7. गुणावगुण पर श्रमिक मंगलराम वर्मा ने क्लेम की तरह ही अपने शपथ पत्र में भी दर्ज किया है कि उसे जुलाई 1986 से 10 जून 1989 तक लगातार पी.एम.जी. कार्यालय में दैनिक वेतन पर बागवानी का कार्य किया है। प्रति-परीक्षा में भी श्रमिक कहता है कि उनके साथ लालाराम, अर्जुनलाल, सत्य नारायण, नन्द लाल आली कार्य करते थे। दफ्तर के अलावा पी.एम.जी. के घर पर भी पौधे लगाये थे। तीन बंगले थे जिनकी दूब काटता था, पानी देता था, दफ्तर में भी पानी की ड्यूटी दी थी, बगीचा का काम तो करते ही थे। 1½ बीघा में बगीचा था। सुबह 8-1/2 बजे से शाम 5 बजे तक काम करते थे। श्रमिक से प्रति परीक्षा में मुझाव के रूप में भी यह नहीं पूछा गया है। उसने सेवा मुक्ति से पूर्व कभी एक वर्ष में 240 दिवस काम नहीं किया हो। नियोजक साक्षी श्री सी.एल. पुरी भी अपने शपथ पत्र में यह नहीं कहता है कि श्रमिक ने एक वर्ष में 240 दिवस की सेवा नहीं की हो। प्रति-परीक्षा में नियोजक साक्षी कहता है कि उसे दिसम्बर, 1990 से पहले की जानकारी नहीं है और रिकार्ड के आधार पर ही वह बयान देने आया है। नियोजक साक्षी यह भी कहता है कि रिकार्ड में ऐसा दर्ज नहीं है कि उक्त श्रमिक से 2-3 घण्टे ही काम लेते थे। नियोजक साक्षी यह स्वीकार करता है कि श्रमिक की हाजिरी हाजिरी रजिस्टर में लगती थी जिसमें भी ड्यूटी आवर्स दर्ज नहीं है। तथा यह भी लिखा नहीं है कि 2-3 घण्टे ही काम करेगा। इन परिस्थितियों में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से साबित है कि श्रमिक ने 10-6-89 को समाप्त हुए एक कलेंडर वर्ष में 240 दिवस से अधिक की सेवा पूरी कर ली थी। निर्विवाद रूप से श्रमिक को धारा 25 एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया अर्थात् न तो एक माह का नोटिस, न उसके एवज में एक माह का वेतन यहां तक कि छंटनी का भत्ता भी नहीं दिया गया है इसलिए श्रमिक की सेवा मुक्ति धारा 25-एफ के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हो जाती है।

8 धारा 25-जी एवं एच की अवहेलना साबित नहीं है क्योंकि श्रमिक यह साबित कर नहीं पाया कि 10-6-89 को उससे कोई घनिष्ठ बागवान भी कार्यरत रहा हो अथवा सेवा मुक्ति के उपरांत किसी अन्य बागवान को भी नियुक्त किया गया हो।

9 उपरोक्त समस्त कारणों से इस निदेश का अधिनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :

“श्रमिक मंगलराम वर्मा, दैनिक वेतन भोगी बागवान की दिनांक 11-6-89 से सेवा मुक्ति अनुचित एवं अवैध है और उसे उक्त पद पर नियोजित घोषित किया जाता है तथा सेवा की निरन्तरता कायम रखते हुए उसे सेवा मुक्ति अवधि का समस्त वेतन एवं अन्य सभी लाभ दिलाये जाते। अगर नियोजक अंदर तीन माह उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 रुपये खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है।”

10. उक्त आशय का अवाई पारित किया जाता है जिसे भारत सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ.1383:- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन जयपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं.एल-42012/52/84-डी. 2 (बी) (पार्ट)]

बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1383.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Khadi and Gramodyog Commission, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-42012/52/84-D.II(B)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer.

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 30/85

रैफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली की आदेश क्रमांक एल-42012 (2)/84-डी. II (बी) दिनांक 21 मई, 1985 मोहन लाल सोलंकी, वरिष्ठ लिपिक खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, बाहेती भवन, रानी बाजार, बीकानेर।

-प्रार्थी

बनाम

1. अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इला रोड विले पार्क, बम्बई
2. निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, आर-7 सहदेव मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर पोस्ट बोग नं. 15, (जी.पी.ओ.)

—प्रार्थीगण

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : श्री के.एल. जोशी

विपक्षी की ओर से : कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवाई : 3-1-1992

अवाई

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली ने अपने उप-रोक्त आदेश द्वारा निम्नविवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

"Whether the action of the Director, V&K Commission Sahdev Marg, 'C' Scheme, Jaipur in stopping one increment of Shri Mohanlal Solanki U.D.C. of Bikaner Office with cumulative effect from 25-6-81 for one year is legal? If not, what relief Shri Solanki is entitled to?"

2. श्री मोहन लाल सोलंकी जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बीकानेर कार्यालय में 26-4-85 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी। उसका कार्य हमेशा सन्तोषजनक था परन्तु वह खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन का सदस्य था जो एक मान्यता प्राप्त यूनियन थी और अप्रार्थीगण ने एक प्रतिद्वन्दी राष्ट्रीय खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन खड़ी कर रखी थी जिसकी आड़ में कर्मचारियों का शोषण करता था। प्रार्थी श्रमिक उक्त यूनियन का सदस्य नहीं बन रहा था इसलिए नियोजक ने अकारक प्रार्थी श्रमिक का स्थानान्तरण कर दिया तथा चार्ज शीट आदि भी देते रहते थे। प्रार्थी श्रमिक का कहना है कि उक्त कारण से ही उसका स्थानान्तरण बाडमेर से बीकानेर किया गया था और उसने नियमानुसार टी.ए. डी.ए. भी बिल बनाकर प्राप्त किया था व अपना सामान अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी बाडमेर की बिल्टी सं. 3280 से लाया था जिसका 467/- रुपये प्रार्थी श्रमिक ने कमीशन से लिये थे। श्रमिक का कहना है कि 3280 नं. बिल्टी की दूसरी प्रति अर्थात् ड्राइवर कापी से खादी कार्यालय का समान आया व उसका भुगतान हुआ जो सब कार्य फर्ज थे इसलिए 13-1-81 को खादी कमीशन के निदेशक बीकानेर आये जिन्होंने प्रार्थी श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से धमकाया और कहा कि प्रार्थी ने गलत बिल्टी प्राप्त करके झूठा क्लेम किया है तथा प्रार्थी को बर्खास्त कर देंगे या फिर प्रार्थी अपनी बात सही होते हुए भी गलती मान

ले और लिखकर दे दे व पैसे वापस करे अन्यथा उसे नौकरी से निकाल दिया जायेगा। श्रमिक कहता है 27-2-81 को अप्रार्थी सं. 2 ने उसे सूचित किया कि उसने गलत काम किया है क्यों न उसकी 2 वेतन वृद्धियां रोक दी जायें। बाद में 25-6-81 के पत्र द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई जिसकी भी प्रार्थी श्रमिक को सूचना नहीं दी गई इसलिए यह अपील पेश करने में असमर्थ रहा। श्रमिक कहता है हालांकि 25-6-81 के आदेश द्वारा उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी गई थी फिर भी उसे अप्रार्थी नियोजक ने संचयी प्रभाव से मानते हुए आगामी वर्षों की वेतन वृद्धियां नियमानुसार नहीं दी। श्रमिक कहता है खादी कमीशन के कन्डक्ट डिप्टीपिलीन एवं अपील रीगुलेशन की धारा 27 के अनुसार छोटी सजा देने की प्रक्रिया है और धारा 26 में बड़ी सजा देने की प्रक्रिया है। प्रार्थी श्रमिक के विरुद्ध धारा 27 के अन्तर्गत ही कार्यवाही की गई है जिसके अनुसार भी संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि नहीं रोकी जा सकेगी। श्रमिक का कहना है जब वेतन वृद्धि रोकी गई उस समय उसका मूल वेतन 452/- रुपये था जो 5-5-81 को श्रमिक प्राप्त कर रहा था 5-5-82 से मिलने वाली वेतन वृद्धि से वह वंचित रहा। 5-5-83 को उसे एक साथ दो वेतन वृद्धियां देनी अपेक्षित थी, 10/- रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि थी परन्तु नियोजक ने 5-5-83 को 472/- की वजह 462/- रुपये ही वेतन वृद्धि लगाकर दिये और इस प्रकार हालांकि संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकने का आदेश नहीं था फिर भी वास्तव में संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी गई है जो नियम विरुद्ध है।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये संयुक्त प्रत्युत्तर कहा है कि खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन कोई मान्यता नहीं रखती है। प्रार्थी का उक्त यूनियन से क्या संबंध है पता नहीं। विपक्षी ने किसी किस्म की कोई यूनियन राजस्थान में खड़ी नहीं की है तथा राष्ट्रीय खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन ही मान्यता प्राप्त एक मात्र यूनियन है इसलिए प्रार्थी का यह कथन गलत है कि नियोजक ने उसे उक्त यूनियन का सदस्य बनने हेतु किसी प्रकार प्रताड़ित किया हो।

4. गुणावगुण पर नियोजक का कहना है कि श्रमिक मोहन लाल सोलंकी का स्थानान्तरण बाडमेर से बीकानेर किया गया था और उसने 27-8-79 से 16-8-79 की अवधि का यात्रा बिल भी प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार अपना घरेलू सामान बाडमेर से बीकानेर लाने की अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्टी सं. 3290, 467/- रुपये की पेश की थी और उक्त राशि चार्ज की थी। विपक्षी संस्थान के कार्यालय द्वारा जांच करने पर उक्त बिल्टी गलत पाई गई थी और श्रमिक ने भी अपने पत्र 31-1-81 द्वारा अपनी मूल स्वीकार की थी और भविष्य में ऐसी भूल नहीं करने का वायदा भी किया था तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निवेदन किया गया था। नियोजक यह भी कहते हैं कि उन्होंने श्रमिक को 15-1-81 के पत्र द्वारा यह सूचना दी थी कि

गलत बिल्टी देकर जो 467 रुपये कार्यालय से प्राप्त किये हैं वे बीकानेर कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे इस पर श्रमिक ने 23-1-81 को अपने पत्र द्वारा 10 किशतों में उक्त रकम काटने का निवेदन किया था जो प्रार्थना नियोजक ने 4-2-81 के पत्र द्वारा अस्वीकार कर दी इस पर श्रमिक ने 9-2-81 को 467 रुपये बीकानेर कार्यालय में रसीद सं. 5113 द्वारा जमा करा दिये तत्पश्चात श्रमिक को 27-2-81 के ज्ञापन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उसने कमीशन के सी.डी.ए. नियमों का उल्लंघन किया है क्यों न उसे दो वार्षिक वेतन वृद्धियां बन्द करने की सजा दी जाए। इस पर श्रमिक ने 5-3-81 के पत्र द्वारा निवेदन किया कि प्रस्तावित सजा आत्याधिक है और सहानुभूति-पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। फरवरी 25-6-81 के ज्ञापन द्वारा श्रमिक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की सूचना दी गई। इस पर श्रमिक ने कोई आपत्ति नहीं की न ही उच्चाधिकारियों को कोई अपील की। नियोजक का कहना है कि खादी कमीशन के निदेशक ने 13-1-87 को श्रमिक को नहीं धमकाया और न ही नौकरी से बर्खास्त करने की धमकी दी। उक्त तथ्य श्रमिक ने झूठे, मनगढ़त एवं कूट रचित किये हैं। माईनर पैन्ल्टी के प्रावधान धारा 27 में दिये गये हैं जिनके अनुसार श्रमिक को एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है और श्रमिक अधिकारी नहीं है।

5. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक मोहन लाल ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री वेद प्रकाश आर्य ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रालेखिक साक्ष्य में एम-1 लगाय एम-9 प्रलेखों की फोटो प्रतियां पेश कीं। तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

6. प्रार्थी श्रमिक का कहना है कि वह नियोजक द्वारा खड़ी की गई प्रतिद्वन्द्वी यूनियन राष्ट्रीय खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन का सदस्य नहीं बना इसलिए दुर्भाग्य से उसे दण्डित किया गया है। श्रमिक के उक्त कथनों में सत्यता का आभास नहीं होता क्योंकि न तो श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है और न ही वेद प्रकाश आर्य से उक्त विषय में कोई प्रति-परीक्षा की है, इसलिए प्रार्थी श्रमिक का यह कथन साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रीय खादी कमीशन कर्मचारी यूनियन का सदस्य नहीं बनने के कारण दुर्भाग्य से श्रमिक को दण्डित किया गया हो।

7. गुणावगुण पर श्रमिक कहता है बाड़मेर से बीकानेर स्थानान्तरण होने पर वह अग्रवाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी बाड़मेर की बिल्टम नं. 3280 से घरेलू सामान लाया था जिस बाबत 467 रुपये अप्रार्थी से प्राप्त किये थे। श्रमिक का यह भी कहना है कि उक्त बिल्टी को ड्राईवर काँपी से कमीशन कार्या-

लय का सामान आया व उसका भुगतान हुआ था जो श्रमिक ने अनुसार कमीशन ने फर्जी, कार्यवाही की थी जिस बाबत 13-1-88 को कमीशन के निदेशक श्री छोटे लाल शर्मा ने बीकानेर आकर उसे डराया, व धमकाया था और कहा था कि उक्त बिल्टी से कमीशन का सामान आता है इसलिए वह रुपये जमा करा दे। हालांकि उक्त विषय का उल्लेख श्रमिक ने अपने शपथ पत्र में भी किया है परंतु श्रमिक के उपरोक्त अप्रुष्ट कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि बिल्टी नं. 3280 से उसका सामान आया था और बीकानेर कार्यालय का सामान नहीं आया था क्योंकि श्रमिक के उक्त कथनों के विपरीत नियोजक की तरफ से वेद प्रकाश आर्य ने अपने शपथ पत्र में दर्ज किया है कि बिल्टी एम-2 से बीकानेर कार्यालय का ही सामान आया था। श्रमिक ने 3280 नं. की बिल्टी से अपना सामान बाड़मेर से बीकानेर लाने का फर्जी क्लेम किया था जिस बाबत उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी से भी पूछताछ की गई थी जिन्होंने भी कहा था कि वास्तव में इस बिल्टी से श्रमिक मोहन लाल का सामान नहीं आया बल्कि खादी कमीशन का सामान आया था और 3280 नं. की बिल्टी की कार्बन काँपी श्री सोलंकी के कहने से ट्रांसपोर्ट कम्पनी के लिपिक श्री बाबू लाल ने श्री सोलंकी को दी थी। नियोजक साक्षी श्री वेद प्रकाश आर्य से श्रमिक की तरफ से उक्त विषय पर नाम मात्र की भी प्रति परीक्षा नहीं की गई है। नियोजक साक्षी के कथनों पर विश्वास करना सुरक्षित है क्योंकि 3280 नं. की बिल्टी से खादी कमीशन का सामान 12-7-80 को आया था जबकि एम-2 उसकी कार्बन काँपी है जो श्रमिक की तरफ से पेश हुई है इस पर 15-8-79 को तारीख अंकित है। यह उल्लेखनीय है कि 3279 नं. की बिल्टी से 11-11-79 से 1-7-80 तक की अवधि का वृज मोहन कल्ला का सामान आया था जिससे भी यह निष्कर्ष निकलता है कि 3279 बिल्टी के उपरांत 3280 नं. बिल्टी से 15-8-79 को सामान आना संभव नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि 31-1-81 के पत्र एम-3 द्वारा श्रमिक ने अपनी भूल स्वीकार की थी। 23-1-81 के पत्र एम-7 द्वारा भी श्रमिक ने 10 किशतों में 467 रुपये की राशि जमा कराने का निवेदन किया था और 9-2-81 को श्रमिक ने रसीद सं. 5113 द्वारा 467 रुपये बीकानेर कार्यालय में जमा करा दिये थे। 5-3-81 को भी श्रमिक ने एम-4 पत्र द्वारा सूचित किया था कि 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने की प्रस्तावित सजा बहुत अधिक है और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया था। तत्पश्चात 25-6-81 प्रदर्श एम-9 द्वारा प्रार्थी को एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। यह उल्लेखनीय है कि इसमें से किसी भी पत्र में यह दर्ज नहीं किया है कि उसने कोई दुराचरण नहीं किया है बल्कि खादी कमीशन के निदेशक द्वारा डराने धमकाने से ही उसने गलती स्वीकार की है। अगर वास्तव में निदेशक ने कभी डराया धमकाया होता तो क्लेम पेश करने के पूर्व श्रमिक ने उक्त विषय की शिकायत किसी उच्चाधिकारी को क्यों नहीं की। उपरोक्त समस्त

कारणों से मेरी राय में नियोजक के कथनों में सत्यता का आभास होता है कि श्री मोहन लाल सोलंकी ने 3280 नं. की बिल्टी से वास्तव में घरेलू सामान नहीं लाकर खादी कमीशन, बीकानेर कार्यालय से 467 रुपये कर फर्जी भुगतान प्राप्त कर लिया था जिसके लिए कमीशन द्वारा श्रमिक को 25-6-81 के आदेश एम-9 द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी। अतः इन परिस्थितियों में प्रार्थी श्रमिक के कथनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. प्रार्थी श्रमिक के प्रतिनिधि का अंतिम तर्क यह था कि एम-9 आदेश द्वारा एक वार्षिक वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव के रोकने का आदेश था परंतु वास्तव में नियोजक ने उक्त वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक रखी है। इस विषय में यह उल्लेखनीय है कि जब 25-6-81 के आदेश द्वारा बिना संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकी गई थी तो नियोजक से यह अपेक्षा थी कि वह एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक वर्ष तक रोकने के उपरांत श्रमिक को वेतन वृद्धियों का पूरा लाभ देता। अतः इन परिस्थितियों में इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है:

“श्रमिक श्री मोहन लाल सोलंकी, यू.डी.सी. बीकानेर की 25-6-81 से एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकना न्यायोचित नहीं है। उक्त वेतन वृद्धि बिना संचयी प्रभाव से ही रोकी गई है इसलिए यह श्रमिक संचयी प्रभाव से रोकी गई वेतन वृद्धियों की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। 100 रुपये खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है।”

9. अवार्ड की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 17(1) अधिनियम पठाई जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1384—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, बीकानेर के प्रबन्धत्व के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5 मई, 1992 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-41012/152/89-आई.आर. (डी.यू.)पीटी]

बी.एम.डेविड, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1384.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Railway, Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-41012/152/89-IR. (DU)(Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी. आई.टी. 47/1990

रफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-41012/152/89-आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 27-7-90

श्री दिलदार पुत्र श्री रामजान जरिये महापंडित, रेलवे कैंज्युअल लेबर यूनियन (प. 33/69) डाना स्कूल के पास, बीकानेर।

—प्रार्थी

बनाम

1. जनरल मैनेजर, नोर्दन रेलवे, मुख्यालय बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली।
2. डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर (वर्कशाप) उत्तर रेलवे, लालगढ़ (बीकानेर)
3. सहायक कार्मिक अधिकारी, (वर्कशाप) उत्तर रेलवे अप्रायौगण लालगढ़ (बीकानेर)

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से: श्री अरविन्द सिंह

अप्रायौगण की ओर से: श्री धन सिंह

दिनांक अवार्ड: 20-2-1992

अवार्ड

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 17(1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है:

“Whether the action of the management of Dy. Chief Mechanical Engineer, Northern Railway, Kikaner is justified in terminating the services of Shri Dildar Khan S/o Shri Mohd. Ramzana w.e.f. 16-9-85? If not, what relief he is entitled to and from what date?”

2. महामंत्री, रेलवे कैंज्युअल लेबर यूनियन, बीकानेर जिसे तत्पश्चात् प्रार्थी संघ, संबोधित किया है ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि श्रमिक श्री दिलदार खान दिनांक 23-10-82 को नोर्दन रेलवे मैकेनिकल वर्कशाप बीकानेर की प्रोडक्शन शाखा में खलासी के पद पर नियुक्त हुआ था। और उसके तत्पश्चात् लगातार सेवा की थी तथा प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 240 दिवस के अधिक सेवा पूरी कर ली थी। श्रमिक को 17-9-85 को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सी-1 कैटेगरी में अनफिट कर दिया गया। प्रार्थी संघ कहता है कि श्रमिक ने सी-2 कैटेगरी में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बारम्बार निवेदन किया परन्तु नियोजक श्रमिक को सी-2 कैटेगरी में परीक्षण हेतु मेडिकल मीमो नहीं दिया। अंततोगत्वा श्रमिक की प्रार्थना पर मेडिकल बोर्ड बिठाया गया जिसने क्रमांक एम. जे. 2192/90 दिनांक 21-7-1990 द्वारा परीक्षण की सी-1 कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया किया। प्रार्थी संघ कहता है कि उत्तर रेलवे वर्कशाप की शाप नं. 21 में खलासी की जगह सी-डू मेडिकल कैटेगरी खाली है फिर भी कर्मचारी को उपरोक्त नियोजन में नहीं लिया और 16-9-85 के दोषहर बाद से उसे रिट्रेन्च कर दिया। रिट्रेन्च करने से पहले न तो वरिष्ठता सूची तैयार की और न ही 25-एफ के प्रावधानों को पालना की। सेवा मुक्ति के उपरान्त से भी अनेकों श्रमिकों की भर्ती की गई है परन्तु श्रमिक को सूचना तक नहीं दी गई और इस तरह 25-एफ का भी उल्लंघन हुआ है। प्रार्थी संघ की प्रार्थना है कि सेवा मुक्ति आदेश अनास्त किये जायें और श्रमिक को खलासी के पद पर नियोजित मानते हुए दिनांक 16-9-85 से उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि 28-11-85 को कार्यालय पत्रांक 131 ई-1/भाग 6 दिनांक 28-11-85 द्वारा प्रार्थी को सी-टू में चिकित्सा परीक्षा कराने हेतु पत्र लिखा गया, परन्तु प्रार्थी उक्त पत्र लेने कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ इसलिए उसकी कोई चिकित्सा परीक्षा नहीं कराई गई। बर्क-शाप में सी-टू कैटेगरी का कोई स्थान नहीं है। प्रार्थी की छंटनी नहीं की गई बल्कि सी-वन कैटेगरी की मेडिकल परीक्षा में असफल घोषित होने से वह खलासी के पद पर नियुक्त होने के पूर्णतः अयोग्य हो गया। श्रमिक को कभी भी सी.पी.सी. स्केल के अन्तर्गत अस्थाई पद नहीं दिया गया था इसलिए उसे नोटिस अथवा नोटिस वेतन या छंटनी का मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता। धारा 25-एफ, 25-सी या नियम 77 लागू नहीं होते हैं इसलिए क्लेम खारिज किया जाये।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्री दिलदार खान ने अपना स्वयं का शपथ पत्र पेश कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक के प्रतिनिधि ने जिरह की और प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 व डब्ल्यू-2 फोटो प्रतियां पेश की गईं। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से राम चन्द्र मीणा ने शपथ पत्र पेश किया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। प्रालेखिक साक्ष्य में एम-1 लगायत एम-5 फोटो प्रतियां पेश की गईं। तत्पश्चात मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तार-पूर्वक सुना।

5. श्रमिक कहता है 23-10-82 को उसे खलासी के पद पर नियुक्त किया गया था जहां पर उसने 16-9-85 तक लगातार सेवा की है। 29-20-85 को उसे स्वास्थ्य परीक्षण सी-वन कैटेगरी में अनफिट कर दिया। साथी कहता है सी-टू कैटेगरी में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसने बारम्बार निवेदन किया था परन्तु सी-टू कैटेगरी में परीक्षण हेतु उसे मेडिकल मीमो नहीं दिया गया। प्रति परीक्षा में भी श्रमिक कहता है 28-11-85 को उसे सी-टू कैटेगरी का लैटर नहीं दिया गया, सी-वन का दिया था जिसमें मैं फेल हो गया था इसलिए मुझे निकाल दिया। श्रमिक के उक्त कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है विशेषकर, उस परिस्थिति में जबकि सी-टू कैटेगरी में मीमो की तथाकथित पत्र की फोटो प्रति भी पेश नहीं की गई है। जिस पत्र प्रदर्श एम-5 का उल्लेख नियोजक साक्षी ने किया है उसके निरीक्षण से भी वही निष्कर्ष निकलता है कि श्रमिक सी-वन कैटेगरी में फेल हो गया था और सी-टू मेडिकल कैटेगरी में कोई पद खाली नहीं था इसलिए उक्त कैटेगरी के लिए उसका मुआयना नहीं कराया गया। अभिप्राय यह है कि एम-5 पत्र से भी श्रमिक के ही कथनों की पुष्टि होती है। यह उल्लेखनीय है कि दैनिक वेतन पर खलासी की नियुक्ति श्रमिक की की गई थी। और उसे नियमित करने के लिए ही सी-वन कैटेगरी का स्वास्थ्य परीक्षण पास करना आवश्यक था। अगर वास्तव में खलासी के पद पर उसे नियमित नहीं किया जा सकता था तो कम से कम खलासी के दैनिक वेतन वाले पद पर तो श्रमिक को नियोजित रखा जा सकता था। तर्क के लिए मान भी लें कि खलासी वाला पद या कार्य समाप्त हो गया था तो भी नियोजक से यह अपेक्षा थी कि वे धारा 25-एफ के प्रावधानों की तो पालना करते क्योंकि श्रमिक की ही तरह नियोजक साक्षी श्री रामचन्द्र मीणा ने भी स्वीकार किया है कि 16-9-84 से 14-9-85 तक इस श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी। इन परिस्थितियों में चाहे दैनिक वेतन पर ही नियोजित था, चूंकि श्रमिक ने एक कलेंडर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी इसलिए धारा 25-एफ के प्रावधानों की अनुपालना करना आवश्यक था इसके अभाव में की गई सेवा मुक्ति स्वतः ही अनुचित अवैध एवं शून्य हो जाती है।

6. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है:

“श्रमिक दिलदार खान खलासी की दिनांक 16-9-85 से की गई सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है और उसे खलासी के उक्त पद पर नियोजित मानते हुए, सेवा की निरन्तरता कायम

रखते हुए इसे उक्त पद का समस्त वेतन एवं अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक ने अन्दर तीन माह उक्त राशि अदा नहीं की तो 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।”

7. उपरोक्त आशय का अर्वाइड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को वास्ते प्रकाशन अन्तर्गत धारा 17(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम भेजा जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1385—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. डी. ओ. (फोन्स) जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5 मई, 1992 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 40012/197/90/आई आर (डी यू) बी. एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1385.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SD.O. (Phones), Jodhpur and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/197/90-IR (DU) Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण

केस नं. सी.आई.टी. 62/1991

रेफरेंस : भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/197/90-आई.आर. (डी यू.) दिनांक 12-9-91

श्री जवरो लाल पुत्र श्री रामोजी प्रजापत निवासी नागौरी बेरा, मन्दौर, जोधपुर।

—प्रार्थी

बनाम

सब डिवीजनल ऑफीसर, कोन्स, जोधपुर

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से : कोई हाजिर नहीं
दिनांक अर्वाइड : 23-12-1991

अर्वाइड

फरीकेन की ओर से कोई हाजिर नहीं है। प्रार्थी की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश करने हेतु यह केस आज निश्चित है किन्तु न तो प्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित आया और ना ही कोई क्लेम पेश हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार अब इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं,

अतः मामले में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1386.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डिब्रीजनल इंजीनियर टेलीकॉम्यूनिकेशन, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-40011/5/91-आई.आर. (डी.यू.) (पार्टे)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1386.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Divisional Engineer Telecom Jodhpur and their workmen which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40011/5/91-IR (DU) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 56/1991

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश दिनांक 11-10-91 क्रमांक एल-40011/5/91-आई.आर. (डी.यू.) सर्वश्री दिलावर खां, ताज मोहम्मद, सूरज मल एवं खाजू खान मार्फत भारतीय मजदूर संघ, पुरानी मण्डी अजमेर।

—प्राथी

बनाम

डिब्रीजनल इंजीनियर, टेलीकॉम्यूनिकेशन, जोधपुर।

—अप्राथी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर.एच.जे. एस.

प्राथी की ओर से:

कोई हाजिर नहीं

अप्राथी की ओर से

कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड:

23 दिसम्बर, 1991

अवार्ड

पक्षकारों की ओर से कोई हाजिर नहीं है। आज यूनियन की ओर से क्लेम पेश करना था किन्तु न तो कोई हाजिर हुआ और न ही क्लेम पेश हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार अब इस मामले में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः प्रकरण में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है जो भारत सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1387.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मिलट्री फार्म डिपो, नसीराबाद के प्रबन्धतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर

के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-14012/82/91-आई.आर. (डी.यू.) (पार्टे)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1387.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Military Farm Depot, Naseerabad and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-14012/82/91-IR (DU) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 57/91

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-14012/82/91-आई.आर. (डी.यू.) (दिनांक 11-10-91) श्री सोम दत्त शर्मा पुत्र श्री राम वालिमकी छोटी बजारी मिलिट्री अस्पताल के पास, नसीराबाद।

—प्राथी

बनाम

आफीसर इंचार्ज, मिलिट्री फार्म डिपो, नसीराबाद।

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंहजी, आर.एच.जे. एस.

प्राथी की ओर से

कोई हाजिर नहीं

अप्राथी की ओर से

कोई हाजिर नहीं

दिनांक अवार्ड:

23-12-91

अवार्ड

पक्षकारों की ओर से कोई हाजिर नहीं है। प्राथी की ओर से स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश करने हेतु यह केस आज नियत था किन्तु न तो प्राथी स्वयं अथवा उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित आया और न ही कोई क्लेम पेश हुआ। ऐसा लगता है श्रमिक अब इस मामले को आगे चलाने में रुचि नहीं रखता है। अतः प्रकरण में नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली 14 मई, 1992

का.आ. 1388.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. (टी) सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-40012/75/89-आई.आर. (डी.यू.) (पार्टे)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1388.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between

the employers in relation to the management of S.D.O. (T) Suratgarh and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/75/89-IR (DU) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर ।

केस नं. सी.आई.टी. 7/1990

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/75/89/आई.आर. (डी.यू.) दिनांक 15-1-90 श्री गजानगर माफ़त जनरल सैक्रेट्री भारतीय मजदूर संघ जे.सी.टी. मिल्स के सामने, श्री गंगानगर 33500

--प्रार्थी

बनाम

सब डिबेंजनल ऑफिसर (टो) सूरतगढ़।

--अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी युनियन को ओर से श्री जसवीर सिंह यादव
अप्रार्थी की ओर से: श्री एन. के. शर्मा, एस.डी.ओ.
दिनांक अर्वाइ: 30-12-91 (कैम्प श्री गंगानगर)

अर्वाइ

श्री जसवीर सिंह यादव संघ की ओर से तथा श्री एन. के. शर्मा एस.डी.ओ. (टी) श्री गंगानगर उपस्थित हैं। संघ की शहादत हेतु आज यह केस नियत है। श्री जसवीर सिंह शहादत के लिए समय चाहते हैं, श्री शर्मा को ऐतराज है। श्री यादव ने जाहिर किया कि श्रमिक को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. कई बार शहादत देन के लिए लिखा गया लेकिन आज तक श्रमिक हाजिर नहीं हुआ है। युनियन को लगातार दिनांक 14-11-90 से शहादत पेश करने के लिए अवसर दिया जा रहा है और मेरी राय में अब और समय दिया जाना उचित नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में इस प्रकरण में नो डिस्प्यूट अर्वाइ पारित किया जाता है जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ. 1389 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. (टेलीग्राफ्स) के श्री गंगा नगर के प्रबन्धतल के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-40012/149/89-डी. 2(बी). (पार्ट)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1389.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between SDO (Telegraphs) Sriganganagar and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/149/89-II(B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर

केस नं. सी.आई.टी. 44/1990

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्रमांक एल-40012/149/89-डी. 2 (बी) दिनांक 11-7-1990 श्री परमानन्द पुत्र श्री मंगोलसल, श्रमिक टेलीफोन विभाग, सूरतगढ़

—प्रार्थी

बनाम

उप मंडल अधिकारी (तार) (एस.डी.ओ.) (टो) सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जो, आर.एच.एस.

प्रार्थी की ओर से: श्री जसवीर सिंह यादव

अप्रार्थी की ओर से: श्री प्रवीन बलवदा

दिनांक अर्वाइ: 3 फरवरी, 1992

अर्वाइ

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपनी उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1)(घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है :

Whether the SDO (T) Suratgarh is just and legal in terminating the services of the workman Shri Parmanand S/o Shri Mangilal w.e.f. 1-7-88 without paying him retrenchment compensation though he has worked for more than 240 days in twelve calendar months. If not to what relief is the concerned workman entitled for ?

2. प्रार्थी परमानन्द जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संबोधित किया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति लेबर के स्थाई पद पर 1-12-81 को की गई थी और उसने बिना विधि-व्यवधान के निरन्तर 30-6-88 तक ड्यूटी अंजाम दी थी और एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा अवधि पूरी कर ली थी परन्तु फिर भी उसे बिना कारण बताये 1-7-88 से सेवा मुक्त कर दिया गया। इतना ही कहा कि अब काम समाप्त हो गया है। श्रमिक कहता है सेवा मुक्ति से पूर्व कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई, न छंटनी की लिस्ट तैयार की। "पीछे आओ पहले जाओ" के सिद्धान्त को भी नहीं अपनाया व न ही 25-एफ के प्रावधानों की पालना की गई। सेवा मुक्ति के उपरांत भी बहुत से अन्य श्रमिकों को नियुक्त किया गया है और श्रमिक से कनिष्ठ व्यक्ति भी कार्य-रत हैं, इस प्रकार धारा 25-एफ, व 25-एच की अवहेलना की गई है। इसलिए सेवा मुक्ति आदेश अपास्त किया जाये और प्रार्थी को सेवा में मानते हुए उसके पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर कहा है कि वादी को किसी स्थाई पद पर या स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं की गई थी बल्कि उसे दिन प्रति दिन के कार्य हेतु मस्टररोल पर रखा गया था। उसने 1-12-81 से 30-6-88 तक ड्यूटी भी लगातार नहीं दी थी अगस्त, 1983 से फरवरी 1987 तक उसने एक दिन भी कार्य नहीं किया है। अप्रार्थी यह तो स्वीकार करता है कि वादी ने अपना कार्य सही ढंग से किया है परन्तु दैनिक वेतन भोगी श्रमिक होने के कारण अनुमानात्मक कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था। विभागीय नियमानुसार 30-3-85 के पश्चात् रखे गये दैनिक श्रमिकों को हटाना था, उन्ही नियमों की अनुपालना में श्रमिक को भी एक मास पूर्व लिखित में सूचित कर हटाया गया था। नियोजक स्वीकार करता है कि धारा 25-एफ के प्रावधानों की पालना नहीं की गई अर्थात् छंटनी भत्ता नहीं दिया गया जो नियोजक के अनुसार आवश्यक नहीं था।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक श्री परमानन्द ने अपनी शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-7 फोटो प्रतियां प्रस्तुत की हैं। इसके विपरीत नियोजक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा सहायक अभियन्त ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की। तत्पश्चात् मंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

5. क्लेम में तो श्रमिक ने दर्ज किया है कि उसकी नियुक्ति लेबर के स्थाई व स्वीकृत पद पर की गई थी इस तथ्य को नियोजक ने अस्वीकार किया है। अपने शपथ पत्र में भी परमानन्द क्लेम के कथनों को ही दोहराता हुआ कहता है कि उसकी नियुक्ति स्थाई व स्वीकृत पद पर की गई थी। परन्तु श्रमिक की तरफ से जो प्रलेख डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-4 पेश किये गये हैं उनमें मस्टररोल के नम्बर दर्ज हैं जिनके अनुसार श्रमिक को नियोजित कर उससे कार्य लिया गया था इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखिक व मौखिक साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि श्रमिक को लेबर के स्थाई एवं स्वीकृत पद पर नियोजित किया गया हो।

6. क्लेम में श्रमिक ने यह भी कहा है कि उसने 1-12-81 से 30-6-88 तक लगातार सेवा की है। परन्तु प्रति परीक्षा में परमानन्द स्वीकार करता है कि उसने 1-12-81 से 30-6-83 तक नौकरी की थी तत्पश्चात् 1983 से 1987 तक वह बीमार रहा था इसलिए काम पर नहीं आया। 1-3-87 को वह दुबारा नौकरी पर आया था तब से लेकर जुलाई 1988 तक उसने लगातार सेवा की है जिस बाबत प्रलेख डब्ल्यू-3 का उल्लेख किया है। नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार शर्मा सहायक अभियन्ता ने भी प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि मार्च 1987 से 30-6-88 तक परमानन्द लगातार काम पर रहा था। अतः इस स्वीकारोक्ति से तथा उपरोक्त मौखिक व प्रालेखिक साक्ष्य से यह साबित है कि श्रमिक परमानन्द मार्च 1987 से 30-6-88 तक लगातार सेवारत रहा है और इस प्रकार उसने सेवा मुक्ति के दिन समाप्त हुए एक कलैन्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी कर ली थी।

7. क्लेम में तो श्रमिक कहता है कि उसे सेवा मुक्ति से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया। परन्तु नियोजक साक्षी श्री नरेन्द्र कुमार का कहना है कि उसे एक माह का नोटिस दिया था। तथ्याकथित नोटिस की प्रति न तो अभिलेख पर पेश की गई है और न ही श्रमिक से इस बाबत प्रति परीक्षा की गई है। इसलिए यह साबित नहीं है कि सेवामुक्ति से पूर्व एक माह का नोटिस श्रमिक को दिया गया हो। निर्विवाद रूप से श्रमिक को छंटनी भत्ता भी नहीं दिया गया इसलिए धारा 25-एफ के प्रावधानों की अवहेलना हुई है। कोई वरिष्ठता सूची भी नहीं बनाई गई, इसलिए भी यह नहीं कहा जा सकता कि नियोजक ने "पीछे आओ पहले जाओ" के सिद्धान्त का पालन किया हो। इस प्रकार धारा 25-जी को भी अवहेलना की गई है। अभिलेख पर यह साबित नहीं है कि सेवा मुक्ति के समय कनिष्ठ व्यक्ति कार्य कर रहे थे और न ही यह साबित है कि सेवा मुक्ति के उपरान्त अन्य व्यक्तियों को नियोजन में लिया हो इसलिए धारा 25-एच की अवहेलना होना साबित नहीं है।

8. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से नियोजक ने धारा 25-एफ व 25-जी की अवहेलना की है। सेवा मुक्ति के समय श्रमिक को न तो कोई छंटनी भत्ता दिया और न ही एक माह का नोटिस या नोटिस के एवज में एक माह का वेतन दिया गया। इसलिए गैमन इंडिया बनाम निरंजनदास 1984 (2) उ.म.नि.प. 727 के न्याय दृष्टांत के अनुसार धारा 25-एफ के प्रावधानों की पूर्वापेक्षा के अनुपालन के अभाव में सेवा मुक्ति प्रारंभ से ही शून्य है और इस निर्देश पर अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है:

"दिनांक 1-7-1988 से श्रमिक परमानन्द की सेवा मुक्ति उचित एवं वैध नहीं है। उसे उसके पद पर नियोजित मानते हुए उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। उसकी सेवा की निरन्तरता

कायम रखी जाती है। अगर उक्त राशी अंदर माह नियोजक द्वारा अदा नहीं की गई तो 12 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। 100 रुपये खर्चा मुकदमा भी दिलाया जाता है।"

9. आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रकाशनार्थ अंतर्गत धारा 17(1) अधिनियम भेजी जाये।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी

नई, दिल्ली, 14 मई 1992

का.आ. 1390.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947) का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. डी. ओ. (टी) श्री गंगानगर के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-40012/144/89-डी. 2(बी)(पाट)]

बी. एम डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1390.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (T) Sriganganagar and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/144/89-D.II (B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं. सी.आई. टी. 48/1990

रैफरेंस: भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का

आदेश क्रमांक एल-40012/144/89-डी. 2(बी) दिनांक 25-7-90

श्री राम प्रसाद पुत्र श्री भगवती प्रसाद, श्रीगंगानगर।

—प्रार्थी

बनाम

सब डिपो ऑफीसर एस. डी. ओ. (टी.)

श्रीगंगानगर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित

माननीय न्यायाधीश श्री जगतसिंह जी, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से:

श्री जसवीर सिंह यादव

अप्रार्थी की ओर:

श्री प्रवीन बलवदा

दिनांक अवाद:

3 फरवरी, 1992

अवाद

भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश द्वारा निम्न विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) (घ) के अंतर्गत प्रेषित किया है:

"Whether the SDO(T) is just and legal in terminating the services of the workman Shri Ram Prasad Pal w.e.f. 16-6-1988? If not, what relief he is entitled for?"

2. प्रार्थी राम प्रसाद जिसे तत्पश्चात् श्रमिक संवोधित किया है ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी प्रथम नियुक्ति लेबर के स्थाई व स्वीकृत पद पर 1-8-81 को की गई थी और उसने बिना किसी व्यवधान के निरंतर 15-6-88 तक ड्यूटी अंजाम दी है तथा एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक अवधि तक कार्य किया है फिर भी उसे दिनांक 16-6-88 से बिना कारण बताये सेवा मुक्त कर दिया और सेवा मुक्ति से पूर्व न तो वरिष्ठता सूची बनाई और न ही उसे धारा 25-एफ के प्रावधानों का लाभ दिया। श्रमिक का यह भी कहना है कि उसकी नियुक्ति के बाद से अन्य बहुत से श्रमिकों को लेबर के पद पर नियुक्त किया गया है और प्रार्थी से कनिष्ठ अभी भी सेवा में कार्यरत हैं। इस प्रकार सेवा मुक्ति आदेश स्वतः ही अनुचित एवं अवैध हैं जिसे अपास्त करते हुए उसे पुनर्नियोजित मानते हुए उसके पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जायें।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रत्युत्तर यह अस्वीकार किया है कि श्रमिक को स्वीकृत व स्थाई पद पर लगाया गया हो या उसने 1-8-81 से 15-6-88 तक लगातार कार्य किया हो बल्कि अप्रैल, 1983 से जून 1985 तक यह श्रमिक लगातार अनुपस्थित रहा है और उसने किसी भी कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस कार्य नहीं किया। श्री गंगानगर सब डिवीजन में, जहां यह श्रमिक कार्यरत था, कार्य समाप्त हो गया था, सूरतगढ़ सब डिवीजन में जहां कार्य चल रहा था वहां यह श्रमिक नहीं गया। प्रार्थी की नियुक्ति दैनिक एवं अस्थित कार्य के लिए मास्टररोल पर की गई थी जिसे कोई नोटिस देने का या छुटनी भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपने क्लेम के समर्थन में राम प्रसाद ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया है जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की प्रालेखिक साक्ष्य में डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-9 फोटो प्रतियां पेश की गई हैं। इसके विपरित नियोजक की तरफ से श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक अभियंता ने शपथ पत्र पेश किया है जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की है। तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का निरीक्षण किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक सुना।

4. क्लेम में तो श्रमिक ने कहा है कि उसकी नियुक्ति श्रमिक के स्थाई पद पर 1-8-81 को की गई थी परन्तु अपने शपथ पत्र में श्रमिक यह स्वीकार करता है कि उसकी नियुक्ति अगस्त 1981 में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के पद पर की गई थी। नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार शर्मा ने भी कहा है कि यह दैनिक वेतन पर मास्टररोल पर नियोजित हुआ था। श्रमिक की तरफ से जहां प्रालेखिक साक्ष्य पेश की गई है उनमें डब्ल्यू-1 में भी मास्टररोल का नम्बर व अवधि दर्ज है। डब्ल्यू-2 लगायत डब्ल्यू-4 में कैड्यूसल वर्कर का उल्लेख है अतः उपरोक्त समस्त कारणों से यह तो साबित नहीं है कि श्रमिक को किसी स्वीकृत या स्थाई पद पर नियुक्ति दी गई हो।

5. श्रमिक ने क्लेम में यह भी कहा है कि 1981 से 15-8-88 तक उसने निरंतर ड्यूटी दी है जिस तथ्य को नियोजक ने अस्वीकार किया है और कहा है कि अप्रैल 1983 से जून 1985 तक श्रमिक लगातार गैर-हाजिर रहा है। नियोजक साक्षी नरेन्द्र कुमार शर्मा ने भी अपने शपथ पत्र में उक्त तथ्यों को दोहराया है। श्रमिक राम प्रसाद भी प्रति परीक्षा में स्वीकार करता है कि वह मार्च, 1983 तक नौकरी में रहा था, दुबारा नौकरी पर 1985 के सातवें महीने में आया था। श्रमिक स्वीकार करता है कि वह बीमार था इसलिए बीच में दो वर्ष कुछ महीने नौकरी पर नहीं आ सका। इन परिस्थितियों में श्रमिक का यह कथन भी साबित नहीं है कि उसने अगस्त 1981 से जून 1988 तक लगातार सेवा की हो बल्कि नियोजन का कथन ही साबित है कि यह श्रमिक अप्रैल 1983 से जून 1985 तक लगातार गैर हाजिर रहा था।

6. श्रमिक का क्लेम में एक तर्क यह है कि उसने 15-6-88 तक लगातार सेवा की है और उक्त दिवस को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा अवधि पूरी कर ली थी फिर भी उसे सेवा मुक्ति के समय कोई कारण बताये बिना ही सेवा मुक्त कर दिया। ना तो कोई नोटिस दिया ना ही नोटिस के एवज में एक माह का वेतन यहां तक कि छुटनी भत्ता भी नहीं दिया गया। क्लेम के प्रत्युत्तर में तो

नियोजक ने उक्त तथ्यों को अस्वीकार किया है परन्तु नियोजक साक्षी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि जुलाई 1985 से जून 1988 तक इस श्रमिक ने लगातार काम किया है। डब्ल्यू-1 लगायत डब्ल्यू-6 प्रलेख हमारे विभाग के हैं। दिये हुए हैं इस पर हमारे तत्कालीन एस.डी.ओ. (टी.) के हस्ताक्षर हैं। डब्ल्यू-8 पर डी ई.टी. के हस्ताक्षर हैं। श्रमिक राम प्रसाद ने भी अपने शपथ पत्र में कहा है कि उसने 15-6-88 तक लगातार कार्य किया था। 16-6-88 को भी वह निर्धारित काम पर हाजिर हुआ था परन्तु उसे काम पर लेने से इंकार कर दिया। उस रोज समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में उसने 240 दिवस से अधिक कार्य कर लिया था। शपथ पत्र की चरण सं. 7 में श्रमिक दर्ज करता है कि उसने 1-8-87 से 31-12-87 तक 133 दिवस तथा 1-1-88 से 15-6-88 तक 119 दिवस प्रदर्श डब्ल्यू-5 व 6 के अनुसार कार्य किया है। डब्ल्यू-5 व 6 को अप्रार्थी के साथी ने भी स्वीकार किया है और इस प्रकार श्रमिक की मौखिक साक्ष्य की पुष्टि उसी के द्वारा प्रस्तुत तथा नियोजक साक्षी द्वारा स्वीकृत प्रलेखों द्वारा हो जाने से यह साबित है कि 16-6-88 को समाप्त हुए एक कलैण्डर वर्ष में इस श्रमिक ने 240 दिवस से अधिक सेवा अवधि पूरी कर ली थी।

7. निविवाद रूप से नियोजक ने सेवा मुक्ति के समय न तो श्रमिक को एक माह का नोटिस दिया अथवा नोटिस के एवज में एक माह का वेतन और न ही छुटनी का मुआवजा दिया इसलिए नियोजक द्वारा की गई सेवा मुक्ति धारा 25-एफ के प्रावधानों के विपरीत की गई है जो स्वतः ही प्रारम्भ से ही शून्य है। इस विषय में गैमन इण्डिया बनाम निरंजनदास (1984) 12 उम. निप. 727 के न्याय दृष्टान्त का उल्लेख किया जा सकता है जिसमें भी श्रमिक द्वारा 240 दिवस की सेवा अवधि एक कलैण्डर वर्ष में पूरी कर ली गई थी और उसकी सेवा मुक्ति धारा 25-एफ को पालना किए बिना की गई थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रारम्भ से ही शून्य मानी गई थी। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अग्रनिर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

“श्रमिक राम प्रसाद पाल की दिनांक 16-6-88 से की गई सेवा मुक्ति धारा 25-एफ के प्रावधानों की पालना किये बिना ही की गई है जो प्रारम्भ से ही शून्य है और यह श्रमिक अपने पद पर नियोजित घोषित किया जाता है। इसकी सेवा की निरन्तरता कायम रखी जाती है। इसे उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। 100/- रुपये खर्च मुकदमा भी दिलाया जाता है। अगर नियोजक उक्त राशि अन्तर तीन माह अदा नहीं करेगा तो 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी देना पड़ेगा।”

8. अदाई की प्रति भारत सरकार को वास्ते प्रकाशन अन्तर्गत धारा 17(1) अग्रनियम पठाई जावे।

जगत सिंह, पीठासीन अधिकारी,

नई दिल्ली, 14 मई, 1992

का.आ.1391-—औद्योगिक विवाद अग्रनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस डी ओ (टेलीफोनस) बीकानेर के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निविवाद औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-5-92 को प्राप्त हुआ था।

[संएल-40012/42/89-डी-2(बी) (पीटी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th May, 1992

S.O. 1391.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (Telephones) Bikaner and their workmen, which was received by the Central Government on 5-5-92.

[No. L-40012/42/89-D.II (B) (Pt.)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर,

केस नं. सी.आई.टी. 113/89

केन्द्र सरकार श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या:

एल-40012/42/89-2(बी) दिनांक 30-10-89

जनरल सैक्रेटरी, रेलवे केजुअल लेबर यूनियन, डागा स्कूल के पास, बीकानेर।

बनाम

सब डिवीजनल आफिसर (टेलीफोन्स), बीकानेर।

उपस्थिति

माननीय न्यायाधीश श्री जगत सिंह, आर.एच.जे.एल.

यूनियन की ओर से: श्री अरविन्द सिंह सेंगर

नियोजक पक्ष की ओर से: श्री आर. डी. सोनी

दिनांक अवाई: 24-2-92

अवार्ड

केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण की अधि निर्णयार्थ हेतु अपनी अधिसूचना सं० एल. 40012/42/89-डी-2(बी) दिनांक 30-10-89 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) (घ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है --

Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer(I) Bikaner is justified in terminating the services of Shri Badri Prasad, Casual Labour Class IV employee w.e.f. 1-8-85? If not, to what relief is the worker entitled?

2. प्रार्थी बद्रीप्रसाद, जिसे श्रमिक सम्बोधित किया गया है, ने जरिये क्लेम प्रकट किया कि उसकी नियुक्ति 1-10-81 को दैनिक वेतन पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर केजुअल लेबर मजदूर के रूप में की गई थी। और उसे दिनांक 1-8-85 से मौखिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया। श्रमिक कहता है कि उसने प्रत्येक वर्ष में 240 दिवस से अधिक सेवा पूरी करली थी परन्तु फिर भी उसे सेवा मुक्ति के समय धारा 25 एफ के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया और न ही उस जैसे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची घोषित की तथा पहले "आये पीछे जाये" के सिद्धान्त का पालन नहीं किया। श्रमिक कई कनिष्ठ कर्मचारी नियोजित थे और इस प्रकार नियोजक ने धारा 25 एफ व 25 जी एवं नियम 77 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है और इस प्रकार सेवा मुक्ति के आदेश को अपास्त करते हुए सबेतेन नियोजन में रखा जाये।

3. अप्रार्थी नियोजक ने जरिये प्रति उत्तर क्लेम के कथनों को अस्वीकार करते हुए कहा है कि दिनांक 1-8-85 को प्रार्थी स्वयं अपनी इच्छा से कार्य छोड़कर चला गया। उसे कार्य से नहीं हटाया उसे मौखिक रूप से कई बार तथा 14-5-87 को रजिस्टर्ड पत्र ए. डी. द्वारा भी बुलाया गया था परन्तु वह कार्य पर उपस्थित नहीं

हुआ। नियोजक के अनुसार नोटिस अथवा उसकी एबज में एक माह का वेतन या छटनी भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थी की अन्य जगह नौकरी लग गई थी इसलिए भी उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह भी कहा है कि रेलवे केजुअल लेबर यूनियन, बीकानेर को श्रमिक के मामले में कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है न तो उक्त यूनियन भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही श्रमिक उसका सदस्य है। श्रमिक भी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आता है और अप्रार्थी संस्थान इण्डस्ट्री की परिभाषा में नहीं आता है विभाग द्वारा सेवा नियम बनाये हुए हैं इसलिए भी औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

4. अपने कथनों के समर्थन में श्रमिक बद्रीप्रसाद ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्यापित कराया जिससे नियोजक प्रतिनिधि ने जिरह की। इसके विपरीत नियोजक की तरफ से श्री दर्शन सिंह ने शपथ पत्र पेश किया जिससे श्रमिक प्रतिनिधि ने जिरह की। प्रलेखिक साक्ष्य में नियोजक की ओर से प्रदर्श-एम-1 लगायत एम-5 प्रलेखों की फोटो प्रतियां पेश की तत्पश्चात् मैंने पत्रावली का अवलोकन किया और पक्षकारों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक सुना।

5. क्लेम के प्रति उत्तर में तो नियोजक ने कहा है कि प्रार्थी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आता है और अप्रार्थी संस्थान "उद्योग" की परिभाषा में नहीं आता है। परन्तु न तो क्लेम में स्पष्ट किया गया कि प्रार्थी किस प्रकार वर्कमैन नहीं है और अप्रार्थी संस्थान किस प्रकार उद्योग नहीं है। नियोजक साक्षी दर्शन सिंह ने भी अपने शपथ पत्र में उक्त तर्क बाबत नाममात्र का भी कथन नहीं किया और न ही नियोजक प्रतिनिधि ने श्रमिक बद्रीप्रसाद से उक्त विषय बाबत प्रतिपरीक्षा की। निर्विवाद रूप से प्रार्थी बद्रीप्रसाद को दैनिक वेतन पर नियोजित किया गया था और उसका मासिक वेतन भी बहुत कम था इसलिए वह वर्कमैन ही पाया जाता है। अप्रार्थी संस्थान में भी सिस्टेमेटिक एक्टिविटी है तथा नियोजक और नियोजाति के सहयोग से ही समाज की सेवा की जाती है इसलिए बंगलौर वाटर सप्लाई बनाम एन० राजप्पा के अनुसार अप्रार्थी संस्थान "उद्योग" की परिभाषा में आता है। अतः उपरोक्त समस्त कारणों से प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

6. गुणावगुण पर क्लेम की तरह ही श्रमिक कहता है कि उस सेवा मुक्ति से पूर्व एक वर्ष में 240 दिवस से अधिक कार्य किया था नियोजक साक्षी श्री दर्शन सिंह भी साक्ष्य में कहता है कि प्रदर्श डब्ल्यू 2 के अनुसार उसने 381 दिन काम किया है। इन परिस्थितियों में यह साबित है कि धारा 25 (एफ) के प्रावधान श्रमिक पर लागू हो जाते हैं। निर्विवाद रूप से सेवा मुक्ति के समय न तो एक माह का नोटिस दिया गया अथवा नोटिस की एबज में एक माह का वेतन भी नहीं दिया गया। और न ही छटनी भत्ता दिया गया है इसलिए तथाकथित सेवा मुक्ति धारा 25 (एफ) के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वतः ही अनुचित एवं अवैध तथा शून्य है।

7. नियोजक का कथन यह है कि 1-8-85 को श्रमिक स्वयं काम छोड़कर चला गया परन्तु प्रतिपरीक्षा करने पर श्रमिक कहता है कि 1-8-85 के बाद भी वह बराबर डिपार्टमेंट में गया था परन्तु उसे काम पर नहीं लिया। उसने श्री मल्होत्रा साहब सहायक एस. डी. ओ० को पत्र दिये थे और बोला था काम पर ले लूंगा लेकिन काम पर नहीं लिया अगर वास्तव में श्रमिक काम छोड़ कर गया था तो उसे उक्त विषय का लिखित नोटिस काम छोड़ने का क्यों नहीं दिया गया। तर्क के लिए यह मान भी लें कि श्रमिक स्वयं काम छोड़कर गया था तो भी नियोजक के स्थाई आदेशों के अनुसार यह एक दुराचरण था जिसके लिए नियमानुसार आरोप अधिरोपित कर जांच कराकर ही श्रमिक को दण्डित कर सकता अपेक्षित था। इस विषय में 1988 (2) एल. एल. एन.-259, 1986 (1) एल. एल. एन.-912, के अलावा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टान्त रोबर्ट डिसूज

बनाम सर्वान्न रेखे, 1982 (1) एल. एल. एन. - 257 का भी हवाला दिया जा सकता है जो उपरोक्त सिद्धान्त का समर्थन करता है।

8. नियोजक पक्ष की एक आपत्ति यह भी थी कि श्रमिक प्राथी संघ को सदस्य नहीं है और प्राथी संघ अधिपति द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए उसे विवाद उठाने का अधिकार नहीं है। उक्त तथ्यों की बावत न तो नियोजक साक्षी ने अपने शपथ पत्र में कुछ कहा है और न ही अन्य कोई मौखिक व प्रलेखिक साक्ष्य पेश की गई है। श्रमिक बट्टी प्रसाद से भी इस विषय में प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। श्रमिक ने ही क्लेम की चरण संख्या 8 में दर्ज किया है कि बातचीत के जरिये उसकी यूनियन ने विवाद का हल करने की कोशिश की थी जिसका वह सदस्य है परन्तु वार्ता असफल होने के कारण केन्द्रीय सरकार ने यह औद्योगिक विवाद इस न्यायाधिकरण में भेजा है। अपने शपथ पत्र की श्री चरण सं. 8 में बट्टी प्रसाद ने उक्त तथ्यों का उल्लेख किया है परन्तु फिर भी उससे प्रतिपरीक्षा नहीं की गई इसलिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से तो यही साबित है कि श्रमिक बट्टी प्रसाद प्राथी संघ का सदस्य है। तर्क के लिए यह मान भी लिया जाये कि प्राथी संघ को विवाद उठाने का अधिकार नहीं था तो भी चूंकि श्रमिक की सेवा मुक्ति का विवाद है और क्लेम भी श्रमिक ने स्वयं पेश किया है इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (ए) के अंतर्गत भी श्रमिक का विवाद चल सकता है, अतः यह नियोजक की आपत्ति भी निराधार होने से खारिज की जाती है।

9. श्रमिक ने क्लेम में यह दर्ज किया है कि सेवा मुक्ति से पूर्व नियोजक ने उस जैसे कर्मचारी की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई और न

ही पहले आओ पीछे जाओ के सिद्धान्त का पालन किया। क्लेम के प्रति उत्तर में नियोजक ने नहीं कहा कि ऐसी कोई वरिष्ठता सूची बनाई गई हो या उक्त सिद्धान्त का पालन किया गया हो बल्कि इतना ही कहा है कि धारा 20 (जी) व नियम 77 लागू नहीं होते हैं क्लेम के अनुसार ही बट्टी प्रसाद ने अपने शपथ पत्र में भी उक्त तथ्यों को अंकित किया है फिर भी न तो श्रमिक से उक्त विषय में प्रतिपरीक्षा की गई और न ही नियोजक साक्षी दर्शन सिंह ने अपने शपथ पत्र में इस बाबत कुछ कथन किया। अगर वास्तव में वरिष्ठता सूची बनाई गई होती तो उसका उल्लेख क्लेम के प्रति उत्तर में होता तथा ऐसी वरिष्ठता सूची प्रस्तुत की जाती। अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं उपरोक्त परिस्थितियों से मेरी राय में श्रमिक जैसे श्रमिकों की वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई थी इसलिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (जी) एवं औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमावली, 1957 की नियम 77 का भी उल्लंघन किया गया है। अतएव उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का अधिनियम निम्न प्रकार से किया जाता है—

श्रमिक बट्टी प्रसाद केजुअल लैबर क्लास फॉर्य को दिनांक 1-8-85 से सेवा मुक्त करना न्यायोचित नहीं है और इसे सेवा में नियोजित घोषित किया जाता है तथा इसे 1-8-85 से ही उक्त पद का वेतन व अन्य सभी लाभ दिलाये जाते हैं। श्रमिक को 100 रु. खर्चा मुकदमा दिलाया जाता है। अगर नियोजक तीन माह में उक्त राशि अदा नहीं करेगा तो उक्त राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर ब्याज भी श्रमिक को अदा करेगा। उक्त आशय का अवार्ड पारित किया जाता है, जिसे प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17 (1) अधिनियम भेजा जावे।

जगत सिंह, न्यायाधीश